राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 246

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 12 फरवरी 2020

www.jagran.com

पृष्ठ 16

दिल्लीवालों गजब कर दिया आपने, आइ लव यू। मैं सभी दिल्लीवासियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार अपने बेटे पर भरोसा किया। हनुमान जी का मुझ पर आशीर्वाद है।
–अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री

फिर आप की हुई दिल्ली

नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद आप कार्यालय में लोगों का धन्यवाद करते (बाएं से) राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ● ध्रुव कुमार

आप की ताकत

- आप सरकार का शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए शानदार काम, मुफ्त बिजली-पानी, महिलाओं के लिए निशुल्क बस यात्रा
- चुनावी घोषणा पत्र में किए गए दावों पर भी मतदाताओं ने विश्वास जताया
- मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल की लोकप्रियता जीत का बड़ा कारण
- चुनाव प्रचार में आक्रामक बयान से परहेज, सकारात्मक दावों पर जोर
- आरोप-प्रत्यारोप से दूरी, अपने किए काम को जनता तक पहुंचाना
- महिलाओं का भरोसा, एक्सिस माय इंडिया के एक्जिट पोल के मुताबिक 53 फीसद पुरुषों और 59 फीसद महिलाओं का आप को वोट देना

भाजपा की कमजोरी

- मुख्यमंत्री के चेहरे का न होना
- बड़े नेताओं की भीड़ और आक्रामक प्रचार के बीच स्थानीय मुद्दे पीछे छूटे
- केजरीवाल के खिलाफ नकारात्मक प्रचार पर जोर भी खिलाफ गया
- सीएए, एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन का लंबा खिंचना
- कांग्रेस का अनमने ढंग से चुनाव लड़ने का भी आप को फायदा मिला

कांग्रेस की नाकामी

- शीला दीक्षित से आगे नहीं सोच पाना कांग्रेस पर भारी पड़ा
- पूरे चुनाव प्रचार के दौरान ठोस मुद्दों का अभाव नजर आया
- चुनाव प्रचार में बड़े नेता औपचारिकता पूरी करते दिखे। राहुल और प्रियंका आखिरी दो दिनों में सक्रिय हुए
- राहुल गांधी का पीएम मोदी पर दिया गया विवादित बयान भारी पड़ा
- पूरे चुनाव अभियान में स्थानीय से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक विफल रहा

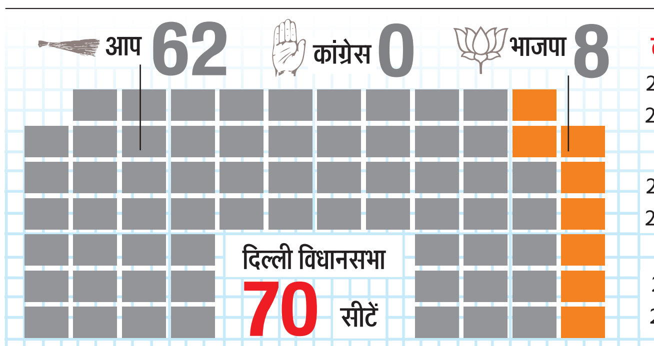

वोट फीसद

	2015	2020
आम आदमी पार्टी	54	53.57
भारतीय जनता पार्टी	32	38.51
कांग्रेस	10	4.26

क्या कहते हैं वोट के आंकड़े

- आप ने सीटें भले ही सबसे ज्यादा जीतीं पर भाजपा को पिछली बार से 6.51 फीसद ज्यादा वोट मिले। भाजपा की 5 सीटें भी बढ़ीं।
- आप की सीटें घटीं। उसे मिले मतदान फीसद में मामूली कमी आई।
- आंकड़े बता रहे हैं कि द्विपक्षीय मुकाबले का फायदा आप को मिला
- कांग्रेस इस बार भी कोई सीट नहीं जीत सकी है। उसका वोट फीसद भी पिछली बार से 5.74 फीसद घट गया है।
- 2013 में कांग्रेस को 24.55 फीसद वोट व आठ सीटें मिली थीं। वहीं, आप को 29.49 फीसद वोट व 28 सीटें मिली थीं।

केजरीवाल की पत्नी को जन्मदिन का तोहफा

11 फरवरी को अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता का जन्मदिन भी था। भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) की पूर्व अफसर रहीं सुनीता ने कहा कि वह अपने जन्मदिन पर इससे बेहतर तोहफे की उम्मीद नहीं कर सकती थीं जो दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है।

43108 वोट नोटा (कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं) को पड़े, जो कुल मतदान का 0.5 फीसद है।

46 मौजूदा विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा था आप ने, इनमें से 44 ने जीत दर्ज की

प्रत्याशी	जीत का अंतर
अरविंद केजरीवाल	21,650
मनीष सिसोदिया	3,207
राघव चड्ढा	20,058
आतिशी	11,393
अमानतुल्लाह खां	71,823

आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को मेरी तरफ से जीत के लिए बधाई और शुभकामनाएं।
राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के लिए आप और अरविंद केजरीवाल को बधाई। दिल्ली के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं।
नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

केजरीवाल तीसरी बार बनेंगे मुख्यमंत्री

- विस चुनाव में 70 में से 62 सीटें जीतीं
- 14 को रामलीला मैदान में शपथ संभव
- 17 आप विधायकों ने भी लगाई हैट्रिक

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली की जनता ने फिर अरविंद केजरीवाल पर विश्वास जताया है। सरकार के पांच साल में किए गए विकास कार्यों का जादू इस कदर चला कि आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 62 सीटें जीतकर जबर्दस्त सफलता का इतिहास दोहरा दिया। कांग्रेस इस बार भी खाता नहीं खोल सकी। भाजपा को वोट प्रतिशत में वृद्धि के साथ पांच सीटों का भी फायदा हुआ। उसे आठ सीटें मिली हैं। वहीं, केजरीवाल की अगुआई में आप दिल्ली में लगातार तीसरी बार जीतकर सरकार बनाएगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुक्रवार 14 फरवरी को रामलीला मैदान में हो सकता है, हालांकि इस बारे में अंतिम फैसला बुधवार को आप विधायक दल की बैठक में होगा।

दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल के बिजली, पानी, शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कामों और महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के फैसले को भरपूर समर्थन दिया है। यही वजह है कि आप अपना जनाधार बरकरार रखने में कामयाब रही।

लगातार दूसरी बार 60 से ज्यादा सीटें : पिछले विधानसभा चुनाव (2015) में आप ने 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटें जीतकर इतिहास रचा था। आप लगातार दूसरी बार दिल्ली में 60 से अधिक सीटें जीतकर सत्ता में आई है। दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में शीला दीक्षित की तीन बार सरकार रही थी, लेकिन कांग्रेस कभी 60 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी।

तीन लोस क्षेत्र में आप का क्लीन स्वीप: इस चुनाव में आप ने सात लोकसभा क्षेत्र में से तीन पश्चिमी दिल्ली, नई दिल्ली, चांदनी चौक की सभी 30 विधानसभा सीटें जीत ली हैं। पार्टी के सभी दिग्गज जीतने में सफल रहे हैं। इनमें केजरीवाल, गोपाल राय, सत्येंद्र जैन, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, राजेंद्र पाल गौतम, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, उपाध्यक्ष राखी बिड़ला व सौरभ भारद्वाज शामिल हैं। भाजपा सांसद गौतम गंभीर के लोकसभा क्षेत्र पूर्वी दिल्ली व मनोज तिवारी के लोकसभा क्षेत्र उत्तर-पूर्व दिल्ली से पार्टी को तीन-तीन विधायक मिले। वहीं, दक्षिण दिल्ली, उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से एक-एक विधायक जीते हैं।

कांग्रेस के 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त

कांग्रेस के 66 में से 63 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। उसके उम्मीदवार किसी भी सीट पर दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे। शीला सरकार में मंत्री रहे डॉ. एके वालिया, अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, डॉ. नरेंद्र नाथ सहित कांग्रेस के सभी दिग्गजों को करारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री आरपी सिंह भी चुनाव हार गए।

जनादेश (विशेष) पेज-4,5
दिल्ली का जनादेश (संपादकीय)

सरोकार

करेगा मधुमेह की जांच और बताएगा कि कितना इंसुलिन लें

धनबाद : आइआइटी के छात्रों ने सिर्फ दो हजार रुपये में ऐसा उपकरण तैयार किया है, जिसमें इंसुलिन पेन और ग्लूकोमीटर दोनों उपलब्ध हैं। यह शर्करा का स्तर तो बताएगा ही, यह भी तुरंत बताएगा कि कितना इंसुलिन लें। इस उपकरण का वजन महज 70 ग्राम है। यह बाजार में उपलब्ध उपकरणों से कहीं सस्ता व कारगर है। (पेज-11)

जागरण विशेष

अब स्टीव वॉ की किताब में छाएगा क्रिकेट का 'वंडर किड'

कोलकाता : अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाला तीन साल का शेख शाहिद अब क्रिकेट बुक में छाने को तैयार है। यह किताब कोई और नहीं पूर्व क्रिकेटर स्टीव वॉ लिख रहे हैं, जो शाहिद से मिलने चुपचाप उसके घर पहुंचे। ऑस्टेलिया के दिग्गज खिलाड़ी ने शाहिद के साथ क्रिकेट खेला, तस्वीरें खिंचवाने के साथ ही भविष्य संवारने में मदद का भरोसा भी दिया। (पेज-11)

अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण साफ दिखाई दे रहे : सीतारमण

- लोकसभा में वित्त मंत्री ने गिनाए सात 'ग्रीन शूट्स'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अर्थव्यवस्था की दिशा और सुधार के संकेत को लेकर बार-बार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों में सात 'ग्रीन शूट्स' (सुधार के अच्छे संकेत) गिनाए हैं। लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने आंकड़ों के साथ यह भी साबित किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अर्थ प्रबंधन पूर्व की यूपीए सरकार से हर लिहाज में बेहतर है।

वित्त मंत्री ने आम बजट में उठाए गए 13 विभिन्न कदमों के जरिये यह भी दावा किया कि अर्थव्यवस्था के समक्ष जो भी चुनौतियां हैं उनके समाधान की सारी कोशिशें की गई हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के लक्षण गिनाते हुए उन्होंने कई तर्क रखे। सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर भारत को लेकर बने सकारात्मक माहौल, पाइपलाइन में चल रही इन्फ्रा परियोजनाओं, औद्योगिक उत्पादन में सुधार, बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार को अच्छी आर्थिक सेहत का लक्षण बताया। जीएसटी संग्रह में सुधार व मैन्यूफैक्चरिंग इंडेक्स को भी वित्त मंत्री ने सुधार के लक्षणों में गिनाया।

कांग्रेस के काबिल डॉक्टरों ने अर्थव्यवस्था का किया गलत इलाज : निर्मला पेज>>12

ऐसे सुधर रही आर्थिक सेहत

- भारत को लेकर सकारात्मक वैश्विक माहौल। चालू वित्त वर्ष के पहले आठ माह में विदेशी निवेश 24.4 अरब डॉलर पर पहुंचा, जो पहले 21.4 अरब डॉलर था।
- 106 लाख करोड़ रुपये की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पाइपलाइन में। इनसे भी अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- औद्योगिक उत्पादन में कई माह से जारी गिरावट थमी। नवंबर, 2019 में औद्योगिक उत्पादन दर 1.8 फीसद रही।
- मैन्यूफैक्चरिंग का पीएमआइ इंडेक्स भी सकारात्मक है। यह अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है।
- विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 466.69 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है।
- जीएसटी संग्रह भी पिछले कुछ माह से यह एक लाख करोड़ रुपये के स्तर से ऊपर चल रहा है। जनवरी, 2020 में जीएसटी संग्रह 1.18 लाख करोड़ रुपये रहा था।
- प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में भी तेजी दिखने लगी है। आंकड़े अब इनमें सुधार की गवाही दे रहे हैं।

रिश्तों को मजबूती देने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप आएंगे भारत

- दो दिन की यात्रा पर 24 को पहुंचेंगे नई दिल्ली, अहमदाबाद भी जाएंगे
- दो अहम रक्षा सौदों समेत तीन बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर के आसार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा की तारीख तय हो गई है। ट्रंप 24 फरवरी को दिल्ली पहुंचेंगे। दो दिन के प्रवास के दौरान वह अहमदाबाद भी जाएंगे। उनकी यात्रा की घोषणा दोनों देशों की सरकार की तरफ से मंगलवार को अलग-अलग की गई। इस दौरान ट्रंप की पीएम नरेंद्र मोदी से चार से पांच दफे मुलाकात होगी। दोनों देशों के बीच कई समझौते हो सकते हैं, जिनमें दो अहम रक्षा सौदे भी शामिल हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 'पीएम नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पत्नी मेलानिया के साथ 24-25 फरवरी, 2020 को भारत आएंगे। यह राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। ट्रंप दंपती दिल्ली और अहमदाबाद में भारतीय समाज के कई वर्गों से मिलेंगे। भारत-अमेरिका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी सामान मूल्यों, आदर व आपसी सूझबूझ पर आधारित है। मोदी व ट्रंप की अगुवाई में दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। कारोबार, रक्षा, ऊर्जा, आतंकरोधी अभियान, क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर दोनो देशों के बीच सहयोग काफी प्रगाढ़ हुए हैं। इस दौरे के दौरान दोनों नेताओं को रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने का मौका मिलेगा।' उधर, वाशिंगटन में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम ने कहा, 'पिछले सप्ताहांत मोदी-ट्रंप के बीच टेलीफोन पर बात हुई थी जिसमें भारत दौरे पर अंतिम सहमति बनी थी। यह यात्रा रणनीतिक रिश्तों को और प्रगाढ़ करेगी।' ट्रंप कार्यकाल के आखिरी साल में भारत आ रहे हैं। वैसे मोदी-ट्रंप की कई बार भेंट हो चुकी है। जून, 2017 में वाशिंगटन में मोदी पहली बार ट्रंप से मिले थे। मोदी ने उन्हें भारत यात्रा का न्योता दिया था। 2019 में उन्हें गणतंत्र दिवस पर बुलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इच्छा के बावजूद ट्रंप नहीं आ सके थे।

डोनाल्ड ट्रंप फाइल फोटो

वर्ष 2000 के बाद हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने की भारत की यात्रा पेज>>3

प्रोन्नति में कोटे के विवाद में सभी विकल्पों पर काम शुरू

- फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और विधेयक जैसे कदमों पर सरकार कर रही मंथन
- कानूनी पहलुओं के अध्ययन के लिए भी लगाई टीम, कई राज्यों में इसे लेकर है विवाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पदोन्नति में आरक्षण पर उठे विवाद के बड़ा बवाल बनने से पहले ही केंद्र सरकार इसका रास्ता तलाशने में जुट गई है। उन सभी कानूनी पहलुओं पर विचार हो रहा है जो संभव हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और संसद में इसे लेकर विधेयक लाने जैसे विकल्पों को भी प्रमुखता से रखा गया है।

सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को इससे जुड़े कानूनी पहलुओं को जुटाने के काम में लगाया है। साथ ही उन राज्यों से भी संपर्क करने को कहा है जहां पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है। मौजूदा समय में उत्तराखंड ही नहीं, देश के कई राज्यों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है। इनमें मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। जिनके मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसके साथ ही कानूनविदों के साथ भी चर्चा शुरू कर दी गई है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को सक्रियता से लगाया गया है। जबकि पीएमओ के स्तर पर भी मंथन चल रहा है।

इससे पहले सरकार एससी-एसटी उत्पीड़न विरोधी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आए फैसले पर भी इसी तरह से एक विधेयक संसद में लाई थी। जिसके तहत उनके उत्पीड़न को रोकने के कानून के पुराने स्वरूप को बहाल कर दिया था।

सूत्रों के मुताबिक यदि विधेयक लाने का फैसला हुआ तो इसे बजट सत्र के दो मार्च से शुरू होने वाले अगले चरण में संसद में पेश किया जाएगा। एक मत पुनर्विचार याचिका का भी है, लेकिन वैसी स्थिति में मामला कोर्ट में रहते हुए विधेयक लाना थोड़ा असहज हो सकता है। पदोन्नति में आरक्षण का यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब उत्तराखंड के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि यह मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य सरकारें इस पर अपने विवेक से फैसला कर सकती हैं।

बड़ा काम

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में गर्बाधार से चीन सीमा लिपूलेख तक बन रही है 75 किलोमीटर लंबी सड़क, सामरिक दृष्टि से बेहद है इस सड़क का बनना

चीन सीमा अब चार किमी दूर, मालपा तक सड़क तैयार

- नेपाल-चीन सीमा पर तैनात जवानों को होगा फायदा
- कैलास मानसरोवर यात्रियों को होगा सीधा फायदा
- सीधे वाहन से चीन सीमा तक पहुंच सकेंगे

तेज सिंह गुंज्याल, पिथौरागढ़

उत्तर भारत को चीन से जोड़ने के लिए उत्तराखंड में बनाई जा रही गर्बाधार- लिपूलेख सड़क का काम मालपा तक पूर्ण हो गया है। अब मात्र चार किलोमीटर का काम बाकी है, जो इस वर्ष पूरा हो जाएगा। इसे नेपाल सीमा के समानांतर बनाया गया है। सड़क तैयार होने के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जवानों को काफी फायदा होगी। इसके साथ ही कैलास मानसरोवर यात्रियों की राह भी आसान हो जाएगी। श्रद्धालु सीधे वाहन से चीन सीमा तक पहुंच सकेंगे।

भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क के तैयार होने से जवानों का नेपाल एवं चीन सीमा क्षेत्र तक आवागमन आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें सीमा तक आवश्यक सामाग्री पहुंचाने में भी मदद मिलेगी। अभी तक यह काम घोड़े और खच्चरों की मदद से किया जाता रहा। घोड़े और खच्चरों के माध्यम से धारचूला से अंतिम सीमा क्षेत्र तक पहुंचने में चार दिन का समय लगता है, लेकिन सड़क तैयार होने के बाद यह सफर एक दिन में ही पूरा हो जाएगा।

सबसे बड़ी बाधा पार : गर्बाधार से चीन सीमा लिपूलेख तक 75 किमी सड़क का निर्माण हो रहा है। इसमें सबसे दुर्गम माने जाने वाले मालपा तक सड़क तैयार कर सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने बड़ी बाधा पार कर ली है। असल में गर्बाधार से नजंग होते हुए मालपा तक सड़क निर्माण बीआरओ के लिए चुनौती था। 2006 में गर्बाधार से काम शुरू हुआ। मात्र नौ किमी सड़क तैयार करने में 14 साल लग गए। 2006 से 2017 तक पहाड़ काटकर मात्र तीन किमी सड़क बनाई जा सकी। काम में देरी होते देख 2017 में बीआरओ ने यह जिम्मा निजी कंपनी गर्ग एंड गर्ग को सौंप दिया था। यह प्रयोग सफल रहा। 2017 से अब तक 6.4 किमी सड़क तैयार हो गई। अब बस बीच में चार किमी की सड़क और तैयार करनी है।

अंतिम भारतीय पड़ाव तक आसान होगी आवाजाही : गर्बाधार- लिपूलेख मार्ग कैलास मानसरोवर यात्रियों के लिए विशेष लाभकारी होगा। बीआरओ का दावा है कि अक्टूबर से नवंबर तक गर्बाधार से अंतिम भारतीय पड़ाव नावीढांग तक सड़क तैयार कर ली जाएगी।

पिथौरागढ़ के मालपा में मंगलवार को तैयार सड़क का निरीक्षण करते सीमा सड़क संगठन व सेना के अधिकारी। साभार : सीमा सड़क संगठन

तो मालपा में बाधित नहीं होगी यात्रा

कैलास मानसरोवर यात्रा मालपा क्षेत्र में सर्वाधिक बाधित होती रही है। कठोर चट्टान वाले इस इलाके में अक्सर भूस्खलन होते रहते हैं। तीन वर्ष पहले यहां आई भीषण आपदा के कारण यात्रा को बीच में ही रोकना पड़ा था। बीते वर्ष भी भूस्खलन के कारण कैलास यात्रा करीब 15 दिनों तक बाधित रही। अब मालपा तक सड़क तैयार होने से यात्रा में आसानी होगी।

बीआरओ कमांडर मालपा पहुंचे

मालपा तक सड़क तैयार होने के बाद बीआरओ के कमांडर सोमेंद्र बनर्जी सैन्य अधिकारियों के साथ मंगलवार को मालपा पहुंचे। उन्होंने सड़क का निरीक्षण भी किया।

तबादला प्राथमिक अध्यापकों का अधिकार नहीं : हाई कोर्ट

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अध्यापकों की तबादला नीति में दखल से इन्कार

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों की तबादला नीति के तहत महिला-पुरुष शिक्षकों या उनके परिवार के सदस्यों की गंभीर बीमारी की दशा में वरीयता देने को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा, प्राथमिक अध्यापकों के तबादले के लिए दो दिसंबर 2019 को जारी नीति न तो संविधान के अनुच्छेद 14 के खिलाफ है न विरोधाभाषी। कोर्ट ने कहा, प्राथमिक अध्यापक को शहर से ग्रामीण या ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में तबादला कराने का अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति एसपी केशरवानी ने मनोज कुमार व 29 अन्य अध्यापकों की अर्जी खारिज करते हुए कहा, तबादला नीति में शर्तें लगाना प्रशासन का कार्य है जब तक वह मनमाना या संविधान विरोधी न हो तब तक कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। याचिका में तबादला नीति के कालम 8(4) की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। जिसके तहत पांच क्वालिटी प्वाइंट देकर अध्यापिकाओं को वरीयता देने की व्यवस्था की गई है। कोर्ट ने कहा, महिलाओं को वरीयता देने से कानून का उल्लंघन नहीं होता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइल फोटो

23.0 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान मंगलवार को रहा राजधानी में, जबकि न्यूनतम 5.9 सेल्सियस दर्ज किया। बुधवार को आसमान साफ रहेगा।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 12 फरवरी 2020

नोएडा प्राधिकरण के नौ पूर्व अधिकारियों की गिरफ्तारी तय

नोएडा क्रिकेट स्टेडियम घोटाला ▶ अगस्त में प्राधिकरण से आरोपितों को गिरफ्तार करने और चार्जशीट दाखिल करने मांगी थी अनुमति

सीबीआइ को शासन की ओर से कार्रवाई की संस्तुति मिली

कुंदन तिवारी, नोएडा

नोएडा क्रिकेट स्टेडियम घोटाले में आरोपित नौ पूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों की गिरफ्तारी किसी भी समय सीबीआइ कर सकती है। अगस्त 2019 में आरोपित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की चार्जशीट दाखिल की और उन्हें गिरफ्तार करने की अनुमति नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखकर सीबीआइ ने मांगी थी। मामले पर अब सीबीआइ को शासन की ओर से कार्रवाई की संस्तुति प्रदान कर दी गई है। तीनों प्राधिकरणों के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह की सोमवार को सीबीआइ की ओर से दोबारा गिरफ्तारी करने के बाद अब अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। इससे नोएडा प्राधिकरण में हड़कंप मचा हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2010-11 में सेक्टर-21 ए स्थित नोएडा स्टेडियम में नोएडा स्टेडियम पवेलियन सहित अन्य निर्माण के लिए नोएडा प्राधिकरण की ओर से करीब 60 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया गया था। इसके निर्माण को पूरा करने में 300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया गया है, लेकिन अभी कई सौ करोड़ रुपये का काम स्टेडियम में बाकी है। वर्ष 2015 में जब यादव सिंह के खिलाफ सीबीआइ ने अंडरग्राउंड केबलिंग में 954.38 करोड़ रुपये का मुकदमा दर्ज किया तो उस समय नोएडा स्टेडियम प्रकरण की एफआइआर को इसी के साथ जोड़ दिया गया। नोएडा क्रिकेट स्टेडियम जांच के प्रथम चरण की कार्रवाई में टेंडर जारी करने में भारी अनियमितताएं मिली हैं। इसमें नोएडा प्राधिकरण में उस समय तैनात नौ लोगों की सीधी संलिप्तता सामने आई। सीबीआइ ने अपने पत्र में सभी के नामों को उनके पदनाम के जरिये स्पष्ट किया है। इसमें तत्कालीन वित्त नियंत्रक से लेकर संविदा पर तैनात जेई तक शामिल हैं। इन पर एफआइआर दर्ज कर गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी गई थी, जिसे शासन ने 31 दिसंबर को संस्तुति प्रदान कर दी है। हालांकि इस संस्तुति में तत्कालीन मुख्य परियोजना अभियंता संतराम का नाम नहीं शामिल है। वह मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता के पद पर तैनात बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम शासन स्तर पर जारी कार्रवाई की संस्तुति में नहीं होने से एक बार फिर से साठगांठ उजागर कर रहा है। यह फिर से चर्चा का केंद्र बन चुका है। वहीं वित्त एवं लेखा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से तत्कालीन वित्त नियंत्रक एसी सिंह पर कार्रवाई की संस्तुति प्रदान कर दी गई है।

संगठित तरीके से टेंडर घोटाले को दिया गया अंजाम : सीबीआइ की जांच में 80 लाख रुपये का हेरफेर पाया गया है। टेंडर जारी करने के लिए एक ही कंसलटेंट कंपनी को दोबारा से शामिल कर लिया गया। टेंडर हासिल करने वाली कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर किया था, जबकि नोएडा प्राधिकरण के टेंडर प्रक्रिया में ज्वाइंट वेंचर को टेंडर जारी करने का प्रावधान नहीं था। हालांकि इस नियम पर तत्कालीन वरिष्ठ परियोजना अभियंता संदीप चंद्रा ने आपत्ति लगाई थी, लेकिन बाद में इस टेंडर को पास किया गया। चूंकि संदीप चंद्रा ने अपनी नोटिंग में यह स्पष्ट किया है कि इन्हें ज्वाइंट वेंचर को टेंडर जारी करने के प्रावधान के बारे में नहीं पता था इसलिए उन्होंने ये भी लिखा है कि यदि मुख्य टेंडर कंपनी अपने संपूर्ण अनुभव के नियम का पालन करती है तो उसकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी से कोई आपत्ति नहीं है।

नोएडा स्टेडियम में निर्माण में घोटाले का है आरोप। (फाइल)

टेंडर घोटाले के आरोपित की सूची

नाम	पद पर तैनाती
दीपक कुमार	अवर अभियंता
आरके जौहरी	अवर अभियंता (टेक्निकल)
अनिल शर्मा	अवर अभियंता (संविदाकर्मी)
आरके जैन	सहायक परियोजना अभियंता
एसके गुप्ता	परियोजना अभियंता
संतोष कुमार श्रीवास्तव	मुख्य परियोजना अभियंता
संतराम	मुख्य परियोजना अभियंता
यादव सिंह	मुख्य अनुरक्षण अभियंता (जल)
एसी सिंह	वित्त नियंत्रक

कोर्ट ने यादव सिंह को दो दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

सीबीआइ कोर्ट परिसर से सोमवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआइ द्वारा गिरफ्तार किए गए नोएडा टेंडर घोटाले के मुख्य आरोपित यादव सिंह को अदालत में पेश किया गया। सीबीआइ की टीम ने विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत में अर्जी देकर आरोपित यादव सिंह का सात दिन पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने इसका जमकर विरोध किया। वहीं, अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित का 48 घंटे पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है। अब सीबीआइ की टीम 13 फरवरी को शाम पांच बजे आरोपित को अदालत में पेश करेगी।

मंगलवार दोपहर बाद दिल्ली सीबीआइ ब्रांच की टीम आरोपित यादव सिंह को लेकर गाजियाबाद स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत पहुंची।

सीबीआइ ने आरोपित को कोर्ट में पेश कर सात दिन पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की। सीबीआइ ने दलील दी कि उन्हें यादव सिंह को रिमांड पर लेकर केस के संबंध में पूछताछ करनी है और संबंधित दस्तावेज जुटाने हैं। वहीं, बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि यादव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही तीन अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है, जिसके बाद भी सीबीआइ ने उन्हें गिरफ्तार किया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित यादव सिंह का 48 घंटे का पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर किया है।

सीबीआइ से मिली जानकारी के अनुसार, 2007 से 2012 के बीच यादव सिंह नोएडा प्राधिकरण में मुख्य अभियंता के तौर पर तैनात था। इस बीच उसने 29 निजी फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को दरकिनार कर 116.39 करोड़ रुपये के टेंडर बांट दिए थे। इनमें कई ऐसी फर्म थीं, जो उसके परिवार के सदस्यों और दोस्त संजय गुप्ता, संजय शर्मा और जावेद के नाम रजिस्टर्ड थीं। जिससे नोएडा प्राधिकरण को भारी नुकसान हुआ और ठेकेदारों व फर्मों को फायदा हुआ। आरोप है कि यादव सिंह ने प्राधिकरण में रहते हुए फर्म को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें गलत तरीके से टेंडर जारी किए थे।

मनमाने तरीके से फीस का निर्धारण नहीं कर पाएंगे निजी विद्यालय

जासं, गाजियाबाद : निजी विद्यालय अब मनमाने तरीके से फीस का निर्धारण नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जनपद के सीबीएसई व आइसीएसई से संबद्ध स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए डीआइओएस (जिला विद्यालय निरीक्षक) ने एक सप्ताह में सभी निजी स्कूलों को पीटीए (पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन) का गठन करने के निर्देश दिए है। पीटीए के पदाधिकारी मिलकर स्कूल फीस का निर्धारण करेंगे। इसके साथ ही यह भी कहा कि सभी स्कूल सर्कुलर के अनुसार एनसीईआरटी पाठ्यक्रम ही लागू करें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

जिला विद्यालयों निरीक्षक के आदेश पर सभी विद्यालयों में पीटीए का गठन होने से अभिभावकों को काफी राहत मिलने वाली है। इससे फीस को लेकर आए दिन होने वाली खींचातान से भी निजात मिल जाएगी। साथ ही निजी विद्यालय मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी नहीं कर पाएंगे। पीटीए गठित होने से विद्यालय प्रबंधन और अभिभावक मिलकर फीस का निर्धारण करेंगे। डीआइओएस रविंदर शर्मा ने बताया कि सभी विद्यालयों को पीटीए गठित करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। सप्ताह भर के अंदर इसकी जानकारी कार्यालय में देनी होगी। कुछ स्कूलों में मनमाने तरीके से नए-नए प्रकाशन का पाठ्यक्रम चलाने व अभिभावकों पर अपनी बताई हुई दुकान से ही किताबें खरीदने का दवाब बनाने की शिकायत मिली थी।

न्यूज गैलरी

एयरपोर्ट पर दो यात्रियों से पांच कारतूस बरामद

नई दिल्ली : इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आइजीआइ) एयरपोर्ट के टर्मिनल थ्री पर पंजाब के दो यात्रियों से पांच कारतूस बरामद किए गए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस जांच में जुट गई है। आरोपितों की पहचान पंजाब के मोहाली के कुराली थाना क्षेत्र के नांगल गारिया गांव निवासी अमरिक सिंह और गुरदासपुर के शास्त्री नगर निवासी जोबनजीत सिंह के रूप में हुई है। एयरपोर्ट अधिकारी ने बताया कि पहले मामले में 10 फरवरी को अमरिक सिंह मिलान जाने के लिए टर्मिनल-3 पर पहुंचा था। चेकिंग के दौरान उसके बैग से 0.32 बोर के चार कारतूस बरामद हुए। वहीं, 11 फरवरी को जोबनजीत सिंह लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। तलाशी के दौरान उसके बैग से 0.32 बोर का एक कारतूस बरामद हुआ। (जासं)

तेजाब बिक्री पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली : देश की राजधानी में आसानी से बिक रहे तेजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर तेजाब हमले की शिकार पीड़िता की याचिका पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तेजाब की बिक्री पर रोक लगाने के बावजूद दिल्ली में तेजाब बिक रहा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने दिल्ली सरकार को इस बाबत शपथ पत्र दाखिल कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। 37 वर्षीय शाहीन मलिक ने आरोप लगाया कि तेजाब की बिक्री पर रोक लगाने वाले नियमों को राजधानी में लागू नहीं किया गया है। तेजाब हमले का शिकार हुई मलिक का आरोप है कि दिल्ली के विभिन्न किराना दुकानों पर तेजाब आसानी से उपलब्ध है। उन्होंने इस बाबत बनाए गए नियमों का सख्ती से दिल्ली में लागू करने का निर्देश देने की याचिका में मांग की। (जासं)

गोविंदपुरी में पानी के टैंकर में गिरकर मासूम की मौत

नई दिल्ली : गोविंदपुरी स्थित निर्माणाधीन मकान की हौदी में पांच वर्षीय प्रिंस कुमार की गिरकर मौत हो गई। मृतक के पिता मिथिलेश कुमार शाह ने बताया कि प्रिंस इलाके के एक निजी स्कूल में नर्सरी कक्षा में पढ़ता था। सोमवार को स्कूल से वापस आने के बाद वह खाना खाकर बाहर खेलने के लिए गया था। देर शाम तक प्रिंस के घर न लौटने पर स्वजनों ने उसकी तालाश शुरू कर दी। (जासं)

प्रदूषण करना है कम, अब लगानी होगी एंटी स्मॉग गन

सौरभ पांडेय, गाजियाबाद

▶ दो हजार वर्गमीटर से अधिक की निर्माण साइट पर लगानी होंगी एंटी स्मॉग गन

▶ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए आदेश, बिल्डरों को भेजे जाएंगे नोटिस

लगातार देश के सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी में शामिल गाजियाबाद और नोएडा के लिए उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नए आदेश जारी किए हैं। गाजियाबाद और नोएडा में दो हजार वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट पर निर्माण कर रहे सभी बिल्डरों को अब धूल और धुआं रोकने के लिए एंटी स्मॉग गन लगानी होगी। 15 दिन के अंदर सभी साइटों पर इसे स्थापित कर रिपोर्ट लखनऊ स्थित मुख्यालय भेजनी होगी। एंटी स्मॉग गन न लगाने पर बिल्डरों पर एक करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

दरअसल, बीते एक साल से गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रदूषण के स्तर में भारी बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते गाजियाबाद और नोएडा लगातार सबसे अधिक प्रदूषण वाले शहरों में बने हुए हैं। प्रशासन और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लिए यह चिंता का विषय बना हुआ है। इसे देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी साइटों पर निर्माण कर रहे बिल्डरों के लिए नए आदेश जारी किए हैं।

18 परियोजनाओं को किया गया चिह्नित : सभी बिल्डरों को एंटी स्मॉग गन लगानी होंगी जिससे धुएं और धूल को रोका जा सके। वर्तमान में गाजियाबाद के वसुंधरा, सिद्धार्थ विहार, कोयल एंक्लेव, राजनगर एक्सटेंशन आदि में निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसे में 18 बिल्डरों की परियोजनाओं को शुरुआत में चिह्नित किया गया। इन परियोजनाओं में सबसे पहले एंटी स्मॉग गन लगाई जाएगी। 15 दिन में इन साइटों पर एंटी स्मॉग गन लगाकर रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए भी जल्द ही यह आदेश लागू किया जाएगा।

हो सकता है एक करोड़ तक का जुर्माना : प्रदूषण फैलाने पर और गन नहीं लगाने पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि प्रदूषण के स्तर को देखते हुए इस राशि को तय किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो बोर्ड ने शुरुआत में दो हजार वर्ग मीटर और इससे अधिक की साइटों के लिए यह नया नियम लागू किया है। अगर प्रदूषण के स्तर में कमी नहीं आती तो एक हजार वर्गमीटर तक के प्लॉटों पर हो रहे निर्माणों अथवा सभी कंस्ट्रक्शन साइटों पर इसे अनिवार्य किया जा सकता है।

साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हो रहा प्रदुषण। जागरण

> प्रदूषण को देखते हुए मुख्यालय की ओर से दो हजार वर्गमीटर या उससे बड़ी निर्माणाधीन साइटों पर एंटी स्मॉग गन लगाने के निर्देश मिले हैं। गाजियाबाद और नोएडा के लिए मिले इन आदेशों को लागू करवाया जा रहा है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नोएडा विकास प्राधिकरण और आवास विकास जैसी संस्थाओं से निर्माणाधीन साइटों की डिटेल ली जा रही है।
>
> **– उत्सव शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

'ट्विटर को वरिष्ठ अधिवक्ता का डाटा डिलीट नहीं करना चाहिए'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को सुझाव दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े से जुड़ा डाटा अपने सर्वर से डिलीट न करे। संजय हेगड़े का अकाउंट ट्विटर द्वारा स्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया था। हालांकि संविधान के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सोशल मीडिया पर सेंसरशिप के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग को लेकर हेगड़े की तरफ से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कोई औपचारिक आदेश जारी करने से इन्कार कर दिया। हेगड़े ने इसके साथ ही 5 नवंबर 2019 को उनका अकाउंट निलंबित करने के ट्विटर के फैसले को भी चुनौती दी है। अधिवक्ता जयदीप गुप्ता के माध्यम से याचिका दायर कर हेगड़े ने अंतरिम राहत के तौर पर कहा कि उनका अकाउंट डिलीट नहीं किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान ट्विटर की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सजन पूवैया ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि इसका कोई आधार नहीं है। साथ ही उन्होंने इस पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर पीठ ने ट्विटर को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। इस दौरान केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए स्टैंडिंग काउंसल कीर्तिमन सिंह ने कहा कि अकाउंट निलंबित करने का मामला प्राथमिक तौर पर याचिकाकर्ता व ट्विटर के बीच है और सरकार ने निलंबन का निर्देश नहीं दिया था।

याचिका के अनुसार हेगड़े ने गोरख पांडे की एक कविता को री-ट्विट करते हुए कमेंट लिखा था। याचिका के अनुसार हेगड़े के खाते को उन दो री-ट्वीट के बाद निलंबित कर दिया गया था, जबकि मूल ट्वीट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट निलंबित करना गैरकानूनी और मनमाना है। याचिका के अनुसार अदालत में आने से पहले हेगड़े ने ट्विटर की आंतरिक अपील प्रक्रिया का पालन किया, लेकिन उनकी अपील खारिज कर दी गई थी।

पत्नी ने डीपी यादव के लिए मांगी दो माह की पैरोल

आयुष गंगवार, गाजियाबाद

देहरादून जेल में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे डीपी यादव की पत्नी ने उसके लिए दो माह की पैरोल मांगी है। अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उसकी पत्नी उमलेश यादव ने उत्तराखंड के प्रमुख सचिव गृह को करीब दो सप्ताह पूर्व पत्र लिखा था। इसमें कहा कि डॉक्टरों ने उनके आपरेशन की सलाह दी है। परिवार में देखरेख के लिए कोई नहीं है इसलिए आपरेशन के समय पति का साथ रहना जरूरी है। बता दें कि नितीश कटारा हत्याकांड में डीपी यादव के बेटे विकास यादव को भी उम्रकैद की सजा मिली थी। इस बारे में देहरादून के आइजी कारागार व गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडेय से रिपोर्ट मांगी गई है।

उमलेश ने लिखा कि वह बुजुर्ग हैं और 12 साल से गंभीर बीमारियों से जूझ रही हैं। चलने-फिरने में असमर्थ बताते हुए कहा कि दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल व इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर के डॉक्टरों ने सामान्य जीवन के लिए आपरेशन ही एकमात्र उपाय बताया है। उन्होंने अपने उपचार व जीवन का हवाला दे पति को दो माह की पैरोल देने की गुहार लगाई है। प्रमुख सचिव गृह ने आइजी कारागार के अलावा डीएम से पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी है। डीपी यादव के आपराधिक इतिहास, लंबित मामलों, परिवार के सदस्यों और पूर्व में पैरोल के दौरान उसके चाल-चलन के बारे में पूछा गया है। पैरोल के लिए बताए गए कारण की पुष्टि करने के साथ पैरोल देने या नहीं देने की स्पष्ट संस्तुति मांगी गई है। एक जमाने में बाहुबली रहे और सभी राजनीतिक पार्टियों में रसूख रखने वाले डीपी यादव को मार्च 2019 में गाजियाबाद पुलिस ने बिना इलाज लौटा दिया था। आम चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद डीपी यादव कोर्ट के आदेश लेकर इलाज के लिए नेहरूनगर स्थित यशोदा अस्पताल में भर्ती हुआ था। महज 24 घंटे में ही पुलिस ने देहरादून जेल प्रशासन की अभिरक्षा में उसे जिले की सीमा से बाहर भिजवा दिया था।

> फिलहाल मेरे संज्ञान में यह मामला नहीं आया है। प्रार्थना-पत्र आने पर पुलिस से आख्या मांगकर रिपोर्ट भेज दी जाएगी।
>
> **–अजय शंकर पांडेय, डीएम**

डीजल का विकल्प बनेगी एलएनजी, देश भर में खुलेंगे स्टेशन

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : जीवाश्म ईंधन पर बढ़ते दबाव और पर्यावरण संरक्षण के लिए ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश की जा रही है। डीजल, पेट्रोल, एलपीजी व सीएनजी के बाद अब एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस से वाहनों को दौड़ाने की योजना पर काम चल रहा है। गेल इंडिया लिमिटेड इस योजना पर काम कर रही है। देश भर में एलएनजी के स्टेशन स्थापित होंगे। इसके लिए गेल ने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग को चुना है। 2024 तक एलएनजी के स्टेशन नजर आने लगेंगे।

पेट्रोल व डीजल के विकल्प के तौर पर वाहनों में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग हो रहा है। इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में तो मदद मिली है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। सीएनजी की देश के सभी इलाकों में अभी तक उपलब्धता नहीं है। इसके अलावा लंबी दूरी तय करने वालों वाहनों के लिए यह ईंधन के रूप में कारगर नहीं है। एक बार सीएनजी लेने के बाद वाहन अधिकतम दो से ढाई सौ किमी की दूरी तय कर पाता है। इसलिए लंबी दूरी तय करने वाले ट्रांसपोर्ट वाहनों में अधिकतर डीजल का उपयोग हो रहा है।

गार्गी की छात्राओं ने किया कक्षा का बहिष्कार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

गार्गी कॉलेज के वार्षिकोत्सव के दौरान छह फरवरी को कॉलेज में घुसकर बाहरी लोगों द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को छात्राओं ने कक्षा का बहिष्कार किया। दोषियों पर जल्द कारवाई की मांग को लेकर बुधवार को छात्राएं कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करेंगी। कॉलेज प्रांगण में पूरा दिन छात्राओं ने बाहरी उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कॉलेज का पूरा कामकाज भी ठप रहा। छेड़छाड़ की खबर के बाद कुछ छात्राओं को उनके स्वजनों ने उन्हें घर बुला लिया है। छात्राओं की नाराजगी इसलिए भी है क्योंकि वारदात के बाद जब उन्होंने प्रिंसिपल प्रोमिला कुमार से इसकी शिकायत की तो उन्होंने भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद मंगलवार को गार्गी कॉलेज पहुंचीं और वहां छेड़छाड़ की पीड़ित छात्राओं से मिलीं। उसके बाद कॉलेज की ओर से हौजखास थाने में शिकायत दी गई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।

छात्राओं ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में पोस्ट करके बताया है कि नशे में धुत बाहरी लोगों ने इन लड़कियों से छेड़छाड़ और मारपीट की। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि आरोपित उनका पीछा करते हुए शौचालय तक पहुंच गए और उन्हें बाहर से बंद कर दिया। महिला आयोग ने इस मामले में दक्षिणी जिले के पुलिस उपायुक्त और गार्गी कॉलेज की प्रधानाचार्य को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

छात्राओं ने शुरू किया 'स्पीक-अप गार्गी' अभियान : गार्गी कॉलेज में हुई छेड़छाड़ की वारदात के बाद से यहां की छात्राओं में जबरदस्त रोष है। घटना के बाद से ही प्रिंसिपल के इस्तीफे पर अड़ी कॉलेज की छात्राओं का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, वे प्रदर्शन करती रहेंगी। उन्होंने मांग नहीं माने जाने पर कॉलेज की होने वाली जनरल बॉडी मीटिंग भी नहीं होने देने की बात कही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस मुहिम को और ज्यादा धार देने के लिए 'स्पीक-अप गार्गी' नाम से अभियान शुरू किया है। इस मुहिम को इंस्टाग्राम से चलाया जा रहा है। उन्होंने कॉलेज में छात्राओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की भी मांग की है और इसके लिए लिखित आश्वासन दिए जाने की मांग भी की है।

डूसू ने डीयू प्रॉक्टर को सौंपा ज्ञापन

जासं, नई दिल्ली : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) व दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) ने गार्गी कॉलेज के वार्षिकोत्सव में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की घटना के मामले में डीयू के नॉर्थ कैंपस स्थित ऑर्ट्स फैकल्टी पर विवि प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद दोनों के पदाधिकारियों ने डीयू की प्रॉक्टर नीता सहगल से मुलाकात कर आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा। डूसू अध्यक्ष अक्षित दाहिया, उपाध्यक्ष प्रदीप तंवर और संयुक्त सचिव शिवांगी खरवाल ने अपने हस्ताक्षर करते हुए प्रोक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनके साथ एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री सिद्धार्थ यादव भी मौजूद थे। डूसू ने प्रॉक्टर से मांग की है कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करते हुए इस घटना की जांच कराने की मांग की। डूसू के अध्यक्ष अक्षित दाहिया ने कहा कि उन्हें प्रॉक्टर से आश्वासन मिला है कि वह आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस आयुक्त से होने वाली बैठक में डूसू व एबीवीपी की मांगों को उनके समक्ष रखेंगी।

सूरजकुंड मेला

आकर्षण का केंद्र बनी 1.5 लाख की जामदानी बनारसी साड़ी

रेशम की साड़ी बनाने में चांदी का भी किया गया है प्रयोग, तीन कारीगरों ने साढ़े चार महीने में तैयार की है एक साड़ी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद

विभिन्न बाजारों में साड़ियों की वैसे तो काफी वैरायटी मिलती हैं, लेकिन जामदानी बनारसी साड़ी की अपनी अलग ही अहमियत और आकर्षण है। 34वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में नेशनल अवार्डी नसीम अहमद का बनारसी साड़ी और सूट का स्टाल नंबर 974 है। वीआइपी गेट के पास उनके स्टाल पर 2200 रुपये के सूट (तीन पीस, यानी दुपट्टा सहित) से लेकर 1.5 लाख रुपये तक की बनारसी जामदानी साड़ी उपलब्ध है। नसीम अहमद कहते हैं कि रेशम की जामदानी साड़ी तैयार करने में शुद्ध चांदी का भी प्रयोग किया है। इस साड़ी को तीन कारीगरों ने मिलकर साढ़े चार महीने में तैयार किया है। नसीम अहमद के अनुसार उनके यहां मूंगा रेशम, टसर तथा मलबरी के सूट और साड़ियां भी हैं।

जामदानी साड़ी की विशेषता व इतिहास : जामदानी दो शब्दों के मेल जाम और दानी को मिलाकर बना है। जाम का मतलब है फूल और दानी का मतलब होता है गुलदस्ता। जामदानी एक प्रकार की कसीदा की हुई बुनकरों की उत्कृष्ट उपलब्धि है। विस्तृत और बारीक काम इसकी विशेषता है। अवध के नवाबों के शासन काल में जामदानी ने कलात्मक श्रेष्ठता प्राप्त कर ली थी। कभी जामदानियों की बुनाई लखनऊ, उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुई थी। इसे बनाने में बड़े हुनर की जरूरत होती है। जामदानी साड़ी पर चटख रंग के धागे तथा चांदी की तारों से सजावट की जाती है। साड़ी में किनारों पर शॉल जैसे डिजाइन बुने जाते है। साड़ी पर पुष्प गुच्छ के रूप में डिजाइन जमा कर आकर्षक बनाया जाता है। बनारस का ये पारंपरिक काम आज विश्व प्रसिद्ध है। कभी इसमें शुद्ध सोने की जरी का प्रयोग होता था, किंतु बढ़ती कीमत को देखते हुए अब तो सोने के स्थान पर चांदी का प्रयोग करते हुए बूटी, बूटा, बेल, जाल और झालर से ही साड़ी तैयार की जाती है।

कीड़े से निकलता है रेशम : रेशमी साड़ियां और कपड़े तो आपने देखे होंगे, लेकिन यहां यह बताना अहम है कि कीड़े से रेशम निकलता है और फिर पहले रेशम के धागे बनाए जाते हैं। बुनकरों की कड़ी मेहनत के बाद बनती हैं रेशमी साड़ियां। रेशम के अलग-अलग प्रकारों में मूंगा रेशम, टसर, मलबरी बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। यह कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है।

जामदानी बनारसी साड़ी की क्वालिटी के बारे में जानकारी देते नेशनल अवार्डी नसीम अहमद। जागरण

सोनीपत में बाइक सवारों ने होमगार्ड जवान को 500 मीटर तक घसीटा

जागरण संवाददाता, सोनीपत

बाइक सवार तीन युवकों में दो ने शहर के महाराणा प्रताप चौक पर वाहनों की जांच कर रहे होमगार्ड के एक जवान की गर्दन और बाजू पकड़कर करीब 500 मीटर तक घसीटा। बाइक सवार युवक होमगार्ड जवान को सिविल लाइन थाना के पास श्मशान घाट चौक पर फेंककर भाग गए। घायल जवान का खानपुर मेडिकल में उपचार किया गया। पुलिस ने सूचना मिलने के 24 घंटे बाद तक इसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बाद में इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर एसपी ने संज्ञान लिया और घटना की जांच डीएसपी हेडक्वाटर को सौंपी है।

शहर के नागरिक अस्पताल के पास महाराणा प्रताप चौक के पास पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी। टीम में सब इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह, सिपाही अनिल कुमार और होमगार्ड के जवान विजेंद्र सिंह और जयदीप खोखर शामिल थे। दोपहर में वहां एक सफेद रंग की अपाचे बाइक पर सवार तीन युवक वहां आते दिखे। होमगार्ड जवान जयदीप ने उन्हें रुकने का इशारा किया। जयदीप ने बताया कि बाइक सवारों ने रफ्तार धीमी की, लेकिन इसी दौरान उनके बीच एक कार आ गई। जैसे ही उसने आगे बढ़कर बाइक सवारों को पकड़ने का प्रयास किया, बाइक पर बैठे दो युवकों ने उसका हाथ व गर्दन पकड़ लिया और बाइक को सेक्टर-14-15 के डिवाइडर रोड पर भगा लिया।

> होमगार्ड के जवान को बाइक सवार युवकों द्वारा घसीटने का वीडियो वायरल हुआ है। उसकी शिकायत पर मामला दर्ज करने का आदेश देते हुए डीएसपी हेडक्वाटर को इसकी जांच सौंपी गई है। बाइक सवार युवकों के साथ ही जांच में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
>
> **–जशनदीप सिंह रंधावा, पुलिस अधीक्षक, सोनीपत**

422 विदेशी कालाधन के मामलों में आयकर विभाग ने नोटिस जारी किए हैं 2019 में। इन मामलों में कुल 12 हजार करोड़ रुपये की रकम का पता चला है। यह जानकारी संसद में दी गई है।

पांच वर्षों में 21 हजार अवैध घुसपैठिए बांग्लादेश वापस भेजे गए

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश से घुसपैठ के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। सरकार बड़ी संख्या में घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजने में भी सफल रही है। लोकसभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में पिछले पांच वर्षों में घुसपैठियों के पकड़े जाने और उन्हें वापस भेजने के आंकड़े पेश किए। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ को कम करने के लिए बहुआयामी उपाय किए गए हैं।

लोकसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 से 2019 के बीच पांच वर्षों में 9,145 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 21,348 घुसपैठियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया। ये आंकड़े बांग्लादेश की सीमा से घुसपैठ में कमी आने के संकेत देते हैं। वर्ष 2015 में कुल 3,426 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और 5,930 को वापस भेजा गया। वर्ष 2016 में घुसपैठ करते समय पकड़े जाने वाले और वापस भेजे जाने वालों की संख्या क्रमशः 2,075 और 5,147 हो गई। यह धीरे-धीरे घटकर वर्ष 2019 में क्रमशः 1,351 और 2,175 रह गई।

नित्यानंद राय के अनुसार, घुसपैठ को रोकने में यह सफलता सरकार द्वारा सीमा की निगरानी के लिए बहुस्तरीय व बहुआयामी पद्धति अपनाने के कारण मिली है। इसमें सीमा पर होने वाली हरकतों की 24 घंटे निगरानी के साथ-साथ लगातार पेट्रोलिंग शामिल है। इस दौरान सीमा पर निगरानी पोस्ट की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही रात में घुसपैठ की आशंका वाले स्थानों पर फ्लड लाइट भी लगाई जा रही हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से खुफिया तंत्र को भी मजबूत किया गया है। जिन-जिन स्थानों पर बाड़ लगाना संभव नहीं है, वहां सेंसर लगाने के साथ-साथ नाइट विजन कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही रडार की मदद ली जा रही है। एक परिष्कृत कमांड व कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से इस पर नजर रखी जा रही है।

- सरकार ने लोकसभा में कहा, घुसपैठ के मामलों में आ रही है लगातार कमी
- नित्यानंद बोले, बहुआयामी निगरानी तंत्र से सीमा पर रखी जा रही नजर

लोकसभा में सवाल का जवाब देते नित्यानंद राय। (फाइल)

रोहिंग्या की वापसी की प्रक्रिया तेज करने पर बांग्लादेश सहमत

गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि रोहिंग्या के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ उच्चस्तरीय बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश रोहिंग्या को उनके मूलदेश म्यांमार भेजने की प्रक्रिया को तेज करने पर सहमत है। राय ने कहा कि इस बात की भी जानकारी मिली है कि कुछ रोहिंग्या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हैं।

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अंतिम सूची से बाहर बच्चों को राहत

सरकार असम के उन बच्चों को हिरासत केंद्रों में नहीं भेजेगी, जिनके नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनके परिजनों के नाम सूची में हैं। गृह राज्यमंत्री राय ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, 'भारत के अटॉर्नी जनरल ने 6 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि असम के जिन परिजनों के नाम एनआरसी में हैं, उनके बच्चों को उनसे अलग नहीं किया जाएगा। जब तक उनके आवेदन विचाराधीन हैं, बच्चों को हिरासत केंद्रों में नहीं भेजा जाएगा।'

संसद प्रश्नोत्तर

केवल पीएम को एसपीजी सुरक्षा 56 वीआइपी को सीआरपीएफ

नई दिल्ली, प्रेट्र : केवल प्रधानमंत्री को ही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) सुरक्षा मिली हुई है जबकि सीआरपीएफ देश के 56 अति महत्वपूर्ण लोगों (वीआइपी) की सुरक्षा में तैनात है। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने लोकसभा में मंगलवार को एक लिखित उत्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि एसपीजी सुरक्षा केवल एक व्यक्ति को मिली हुई है।

हाल ही में एसपीजी अधिनियम में हुए संशोधन के मुताबिक, यह बल प्रधानमंत्री और सरकारी आवास में उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के निकटवर्ती सदस्यों की सुरक्षा करता है। यह पूर्व प्रधानमंत्रियों और उन्हें आवंटित आवास में उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों की भी सुरक्षा करता है। पूर्व प्रधानमंत्रियों को पद मुक्त होने की तारीख से पांच साल तक के लिए आवास आवंटित किया जाता है।

- पूर्व प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले परिवार के सदस्यों को भी मिलती है एसपीजी सुरक्षा

केंद्र सरकार ने हाल ही में पांच लोगों से एसपीजी सुरक्षा हटाकर सीआरपीएफ सुरक्षा मुहैया कराई है। इन लोगों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं।

2017 से नक्सली हिंसा में कमी आई

गृह राज्यमंत्री ने एक अन्य सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि 2017 के बाद से पिछले तीन साल की अवधि में नक्सली हिंसा की घटनाएं और हताहत होने वाले नागरिकों एवं सुरक्षा बल के जवानों की संख्या में कमी आई है। उन्होंने इस संबंध में आंकड़ा भी मुहैया कराया। केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक, 2017 में 908, 2018 में 833 और 2019 में 670 नक्सली हिंसा की घटनाएं हुईं। इस अवधि में मारे गए नक्सलियों की संख्या में उतार-चढ़ाव है।

44,951 तीर्थयात्रियों ने की करतारपुर साहिब की यात्रा

नवंबर 2019 में मार्ग खुलने के बाद से कुल 44,951 तीर्थयात्रियों ने अब तक पाकिस्तान में स्थित श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा की यात्रा की है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डेरा बाबा नानक में अत्याधुनिक इंटिग्रेटेड पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग और डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक फोर लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है। यह मार्ग पूरे वर्ष तीर्थयात्रियों को बिना बाधा आवाजाही की सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। रेड्डी ने कहा कि तीर्थयात्रियों के पासपोर्ट पर आव्रजन अधिकारी द्वारा मुहर नहीं लगाई जाती है और केंद्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार से तीर्थयात्रियों पर कोई शुल्क या अधिभार नहीं लगाने का आग्रह किया है। पाकिस्तान हर भारतीय तीर्थयात्री से 20 अमेरिकी डॉलर (करीब 1400 रुपये) वसूल रहा है।

किसी कानून में नहीं है कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी : सरकार

दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड ▸ फांसी पर रोक के खिलाफ दाखिल सरकार की अर्जी पर चारों दोषियों को नोटिस

तीन दोषियों मुकेश, विनय व अक्षय के कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषियों की फांसी पर रोक लगाने और सभी को साथ फांसी देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर चारों दोषियों को नोटिस जारी किया है। केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि यह किसी कानून में नहीं है कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी। हाई कोर्ट का यह कहना गलत है कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जानी चाहिए। गुनहगारों को फांसी आनंद के लिए नहीं दी जाती है। कानून के तहत सजा पर अमल जरूरी है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति आर भानुमति, अशोक भूषण और एएस बोपन्ना की पीठ ने तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद दोषियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा कि दोषियों को आज ही यह नोटिस जेल सुपरिंटेंडेंट के जरिये दिया जाएगा। मामले पर 13 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। याचिका में केंद्र और दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट का यह कहना कि सभी दोषियों को एक साथ फांसी दी जाएगी, गलत है। जिन दोषियों के सारे कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं, उन्हें फांसी देने की इजाजत दी जाए। याचिका पर बहस करते हुए मेहता ने कहा कि दोषियों को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए एक सप्ताह की अवधि मंगलवार को समाप्त हो रही है। लेकिन दोषियों ने कोई कदम नहीं उठाया है। चार दोषियों में तीन मुकेश, विनय और अक्षय के सभी कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं। चौथे दोषी पवन ने अभी तक क्यूरेटिव और दया याचिका दाखिल नहीं की है। मेहता ने कहा कि किसी को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

तुषार मेहता ने कहा, लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठने लगा है : मेहता ने कहा कि जिनके विकल्प समाप्त हो चुके हैं उनकी फांसी की सजा पर अमल की इजाजत मिलनी चाहिए। एक दोषी का कुछ न करना अन्य के लिए मददगार नहीं होना चाहिए। दया याचिका हर दोषी के व्यक्तिगत कारणों और आधारों पर निपटाई जाती है। उसका सभी दोषियों से या मुख्य मामले से कोई लेना-देना नहीं होता। इस मामले में चारों दोषियों को सुप्रीम कोर्ट तक से 2017 में फांसी की सजा हो चुकी है। लेकिन दोषी लगातार कानूनी पेचों का फायदा उठाकर सजा में देरी कर रहे हैं। मेहता ने दुष्कर्म के आरोपितों के हैदराबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने का उदाहरण देते हुए कहा कि वह उस घटना को सही नहीं ठहरा रहे। लेकिन, उस घटना पर लोगों ने खुशी मनाई थी। यह दर्शाता है कि लोगों का व्यवस्था से विश्वास उठने लगा है।

नया डेथ वारंट जारी कराने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म कांड के दोषियों को कानूनी विकल्प अपनाने के लिए हाई कोर्ट द्वारा तय की गई एक सप्ताह की समयसीमा समाप्त होने पर केंद्र सरकार को फांसी की नई तारीख तय कराने के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यहां याचिका लंबित रहने का ट्रायल कोर्ट के विचार करने पर असर नहीं पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट मेरिट के आधार पर फैसला लेगा।

विनय ने याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के आदेश को दी चुनौती

दोषी विनय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में याचिका निपटाई है। याचिका निपटाने में तय प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले दोषी मुकेश ने भी राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

निर्भया के परिजनों ने डेथ वारंट के लिए दायर की याचिका

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : निर्भया दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी करने की मांग को लेकर निर्भया के परिजनों एवं दिल्ली सरकार की तरफ याचिका दायर की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने याचिका पर सभी दोषियों को नोटिस जारी कर सुनवाई को बुधवार के लिए स्थगित कर दिया। निर्भया के परिजनों ने अदालत में कहा कि सभी दोषी कानून का मजाक बना रहे हैं।

निर्भया के स्वजनों व दिल्ली सरकार की तरफ से आवेदन तब दाखिल किया गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करने के संबंध में प्राधिकारियों को निचली अदालत में संपर्क करने की अनुमति दी। इसके साथ ही तिहाड़ जेल प्रशासन ने मंगलवार को निचली अदालत में बताया कि कानूनी उपचार के इस्तेमाल के लिए हाई कोर्ट द्वारा 5 फरवरी को स्वीकृत किए गए एक सप्ताह की समय-सीमा के दौरान दोषियों द्वारा किसी भी कानूनी उपचार का प्रयोग नहीं किया गया। निचली अदालत ने चारों दोषियों के नया डेथ वारंट जारी करने की मांग करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन व दिल्ली सरकार द्वारा दायर आवेदन को 7 फरवरी को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने 31 जनवरी को अगले आदेश तक डेथ वारंट पर रोक लगा दी थी। निचली अदालत के इस फैसले को गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को गृह मंत्रालय की याचिका को खारिज करते हुए दोषियों को कानूनी उपचार एक सप्ताह में पूरी करने का आदेश दिया था।

शाहीन बाग, चांद बाग में चल रहे धरने की लोस में सरकार ने दी जानकारी

नई दिल्ली, प्रेट्र : गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के शाहीन बाग और चांद बाग में दो सड़कों को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर रखा है। सड़क जाम के कारण आम लोगों को हुए नुकसान का आकलन नहीं किया जा सका है।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि दक्षिण पूर्व दिल्ली में शाहीन बाग में सड़क संख्या 13ए कालिंदी कुंज को प्रदर्शनकारियों ने 15 दिसंबर 2019 से जाम कर रखा है। उसी दिन से शाहीन बाग में सीएए विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। इसी तरह उत्तर पूर्व दिल्ली में भजनपुरा के समीप चांद बाग में एक सर्विस रोड पर प्रदर्शनकारियों ने 18 जनवरी 2020 से जाम कर रखा है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस उचित कदम उठा रही है।

टुकड़े टुकड़े गैंग नाम के किसी समूह की सूचना नहीं

लोकसभा में लिखित सवाल का जवाब देते हुए रेड्डी ने कहा कि गृह मंत्रालय को टुकड़े टुकड़े गैंग नाम के किसी समूह के बारे में सूचना नहीं है। कांग्रेस के वीएच पाला और जसबीर सिंह के सवाल के जवाब में गृह राज्यमंत्री ने यह जानकारी दी।

रास सदस्यों का आरोप, एससी-एसटी कल्याण के लिए आवंटन अपर्याप्त

नई दिल्ली, प्रेट्र : राज्यसभा में सदस्यों ने मंगलवार को एससी-एसटी समुदाय के कल्याण के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन का मुद्दा उठाया। नामित सदस्य नरेंद्र जाधव ने बजट पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा, 'एससी-एसटी कल्याण के लिए ज्यादा प्रावधान होना चाहिए था क्योंकि बजट में सिर्फ 83,257 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो पिछले बजट के मुकाबले सिर्फ 2.35 फीसद अधिक हैं। महंगाई के मद्देनजर यह बढ़ोतरी शून्य है।' आइयूएमएल के अब्दुल वहाब ने कहा, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय किया गया है, बजट में उनकी पूरी तरह अनदेखी की गई है। रुपये का अवमूल्यन बड़ी चिंता का विषय है।

कांग्रेस की अमी याज्ञनिक ने कहा, 5,000 दौलतमंद लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। स्किल इंडिया अभियान विफल हो चुका है क्योंकि छह करोड़ माइक्रो इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं और सरकार विकास के फर्जी आंकड़े उपलब्ध करा रही है। कांग्रेस के ही मुहम्मद अली खान ने कहा कि वर्तमान शासन में क्षेत्रीय सरकारें कमजोर हुई हैं। भाजपा के केजे अल्फोंस ने बजट को समग्र बताते हुए कहा, सरकार के प्रयासों से प्राइमरी स्तर पर लड़कियों का नामांकन 93 फीसद, हाई स्कूल स्तर पर 83 व हायर सेकेंडरी स्तर पर 53 फीसद हो गया है।

उत्तराखंड में कैबिनेट में हो सकती है पदोन्नति में आरक्षण मामले पर चर्चा

राज्य ब्यूरो, देहरादून

उत्तराखंड में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद से प्रदेश की राजनीति में उबाल है। संभवतया यही वजह रही कि मंगलवार को भी शासन ने पदोन्नति पर रोक हटाने के संबंध में कोई फैसला नहीं लिया। माना जा रहा है कि अब बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में पदोन्नति में आरक्षण, पदोन्नति पर रोक और सीधी भर्ती में रोस्टर प्रक्रिया के संबंध में चर्चा होगी। इसके बाद ही पदोन्नति पर रोक हटाने के संबंध में कोई निर्णय लिया जा सकता है।

प्रदेश में इस समय पदोन्नति में आरक्षण को लेकर कर्मचारी संगठन आमने-सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार जल्द पदोन्नति पर लगाई गई रोक हटा देगी। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी होने की उम्मीद थी।

इस बीच सोमवार को यह मामला संसद में भी उठा, जिससे मुद्दा और गर्मा गया। मंगलवार को भी कर्मचारी इस मसले पर शासन की ओर टकटकी लगाए रहे, लेकिन देर शाम तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते रोज ही इस मामले का अध्ययन करने के बाद निर्णय लेने की बात कह चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार को सचिवालय में होने वाली कैबिनेट की बैठक में यह मसला प्रमुखता से रखा जा सकता है और इस पर चर्चा होगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद पदोन्नति से रोक न हटने पर कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण व पदोन्नति पर रोक हटाने के विषय आपस में जुड़े हुए हैं। इस पर कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की गई है। अधिकारियों से भी इस विषय में विमर्श किया गया है। सरकार इस विषय पर विस्तृत चर्चा के बाद कोई निर्णय लेगी।

केंद्रीय मंत्री गहलोत के खिलाफ कांग्रेस ने दिया विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव

नई दिल्ली, प्रेट्र : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को कहा कि आरक्षण मुद्दे पर बयान के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत के खिलाफ कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव उनके विचाराधीन है।

कांग्रेस ने सोमवार को गहलोत पर आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा को गुमराह करने का आरोप लगाया था और कहा था कि वह उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस ने कहा था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म करने की मोदी सरकार की साजिश को बेनकाब करने के लिए वह जिला स्तर पर आंदोलन करेगी।

सरकार ने सोमवार को लोकसभा को सूचित किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि राज्य सरकारें नियुक्तियों में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं हैं, उसमें वह कोई पक्ष नहीं है। लोकसभा में बयान देते हुए गहलोत ने कहा था कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर हलफनामा तक दाखिल करने के लिए नहीं कहा गया था।

वर्ष 2000 के बाद हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया भारत का दौरा

प्रथम पृष्ठ से आगे

बिल क्लिंटन से पहले तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों की भारत के आधिकारिक दौरे पर आने की परंपरा नहीं थी। वर्ष 2000 में क्लिंटन के भारत आने के बाद से वहां के सभी राष्ट्रपति नई दिल्ली आ चुके हैं जो अमेरिकी कूटनीति में भारत की बढ़ती साख को भी बताता है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दो बार भारत की यात्रा की थी। अंतिम बार वह वर्ष 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में राजकीय मेहमान भी थे।

भारत के लिए क्या लेकर आ सकते हैं ट्रंप : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा के दौरान यूं तो कई समझौते होने के आसार हैं। लेकिन दो रक्षा सौदों और एक कारोबारी समझौते पर सबकी नजर लगी है। ट्रंप प्रशासन ने भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (आइएडीडब्लूएस) बेचने के अपने फैसले की संसद को पहले ही जानकारी दे दी है। 1.9 अरब डॉलर (लगभग 13000 करोड़ रुपये) के इस सौदे पर ट्रंप की यात्रा के दौरान मुहर लग सकती है। अमेरिका से नौ सेना के लिए दो दर्जन सीहॉक हेलीकॉप्टर खरीदने के समझौते पर भी हस्ताक्षर हो सकता है। यह सौदा लगभग 2.6 अरब डॉलर (18000 करोड़ रुपये) का है। एक समझौता कारोबार के क्षेत्र में करने की तैयारी है जो भारत व अमेरिका के बीच मौजूदा कारोबारी तनाव को दूर करने में मदद करेगा। सितंबर, 2019 में जब मोदी अमेरिका की यात्रा पर गए थे तभी इस समझौते पर काफी बात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक यह एक सीमित दायरे वाला ट्रेड एग्रीमेंट होगा जो कई तरह के अमेरिकी उत्पादों पर लगे प्रतिबंधों में रियायत देगा।

ट्रंप की यात्रा के मायने

वाशिंगटन, प्रेट्र : ट्रंप की यात्रा के कई मायने हैं। भारत-अमेरिकी रिश्तों और दक्षिण एशिया के मामलों के विशेषज्ञों की माने तो ट्रंप की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूती देने का काम तो करेगी ही, क्षेत्रीय ताकतों को भी एक संदेश देगी। यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के अध्यक्ष मुकेश अघी के मुताबिक, पिछले तीनों अमेरिकी राष्ट्रपति भारत गए थे। इसलिए क्षेत्र को यह संदेश देना जरूरी था कि भारत अमेरिका का अहम साथी है और ट्रंप उसे अहमियत देते हैं। दक्षिण चीन सागर व प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने में भी अमेरिका भारत को अहम मानता है।

अश्लील बाल सामग्री पर रोक को इंटरनेट कंपनियों से होगी बात

नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्र सरकार इंटरनेट पर अश्लील बाल सामग्री, जिसमें तस्वीरें और वीडियो शामिल है, के प्रसारण को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों और दूसरे पक्षकारों के साथ बैठक करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी।

प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले पर चार हफ्ते बाद सुनवाई करने का फैसला किया। इस दौरान केंद्र सरकार गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक व अन्य पक्षकारों के साथ बैठकें कर इंटरनेट पर अश्लील सामग्रियों के प्रसारण को रोकने के उपाय तलाश करेगी। अदालत 2015 में हैदराबाद स्थित एनजीओ प्रज्वला द्वारा भेजे गए पत्र में उठाए गए मामले पर सुनवाई कर रही थी। एनजीओ ने पत्र के साथ पेन ड्राइव में बच्चों के साथ दुष्कर्म के दो वीडियो भी भेजे थे।

एक पक्षकार की वकील अपर्णा भट ने कोर्ट को बताया कि सरकार तब एक पोर्टल लेकर आई थी, लेकिन सितंबर के बाद से सरकार ने पक्षकारों और इंटरनेट मुहैया कराने वाली कंपनियों के साथ कोई बैठक नहीं की है। सरकार ने यह पोर्टल इंटरनेट पर अश्लील बाल सामग्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए शुरू किया था।

सरकार बोली

गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी लोकसभा में कही यह बात, विपक्ष ने पूछा था सवाल- भारतीय प्रतिनिधिमंडल को घाटी में जाने की कब मिलेगी इजाजत

'भारतीयों के जम्मू-कश्मीर जाने पर रोक नहीं'

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि किसी भी भारतीय नागरिक के जम्मू-कश्मीर जाने पर कोई रोक नहीं है। गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी लोकसभा में उस सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें यह पूछा गया था कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल को जम्मू-कश्मीर जाने की इजाजत कब दी जाएगी।

विदेशी राजनयिकों के जम्मू-कश्मीर दौरे को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा, 9-10 जनवरी के उनके दौरे का आयोजन विभिन्न देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के आग्रह पर किया गया था। इसका उद्देश्य था कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की मौजूदा स्थितियों के बारे में दूसरे देशों की समझ बेहतर हो। 15 देशों के राजनयिकों ने जम्मू-कश्मीर के नागरिक प्रशासन, राजनेताओं, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, विभिन्न समुदायों के युवाओं, धार्मिक और सामाजिक-आर्थिक समुदायों, कश्मीर की मुख्यधारा के मीडियाकर्मियों और विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय से मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान महसूस किया कि जम्मू-कश्मीर में सबकुछ सामान्य है।

- जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में दूसरे देशों की समझ बेहतर हो इसीलिए राजनयिकों ने किया था दौरा
- इस दौरान उन्होंने प्रदेश के राजनेताओं, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों, विभिन्न समुदायों के युवाओं से की थी बात, माना था सबकुछ है सामान्य

लोकसभा में बोलते केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी। (फाइल)

वर्ष 1947 के बाद गुलाम कश्मीर से भारत आए 31,619 विस्थापित परिवार : वर्ष 1947 के बाद से अलग-अलग मौकों पर गुलाम कश्मीर से कुल 31,619 विस्थापित परिवार भारत आए और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में बस गए। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने लोकसभा में बताया कि शुरुआत में जम्मू-कश्मीर में आने वाले ऐसे परिवारों की संख्या 5,300 के आसपास थी, जो बाद में देश के दूसरे राज्यों में फैल गए। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान वर्ष 1965 व 1971 में सीमा पार के छंब नायबात से आए कुल 10,065 विस्थापित परिवारों का पंजीकरण किया गया। गुलाम कश्मीर व छंब से आए इन विस्थापित परिवारों को केंद्र और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर सरकार की तरफ से राहत व पुनर्वास पैकेज मुहैया कराया जाता रहा है। उन्हें भूमि, प्लॉट और क्वार्टर के अलावा आर्थिक मदद भी दी गई।

वेंकैया नायडू बोले, सदन की सेहत के लिए जारी किया गया व्हिप

नई दिल्ली, प्रेट्र : भाजपा द्वारा व्हिप जारी करने के बाद अटकलों पर विराम लगाते हुए राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि व्हिप सदन की सेहत के लिए जारी किया गया। सामान्य तौर पर बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम होती है। यदि पूरे सत्र के दौरान नियमित रूप से व्हिप जारी किया जाए, तो मुझे खुशी होगी। इससे सांसद सदन में मौजूद रहेंगे।

सदन की बैठक शुरू होने पर नायडू ने कहा कि आज कोई विधेयक नहीं लिया जाएगा। सदन में केवल बजट पर चर्चा होगी और बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। संसद के बजट सत्र का पहला चरण मंगलवार को संपन्न हो गया। दोनों सदनों को दो मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक अब दो मार्च से तीन अप्रैल तक होगी, जिसमें केंद्रीय बजट को पारित किया जाएगा।

कह के रहेंगे माधव जोशी

जनादेश

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020

3207 वोटों से पटपड़गंज सीट से जीते मनीष सिसोदिया

66 प्रत्याशी कांग्रेस के जब्त करा बैठे अपनी जमानत

यूं चुनीं दिल्ली ने सरकारें

राजधानी दिल्ली में पहली बार विस चुनाव 1952 में हुए थे और कांग्रेस के चौधरी ब्रह्मप्रकाश मुख्यमंत्री बने थे। 1956 में विधानसभा को भंग कर इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। 1966 में महानगर पालिका का रूप दिया गया। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया जो केंद्र शासित प्रदेश है। आइये जानते हैं दिल्ली ने किस तरह अपनी सरकार चुनी...

कांग्रेस भाजपा आप अन्य

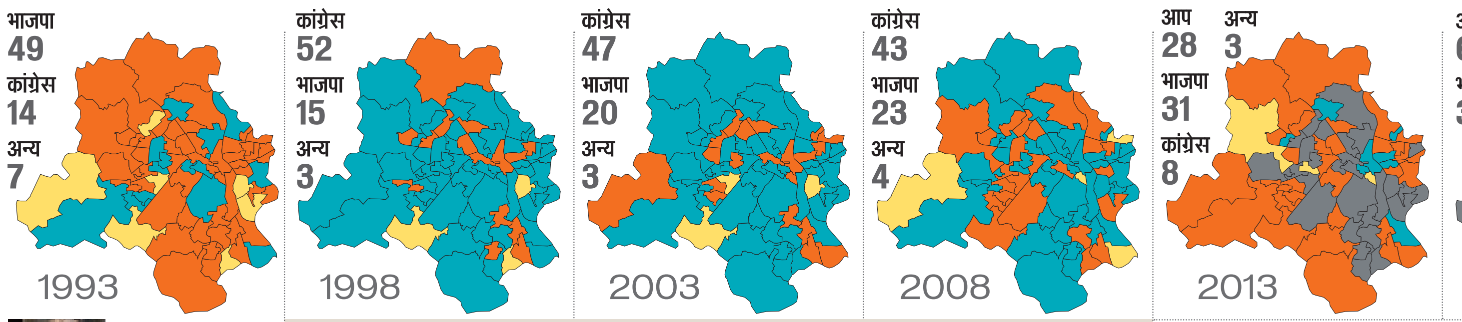

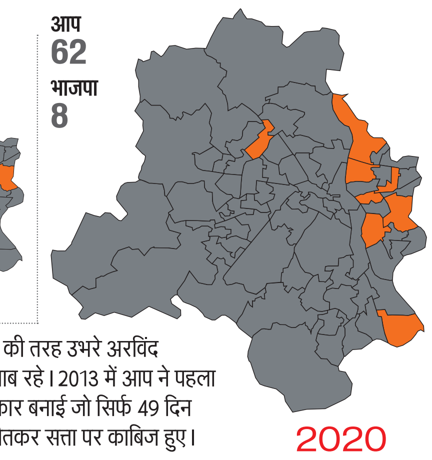

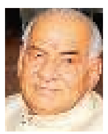

मदनलाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा व सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनीं

1998 से 2003 तक शीला दीक्षित की अगुआई में कांग्रेस सरकार रही। शीला ने ऐसे समय में दिल्ली की कमान संभाली जब यहां की सियासत पर मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, विजय कुमार मल्होत्रा जैसे भाजपा दिग्गजों का दबदबा था। शीला न सिर्फ तीन चुनाव जीतीं, दिल्ली को भी बदल दिया। मेट्रो, सीएनजी, फ्लाईओवर और सड़कों के लिए उन्हें याद किया जाता है।

2013 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन से नायक की तरह उभरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहे। 2013 में आप ने पहला चुनाव लड़ा और 28 सीटें जीत लीं। कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जो सिर्फ 49 दिन चली। 2015 में अविश्वसनीय रूप से उन्होंने 67 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हुए।

भाजपा के लिए गहन मंथन का विषय है दिल्ली चुनाव

राज्यों में प्रभावशाली और वैकल्पिक नेतृत्व की कमी पड़ रही है भाजपा पर भारी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भाजपा ने पिछले तीन-चार महीनों में दो राज्यों में सत्ता गंवाई और दो में निराशाजनक प्रदर्शन किया। जमीनी स्तर पर कुछ तो गलत है। सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को यह अहसास दिलाने के लिए क्या यह काफी नहीं है। अगर पार्टी को इसका पता ही नहीं है तो यह चिंता की बात है। और अगर पता होते हुए भी उसे छिपाने की कोशिश हो रही है तो यह और भी चिंता की बात है। दिल्ली के चुनावी नतीजों से भाजपा को सतर्क होना पड़ेगा वरना आगे समस्या गंभीर हो सकती है।

2019 के लोकसभा चुनाव के कुछ माह पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा के हाथ से सत्ता फिसली थी। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र और झारखंड भी हाथ से निकल गए। हरियाणा जाते-जाते बचा और दिल्ली में जी-तोड़ मशक्कत के बावजूद प्रदर्शन टांय-टांय फिस्स ही रहा।

केंद्रीय स्तर के दिग्गज नेताओं, सैकड़ों भाजपा सांसदों के घर-घर अभियान, राष्ट्रीय सुरक्षा और शाहीन बाग के मुद्दे के बावजूद भाजपा दिल्ली विधानसभा में दो अंकों तक नहीं पहुंच पाई। यह प्रदर्शन भाजपा के लिए गहन मंथन का विषय है। क्योंकि 2015 के नतीजों को भाजपा यह कहकर मन बहलाती रही थी कि जनता ने उसे एक प्रयोग के तौर पर लिया था। इसलिए अन्ना आंदोलन के बाद जन्मी पार्टी को मौका दिया था। लेकिन इस बार जनता ने जो फैसला दिया वह तो आजमाने के बाद दिया है। भाजपा का यह भी दावा रहा है कि सुशासन केवल भाजपा शासित राज्यों में है। दूसरी ओर, भाजपा का जहां झुग्गी वहीं मकान, अनधिकृत मकानों को अधिकृत करने का बड़ा दांव फेल हो गया। लोगों ने उस वादे पर भरोसा क्यों नहीं किया, यह भाजपा को आंकना होगा।

एक बात धीरे-धीरे साबित होती जा रही है कि भाजपा राज्यों में सबल और वैकल्पिक नेतृत्व पैदा नहीं कर पा रही है जो लोगों में भरोसा जगा सके। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां मदनलाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज जैसा चेहरा दो-ढाई दशक में भी नहीं तैयार हो पाया है। जनता ने अब केंद्र और राज्य के चुनाव को अलग कर वोट देना सीख लिया है। वरना कोई कारण नहीं था कि भाजपा को सभी सात सांसद देने वाली दिल्ली विधानसभा में इसे दसवें हिस्से तक रोक देती। इससे पहले हुए चुनावों में भी भाजपा को लोकसभा के मुकाबले काफी कम वोट मिले। जनता ने काम को भी वोट देना सीखा है। इसीलिए अगर लोकसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी पर जताया है।

यह भाजपा के लिए अच्छा है कि अब दूसरा चुनाव इस साल के अंत में बिहार में है, जहां एक भरोसेमंद साथी भी है। इस बीच केंद्र सरकार को जहां अर्थव्यवस्था व रोजगार में अपना प्रभाव दिखाना होगा वहीं यह भी याद रखना होगा कि चुनाव से ठीक पहले की गई घोषणा को जनता कोरे वादों के रूप में लेती है। अनधिकृत कॉलोनी के साथ भी यही हुआ। नतीजे बताते हैं कि भाजपा को इन कॉलोनियों में भी अपेक्षित वोट नहीं मिला। भाजपा के लिए यह वक्त जागने का है, वरना सभी राज्यों में मौजूदगी के स्वर्णिम काल का सपना उससे बहुत दूर हो जाएगा।

पंडित पंत मार्ग स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय ● जागरण

हार की समीक्षा करेगी पार्टी : तिवारी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

कहा, कार्यकर्ताओं की मेहनत से मत फीसद बढ़ा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जीत के लिए दी बधाई

दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी हार की समीक्षा करेगी। प्रेस वार्ता करके उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। साथ ही उन्होंने भाजपा व सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं का आभार जताया और धैर्य बनाए रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिल्लीवासियों के फैसले का भाजपा सम्मान करती है। उम्मीद है दिल्ली की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए केजरीवाल काम करेंगे।

कभी-कभी ऐसा होता है कि अपने पक्ष में निर्णय न होने पर निराशा होती है, लेकिन यही धैर्य रखने का समय होता है। कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होना चाहिए। जनता ने कुछ सोचकर ही यह जनादेश दिया होगा। सभी कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम की है। कार्यकर्ताओं की मेहनत से भाजपा का मत फीसद बढ़ा है। वर्ष 2015 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को लगभग 33 फीसद मत मिले थे। इस बार भाजपा को 38.46 फीसद मत मिले हैं। यदि जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के मत को मिला दिया जाए तो 40 फीसद मत हमें प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में अब नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो रही है। सिर्फ दो दलों के बीच मुकाबला रह गया है। दिल्ली में कांग्रेस लुप्तप्राय हो गई है। कांग्रेस का वोट पिछले चुनाव की तुलना में आधा रह गया है। इस बदले हुए राजनीतिक समीकरण को ध्यान में रखकर हम सभी को मेहनत करनी होगी। भाजपा के सभी सांसद दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के सभी सांसद व अन्य नेता व कार्यकर्ता जिन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसके अनुसार दिल्ली के विकास के लिए काम करेंगे।

केजरीवाल की ताजपोशी: एक्सपर्ट्स से जानें आप, बीजेपी, कांग्रेस के लिए क्या हैं मायने

अरविंद केजरीवाल की इस ऐतिहासिक जीत के साथ-साथ ये नतीजे एक नए राजनीतिक मंथन की ओर इशारा कर रहे हैं. जीतने वाली पार्टी के सामने अपना घोषणा पत्र है और दिल्ली की जनता की बेतहाशा उम्मीदें हैं. बीजेपी ने इस चुनाव में क्या पाया, कांग्रेस ने इस चुनाव में क्या खोया, एक्सपर्ट्स से जानिए.

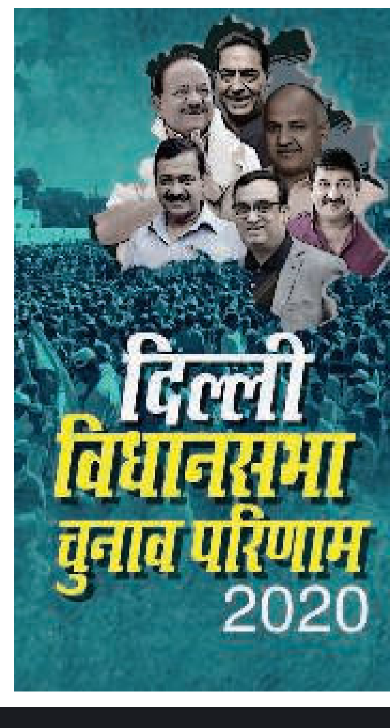

देखें क्या हैं इन नतीजों के मायने तीनों ही बड़े राजनीतिक दलों के लिए ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens से स्कैन करके

वीडियो देखने के लिए

1. अपने मोबाइल पर Google Lens App डाउनलोड करके OPEN करें. Go to goo.gle/lens, or use the Google Lens App on Android/Google App on iOS
2. ऊपर छपी तस्वीर को Google Lens के साथ स्कैन करें
3. छपी तस्वीर पर आधारित विश्लेषणात्मक वीडियो देखें

केजरीवाल को दोहरी खुशी, पार्टी की जीत और पत्नी का जन्मदिन मनाया

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली

यह महज संयोग ही था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का मंगलवार को जन्मदिन भी था। सुबह से सभी का ध्यान मतगणना के रुझानों पर था। मगर दोपहर तक जब आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर बढ़त बना ली तो आप नेताओं ने कुछ राहत की सांस ली। इसी दौरान एक न्यूज चैनल ने खबर चलाई कि आज सुनीता केजरीवाल का जन्मदिन भी है।

इस पर पार्टी मुख्यालय में मौजूद केजरीवाल और उनके साथ बैठे अन्य सदस्यों ने सुनीता केजरीवाल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। इसके बाद कार्यालय में ही जन्मदिन मनाने की योजना बनी। केक मंगाया गया। सुनीता केजरीवाल ने केक काटा। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें खिलाया तो उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को केक खिलाते हुए जीत की बधाई दी। इस पर वहां मौजूद संजय सिंह ने कहा कि आज हमें दोहरी खुशी है। बाद में जब केजरीवाल ने मंच से कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित किया तो भी केजरीवाल ने अपनी पत्नी के जन्मदिन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैंने केक खा लिया है आप लोगों को भी खिलाऊंगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पत्नी सुनीता केजरीवाल के जन्मदिन के अवसर पर आम आदमी पार्टी मुख्यालय में केक खिलाते हुए। प्रेट्र

शर्मिष्ठा ने नेतृत्व पर उठाए सवाल, कहा- अब कार्रवाई का समय

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष एवं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार की नैतिक जिम्मेदारी ली है। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस का पतन हुआ है और वह एक भी सीट नहीं जीत पाई।

उन्होंने ट्वीट कर हार के बाद शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने हार के लिए ऊपर से नीचे तक कई कारणों को जिम्मेदार ठहराया। ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा है कि हम दिल्ली में फिर हार गए। आत्ममंथन बहुत हुआ, अब कार्रवाई का समय है। शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने में देरी, राज्य स्तर पर रणनीति और एकजुटता के अभाव से हारे।

24 सीटों पर भितरघात ने डुबोई कांग्रेस की लुटिया

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

अपने अस्तित्व की लड़ाई हार चुकी कांग्रेस की लुटिया डुबोने में भितरघात की भी बड़ी भूमिका रही। कुछ ही सीटें ऐसी थीं जहां विरोधी दलों के उम्मीदवारों के साथ पार्टी प्रत्याशियों की कांटे की टक्कर दिखी। ज्यादातर सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार मजबूत स्थिति में थे ही नहीं। करीब एक तिहाई सीटों पर उम्मीदवारों को सीधे तौर पर भितरघात ने हराया।

24 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां पार्टी उम्मीदवारों को लेकर स्थानीय नेताओं एवं कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष था। इनमें पटेल नगर और कोंडली ऐसी सीटें थीं जहां पार्टी ने उन्हें ही टिकट दे दिया जो पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। इसी तरह तिमारपुर, आदर्श नगर, मटियामहल, बिजवासन, महरौली, छतरपुर और ओखला इत्यादि कुछ सीटें ऐसी थीं जहां पर पार्टी उम्मीदवार को लेकर वहां के पूर्व विधायक और पार्षद ही नाखुश थे।

बवाना, मुंडका, मोती नगर, आरके पुरम, मटियाला, कस्तूरबा नगर, संगम विहार, त्रिलोकपुरी, बवाना, मुस्तफाबाद और पटपड़गंज इत्यादि सीटों के प्रत्याशियों को लेकर कहीं जिला और ब्लॉक अध्यक्ष खुश नहीं थे वहीं कुछ के नाम पर प्रतिद्वंद्वी दावेदार बगावत का झंडा बुलंद किए हुए थे। कुछ उम्मीदवारों पर पार्टी नेता और कार्यकर्ता यह आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम ही नहीं किया। आलम यह रहा कि कहीं-कहीं यह बगावत खुलेआम देखी गई तो कहीं बगावती नेता दिखावे भर के लिए ही उम्मीदवार का साथ दे रहे थे और पीठ पीछे वोट कटवाने के प्रयास में भी लगे थे। ऐसे में पार्टी उम्मीदवार की जीत पहले से ही संदिग्ध थी।

इन विधानसभा सीटों पर पार्टी को भितरघात ने हराया

विस सीट	प्रत्याशी
तिमारपुर	अमरलता सांगवान
आदर्श नगर	मुकेश गोयल
बवाना	सुरेंद्र कुमार
मंगोलपुरी	राजेश लिलोठिया
चांदनी चौक	अलका लांबा
मटिया महल	मिर्जा जावेद अली
करोल बाग	गौरव धानक
पटेल नगर	कृष्णा तीरथ
मोती नगर	रमेश कुमार पोपली
मटियाला	सोमेश शौकीन
बिजवासन	प्रवीण राणा
कस्तूरबा नगर	अभिषेक दत्त
आर के पुरम	प्रियंका सिंह
महरौली	महेंद्र चौधरी
छत्तरपुर	सतीश लोहिया
देवली	अरविंदर सिंह लवली
संगम विहार	पूनम आजाद
ओखला	परवेज हाशमी
त्रिलोकपुरी	विजय कुमार
कोंडली	अंबरीश गौतम
पटपड़गंज	लक्ष्मण रावत
सीमापुरी	वीर सिंह धींगान
बाबरपुर	अन्वीक्षा त्रिपाठी
मुस्तफाबाद	अली मेंहदी

चुनाव प्रचार से लेकर परिणाम आने तक चर्चा का केंद्र रहे हनुमान जी

राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव प्रचार से लेकर परिणाम तक चर्चा का विषय बने रहे सभी के आराध्य हनुमान जी ने आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आशीर्वाद दे दिया। केजरीवाल ने भी कहा है कि हनुमान जी की कृपा से वह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

चुनाव-प्रचार के दौरान हनुमान जी को लेकर आप और भाजपा के नेताओं के बीच जोरदार जुबानी जंग देखने को मिली थी। परिणाम आने के बाद केजरीवाल ने कहा कि आज मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है। हनुमान जी ने दिल्ली पर कृपा बरसाई है। मैं इसके लिए हनुमान जी को धन्यवाद देता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी हमें सही रास्ता दिखाते रहें ताकि हम अगले पांच वर्षों तक लोगों की सेवा जी-जान से करते रहें।

चुनाव से पहले केजरीवाल ने एक कार्यक्रम के दौरान हनुमान चालीसा पढा था। जिसके बाद मनोज तिवारी सहित कई भाजपा नेताओं ने उन पर तंज कसा था। इसके बाद आप और भाजपा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के बीच हनुमान जी एक धुरी बन गए थे।

विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद आप कार्यालय में खुशी का इजहार करते कार्यकर्ता ● ध्रुव कुमार

दिल्ली में कांग्रेस ने खोया अपना रहा-सहा जनाधार

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

आप और भाजपा के संघर्ष में कांग्रेस इस बार दिल्ली में अपना वजूद भी करीब-करीब खो बैठी है। 2015 के मुकाबले पार्टी का वोट फीसद इस बार आधे से भी कम रह गया है। यही नहीं शीला दीक्षित के नेतृत्व में 2019 में कांग्रेस ने जो जनाधार बढ़ाया था, वह भी धड़ाम से नीचे आ गया। यहां तक कि एक भी प्रत्याशी खुद को दूसरे नंबर पर लाने में कामयाब नहीं हो सका।

2015 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस शून्य पर सिमट गई थी। लेकिन, तब कांग्रेस को नौ फीसद वोट मिले थे। वहीं मई 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट फीसद बढ़कर 22.4 फीसद हो गया था। इससे 70 में से 65 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस आप को पछाड़ कर दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। लेकिन, शीला के निधन के बाद पार्टी इस वोट फीसद को बढ़ाना तो दूर बरकरार भी न रख सकी। इस चुनाव में पार्टी महज चार फीसद वोटों पर ही सिमटकर रह गई।

गठबंधन रहा बेअसर, 66 सीटों पर जमानत जब्त: पहली बार कांग्रेस ने दिल्ली में बिहार की क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के साथ चार सीटों पर गठबंधन किया, लेकिन यह भी बेअसर रहा। इन चारों सीटों सहित कांग्रेस उम्मीदवार 66 सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा सके।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा की बेटी शिवानी चोपड़ा, प्रचार समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता कीर्ति आजाद की पत्नी पूनम आजाद, मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा, पूर्व सांसद परवेज हाशमी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ, पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली, हारून यूसुफ, डा. नरेंद्र नाथ, पूर्व कद्दावर विधायक जयकिशन, राजेश लिलोठिया और सोमेश शौकीन सहित पार्टी के सभी दिग्गजों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ गांधी नगर से अरविंदर सिंह लवली, सीलमपुर से चौ. मतीन अहमद, समयपुर बादली से देवेंद्र यादव और कस्तूरबा नगर से अभिषेक दत्त ही जमानत बचाने में कामयाब रह पाए। आप छोड़कर कांग्रेस में आए आदर्श शास्त्री और अलका लांबा को भी जनता ने पूरी तरह से नकार दिया।

निराशाजनक प्रदर्शन

- 2015 में पार्टी को मिले थे नौ फीसद वोट, इस बार चार
- 2019 के लोस चुनाव में मिली बढ़त नहीं रख सकी बरकरार

प्रदेश अध्यक्ष चोपड़ा ने ली हार की नैतिक जिम्मेदारी इस्तीफे की पेशकश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आलाकमान सोनिया गांधी को इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद तीन माह पूरी मेहनत की। चुनाव भी मजबूती से लड़ा, लेकिन शायद मुद्दों की लड़ाई में जनता ने कांग्रेस को महत्व नहीं दिया। इसके साथ ही उन्होंने जीत के लिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को बधाई भी दी है।

"भाजपा दिल्ली की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सम्मान करती है। सभी कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में अथक परिश्रम किया और दिनरात लगे रहे। सभी का हृदय से अभिनंदन और साधुवाद। भाजपा इस जनादेश को स्वीकारते हुए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी और प्रदेश के विकास से जुड़े हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगी। इस विश्वास के साथ की आप की सरकार दिल्ली का विकास करेगी, मैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बधाई देता हूं।

जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष

दिल्ली के सभी मतदाताओं का धन्यवाद। सभी कार्यकर्ताओं को उनके कठिन परिश्रम के लिए साधुवाद। दिल्ली की जनता का जनादेश सिर माथे पर। अरविंद केजरीवाल को बहुत-बहुत बधाई। दिल्ली के विकास के लिए भाजपा काम करती रहेगी।"

मनोज तिवारी
दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष

धैर्य | कई राउंड तक पिछड़ते रहे आप प्रत्याशी सिसोदिया, कमजोर समझे जा रहे रवि नेगी ने दी जबर्दस्त चुनावी टक्कर

हार के 'अंदेशे' के बीच भी विचलित नहीं हुए सिसोदिया

सुधीर कुमार, पूर्वी दिल्ली

14वें राउंड में मिली जीत, पर जीत का अंतर बहुत कम रहा, पिछली बार मिले थे 75,477 वोट इस बार मिले 70,163 वोट

दिल्ली की महत्वपूर्ण सीटों में से एक पटपड़गंज विधानसभा सीट से आप उम्मीदवार और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मतगणना के शुरुआती कई राउंड तक लगातार पिछड़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से कई बार लोगों को उनकी हार का अंदेशा तक होने लगा। हालांकि, इस बीच सिसोदिया बिना विचलित हुए परिणाम को लेकर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करते रहे। लेकिन, 14वें राउंड में जीत सुनिश्चित होते ही उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर ही गई। जिस भाजपा प्रत्याशी रवि नेगी को कमजोर आंका जा रहा था उन्होंने सिसोदिया की मुस्कान को कई घंटों तक गायब रखा।

सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो इसमें ही सिसोदिया पिछड़ गए। पहले राउंड में सिसोदिया ने 112 वोटों की बढ़त ली, लेकिन दूसरे व तीसरे राउंड में वह पिछड़ गए। चौथे राउंड में थोड़ी बढ़त मिली लेकिन पांचवें व छठे राउंड फिर पीछे हो गए। सातवें व आठवें राउंड में उनके वोट बढ़े फिर नौवें राउंड में वोट कम हो गए। दसवें राउंड में करीब बराबरी का मामला रहा। मनीष सिसोदिया 600 से लेकर दो हजार वोटों से पीछे हो गए। जैसे जैसे राउंड की गिनती आ रही थी वह किसी से कुछ भी नहीं बोल रहे थे, मीडिया कर्मियों ने कई बार उनकी प्रतिक्रिया लेनी चाही लेकिन उनकी नजरें सिर्फ राउंड की रिपोर्ट पर रही, वह अपने अगल बगल बैठे सहयोगियों से मिले वोटों को लेकर चर्चा करते रहे। इलाकों की जानकारी लेते रहे, जहां से उन्हें कम वोट मिले हैं। उन्हें राहत 11 वें राउंड से मिलनी शुरू हुई।

इसके बाद उनके वोटों में थोड़ा-थोड़ा इजाफा होता गया। 14वें राउंड में उनकी जीत सुनिश्चित हुई। हालांकि, 15 वें व अंतिम राउंड में उन्हें थोड़े कम वोट मिले लेकिन तब तक वह जीत का आंकड़ा पार कर चुके थे। और 3207 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई। उन्होंने हैट्रिक तो मार ली लेकिन इस बार उनकी जीत का फासला बहुत ही कम रहा। यहां तक कि पिछली बार उन्हें 75,477 वोट मिले थे और जीत का अंतर 28,761 वोट था। वहीं 2013 में उनकी जीत का अंतर 11,476 था। लेकिन इस बार उन्हें मात्र 70,163 वोट ही मिले हैं।

भाजपा ने यहां से युवा प्रत्याशी रविंदर सिंह नेगी को उतारा था। पहले इन्हें कमजोर प्रत्याशी के रूप में आंका जा रहा था हालांकि भाजपा के कई नेताओं का कहना था कि इस युवा नेता में उलटफेर करने की पूरी क्षमता है। नेगी के रूप में यहां भाजपा का प्रदर्शन पिछले चुनावों की तुलना में काफी बेहतर रहा। वहीं, इस सीट पर कांग्रेस की स्थिति और भी खराब हो गई।

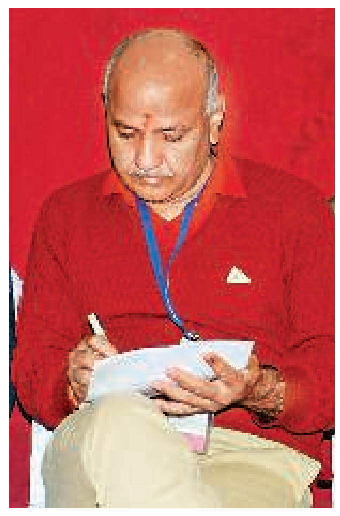

मतगणना केंद्र पर बैठे पटपडगंज विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया ● जागरण

नेतृत्व ही नहीं नैरेटिव के मोर्चे पर भी विफल कांग्रेस

गिरती साख ▸ दिल्ली विधानसभा चुनाव में दुर्गति से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का संकट किया और गहरा

राज्यों में भी पार्टी चुका रही है इसकी भारी कीमत

संजय मिश्र, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई भारी दुर्गति से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि बदली राजनीति में सबसे कारगर साबित हो रहे 'नेतृत्व' और 'नैरेटिव' के दो सबसे अहम मानकों पर पार्टी खरी नहीं उतर पा रही है। खुद को पंथनिरपेक्षता की वैचारिक लड़ाई की सबसे मजबूत ताकत के रूप में पेश करने के बावजूद नेतृत्व और नैरेटिव की इस कमजोरी के कारण ही भाजपा का विकल्प बनने से कांग्रेस बार-बार चूक रही है। उसकी इस कमजोरी का फायदा क्षेत्रीय दलों और उसके क्षत्रपों को सीधे तौर पर मिल रहा है। राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के विकल्प को लेकर पार्टी का लगातार जारी असमंजस काफी हद तक कांग्रेस के इस संकट के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भाजपा को कमजोर करने की रणनीति के तहत आप की जीत में कांग्रेस नेता सांत्वना भले तलाश लें मगर सियासी हकीकत तो यही है कि दिल्ली की दुर्गति ने नेतृत्व को लेकर पार्टी की चुनौती को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून-एनआरसी के खिलाफ भाजपा को दिल्ली के चुनाव में सीधी चुनौती दी। शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन, जामिया और जेएनयू में हिंसा पर पार्टी न केवल मुखर रही बल्कि उसके कई नेता समर्थन जताने के लिए इन सबके साथ खड़े भी हुए।

चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पसरा सन्नाटा। जागरण

बावजूद इसके कांग्रेस सीएए-एनआरसी की मुखालफत में पड़े होने वाले वोट भी अरविंद केजरीवाल के खाते में जाने से नहीं रोक पायी। जबकि आम आदमी पार्टी ने इन मुद्दों पर सहानुभूति रखते हुए भी सीधे विरोध से परहेज किया। इसी तरह भाजपा के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के सियासी दांव के फंदे में कांग्रेस बार-बार उलझती दिखाई पड़ी। कांग्रेस की इस उलझन का साफ तौर पर फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। दिल्ली में हुई दुर्गति पर ईमानदारी से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया तो यह बिल्कुल साफ दिखाई देगा कि कांग्रेस अपनी पुरातन 'मध्यमार्गी राजनीति' के समावेशी नैरेटिव का संदेश जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है।

वहीं दिल्ली में चाहे अरविंद केजरीवाल हों, ओडिशा में नवीन पटनायक, बिहार में नीतीश कुमार, तेलंगाना में के.चंद्रशेखर राव या आंध्रप्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जैसे क्षेत्रीय क्षत्रप ये सभी कांग्रेस के समावेशी या मध्यमार्गी विमर्श के पुराने फार्मूले के सहारे अपनी राजनीति को परवान चढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की चुनौती केवल इसी मोर्चे पर ही नहीं है। उसकी दूसरी बड़ी चुनौती राज्यों में मजबूत नेतृत्व का जारी संकट भी है।

चुनाव दर चुनाव साबित हो गया है कि कांग्रेस केवल उन्हीं राज्यों में सत्ता या विपक्ष में मजबूती से खड़ी है जहां उसके क्षेत्रीय नेता मजबूत हैं। पंजाब, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा जैसे सूबे इसके उदाहरण हैं। लेकिन देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के बाद अब महाराष्ट्र भी इस सूची में शामिल हो गया है जिन सूबों में नेतृत्व का दमदार चेहरा नहीं होने की वजह से कांग्रेस दूसरे से लेकर चौथे नंबर की पार्टी बन चुकी है।

दिल्ली में शीला दीक्षित के 15 सालों के बेमिसाल प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस बीते छह साल में उनका विकल्प नहीं तलाश पायी। इसी का नतीजा रहा कि लगातार दूसरे चुनाव में कांग्रेस का खाता खुलना तो दूर उसके अधिकांश उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। हालांकि सूबों में कांग्रेस के विकल्प बनने वाले नेतृत्व के नहीं उभर पाने की इस कमजोरी का दोष राज्यों के नेताओं पर मढ़ना उन पर ज्यादती होगी। हकीकत की कसौटी पर देखा जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की लगातार फीकी पड़ी चमक का असर राज्यों के नेतृत्व पर पड़ा है। सोनिया गांधी के दो दशक के पार्टी अध्यक्ष के कार्यकाल में राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय नेताओं को उभारने की राजनीतिक प्रक्रिया पर लगभग ताला लग गया है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का उभरना एक अपवाद जरूर है। जबकि राहुल गांधी अपने छोटे से कार्यकाल में अपने नेतृत्व को साबित करने के संघर्ष से जूझते रहे। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के युवा चेहरों के रूप में सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, राजीव सातव जैसे लोगों ने अपनी जो जगह बनाई है, उसमें उनकी राजनीतिक विरासत का योगदान कहीं ज्यादा रहा है। इन चुनौतियों से उबरने की जगह कांग्रेस अब भी अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सबसे बड़े संकट का स्थायी समाधान नहीं तलाश पा रही। सोनिया गांधी लंबे समय तक पार्टी का नेतृत्व करने को तैयार नहीं और न ही उनकी सेहत इसकी इजाजत दे रही है। राहुल गांधी की दोबारा वापसी पर भी पार्टी जल्द इधर-उधर का साहसी फैसला लेने का जोखिम नहीं उठा रही और इस असमंजस का सीधा असर राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर पड़ रहा है। राहुल के इस्तीफे के बाद दिल्ली समेत चार राज्यों में हाल में हुए चुनावों के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के असमंजस का सीधा नुकसान पार्टी को होता हुआ दिखाई दिया।

ये हैं विधानसभा चुनाव के विजेता

विधानसभा सीट	विजेता का नाम	पार्टी	प्राप्त मत
1. नरेला	शरद कुमार	आप	86262
2. बुराड़ी	संजीव झा	आप	139598
3. तिमारपुर	दिलीप पांडेय	आप	71432
4. आदर्श नगर	पवन शर्मा	आप	46892
5. बादली	अजेश यादव	आप	69357
6. रिठाला	मोहिंदर गोयल	आप	87940
7. बवाना	जय भगवान	आप	95715
8. मुंडका	धर्मपाल लाखड़ा	आप	90293
9. किराड़ी	ऋतुराज गोविंद	आप	86312
10. सुल्तानपुर माजरा	मुकेश कुमार अहलावत	आप	74573
11. नांगलोई जाट	रघुविंदर शौकीन	आप	74444
12. मंगोलपुरी	राखी बिड़ला	आप	74154
13. रोहिणी	विजेंद्र गुप्ता	भाजपा	62174
14. शालीमार बाग	वंदना कुमारी	आप	57707
15. शकूरबस्ती	सत्येंद्र जैन	आप	51165
16. त्रिनगर	प्रीति तोमर	आप	58504
17. वजीरपुर	राजेश गुप्ता	आप	57331
18. मॉडल टाउन	अखिलेश पति त्रिपाठी	आप	52665
19. सदर बाजार	सोम दत्त	आप	68790
20. चांदनी चौक	प्रह्लाद सिंह साहनी	आप	50891
21. मटियामहल	शोएब इकबाल	आप	67282
22. बल्लीमारान	इमरान हुसैन	आप	65644
23. करोलबाग	विशेष रवि	आप	67494
24. पटेल नगर	राजकुमार आनंद	आप	73463
25. मोतीनगर	शिवचरण गोयल	आप	60622
26. मादीपुर	गिरीश सोनी	आप	64440
27. राजौरी गार्डन	धनवती चंदेला	आप	62212
28. हरिनगर	राजकुमारी ढिल्लों	आप	58087
29. तिलक नगर	जरनैल सिंह	आप	62436
30. जनकपुरी	राजेश ऋषि	आप	67968
31. विकासपुरी	महिंदर यादव	आप	133898
32. उत्तम नगर	नरेश बाल्यान	आप	99622
33. द्वारका	विनय मिश्रा	आप	71003
34. मटियाला	गुलाब सिंह	आप	139010
35. नजफगढ़	कैलाश गहलोत	आप	81507
36. बिजवासन	भूपिंदर सिंह जून	आप	57271
37. पालम	भावना गौर	आप	92775
38. दिल्ली कैंट	वीरेंद्र सिंह कादियान	आप	28971
39. राजेंद्र नगर	राघव चड्ढा	आप	59135
40. नई दिल्ली	अरविंद केजरीवाल	आप	46758
41. जंगपुरा	प्रवीण कुमार	आप	45133
42. कस्तूरबा नगर	मदन लाल	आप	37100
43. मालवीय नगर	सोमनाथ भारती	आप	52043
44. आरके पुरम	प्रमिला टोकस	आप	47208
45. महरौली	नरेश यादव	आप	62417
46. छतरपुर	करतार सिंह तंवर	आप	69411
47. देवली	प्रकाश जारवाल	आप	92575
48. अंबेडकर नगर	अजय दत्त	आप	62871
49. संगम विहार	दिनेश मोहनिया	आप	75345
50. ग्रेटर कैलाश	सौरभ भारद्वाज	आप	60372
51. कालकाजी	आतिशी	आप	55897
52. तुगलकाबाद	सही राम	आप	58905
53. बदरपुर	रामवीर सिंह बिधूड़ी	भाजपा	90082
54. ओखला	अमानतुल्ला खां	आप	130367
55. त्रिलोकपुरी	रोहित कुमार मेहरौलिया	आप	69947
56. कोंडली	कुलदीप कुमार	आप	68348
57. पटपड़गंज	मनीष सिसोदिया	आप	70163
58. लक्ष्मी नगर	अभय वर्मा	भाजपा	65735
59. विश्वास नगर	ओमप्रकाश शर्मा	भाजपा	65830
60. कृष्णा नगर	एसके बग्गा	आप	72111
61. गांधी नगर	अनिल कुमार वाजपेयी	भाजपा	48824
62. शाहदरा	रामनिवास गोयल	आप	62103
63. सीमापुरी	राजेंद्र पाल गौतम	आप	88392
64. रोहतास नगर	जितेंद्र महाजन	भाजपा	73873
65. सीलमपुर	अब्दुल रहमान	आप	72694
66. घोंडा	अजय महावर	भाजपा	81797
67. बाबरपुर	गोपाल राय	आप	84776
68. गोकलपुर	सुरेंद्र कुमार	आप	88452
69. मुस्तफाबाद	हाजी यूनुस	आप	98850
70. करावल नगर	मोहन सिंह बिष्ट	भाजपा	96721

संघर्ष का दूसरा नाम है अरविंद केजरीवाल

निहाल सिंह, नई दिल्ली

लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रहे अरविंद केजरीवाल को संघर्ष का दूसरा कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ काफी संघर्ष किया है। यही कारण रहा कि इस बार भी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को जनता ने सिर-आंखों पर रखा है।

हरियाणा में 16 अगस्त 1968 को जन्मे अरविंद केजरीवाल दिल्ली को कर्मभूमि बनाकर यहां की जनता के दुख और समस्याओं को खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। केजरीवाल ने आइआइटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और टाटा स्टील में काम किया। वह वर्ष 1992 में भारतीय राजस्व सेवा (आइआरएस) में शामिल हुए। बतौर आइआरएस अधिकारी उन्होंने दिल्ली में अपनी सेवाएं दीं। लेकिन, उन्हें यह नौकरी ज्यादा रास नहीं आई। केजरीवाल वर्ष 2006 में आइआरएस की नौकरी से इस्तीफा देकर सामाजिक गतिविधियों में कूद गए। उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए 2006 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। उन्होंने सूचना का अधिकार कानून बनाने के लिए सामाजिक आंदोलन भी चलाया और इसे देशव्यापी कानून बनवाने में मदद की। इसके बाद दिल्ली के नंदनगरी से परिवर्तन नामक संस्था चलाकर राशन माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के लिए भी केजरीवाल को पहचान मिली।

▸ केजरीवाल ने व्यवस्था परिवर्तन से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ किया संघर्ष

वर्ष 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए आंदोलन में अरविंद केजरीवाल चेहरा बनकर उभरे। यहां उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक के लिए जन लोकपाल बिल के लिए दिल्ली में एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। इससे तत्कालीन केंद्र की कांग्रेस सरकार की सांसें तक फूल गईं। जब जन लोकपाल बिल की मांग पर केंद्र सरकार ने बेरुखी दिखाई तो केजरीवाल व्यवस्था परिवर्तन के लिए राजनीति में कूद गए। 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक दल का गठन किया। इस पार्टी ने वर्ष 2013 के पहले ही विधानसभा चुनाव में 70 में 28 सीटें जीती। साथ ही कांग्रेस के 8 विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। 49 दिन की सरकार चलाने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2015 में फिर से हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में 67 सीटें जीतकर ऐतिहासिक रूप से सरकार बनाई। अब एक बार फिर 62 सीटें जीतकर केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। केजरीवाल के परिवार की बात करें तो वह तीन भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। उनकी पत्नी सुनीता भी आइआरएस अधिकारी रही हैं। केजरीवाल की एक बेटी हर्षिता आइआइटी दिल्ली से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं तो वहीं बेटा पुलकित आइआइटी दिल्ली में पढ़ रहा है।

शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी मिल गया मौका

राज्य ब्यूरो, मुंबई

दिल्ली में भाजपा की करारी हार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एवं राकांपा अध्यक्ष शरद पवार को भी भाजपा पर टिप्पणियां करने का मौका दे दिया है। कभी भाजपा के सहयोगी रहे उद्धव ने केजरीवाल और दिल्ली की जनता को बधाई दी, तो शरद पवार ने कहा है कि अब भाजपा की हार का सिलसिला रुकने वाला नहीं है।

उद्धव ठाकरे ने हार पर भाजपा की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि खुद को देशप्रेमी एवं अपने विरोधियों को देशद्रोही समझने वालों के मन का भ्रम दिल्ली वालों ने तोड़ दिया। रेडियो पर प्रधानमंत्री द्वारा प्रसारित 'मन की बात' का भी मजाक उड़ाते हुए उद्धव ने कहा कि अब देश में 'जन की बात' चलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की 'जन की बात' लोगों ने मान ली है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने भी भाजपा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली एक अलग तरह का शहर है। वहां देश के सभी हिस्सों के लोग रहते हैं, इसलिए दिल्ली के चुनाव परिणामों का असर पूरे देश में होगा और भाजपा की हार का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहते हुए ही परिणामों का अनुमान लगा लिया था। वहां मेरे निवास पर रहने वाले मेरे कर्मचारी एवं करोलबाग में रहने वाले मराठी भाषियों से मैंने बात की थी। सभी लोग केजरीवाल का नाम ले रहे थे।

▸ राकांपा अध्यक्ष ने कहा, भाजपा की हार का सिलसिला रुकने वाला नहीं

▸ उद्धव ने कहा कि अब देश में 'जन की बात' चलेगी

पवार का कहना है कि दिल्ली का परिणाम शुरुआत नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड से यह प्रक्रिया चलती आ रही है। कांग्रेस की हार पर पवार ने कहा कि उनका अनुभव है कि लोग अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। वे जानते हैं कि किसे वोट देने से किसकी हार होगी। लोगों ने भाजपा को हराने की ठानी थी, इसलिए कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को वोट दिया।

पंजाब में मंत्री बोले- कांग्रेस पहले भी जीरो, अब भी जीरो

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

दिल्ली में आम आदमी पार्टी की फिर शानदार जीत से पंजाब कांग्रेस में खुशी व गम दोनों हैं। कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर खुश हैं कि दिल्ली में भाजपा हार गई। गम इस बात का है कि कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पहले भी जीरो थी, अब भी जीरो है। हार तो भाजपा की हुई है। वहीं, कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ कहते हैं कि भाजपा का अहंकार छिन्न-भिन्न हो गया, लेकिन कांग्रेस के प्रदर्शन से हुई निराशा को भी नकारा नहीं जा सकता है।

कांग्रेस में इस बात को लेकर बेहद गुस्सा भी है कि दिल्ली में पार्टी ने जोर नहीं लगाया। एक वरिष्ठ मंत्री कहते हैं कि हम इस बात को लेकर खुश नहीं हो सकते कि भाजपा हार गई। कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। जीत न हो तो भी चलता है, लेकिन चुनाव तो जोरदार तरीके से लड़ना चाहिए था। जाखड़ कहते हैं कि भाजपा की नफरत फैलाने वाली राजनीति की हार हुई, लेकिन इस बात से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस का वोट बैंक खिसक गया है। इस बात की समीक्षा जरूर होनी चाहिए।

साधू सिंह धर्मसोत। फाइल

दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की जीत के बाद यह बहस शुरू हो गई है कि पंजाब में आप का क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस जीत से पंजाब में आप को ऑक्सीजन मिल गई है, लेकिन पंजाब में नेतृत्व की स्थिति जो तीन साल पहले थी, वही आज भी है। आप पंजाब में बिखरी हुई है। यह दीवार पर लिखी हुई इबारत है। दिल्ली चुनाव का पंजाब में कोई बड़ा असर पड़ेगा, इसकी संभावना नहीं है।

नहीं चला हरियाणा के दिग्गज नेताओं का स्टारडम

बिजेंद्र बंसल, नई दिल्ली

चार माह पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना स्टारडम साबित करने वाले सूबे के प्रमुख दल भाजपा, कांग्रेस व जजपा के नेता दिल्ली के रण में फ्लॉप साबित हुए। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्टार प्रचारक बनाया था। इसके अलावा जजपा नेता व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी प्रधानमंत्री की द्वारका रैली से भाजपा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया मगर ये सभी नेता चुनाव परिणाम अपने पक्ष में नहीं कर पाए।

इन तीनों प्रमुख नेताओं के अलावा भाजपा के पक्ष में राज्य के गृहमंत्री अनिल विज से लेकर पांच पूर्व मंत्रियों सहित 9 विधायकों ने दिल्ली में 17 विधानसभा क्षेत्रों के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। इन 17 क्षेत्रों में से भाजपा सिर्फ रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में ही चुनाव जीत पाई। कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में कई सभा कीं, लेकिन पार्टी का एक भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर सका। बता दें कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 31 सीट पर जीत दर्ज कर मजबूत विपक्ष देने का काम किया तो भाजपा ने 40 और जजपा ने 10 सीट जीतकर गठबंधन की सरकार बनाई थी। इसके बाद से ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जजपा अपना दबदबा बनाना चाहती थी।

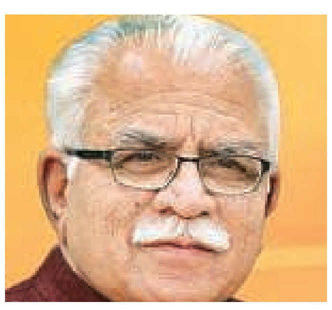

मनोहर लाल

भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइल

हरियाणा में फ्लॉप रही आप, दिल्ली में जीती

हरियाणा के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह असफल रही मगर दिल्ली के रण में आप को जबरदस्त जीत मिली। आम आदमी पार्टी की हरियाणा ईकाई के संयोजक नवीन जयहिंद चुनाव के दौरान 500 कार्यकर्ताओं के साथ पूरे तीन माह से जुटे हुए थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव खत्म होने के एक माह बाद से जयहिंद ने दिल्ली में डेरा डाल लिया था।

कांग्रेस के लिए हुड्डा और सैलजा ने भी लगाया था दम : दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी प्रचार किया मगर ये नेता भी दिल्ली में कोई चमत्कार करवाने में असफल रहे। हुड्डा और दीपेंद्र ने बाहरी दिल्ली की बादली, मुंडका सहित कई सीटों पर प्रचार किया था। हालांकि हुड्डा ने कभी भी दिल्ली में कांग्रेस की जीत का दावा नहीं किया था।

उम्मीद

अरविंद केजरीवाल के पहले से ही विकास के एजेंडे पर हो रहा बिहार में चुनाव, इस बार भी इसी को मुद्दा बनाने की है तैयारी

अपनी जीत की संभावना देख रहे नीतीश

अरुण अशेष, पटना

दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजग की हार में अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जीत की संभावना देख रहे तो यह ठीक ही है। आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज के आधार पर वोट मांग रही थी। अरविंद केजरीवाल के प्रादुर्भाव से बहुत पहले नीतीश कुमार ने काम को ही अपना मूलमंत्र बना लिया था।

विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नीतीश कुमार काम के आधार पर ही वोट मांगते हैं। साफ-साफ कह देते हैं कि काम नहीं करेंगे तो वोट भी नहीं मांगेंगे। 2015 के विस चुनाव से पहले उन्होंने वादा किया था कि घर-घर बिजली नहीं पहुंची तो हम वोट मांगने नहीं आएंगे। वह इस पर कायम भी रहे। 2005 का विधानसभा चुनाव भी कामकाज के आधार पर हुआ था। 2010 का चुनाव वादा पूरा करने के आधार पर लड़े और जीते भी। 2015 का विधानसभा चुनाव भी नीतीश ने काम के ही नाम पर ही लड़ा। हालांकि, उस समय के सहयोगी राजद ने चुनाव में दूसरे मुद्दे को पकड़ लिया था। राजद प्रमुख लालू प्रसाद भाजपा की जीत में आरक्षण की समाप्ति की आशंका जता रहे थे। वह कमंडल के दौर की याद दिला कर वोटरों को गोलबंद कर रहे थे। उस समय भी नीतीश विकास से इतर नहीं गए। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के साथ रहने के बावजूद उन्होंने अपना एजेंडा नहीं छोड़ा। जाहिर है, इस साल होने जा रहे विस चुनाव में भी नीतीश विकास व कामकाज से अलग किसी एजेंडे का चयन नहीं करेंगे। बीच के पांच साल में उनके पास विकास की कुछ और उपलब्धियां जुड़ गई हैं।

नीतीश कुमार। फाइल

भाजपा को पुरबिया वोटरों का नहीं मिला साथ

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली में पूर्वांचल के वोटरों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखकर भाजपा ने भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी को दिल्ली की कमान सौंपी है। पार्टी को उम्मीद थी कि तिवारी के सहारे वह विधानसभा चुनाव में पुरबिया वोटरों को साधने में सफल रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुराड़ी, संगम विहार, किराड़ी, द्वारका, उत्तम नगर सहित लगभग उन सभी सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा जहां उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज्यादा हैं। पूर्वांचल के लोगों का समर्थन नहीं मिलने और विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन से प्रदेश अध्यक्ष की मुश्किल भी बढ़ेगी, क्योंकि उनके विरोधियों को एक मौका मिल गया है।

दिल्ली में छात्रों और महिलाओं को प्रताड़ित करने का मिला जवाब : ममता

जागरण संवाददाता, कोलकाता

तृणमूल प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार पर तंज कसते हुए मंगलवार को कहा कि देश में जहां कहीं भी चुनाव हो रहे हैं भाजपा को हार मिल रही है क्योंकि जनता ने भाजपा को नकार दिया है। बांकुड़ा जिले में तृणमूल कांग्रेस के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक में ममता ने कहा, दिल्ली की जनता ने छात्रों व महिलाओं को प्रताड़ित करने वालों का करारा जवाब दे दिया है।

बकौल ममता लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भाजपा का अत्याचार बढ़ गया था, लेकिन आज नौबत यह है कि एक के बाद एक राज्यों में भाजपा की करारी हार हो रही है और पार्टी जल्द ही सभी राज्यों को खो देगी। उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी को मिली जीत से बेहद खुश हूं क्योंकि यह लोकतंत्र की जीत हुई है।

ममता बनर्जी। फाइल

आप की जीत क्षेत्रीय दलों के मजबूती के प्रमाण : ममता ने कहा कि आप की जीत इस बात के प्रमाण है कि राजनीति में क्षेत्रीय दलों की पैठ मजबूत हुई है। मैंने अरविंद केजरीवाल को फोन पर शुभकामनाएं दी और उन्होंने मुझे शपथ ग्रहण समारोह में आने का आमंत्रण दिया है। इससे पहले बनर्जी ने पहले फोन कर और फिर ट्वीट कर केजरीवाल को शुभकामनाएं दी। कहा कि लोगों ने भाजपा को नकार दिया है। केवल विकास ही काम करेगा क्योंकि सीएए, एनआरसी और एनपीआर को लोगों ने नकार दिया है।

आप की जीत में अपना भी सहयोग मानती है सपा!

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के बाद भी करारी शिकस्त झेल चुकी सपा का आत्मविश्वास चौंकाता है। चुनाव नतीजों के बाद पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि दिल्ली में राजनीतिक तौर पर चुनाव विधानसभा नहीं लड़ने का फैसला लिया गया था। यह वोटों के बिखराव को रोकने के लिए किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज करते हुए कहा कि वह जिस किसी राज्य में गए वहां भाजपा हारी।

दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के आने के बाद यादव संसद भवन परिसर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी की जीत में परोक्ष रूप से सपा का भी हाथ है। यह और बात है कि पिछले चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस जरूर नौ-10 फीसद वोट पाने में सफल हुई थी, लेकिन बाकी छोटी पार्टियों को सम्मिलित रूप से एक फीसद वोट मिला था।

102 को मृत्युदंड सुनाया 2019 में निचली अदालतों ने। 2018 में 162, 2017 में 108 व 2016 में 150 को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। यह बात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली (एनएलयू) की जनवरी में जारी एक रिपोर्ट में सामने आई।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 12 फरवरी 2020

आतंकी हिंसा मामले में जीएम सरूरी से एनआइए ने की छह घंटे पूछताछ

शिकंजा ▶ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री पर हैं कई संगीन आरोप

पूछताछ के बाद बोले सरूरी, मैं निर्दोष, आज सार्वजनिक करूंगा पक्ष

राज्य ब्यूरो, जम्मू

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीएम सरूरी से किश्तवाड़ जिले में आतंकी हिंसा और भाजपा नेता अनिल परिहार और उनके भाई की हत्या से जुड़े मामलों में करीब छह घंटे पूछताछ की। बुधवार को एनआइए ने सरूरी को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं, एनआइए ने पूछताछ पर किसी तरह का कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सरूरी के करीबी दावा कर रहे हैं कि उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। इस बीच, जीएम सरूरी ने कहा, 'मैं निर्दोष हूं। मैं बुधवार को इस विषय पर अपना पक्ष सार्वजनिक करूंगा। आप कल सुबह 10 बजे तक इंतजार करें।'

किश्तवाड़ जिले में भाजपा नेता अनिल परिहार, उनके भाई और आरएसएस नेता चंद्रकांत शर्मा व उसके अंगरक्षक की हत्या में शामिल आतंकियों के साथ जीएम सरूरी के कथित रिश्तों का पता लगाने के लिए ही सीआरपीसी की धारा 160 के तहत एनआइए ने उन्हें पूछताछ के लिए जम्मू स्थित अपने कार्यालय में तलब किया था। सरूरी पर आरोप है कि पिछले वर्ष अक्टूबर में मारे गए आतंकी ओसामा व जहांगीर सरूरी ने उनके मकान में शरण ली थी।

जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित एनआइए कार्यालय में मंगलवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री जीएम सरूरी से आतंकी गतिविधियों के सिलसिले में छह घंटे पूछताछ हुई। तस्वीर में कार्यालय के बाहर तैनात सुरक्षा बल। जागरण

सुबह 11:15 बजे एनआइए कार्यालय पहुंचे जीएम सरूरी शाम साढ़े पांच वहां से बाहर निकले। एनआइए कार्यालय में पूछताछ के लिए दाखिल होने से पहले जीएम सरूरी ने एक संक्षिप्त बातचीत में कहा मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्यों बुलाया गया है। मुझे एक नोटिस मिला था और उस नोटिस के आधार पर ही मैं आज यहां पूछताछ के लिए आया हूं। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, एनआइए वाले क्या जानना चाहते हैं। मेरे पास तो कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है। वहीं, शाम को एनआइए कार्यालय से निकलने के बाद सरूरी ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, बुधवार को सारी बात सभी को बताऊंगा।

इस बीच, जीएम सरूरी के करीबियों ने दावा किया कि एनआइए ने कांग्रेस नेता को क्लीन चिट दे दी है। सरूरी ने एनआइए अधिकारियों को बताया कि उन्होंने कभी भी किसी भी आतंकी का किसी भी तरह से साथ नहीं दिया है। उन्होंने किसी आतंकी को अपने घर में शरण नहीं दी है। उनके जिस मकान में आतंकियों के शरण लेने का दावा किया जा रहा है, वह 1990 से ही अर्धसैनिकबलों और पुलिस के पहरे में है। उन्होंने कथित तौर पर एनआइए अधिकारियों को बताया कि जिस आतंकी जहांगीर सरूरी का उनके साथ नाम लिया जा रहा है, उसका असली नाम मोहम्मद अमीन बट है। वह सरूर इलाके का रहने वाला है, इसलिए उसे सरूरी भी कहते हैं, लेकिन आतंकी सरूरी का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस नेता ने पूछताछ कर रहे अधिकारियों को बताया कि उनके घर के भीतर और बाहर कई जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इसलिए आतंकियों के लिए उनके मकान में दाखिल होना या किसी अन्य तरीके से शरण लेना संभव नहीं है।

तीन ओवरग्राउंड वर्करों को सामने बैठाकर हुई पूछताछ : सूत्रों की मानें तो सरूरी के समक्ष किश्तवाड़ में आतंकियों के लिए काम करने वाले तीन ओवरग्राउंड वर्करों को भी लाया गया। इनके सामने भी जीएम सरूरी से कई सवाल किए गए। ओवरग्राउंड वर्करों से भी कुछ सवाल पूछे गए। बाद में इन ओवरग्राउंड वर्करों को जम्मू-कश्मीर पुलिस विशेष अभियान दल अपने साथ ले गया।

सरूरी के भाई शफी के खिलाफ दर्ज है मामला

पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के करीबियों में गिने जाने वाले जीएम सरूरी का नाम अगस्त 2013 में किश्तवाड़ में हुई सांप्रदायिक हिंसा को उकसाने वाले लोगों में लिया जाता है। बता दें कि एनआइए ही किश्तवाड़ में हुई राजनीतिक हत्याओं की जांच का जिम्मा संभाले हुए है। पुलिस ने बीते साल सितंबर के दौरान किश्तवाड़ में आतंकियों से जुड़े नौ लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पुलिस ने आतंकियों की मदद करने और उनके लिए सुरक्षित ठिकानों का बंदोबस्त करने के मामले में जीएम सरूरी के भाई मोहम्मद शफी सरूरी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था।

आज आएंगे यूरोपीय सांसद हर वर्ग से करेंगे मुलाकात

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के हालात का जायजा लेने के लिए यूरोपीय संघ के 25 सांसदों के दौरा आज से शुरू हो रहा है। इसके चलते घाटी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह दल उत्तरी कश्मीर के जिला बारामुला में स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक, मजहबी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के अलावा श्रीनगर में भी विभिन्न वर्गों से मिलेगा। इस बार कश्मीर की कुछ महिला पत्रकार भी यूरोपीय संघ के प्रतिनिधियों संग जम्मू-कश्मीर के बदलाव पर अपना पक्ष रखते हुए उन्हें पाकिस्तान व जिहादी तत्वों की साजिशों से अवगत कराएंगी। यूरोपिय सांसदों का डल झील की भी सैर का कार्यक्रम है।

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि यूरोपीय संघ के 25 सांसद सुबह 11:25 बजे दिल्ली से एक विशेष विमान में श्रीनगर पहुंचेंगे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर सैन्याधिकारियों द्वारा उन्हें राज्य की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद उन्हें उत्तरी कश्मीर में जिला बारामुला ले जाया गया है। बारामुला में विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से यूरोपीय संघ के सांसद मिलेंगे। स्थानीय पुलिस व नागरिक प्रशासन के अधिकारियों संग भी विदेशी सांसद हालात पर एक बैठक करेंगे। बारामुला में करीब दो घंटे बिताने के बाद यह लोग श्रीनगर लौटेंगे और एक होटल में स्थानीय सामाजिक, राजनीतिक, मजहबी, व्यापारिक, युवा और बुद्धिजीवी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। यूरोपीय संघ के सांसद पूर्व विधायकों के एक दल के साथ भी बैठक करेंगे।

वह कश्मीर घाटी में मीडियाकर्मियों को पेश आ रही दिक्कतों को जानने के लिए, कश्मीर में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को लागू किए जाने के बाद आए बदलाव और आम लोगों की भावनाओं को समझने के लिए मीडियाकर्मियों के एक दल से भी मिलेंगे। इस बार कश्मीर की महिला पत्रकारों, महिलाओं सशक्तिकरण में जुटी महिला समाज सेविकाओं को भी विदेशी सांसदों से मिलने वालों की सूची में शामिल किया गया है। वहीं, श्रीनगर में सेना की 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लों के नेतृत्व में वरिष्ठ सैन्याधिकारियों का दल राज्य के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिदृश्य की जानकारी यूरोपीय संघ के सांसदों को देगा।

पूर्व मंत्रियों-नेताओं से सरकारी बंगले खाली कराने के निर्देश

जेएनएन, जम्मू : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य प्रशासन को पूर्व मंत्रियों, नेताओं और नौकरशाहों से सरकारी बंगले खाली करवाने का निर्देश दिया है। बेंच ने कहा कि श्रीनगर व जम्मू में ए, बी और सी श्रेणी के जितने भी सरकारी बंगलों और क्वार्टरों पर अवैध कब्जा है, उनका दो सप्ताह के भीतर विवरण दिया जाए और तत्काल खाली करवाए जाएं। बेंच ने वैध और अवैध किरायेदारों से सारा बकाया किराया वसूलने का निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिए अगर जमीन राजस्व कानून लागू करना पड़े, तो किया जाए। मोहम्मद यासीन शाह की ओर से दायर एक जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे व जस्टिस डीएस ठाकुर ने एस्टेट विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देश दिए कि वह अब तक खाली करवाए गए ए, बी व सी श्रेणी के सरकारी बंगलों व क्वार्टरों की पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई तक पेश करें।

जम्मू के किश्तवाड़ में हिजबुल का ओजीडब्ल्यू गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, किश्तवाड़

▶ बड़ी सफलता-पूछताछ जारी, हिजबुल के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए जल्द हो सकती है छापेमारी

▶ परिहार बंधुओं की हत्या सहित कई वारदात के समय आतंकियों की कर चुका मदद

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जिला किश्तवाड़ के गांव हुंजाला से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ओजीडब्ल्यू किश्तवाड़ में सक्रिय हिजबुल आतंकियों को मदद पहुंचाने का काम करता था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ओजीडब्ल्यू से मिले सुराग के आधार पर किश्तवाड़ में आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे ओवरग्राउंड वर्करों और हिजबुल के नेटवर्क का पता लग सकता है।

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार ओजीडब्ल्यू की पहचान मुहम्मद रुस्तम के रूप में हुई है। पुलिस को अपने सूत्रों से पता चला था कि मुहम्मद रुस्तम आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है। वह किश्तवाड़ में सक्रिय हिजबुल आतंकियों को कई बार सहायता पहुंचाता रहा है। पुलिस को यह भी पता चला कि परिहार बंधुओं और आरएसएस पदाधिकारी चंद्रकांत शर्मा और उनके पीएसओ की हत्या में शामिल ओसामा बिन जावेद व उसके साथी इन वारदात को अंजाम देने के बाद रुस्तम के घर पर ही ठहरे थे। इसके अलावा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला अध्यक्ष के पीएसओ की राइफल छीनने वाले आतंकी भी जिस गाड़ी में फरार हुए थे, वे गाड़ी भी हुंजाला गांव के पास बरामद हुई थी।

इन जानकारियों के आधार पर पुलिस काफी समय से रुस्तम की तलाश में थी। उसे इस बात की भनक लग चुकी थी कि पुलिस को उसके बारे में पता चल गया है। इसीलिए वे फरार हो गया था, लेकिन गत सोमवार को पुलिस को पता चला कि रुस्तम अपने पैतृक गांव हुंजाला में देखा गया है। पुलिस ने तुरंत गांव में छापा मारा और रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दावा किया जा रहा है कि रुस्तम की मदद से किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद मिलेगी।

क्रॉस एलओसी ट्रेड से करोड़ों कमाने वालों पर नजर

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर

▶ कीमत में हेरफेर कर व्यापारियों ने किए करोड़ों के वारे-न्यारे

▶ धन का आतंकी फंडिंग और अलगाववादी गतिविधियों में हो रहा था प्रयोग

क्रॉस एलओसी व्यापार के नाम पर आतंकियों और अलगाववादियों को वित्तीय मदद पहुंचाते हुए तिजोरियां भरने वाले व्यापारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। केंद्रीय आयकर विभाग ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को नियंत्रण रेखा के पार से व्यापार में शामिल ऐसे व्यापारियों की सूची सौंपने और उनकी कुंडली खंगालने को कहा है।

क्रॉस एलओसी व्यापार जम्मू-कश्मीर और गुलाम कश्मीर के बीच अक्टूबर 2008 के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत शुरू किया गया था। इस व्यापार में जम्मू-कश्मीर और गुलाम कश्मीर के व्यापारी ही आपस में सिर्फ अनुमोदित सूची में शामिल वस्तुओं का आयात-निर्यात कर सकते थे। इसके तहत केवल सामान के बदले सामान ही भेजा जा सकता था।

कई बार गुलाम कश्मीर से आने वाले सामान में नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप भी बरामद हुई। इसके साथ ही इसकी कमाई से आतंक को वित्तीय ऑक्सीजन मिल रही थी और अप्रैल 2019 में इसे बंद कर दिया गया। राज्य पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, इस काम की आड़ में करोड़ों के वारे-न्यारे करने वाले व्यापारियों की सूची आयकर विभाग ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को भेजी है। विभाग ने इन व्यापारियों की कुंडली खंगालने को कहा है।

सामान की कीमत की जानकारी मांगी: पुलिस ने व्यापारियों की गतिविधियों का विस्तृत ब्यौरा तैयार करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर उद्योग विभाग से इस व्यापार में शामिल सभी व्यापारियों द्वारा मंगवाए गए सामान की कीमत के बारे में जानकारी जमा कराने के कहा है।

जाली करंसी और नशे की तस्करी भी बढ़ी

18 अप्रैल 2019 को केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर क्रॉस एलओसी ट्रेड को बंद करने का निर्देश दिया। अधिसूचना के अनुसार इस व्यापार का इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे आतंकी हिंसा फैलाने, अलगाववादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने, जाली करंसी और नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए कर रहे थे। ऐसे में मजबूत पारदर्शी तंत्र स्थापित होने तक इसे बंद करने का आदेश दिया गया।

यूं समझें क्रॉस एलओसी ट्रेड का खेल

अधिकारियों ने बताया कि क्रॉस एलओसी व्यापार के नाम पर बड़ा खेल बरसों चलता रहा। व्यापारी नियंत्रण रेखा के पार से महंगा सामान कागजों में सस्ता दिखाकर खरीदते और खुले बाजार में महंगी दरों पर बेच देते। इस खेल में करोड़ों की कमाई का बड़ा हिस्सा आतंकी और अलगाववादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता रहा। गुलाम कश्मीर में बैठे कई आतंकी कमांडर भी इस व्यापार को चला रहे थे। एनआइए इस मामले की जांच कर रही है। उक्त अधिकारी ने बताया कि गुलाम कश्मीर से 10 लाख रुपये के समान की कीमत कागजों में चार से छह लाख रुपये दिखाई जाती थी। इसके बदले उसे इतने का सामान ही उस पार भेजना होता था। इस तरह मिलने वाले मोटे मुनाफे का बड़ा हिस्सा आतंकियों व अलगाववादियों तक जाता रहा। इसमें व्यापारी कहीं से संदेह में नहीं आता था।

21 वस्तुओं का आयात-निर्यात

एक समझौते के बाद अक्टूबर 2008 में जम्मू-कश्मीर व गुलाम कश्मीर के व्यापारियों को करमुक्त क्रॉस एलओसी ट्रेड की अनुमति दी गई थी। 21 वस्तुओं के ही आयात-निर्यात की अनुमति थी। इसमें केवल सामान के बदले सामान (बार्टर ट्रेड) भेजने की ही अनुमति थी। इसके तहत कश्मीरी व्यापारी उड़ी सेक्टर में सलामाबाद के रास्ते अमन कमान सेतु के पार गुलाम कश्मीर में मुजफ्फराबाद सामान भेजते थे और मंगाते थे। जम्मू क्षेत्र के व्यापारी पुंछ में चक्का दा बाग के रास्ते रावलकोट (गुलाम कश्मीर) में सामान भेजते थे।

पाकिस्तान की गोलाबारी में जवान घायल

जागरण संवाददाता, राजौरी

▶ भारतीय सेना के जवानों ने घुसपैठ का प्रयास किया विफल

▶ जवाबी कार्रवाई में सीमा पार भी नुकसान की सूचना

पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर राजौरी के लाम सेक्टर में भारी गोलाबारी की, जिसमें भारतीय सेना का एक जवान घायल हो गया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। देर शाम तक दोनों तरफ से गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में सीमा पार नुकसान होने की सूचना है। हालांकि, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

जानकारी के अनुसार, शाम करीब पांच बजे पाकिस्तानी सेना ने एकाएक सैन्य चौकियों को निशाना बनाते हुए गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में लाम सेक्टर में एक अग्रिम चौकी पर तैनात सेना का जवान घायल हो गया। उसे उपचार के लिए तुरंत सैन्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी पाक सेना को जवाब देना शुरू कर दिया।

गोलाबारी की लेते हैं आड़ : सूत्रों के अनुसार, इस सेक्टर में बर्फबारी नहीं होती है और घुसपैठ के लिए आतंकी पहले भी कई बार इस सेक्टर का उपयोग कर चुके हैं। मंगलवार को भी पाक सेना इस गोलाबारी की आड़ में आतंकियों के दल को भारतीय क्षेत्र में दाखिल करवाने का प्रयास कर रही थी, जिसे सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों ने विफल कर दिया।

पुंछ के जंगलों में तलाशी अभियान : पुंछ के खनेतर और मगनाड़ गांव के जंगलों में मंगलवार सुबह सेना की राष्ट्रीय राइफल बटालियन और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने जंगली इलाकों में संदिग्ध लोगों को देखा था, जिसके बाद सेना और पुलिस ने यह तलाशी अभियान चलाया।

उमर की हिरासत के खिलाफ सारा की याचिका पर सुनवाई आज

▶ जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम की बहन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में रखने के खिलाफ उनकी बहन द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। सारा अब्दुल्ला पायलट की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस एनवी रमना की पीठ सुनवाई करेगी। सारा ने अपनी याचिका में कहा है कि उमर को हिरासत में रखना 'जाहिर तौर पर गैरकानूनी' है। उनसे 'सार्वजनिक व्यवस्था को किसी खतरे' का कोई सवाल नहीं है।

याचिका में उमर को पीएसए के तहत हिरासत में रखने के पांच फरवरी के आदेश को रद करने और उन्हें अदालत के समक्ष पेश कराने का अनुरोध किया गया है। सारा ने कहा कि प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुच्छेद-370 को निरस्त करने के खिलाफ विरोध को दबाया जा सके, गलत तरीके से राजनीतिक नेताओं और लोगों को हिरासत में रखा है।

उन्होंने कहा है कि इस शक्ति का इस्तेमाल करने का उद्देश्य न केवल उमर अब्दुल्ला को कैद में रखने के लिए, बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे नेतृत्व को और साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेतृत्व को कैद में रखने का है। इसी तरह का व्यवहार फारूक अब्दुल्ला के साथ किया गया है, जिन्होंने वर्षों तक राज्य और केंद्र की सेवा की। जब भी जरूरत पड़ी, भारत के साथ खड़े हुए।

सारा ने अपनी याचिका में कहा कि चार-पांच अगस्त, 2019 की दरम्यानी रात उमर को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बाद में पता चला कि इसे सही ठहराने के लिए सीआरपीसी का अनुच्छेद 107 लगा दिया गया। याचिका में कहा गया है कि उमर को हिरासत में लेना संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 का उल्लंघन है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रशासन ने पीएसए यह कहकर लगाया कि उन्होंने अनुच्छेद-370 और 35-ए के मामले में लोगों को भड़काने की कोशिश की।

न्यूज गैलरी

सजा के खिलाफ जज को राहत से इन्कार

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री कॉलेज के रीडर को जेल भेजने वाले जज को राहत देने से इन्कार कर दिया है। कोर्ट ने आरोपित जज की चरित्र पंजिका में निंदा (सेंसर) प्रविष्टि के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। विभागीय जांच के आधार पर हाई कोर्ट की प्रशासनिक न्यायाधीशों की समिति द्वारा दी गई निंदा (सेंसर) की सजा पर हस्तक्षेप करने से इन्कार किया और कहा कि प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ ने प्रयागराज निवासी जज लल्ले सिंह की याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि याची ने फैजाबाद जिला अदालत में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर तैनाती के दौरान साकेत परास्नातक महाविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष व रीडर डॉ. राधिका प्रसाद त्रिपाठी के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर उन्हें जेल भेज दिया था। इससे पहले केस में कोई समन भी जारी नहीं किया गया। इसकी शिकायत होने पर विभागीय जांच में याची को लापरवाही बरतने का दोषी करार दिया गया। इस रिपोर्ट पर हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति ने निंदा (सेंसर) की सजा सुनाई है। (जासं)

अमरनाथ यात्रा शुरू करने की तारीख जल्द

जम्मू : केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में 2020 में बाबा अमरनाथ की यह पहली वार्षिक यात्रा होगी। यात्रा की अवधि तय करने और यात्रा से जुड़े पंजीकरण समेत अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए जल्द ही श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक होगी। हालांकि, यात्रा के प्रबंधों को लेकर तैयारियां तो कुछ दिन पहले ही शुरू हो गई थीं, जब मुख्य सचिव ने बैठक कर यात्रा के प्रबंधों का जायजा लिया था। अमरनाथ यात्रा को सफल बनाने के लिए निर्धारित समय के भीतर ही प्रबंध करने के लिए कहा गया है। यात्रा जून महीने के आखिरी सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में शुरू की जा सकती है। यात्रा का पंजीकरण भी मार्च महीने में शुरू हो सकते हैं। बताते चलें कि साल 2019 में सात मार्च को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक हुई थी। पिछले साल 46 दिन की यात्रा एक जुलाई से शुरू होकर यात्रा 15 अगस्त तक तय थी। (राब्यू)

देशद्रोह की आरोपित उर्वशी चूड़ावाला को अंतरिम राहत

मुंबई : बांबे हाई कोर्ट ने देशद्रोह की आरोपित 22 वर्षीय छात्रा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। मुंबई में एक रैली में जेएनयू छात्र शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने के लिए उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। छात्रा उर्वशी चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जस्टिस एसके शिंदे ने कहा कि गिरफ्तारी की हालत में याची को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर छोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने चूड़ावाला को दक्षिणी मुंबई के आजाद मैदान थाने में 12 और 13 फरवरी को सुबह में तीन घंटे के लिए हाजिर होने के लिए कहा। इसी थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। जब भी पुलिस पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उसे हाजिर होना पड़ेगा। इसके बाद जस्टिस शिंदे ने चूड़ावाला की अग्रिम जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई की तारीख 24 फरवरी तय कर दी। (प्रेट्र)

उत्तराखंड में 13 व 14 को बर्फीले तूफान की आशंका

देहरादून : उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फीले तूफान की आशंका है। मौसम विभाग ने गुरुवार व शुक्रवार के लिए एडवाइजरी जारी कर ऊंचाई वाले इलाकों में सतर्क रहने को कहा है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया कि इस सप्ताह अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। मैदानों में यह 29 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। बिक्रम सिंह के अनुसार, आने वाले दिनों में मैदान से लेकर पहाड़ तक मौसम शुष्क रहेगा। (जासं)

तुलना

अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पिता के कातिल से विवाह रचाने से भी नहीं चूकी थीं अंतिम हिंदू रानी, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पीएसए पर डोजियर में महबूबा की तुलना अंतिम हिंदू रानी से की है

महबूबा के डोजियर में फिर 'जिंदा' हुईं कोटा रानी

नवीन नवाज, श्रीनगर

सात सौ साल बाद कश्मीर की अंतिम हिंदू रानी-कोटा रानी, फिर से चर्चा में हैं। इतिहास ने उन्हें भुला दिया, लेकिन जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत बंदी बनाने के लिए दिए डोजियर में फिर से उनकी याद दिला दी है। इस डोजियर में महबूबा की तुलना कोटा रानी से की गई है। हालांकि, यह तुलना भी ज्यादातर लोगों को रास नहीं आ रही है।

बता दें कि कोटा रानी को साम, दाम, दंड, भेद और कूटनीति का माहिर माना जाता था। वह अपने पिता को बहुत प्रिय थीं और उन्होंने अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए पिता के कातिल से विवाह करने से भी गुरेज नहीं किया। उन्होंने दो शादियां कीं। हालांकि, कुछ इतिहासकारों का मत है कि उन्होंने तीसरी शादी भी कर ली थी, लेकिन शादी की रात ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी।

कश्मीर के वरिष्ठ साहित्यकार हसरत गड्डा के मुताबिक रानी बहुत ही चालाक, महत्वाकांक्षी और राजनीतिक रूप से परिपक्व महिला थीं। वह जंग के मैदान से लेकर राजमहल की साजिशों को रचने व उन्हें नाकाम बनाने के खेल में माहिर थीं।

नहीं की जा सकती तुलना: इतिहासकार और जम्मू-कश्मीर मामलों के विशेषज्ञ प्रो. हरि ओम इस तुलना से खफा हैं। उन्होंने कहा कि आप महबूबा मुफ्ती की तुलना कोटा रानी से नहीं कर सकते। रानी ने जो भी कदम उठाया, कश्मीर के शासन को दुश्मनों के हाथ में जाने से रोकने के लिए ही उठाया। अगर सिर्फ सत्ता ही उनका मकसद होती तो वह आत्महत्या करने के बजाय शाहमीर की रानी बन जातीं, जबकि महबूबा की सियासत सिर्फ कुर्सी के लिए है। अगर उन्हें जम्मू-कश्मीर के हितों से सरोकार होता तो वह कभी भी जिहादी तत्वों का साथ नहीं देतीं। कोटा रानी पर टिप्पणी से पूर्व हमें उस समय के हालात को देखना-समझना होगा।

महबूबा मुफ्ती फाइल

क्या लिखा है डोजियर में

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को राज्य प्रशासन के डोजियर में षड्यंत्रकारी व्यक्तित्व का मालिक बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आम लोग महबूबा मुफ्ती के व्यक्तित्व, कपटता और खतरनाक इरादों का जिक्र करते हुए उन्हें 'डैडिज गर्ल' (पिता की लाडली बेटी) और कोटा रानी कहते हैं। डोजियर में महबूबा द्वारा प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी के समर्थन और अनुच्छेद 370 पर दिए गए राष्ट्रविरोधी और सांप्रदायिक भाषणों का भी जिक्र है।

ब्रिटेन के हाई कोर्ट में विजय माल्या के प्रत्यर्पण के फैसले को दी गई चुनौती

लंदन, प्रेट्र: भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट यानी रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने भारत प्रत्यर्पण के वर्ष 2018 के फैसले को चुनौती दी है। 9000 करोड़ रुपये के घोटाले और मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित माल्या के वकीलों ने दावा किया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में कई गलतियां हैं। बचाव पक्ष की वकील क्लेयर मांटगोमरी ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत ने कुछेक सुबूतों पर ही गौर किया है।

किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व बॉस 64 वर्षीय माल्या अप्रैल, 2017 से प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से जमानत पर जेल से बाहर हैं। मंगलवार को रिपोर्टरों के हुजूम से बचने के लिए माल्या अपने वकीलों के साथ कोर्ट में अलग से गए।

विजय माल्या लंदन की रायल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुनवाई के दौरान। एएफपी

जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लैंग की खंडपीठ को माल्या की बैरिस्टर क्लेयर मांटगोमरी ने जिरह के दौरान बताया कि जब अपनी किंगफिशर एयरलाइंस के लिए माल्या ने बैंक से कर्ज लिया था तो उनका धांधली का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह कोई गैरजिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं। बेहद रईस माल्या को चिटफंड स्कीम नहीं चला रहे थे और वह प्रतिष्ठित एयरलाइंस के मालिक थे, जो आर्थिक संकट में फंस गए। माल्या की वकील मांटगोमरी ने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपने मुवक्किल के भारत प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए कहा कि वेस्टमिंस्टर कोर्ट की चीफ मजिस्ट्रेट जज एमा अबोनॉट के वर्ष 2018 में दिए माल्या के भारत प्रत्यर्पण के आदेश में कई खामियां हैं। उनके खिलाफ इस मामले में कुछ ही सुबूतों पर निचली अदालत ने गौर किया था। क्लेयर ने अदालत को बताया कि निचली अदालत की जज ने बिना सभी सुबूतों पर गौर किए ही यह निष्कर्ष निकाल लिया था कि किंगफिशर और उसके प्रतिनिधियों में हिसाब-किताब में गड़बड़ की है। निचली अदालत की जज ने अपने फैसले में कहा था कि प्रत्यर्पण अधिनियम 2003 की धारा 137 (3) के तहत माल्या का भारत प्रत्यर्पण उचित है।

2019 में पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर सीमा पर 3,479 बार किया संघर्ष विराम उल्लंघन। संघर्ष विराम उल्लंघन और सीमा पार से गोलीबारी में सेना के 13 जवान और सीमा सुरक्षा बल के दो जवान शहीद हुए।

यहां हर दिन लगती है बच्चों की मंडी, उम्र के हिसाब से बोली

गिरवी जीवन..

आजादी के 72 साल बाद भी राजस्थान के आदिवासियों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। खबरें आती रही हैं कि यहां कुछ परिवार बच्चों को बेच देते हैं या गिरवी रख देते हैं। लेकिन हालात इससे भी कहीं अधिक बदतर हैं। गुजरात से सटे प्रदेश के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे आदिवासियों के जीवन स्तर को देख रूह कांप उठती है। मजबूरी में ही वे अपने बच्चों को अन्य राज्यों में मजदूरी, यहां तक कि भेड़ चराने जैसे कामों के लिए बेच या गिरवी रख देते हैं। अनेक इलाकों में हर दिन बच्चों की मंडी लग रही है, जहां उम्र के हिसाब से सौदा तय होता है। उदयपुर से जागरण संवाददाता **नरेंद्र शर्मा** की पड़ताल।

साधरा गांव में दो पत्नियों और दो बेटों के साथ रामू। उसने अपने दोनों बच्चों को गिरवी रखा था, जिन्हें दो दिन पहले पुलिस ने गड़रिये से छुड़ाया है (बाएं)। बच्चों को परिजनों के सुपुर्द करते पुलिसकर्मी। जागरण

शुक्रवार सुबह 8 बजे जब जागरण की टीम कोटड़ा पहुंची तो सड़क के किनारे एक कच्चे छप्पर के नीचे चार-पांच लोग बैठे नजर आए। संवाददाता ने खुद को सूरत का साड़ी कारोबारी बताते हुए बच्चों को कारखाने में काम के लिए ले जाने की बात कही तो दलाल ने तत्काल जवाब दिया- बातें बाद में करेंगे, पहले मोबाइल बंद कर के अपनी गाड़ी में रखो...। जैकिट की तलाशी लेने के दलाल सोहनलाल ने साफ कहा कि 10 से 16 साल तक की उम्र के बच्चे वो 150 रुपये प्रतिदिन में गिरवी रखवा देगा, लेकिन इसमें से 25 रुपये प्रति बच्चा कमीशन देना होगा...। मोलभाव के बाद आखिरकार सौदा 130 रुपये प्रति बच्चे पर तय हुआ और इसमें से दलाल 22 रुपये प्रति बच्चा लेने को तैयार हो गया। दलाल ने तीन दिन बाद उसी स्थान पर मिलने और 8 बच्चे साथ ले जाने की बात कही। बाकायदा एक पर्ची में बच्चों के नाम लिखकर दिए। इनमें चुडई गांव की लाली, सुगना, रामेहत एवं टेंगरवाडा गांव के छोटू, भोला, कुसमी, रघु और रमडी शामिल हैं।

राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में ऐसी अनेक आदिवासी बस्तियां हैं। भरण-पोषण का एकमात्र जरिया मजदूरी ही है। परिवार को भूख से बचाने के लिए मुखिया खुद को या फिर अपने बच्चों को मात्र 50 से 100 रुपये प्रतिदिन पर गिरवी रख देता है। आदिवासियों को गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों, व्यापारियों अथवा गड़रियों के यहां गिरवी रखवाने के लिए बाकायदा दलाल का पूरा नेटवर्क यहां पैठ जमाए हुए है। पुलिस-प्रशासन की नाक के नीचे यह धंधा फलफूल रहा है। हालात तब और भी भयावह होते दिखते हैं, जब गिरवी रखे गए बच्चे या तो वापस नहीं लौटते या फिर अपंग होकर लौटते हैं। ये दलाल वयस्क के बजाय 10 से 15 साल तक के बच्चों को प्राथमिकता से गिरवी रखते हैं। बच्चों को गिरवी रखने के बदले परिवार के मुखिया को 50 से 100 रुपये रोजाना के हिसाब से पैसा दिया जाता है। इसमें से भी 20 से 25 रुपये दलाल लेते हैं। बच्चे को दोनों समय भोजन का आश्वासन दलाल देते जरूर हैं, लेकिन उन्हे भरपेट खाना नहीं मिल पाता। आदिवासी क्षेत्रों में इन दलालों को मैट कहते हैं। पूरे बाजार पर इनकी पकड़ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इनकी मर्जी के बिना बच्चों को गिरवी नहीं रखा जा सकता है।

गुजरात से सटे कोटड़ा, फलासिया, झाडोल, गोगुंदा और आमलिया में प्रतिदिन बच्चों की बोली लगती है। यहां बाकायदा बच्चों की चौखटी (मंडी) लगती है। पुलिस के पास अपना बहाना है कि पहाड़ियों के बीच इन इलाकों में पुलिस का पहुंचना मुश्किल है और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक दलाल फरार हो जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से उदयपुर रेंज की पुलिस महानिरीक्षक बिनिता ठाकुर और उदयपुर की जिलाधिकारी आनंदी के प्रयासों से बच्चों का सार्वजनिक रूप से सौदा होने पर लगाम तो लगती दिखती है, लेकिन पूरी तरह नहीं। चोरी-छिपे यह आज भी जारी है।

आदिवासी इलाकों में बच्चों की तस्करी रोकने के लिए नियमित रूप से पुलिस एवं सामाजिक संगठनों के साथ अभियान चलाया जा रहा है। आदिवासियों को जागरूक किया जाता है। पिछले छह माह में करीब सौ बच्चों को दलालों से मुक्त कराया गया है।
–संगीता बेनीवाल, अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकारिता आयोग, राजस्थान

पुलिस इसे रोकने को लेकर कटिबद्ध है। हम वह हर प्रयास कर रहे हैं, जो आवश्यक है। आदिवासी बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। **–बिनीता ठाकुर, पुलिस महानिरीक्षक, उदयपुर रेंज, राजस्थान**

भाजपा विधायक सहित छह पर दुष्कर्म का आरोप

जासं, भदोही : उप्र के भदोही एसपी रामबदन सिंह के सामने सोमवार को पहुंची एक महिला ने भाजपा विधायक रवींद्रनाथ त्रिपाठी, जिला पंचायत सदस्य सचिन त्रिपाठी सहित उनके बेटे दीपक तिवारी, प्रकाश तिवारी, भतीजे संदीप त्रिपाठी व चंद्रभूषण तिवारी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। आरोप लगाया कि 2014 से ही संदीप ने उससे शादी का झांसा देकर लगातार जबरदस्ती की और गर्भपात भी कराया। भदोही विधानसभा चुनाव के समय एक होटल में विधायक सहित सभी ने दुष्कर्म किया। जब उसने शादी करने को कहा तो जान से मारने की धमकी दी गई। एसपी रामबदन सिंह ने बताया कि मामले की जांच एएसपी रवींद्र वर्मा को सौंपी गई है।

वहीं, रवींद्रनाथ ने कहा है कि अवैध खनन की शिकायत की थी। इसी कारण ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र साजिश के तहत एक महिला से फर्जी शिकायत कराकर मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस महिला से शिकायत कराया है, उससे मेरा और मेरे परिवार से कोई लेना-देना नहीं है। वह किसी की भी हत्या कराकर मुझे और मेरे परिवार को फंसा सकते हैं। वहीं, विजय मिश्र का कहना है कि भदोही विधायक से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। उनका अलग क्षेत्र है और मेरा अलग। रही बात अवैध खनन की तो सीसीटीवी कैमरे की नजर में खनन कराया जा रहा है।

न्यूज गैलरी

मॉस्को में भारतीय वायुसेना के चार पायलटों का प्रशिक्षण शुरू

बेंगलुरु : रूस की राजधानी मॉस्को स्थित गैगरीन रीसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर (जीसीटीसी) में इसरो के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए भारतीय वायुसेना के चार पायलटों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। 2022 में पृथ्वी की कक्षा में यह अंतरिक्ष यान चक्कर लगाएगा। इसी मिशन के लिए भारतीय पायलटों को अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि एक साल चलने वाले इस प्रशिक्षण में बायोमेडिकल, शारीरिक अभ्यास, मानव मिशन ले जा चुके रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज का अध्ययन और विशेष यान इल्यूशिन-76 एडीके में भारहीनता मोड का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकारी संस्था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के एक अधिकारी ने बताया कि जिन चार पायलटों का चयन किया गया है, अभी उनका पद और नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। रूसी लांच सर्विस प्रोवाइडर ग्लावकॉसमास के अनुसार कुल 12 महीने सुनियोजित तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। (आइएएनएस)

सेवानिवृत्त कर्नल पर दफ्तर में शारीरिक संबंध बनाने का आरोप

नई दिल्ली : भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल के खिलाफ दफ्तर में शारीरिक संबंध बनाने के आरोपों की कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी शुरू की गई है। दो सैनिकों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा है कि अपने कार्यकाल के दौरान कर्नल ने कथित रूप से एक सिविलियन महिला कर्मचारी के साथ अपने कार्यालय के अंदर शारीरिक संबंध बनाया। सैनिकों ने शिकायत में कहा कि अधिकारी द्वारा यातना दिए जाने के चलते उन्होंने घटना की वीडियो क्लिप बना ली। सूत्रों का कहना है कि घटना उस वक्त की है जब कर्नल पंजाब के अबोहर में तैनात थे। सैनिकों ने रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि कर्नल की करतूतों को बेनकाब करने के लिए उनका उत्पीड़न किया जाता था। (आइएएनएस)

कुर्की नोटिस के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए आजम

रामपुर : धोखाधड़ी के मुकदमे में कुर्की नोटिस और मुनादी होने के बाद भी सांसद आजम खां मंगलवार को कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। अदालत (एमएलए एमपी स्पेशल कोर्ट) अब 20 फरवरी को सुनवाई करेगी। धोखाधड़ी का यह मुकदमा सांसद के बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित है। (जासं)

ब्रजेश ठाकुर को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा

फैसला ▶ मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 19 दोषियों को सजा

रवि रोशन, विकास वर्मा, गुड्डू पटेल को भी मरते दम तक उम्र कैद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिकागृह यौन उत्पीड़न में दोषी करार ब्रजेश ठाकुर मरते दम तक जेल में ही रहेगा। मंगलवार को दिल्ली की विशेष अदालत ने ब्रजेश समेत 19 दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को सामूहिक दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 20 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में ही रवि रोशन, विकास वर्मा, गुड्डू पटेल को भी उम्र कैद (अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है। रवि रोशन पर डेढ़ लाख और विकास पर 14 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दुष्कर्म के सात अन्य दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 जनवरी को सभी अभियुक्तों को पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया था। अदालत ने एक आरोपित विक्की कुमार को दोषमुक्त कर दिया था। कोर्ट ने मंगलवार को सभी अभियुक्तों को सजा सुना दी।

ब्रजेश ठाकुर की फाइल फोटो। जागरण

उम्र कैद : ब्रजेश ठाकुर, रवि रोशन, विकास वर्मा, गुड्डू पटेल, किरण कुमारी, मधु कुमारी, रामानुज ठाकुर, मीनू देवी, विजय तिवारी, कृष्णा कुमार।

दस साल की कैद : नेहा कुमारी, हेमा मसीह, अश्वनी कुमार, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी और रामाशंकर।

अन्य : इंदू कुमारी (3 साल) और रोजी रानी (छह माह) की सजा।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सुनवाई : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 फरवरी-2019 से ही इस मामले की साकेत कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने छह माह में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था। जुलाई- 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी सहायता प्राप्त बालिकागृह में कई बच्चियों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। सीबीआइ को मामले की जांच सौंपी गई थी। 23 फरवरी से साकेत अदालत में सुनवाई चल रही थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट के बाद यह मामला प्रकाश में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की थी। राज्य सरकार की सिफारिश पर मामले की जांच सीबीआइ से करवाई गई थी।

मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में कुछ दोषियों की पैरवी कर रहे वकील धीरज कुमार सिंह ने बताया कि वह फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे। उन्होंने बताया कि मामले में सीबीआइ जांच रिपोर्ट ने भी कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों को बालिकाओं की हत्या के मामले में उन्हें क्लीनचिट दी है।

रोंगटे खड़े करने वाले रहे लड़कियों का बयान

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर

मेरे साथ जबरदस्ती होती थी। ब्रजेश सर (ब्रजेश ठाकुर) नीचे ले जाते थे और नोंचते थे। बुरा काम करने की कोशिश करते थे। मारते थे। बालिका गृह में पूरी तरह हैवानियत थी। न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष सीआरपीसी की धारा-164 के तहत दर्ज बयान में बालिका गृह की पीड़िताओं ने यह बात कही थी। 22 लड़कियों के दर्ज बयान रोंगटे खड़े करने वाले हैं। अधिकतर लड़कियों ने आरोपित मीनू, चंदा व किरण को नशे की दवा खिलाने के लिए कुख्यात बताया। लड़कियों को रात में नशीली दवा खिलाई जाती थी। एक लड़की ने कहा कि दवा खाने के बाद होश नहीं रहता था। सुबह में कपड़े खुले होते थे। उसके साथ क्या हुआ, यह पता नहीं चलता था। बालिका गृह में ब्रजेश, तत्कालीन बाल संरक्षण अधिकारी रवि रोशन व बाल कल्याण समिति के सदस्य विकास कुमार की तिकड़ी की चलती थी। ये लड़कियों को हवस का शिकार बनाते थे। विरोध पर पिटाई की जाती थी। दहशत ऐसी कि मुंह खोलने से भी वे डरती थीं।

महिला कर्मी दिखाती थी क्रूरता : महिला कर्मी काफी क्रूरता दिखाती थी। बात-बात में लड़कियों की पिटाई की जाती थी। चंदा, मीनू व किरण इसमें आगे रहती थीं। झाड़ू-पोछा से लेकर रोटी बनाने तक का काम लिया जाता था। इन्कार पर खूब पिटाई की जाती थी।

अश्लील डांस नहीं करने पर खाने को दी जाती थी नमक-रोटी : लड़कियों ने कहा था कि तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन छोटे कपड़ों में अश्लील गाना गाने व उस पर डांस करने के लिए बाध्य करता था। ऐसा नहीं करने वाली लड़कियों को नमक-रोटी खाने को दी जाती थी।

ब्रजेश ही था मास्टमाइंड : बालिका गृह मामले का मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर था। समाज की नजरों में पत्रकार, अखबार का मालिक, नेता व एनजीओ संचालक, लेकिन अंदर से कुछ और ही। चालाक इतना कि एनजीओ से कोई रिश्ता नहीं और अखबार में नाम का पत्रकार। संवाददाताओं को मान्यता देने वाली कमेटी का सदस्य भी था। उससे भी तेज-तर्रार थी, उसकी खास राजदार शाइस्ता परवीन उर्फ मधु। दोनों ने ही बालिका गृहकांड के पूरे 'खेल' को रचा। पुलिस व सीबीआइ दोनों ने उसे ही एनजीओ का वास्तविक संचालक बताया।

किसी दहशत से कम नहीं था ब्रजेश : बालिका गृह में सभी ब्रजेश ठाकुर को हेड सर के नाम से संबोधित करते थे। लड़कियों के लिए यह नाम किसी दहशत से कम नहीं था। उसे तब बुलाया जाता था, जब किसी लड़की की पिटाई करनी होती थी। लड़कियों ने कहा कि नशीली दवा खिलाने के बाद ब्रजेश उसे हवस का शिकार बनाता था।

मधु के सहारे चलता था पाप का साम्राज्य : मधु पूरे प्रकरण में रहस्यमय रही। ब्रजेश ठाकुर के पाप का साम्राज्य उसके ही सहारे चलता था। वह बेहद शातिराना अंदाज में काम निपटाती थी। वह ब्रजेश की जितनी बड़ी राजदार थी, उतनी ही बड़ी प्लानर भी थी। बालिका गृह कांड में संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस व सीबीआइ उसे महीनों तलाश नहीं पाई थी। वह सीबीआइ के सामने भी तब आई, जब उसने इसकी प्लानिंग कर ली थी। कचहरी जैसे सार्वजनिक स्थान पर सीबीआइ अधिकारी को बुलाकर अपने को पेश करना इसी का हिस्सा था।

सीबीआइ रिश्वत मामले में अस्थाना को क्लीन चिट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ **दिल्ली की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल, सिर्फ दुबई का कारोबारी मनोज प्रसाद ही आरोपित**

सीबीआइ रिश्वत मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। हालांकि अदालत में बुधवार को सुनवाई होगी। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में सिर्फ दुबई के कारोबारी मनोज प्रसाद को ही आरोपित बनाया गया है। जबकि सीबीआइ के तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना, रॉ प्रमुख एसके गोयल और सीबीआइ के तत्कालीन डीएसपी देवेंद्र कुमार को क्लीन चिट दी गई है।

अक्टूबर 2018 में सीबीआइ ने अपने तत्कालीन विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत लेने का केस दर्ज किया था। अस्थाना पर मनी लांड्रिंग के एक मामले में मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से मामले का निपटारा करने के लिए घूस लेने का आरोप लगाया गया था। हैदराबाद के सतीश बाबू सना की शिकायत के बाद राकेश अस्थाना, देवेंद्र और दो अन्य बिचौलिए मनोज प्रसाद और सोमेश्वर प्रसाद के खिलाफ 15 अक्टूबर को एफआइआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2018 के बीच कम से कम पांच बार रिश्वत ली गई थी। यह विवाद इतना बढ़ गया था कि राकेश अस्थाना ने तत्कालीन सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा पर रिश्वत का आरोप लगाया था।

राकेश अस्थाना। फाइल

अब खराब चिकित्सा उपकरण पर तुरंत नपेंगी कंपनियां

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने मानव और जानवरों के काम आने वाले सभी तरह के चिकित्सा उपकरणों को औषधि घोषित कर दिया है। चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया यह फैसला एक अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा तीन के खंड (ब) के उप-खंड (चार) के तहत सभी तरह के चिकित्सा उपकरणों को मंगलवार को औषधि के रूप में अधिसूचित किया। इनमें प्रत्यारोपित किए जाने वाले सभी उपकरण, सीटी स्कैन, एमआरआइ उपकरण, डेफिब्रिलेटर, डायलिसिस मशीन, पीईटी उपकरण, एक्स-रे मशीन और अस्थि मज्जा सेल विभाजक (बोन मैरो सेल सेपरेटर) शामिल हैं। इसका मकसद चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करना है, जिससे कि वो गुणवत्ता के कुछ मानकों पर खरा उतरें। साथ ही खराब और असुरक्षित उपकरणों के लिए उनका उत्पादन करने वाली कंपनियों को जवाबदेह बनाना भी है।

असम में सरकारी वेबसाइट से एनआरसी का डाटा गायब

▶ **संयोजक ने कहा, विप्रो कंपनी ने अनुबंध खत्म होने पर हटाया डाटा**

▶ **कांग्रेस ने उठाए सवाल, जांच की मांग की**

गुवाहाटी, प्रेट्र : असम में सरकारी वेबसाइट से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची का डाटा गायब हो गया है। आइटी कंपनी विप्रो के साथ अनुबंध खत्म होने के चलते ऐसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा है और इसे 'दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई' करार दिया है। असम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देबब्रत सैकिया ने भारत के महानिबंधक को पत्र लिखकर मामले की जांच करने की मांग की है।

एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इस सूची से हटाए गए लोगों के नाम और भारतीय नागरिक के तौर पर शामिल किए गए लोगों के नाम आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। इसको लेकर लोग परेशान हो गए हैं, खासकर जिनके नाम इस सूची में नहीं है और उन्हें अभी तक कोई सर्टिफिकेट भी जारी नहीं किया गया है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है।

इस बारे में एनआरसी के राज्य संयोजक हितेश देव सरमा ने कहा कि किसी गलत नीयत से डाटा को नहीं हटाया गया है। इस डाटा के लिए विप्रो कंपनी की तरफ से क्लाउड स्पेश मुहैया कराया गया था और पिछले साल अक्टूबर में कंपनी का अनुबंध खत्म हो गया। पूर्व के संयोजक ने इसका नवीनीकरण नहीं किया, जिसके चलते 15 दिसंबर के बाद विप्रो ने वेबसाइट से डाटा हटा दिया।

उन्होंने बताया कि राज्य समिति समन्वय समिति ने 30 जनवरी की बैठक में इस संबंध में जरूरी औपचारिकाएं पूरी की थी, जिसके बाद फरवरी के पहले हफ्ते में विप्रो को पत्र लिखा गया था। उम्मीद है दो से तीन दिन में विप्रो डाटा डाल देगी, जिसके बाद वेबसाइट पर फिर वो उपलब्ध हो जाएंगे।

एडुकंप सॉल्यूशन पर 1955 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीआइ ने एडुकंप सॉल्यूशन, उसकी सहयोगी कंपनी और निदेशकों के खिलाफ एसबीआइ की अगुआई वाले 13 बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 1955 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने मंगलवार को आठ स्थानों की तलाशी ली।

सीबीआइ ने एडुकंप सॉल्यूशन लिमिटेड, उसके प्रबंध निदेशक शांतनु प्रकाश, गारंटर जगदीश प्रकाश, उसकी सहयोगी एडु स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और निदेशक विजय कुमार चौधरी एवं विनोद कुमार दनदोना के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। एफआइआर दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी ने दिल्ली, देहरादून और गुरुग्राम में आठ स्थानों पर तलाशी ली। कर्ज खाते को 2016 में एनपीए घोषित कर दिया गया था। सीबीआइ ने 13 बैंकों में से सात की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की है।

निर्णय

पार्टी की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से हुआ फैसला, विधायक दल और संगठन के विलय पर कार्यकारिणी ने लगाई मुहर

झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय को मंजूरी

राज्य ब्यूरो, रांची

लगभग डेढ़ माह की कवायद के बाद मंगलवार को झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय पर मुहर लग गई। झाविमो केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से संगठन के साथ-साथ विधायक दल के भाजपा में विलय को मंजूरी दिये जाने के बाद झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने इसका औपचारिक एलान किया। उन्होंने बताया कि कार्यकारिणी ने भाजपा में झाविमो के विलय का प्रस्ताव पारित किया है। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि 17 फरवरी को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत अन्य शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में वह भाजपा में शामिल होंगे। रैली जगन्नाथपुर मैदान (प्रभात तारा मैदान) में होगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा ने झाविमो के विलय की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि झाविमो के भाजपा में विलय से संगठन और मजबूत होगा।

बोले बाबूलाल, भाजपा में झाड़ू लगाने का भी काम मिला तो करूंगा

● **आप हमेशा कहते थे, कुतुबमीनार से कूद जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा।**

-हंसते हुए....किसी गैर के यहां नहीं जा रहा हूं। भाजपा से निकला था, भाजपा में ही लौट रहा हूं।

● **लेकिन भाजपा में ही क्यों? क्या अन्य दल से कोई ऑफर नहीं था?**

-ऑफर सभी तरफ से था। आप भी सब जानते-समझते हैं। चाहता तो सत्ता के साथ जा सकता था। हम वहीं से आए थे, वहीं गए। जब से हमने भाजपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, तब से कई दल संपर्क कर रहे थे। कई बार परिस्थिति ऐसी बन जाती है, जिसपर हमारा ज्यादा नियंत्रण नहीं रहता है।

● **कहा जा रहा है कि आप शर्त के साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। क्या डील हुई है?**

- क्या डील होगी भाई? मैं क्या व्यापारी हूं कि डील करुंगा। भाजपा में सर्वसम्मति से विलय का प्रस्ताव हमारी कार्यकारिणी के साथियों ने पारित किया है। भाजपा से हमारा पुराना जुड़ाव रहा है। बाकी ज्यादातर पार्टियां परिवार आधारित हैं। उसमें मैं जा नहीं सकता था। भाजपा की अपनी विचारधारा है, रीति-नीति है। भाजपा मुझे झाड़ू लगाने का भी काम देगी तो मैं करूंगा।

● **आप जिन परिस्थितियों में भाजपा से बाहर गए थे, क्या आज वैसी परिस्थिति नहीं है?**

-मैने कहा न, परिस्थिति नियंत्रण में नहीं होती। आज इसकी संभावना बनी है कि मैं भाजपा के साथ जा रहा हूं।

● **आपने प्रदीप यादव सरीखे विश्वासपात्र को भी दल से निकाल दिया? वह आरंभ से आपके साथ थे। क्या उन्हें किसी रणनीति के तहत दल से निकाला गया?**

ऐसी बात नहीं है। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में जाना चाहते थे। वे कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं। कार्यकारिणी ने दोनों के निष्कासन को मंजूरी दी है। वे भाजपा में नहीं आना चाहते थे तो यह उनकी मर्जी है।

रांची में मंगलवार को झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते बाबूलाल मरांडी। एएनआइ

मतभेद का गला न घोटें : सुप्रीम कोर्ट

▶ **सर्वोच्च अदालत ने कहा–लोकतंत्र में मतैक्य होना बेहद जरूरी**

▶ **एनजीओ में विदेशी फंडिंग को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई**

नई दिल्ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के गैर सरकारी संगठनों की विदेशी फंडिंग पर रोक संबंधी मामले में सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी की है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी को भी मतभेद का गला नहीं घोंटना चाहिए। बल्कि लोगों को सवाल पूछने के लिए बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र में मतैक्य होना भी एक बेहद अहम पहलू है।

जस्टिस एल.नागेश्वर राव और जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने मंगलवार को यह टिप्पणी एक एनजीओ इंसाफ (इंडिया सोशल एक्शन फोरम) की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। इस याचिका में फॉरेन कांट्रिब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (एफसीआरए), 2010 और अन्य नियमों की धारा 5 (1) और 5 (4) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। इसी कानून के तहत केंद्र सरकार ने गैर सरकारी संगठनों की विदेशी फंडिंग को रोक रखा है। इस कानून के जरिये केंद्र सरकार को किसी भी ऐसे संगठन की रोकथाम करेगी जो एक राजनीतिक दल न होते हुए भी राजनीतिक दल के तौर पर काम कर रहा हो। इस आधार पर ऐसे एनजीओ को विदेश से मिलने वाले फंड पर प्रतिबंध लगा हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट फाइल

लिहाजा खंडपीठ ने इसी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आप अलग राय रखने वालों का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं। याचिकाकर्ता के वकील संजय पारेख ने एफसीआरए में संविधान के अनुच्छेद 14,19 (1)(ए), 19 (1)(सी) और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। एनजीओ ने इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में याचिका को खारिज कर दिया था।

दैनिक जागरण

ईमानदारी से किए आत्मविश्लेषण से ही सफलता के द्वार खुलते हैं

देश के लिए दिल्ली का संदेश

दिल्ली का जनादेश

दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने लगातार दूसरी बार जैसी प्रचंड जीत हासिल की वैसा करिश्मा कम ही होता है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत यही बता रही है कि दिल्ली की जनता न केवल उसके कामकाज से खुश है, बल्कि उसे यह भी भरोसा है कि वह अपने वायदों को पूरा करके दिखाएगी। चुनाव नतीजे यह भी रेखांकित कर रहे हैं कि भले ही विरोधी दलों और खासकर भाजपा ने राष्ट्रीय मसलों को भुनाने की कोशिश की हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने स्थानीय मसलों पर ही ध्यान केंद्रित किया। यह भी साफ है कि दिल्ली के लोग इस नतीजे पर भी पहुंचे कि इन मसलों का अच्छी तरह से निस्तारण केजरीवाल सरकार ही कर सकती है। शायद इसी कारण जिस जनता ने चंद माह पहले दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें भाजपा को दीं उसने विधानसभा में उसका संख्याबल दहाई तक भी नहीं पहुंचने दिया। भाजपा इस पर संतोष कर सकती है कि उसका वोट प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन उसे इस पर गंभीरता के साथ गौर करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि राजधानी की जनता उसे देश का नेतृत्व संभालने के लिए तो सर्वथा उपयुक्त मानती है, लेकिन दिल्ली के लिए नहीं?

हैरत नहीं कि भाजपा की पराजय के कारणों में एक कारण यह भी हो कि वह अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश नहीं कर पाई। जो भी हो, उसे इसका आभास होना ही चाहिए कि आम तौर पर राज्यों के चुनावों में राष्ट्रीय महत्व के मसले एक सीमा तक ही कारगर होते हैं। यह हैरानी की बात है कि अपने चुनाव नतीजों से वह कांग्रेस भी संतुष्ट नजर आ रही है जिसका खाता भी नहीं खुला। उसे संतुष्टि इस बात की है कि भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा। इसमें संदेह नहीं कि उसके अनमने ढंग से चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को मदद मिली, लेकिन आखिर खुद उसे क्या हासिल हुआ? यदि अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने वाली कांग्रेस दिल्ली में लगातार दूसरी बार अपना खाता न खुलने के बाद भी संतुष्ट है तो यही कहा जा सकता है कि वह आत्मघात पर आमादा है। दिल्ली के नतीजे राजनीतिक दलों पर कुछ न कुछ मनोवैज्ञानिक असर अवश्य डालेंगे, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में कोई बुनियादी बदलाव आने के आसार नहीं और इसकी वजह यही है कि कांग्रेस खुद को कमजोर करने वाले काम कर रही है। निःसंदेह सभी दल अपने-अपने हिसाब से दिल्ली के नतीजों की व्याख्या करेंगे, लेकिन किसी को भी इस निष्कर्ष पर पहुंचने की भूल नहीं करनी चाहिए कि शाहीन बाग का धरना सही है।

बारूदी गंध और चुनाव

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आए दिन हो रहे विस्फोट और विस्फोटकों की बरामदगी पर चिंता जताते हुए यह सवाल उठाया है कि आखिर ऐसे माहौल में शांति पूर्वक चुनाव कैसे संभव है। यह सवाल बहुत ही मौजू और चुनौतीपूर्ण है। संवैधानिक प्रमुख के इस सवाल के पीछे छिपी चिंता पर गौर करना जरूरी है। इसी वर्ष प्रदेश में निकाय चुनाव और अगले वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है। जिस तरह हाल के दिनों में विस्फोट हुए और धरना-प्रदर्शन के दौरान गोलियों और बमों के हमलों से फिजा खराब की गई उससे बंगाल की शांति और उन्नति पर खतरे का साया मंडराने लगा है। आखिर यह क्यों हो रहा है। क्या सत्ता में बने रहने के लिए हिंसा का सहारा लेने की कोशिश हो रही है या फिर आम आदमी को भयाक्रांत करने की कोशिश। यहां तक कि राज्यपाल के मुखर होने की वजह से उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। चाहे जादवपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में उनका विरोध हो या कलकत्ता विश्वविद्यालय में। यद्यपि दोनों पक्षों ने माहौल को समरस बनाने की पहल जरूर की और बजट सत्र के अभिभाषण के दौरान धनखड़ ने सरकार के मन की ही बात बोली, लेकिन अक्सर उनके बयान कुछ लोगों को चुभने लगते हैं। राज्यपाल ने बारूद बरामदगी का सवाल उठाकर एक बड़ा मुद्दा उछाल दिया है। निर्वाचन आयोग ने हमेशा निष्पक्ष चुनाव के लिए शांति व्यवस्था पर जोर दिया है। टीएन शेषन के जमाने से ही चुनाव के दौरान अराजक तत्वों पर नकेल कसने की पहल शुरू हुई तो वह सिलसिला आज भी जारी है। तो फिर पश्चिम बंगाल में भी निकाय चुनाव से पहले बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए बलवा करने वालों और विस्फोटकों से जुड़े लोगों को चिह्नित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी कहते हैं कि राज्यपाल इस तरह के बयान चर्चा में बने रहने के लिए देते हैं। वह राज्यपाल को भी सवालों से घेरते हैं, लेकिन वीरभूम और बर्द्धमान जिले में बरामद हुए बम तो राज्यपाल की बात पर मुहर ही लगाते हैं। उत्तर 24 परगना में अवैध पटाखा बनाने वाली कंपनी में विस्फोट में पांच लोगों की जान चली गई। वहां से जब्त बारूद को गंगा किनारे नष्ट करने के दौरान इतना तेज धमाका हुआ कि दोनों तरफ के इमारतों में दरार आ गई। ऐसे में व्यवस्था बेहतर करना जरूरी है।

> राज्यपाल ने बंगाल में आए दिन होने वाले विस्फोट पर चिंता जाहिर की है। यह चिंता आने वाले चुनावों में शांति और निष्पक्षता को लेकर भी है

एनके सिंह

दिल्ली के नतीजे बता रहे कि जनता अगर चाहे तो सड़क, शिक्षा, अस्पताल और अन्य जन सुविधाएं चुनावी मसले बन सकते हैं

जरा सोचिए कि क्या तब कोई दल जनकल्याण के मुद्दों को खारिज कर चुनावों में संकुचित एवं गैर जरूरी मसलों के सहारे वोट बटोरने का साहस करेगा जब समाज को जाति, मजहब, क्षेत्र जैसे मसले प्रभावित न करते हों? दिल्ली विधानसभा के चुनाव नतीजे देश के करीब 90 करोड़ मतदाताओं को यही संदेश दे रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। वास्तव में आम आदमी पार्टी की ओर से जनकल्याण के मुद्दों पर कहीं अधिक ध्यान केंद्रित करने के कारण ही दिल्ली के मतदाताओं ने उसे फिर से सत्ता सौंपी है। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर प्रचंड जीत मिली। भाजपा को आठ सीटें मिलीं और कांग्रेस का पिछली बार की तरह से खाता भी नहीं खुला। इस तरह के नतीजे आने के क्या कारण रहे, इसकी तह तक जाने का काम सभी राजनीतिक दलों को करना चाहिए। केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की पूरी नजर दिल्ली पर थी और उसकी ओर से चुनाव जीतने के लिए हरसंभव प्रयास भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अनेक सभाएं कीं तो दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता और देश के गृहमंत्री अमित शाह ने एक तरह से दिल्ली में डेरा ही डाल लिया। कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी दिन-रात एक कर रखा था इस चुनाव को जीतने के लिए।

दिल्ली में ऐसे वक्त चुनाव हो रहे थे जब नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी व्याप्त थी और वह उसे खुलकर व्यक्त भी कर रहा था। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में इस कानून के खिलाफ धरना भी जारी था। यह अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस धरने को जनता को बांटने वाला आंदोलन करार देते हुए एक संयोग नहीं, प्रयोग बताया। कुल मिलाकर भाजपा की ओर से शाहीन बाग धरने को चुनावी मुद्दा बनाने की हरसंभव कोशिश की गई। इसमें उसके कुछ नेताओं ने आपत्तिजनक बयान भी दिए। केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया। इस पर एक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केजरीवाल तो खुद को अराजकतावादी कहते हैं और आतंकवादी एवं अराजकतावादी में ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर इस सबके बावजूद आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना तो क्या यह शाहीन बाग आंदोलन पर मतदाताओं की मुहर है? नहीं। यह संदेश है कि जो असल में हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और हमारे कल्याण के लिए बिजली और पानी मुफ्त देगा वही हमारी पसंद भी होगा। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन के दौरान उपजे राष्ट्रव्यापी जनांदोलन की पैदाइश है। आंदोलन के अस्थाई स्वरूप के कारण देश की जनता फिर वापस जाति, संप्रदाय और अन्य संकीर्ण भावनाओं में बहने लगी।

चूंकि दिल्ली में सरकार के पास बहुत ही सीमित शक्तियां हैं लिहाजा 2015 में 70 में से 67 सीटों के साथ सत्ता में आने के बावजूद आप सरकार को पग-पग पर बाधाएं मिलीं, लेकिन उसने अपने पहले बजट में एक तिहाई राशि शिक्षा के लिए और एक बड़ा अंश स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया। करीब 2.10 करोड़ की दिल्ली की कुल आबादी के लिए 2019 में आप सरकार का बजट 60 हजार करोड़ रुपये का हो गया। इसमें से 25 प्रतिशत यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए आवंटित किए और लगभग साढ़े सात हजार करोड़ रुपये यानी 12.5 प्रतिशत स्वास्थ्य के लिए।

इसका अर्थ हुआ कि यह सरकार दिल्ली के प्रत्येक परिवार पर स्वास्थ्य के मद में रोजाना 50 रुपये खर्च करने लगी। इस मद में केंद्र सरकार का 139 करोड़ आबादी के लिए खर्च 67,484 करोड़ रुपये है। यानी प्रत्येक परिवार पर प्रतिदिन साढ़े छह रुपये। अगर उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य को देखें तो 2019-20 में योगी सरकार ने 23,488 करोड़ रुपये यानी प्रति परिवार 12 रुपये का आवंटन किया। केंद्र का अंशदान मिला दें तो यह राशि लगभग 18.50 रुपये पहुंचती है। फिर इसमें 75 प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक खर्च में चला जाता है और शेष भाग का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। दिल्ली का क्षेत्रफल कम होने से जहां प्रशासनिक खर्च कम था वहीं भ्रष्टाचार भी नियंत्रित रहा। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता इतनी दुरुस्त कर दी कि निम्न-मध्यमवर्गीय लोग महंगे निजी स्कूलों के बजाय अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराने लगे।

'मुफ्त बिजली' मुख्यमंत्री का मास्टर स्ट्रोक रहा। दिल्ली के निम्न एवं मध्यम वर्ग जिसकी औसत आय 18,000 रुपये से कम है, उसके लिए अच्छी शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त बिजली-पानी अकल्पनीय राहत थी। मोहल्ला क्लिनिक से लेकर गरीब बच्चों के लिए सस्ती और सुलभ शिक्षा उपलब्ध होना दिल्ली की गरीब जनता के लिए दिवास्वप्न के साकार होने जैसा था। दिल्ली में अमीर-गरीब की खाई काफी चौड़ी है। यहां साक्षरता दर लगभग 90 प्रतिशत है और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का तीन गुना और बिहार के मुकाबले सात गुना है। इस चुनाव परिणाम का संदेश यह भी है कि जैसे-जैसे प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर बढ़ेगी, वैसे-वैसे जातिवाद और संप्रदायवाद का बोलबाला भी कम होगा और जनता राजनीतिक दलों को जनकल्याण पर अधिक ध्यान देने के लिए मजबूर करेगी।

2014 तक सपा और बसपा सरीखे दलों ने दिल्ली में अपनी पैठ बनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। इस चुनाव में वे कहीं भी नहीं हैं तो इसी कारण कि दिल्ली में जातिवादी राजनीति नाम मात्र की है। दिल्ली में जातिवादी राजनीति के बेअसर रहने का कारण यही है कि यहां की बड़ी आबादी बाहरी लोगों की है और वह इसकी परवाह कम ही करती है कि कौन किस जाति का है? दिल्ली के नतीजे राजनीतिक दलों के लिए एक सीख हैं। यह उल्लेखनीय है कि केजरीवाल सरकार ने मुफ्त सुविधाएं देने के बावजूद अपने राजस्व को बढ़ाया। यह इसीलिए संभव हुआ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने टैक्स का जो भी जरिया उपलब्ध था उसमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। इसी कारण उसका राजस्व बढ़ा। क्या अन्य राज्य सरकारें इसे अपनाकर अपने सीमित साधनों से राजस्व बढ़ाने और साथ ही जनता को मुफ्त बिजली-पानी देने का संकल्प ले सकती हैं? जनता अगर चाहे तो मुद्दा आरक्षण पर सस्ती सियासत न होकर सड़क, शिक्षा, अस्पताल और अन्य जन सुविधाएं हो सकती हैं। यह तभी होगा जब जनता संकीर्ण भावनाओं से परे उठकर अपनी सोच को जन कल्याण के मुद्दों की ओर ले जाएगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी के के मूल कारणों पर इसलिए गौर किया जाना चाहिए, क्योंकि वे राजनीतिक दलों के साथ ही देश की जनता को भी संदेश दे रहे हैं।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

तलाशनी होगी कट्टरता की काट

क्षमा शर्मा

आखिर शिक्षा अच्छा मनुष्य बनाने के मुकाबले नफरत करने वाले इंसान में क्यों तब्दील कर रही है?

कुछ साल पहले मैं केरल गई थी। इस दक्षिणी प्रदेश की वह मेरी पहली यात्रा थी। सौ फीसद साक्षरता ने वहां के लोगों में क्या बदलाव किया है, यह देखने की भी उत्सुकता थी। लिहाजा उत्साह होना स्वाभाविक था। उसे 'गॉड्स ओन कंट्री' यानी 'ईश्वर की अपनी भूमि' भी कहा जाता है, लेकिन वहां लोगों से बातचीत करके बहुत निराशा हुई। मेरे एक वामपंथी मित्र ने कहा कि दूर से चीजें बहुत आकर्षक लगती हैं, मगर यहां कट्टरपंथ लगातार बढ़ता जा रहा है। उनकी बातें सुनकर मेरे उत्साह पर पानी फिर गया। कुछ दिनों पहले एक खबर पढ़ी तो मुझे उस मित्र की बातें याद आ गईं। उसमें बताया गया था कि केरल में बहुत से मुस्लिम माता-पिता अपने बच्चों से परेशान हैं, क्योंकि वे बहुत कट्टर हो रहे हैं। वे उस कार में नहीं बैठना चाहते जो कर्ज लेकर ली गई हो। वे उस घर में भी नहीं रहना चाहते जो ऋण लेकर खरीदा गया हो। वे कहते हैं कि ये सब बातें इस्लाम के खिलाफ हैं। यह अकारण नहीं कि केरल में ही पीएफआइ जैसे कट्टरपंथी संगठन बहुत मजबूत हैं। इसी संगठन ने विगत में एक प्रोफेसर के हाथ काट दिए थे। समस्या यह है कि यदि ऐसे संगठनों पर रोक लगा भी दी जाए तो वे दूसरे नामों से अपना काम करने लगते हैं। इन पर रोक लगाने के मुकाबले सोचने की बात तो यह है कि आखिर कट्टरपंथी विचारधारा फैलती कैसे है?

शिक्षा अच्छा मनुष्य बनाने के मुकाबले नफरत करने वाले इंसान में क्यों तब्दील कर रही है? आखिर अपने अधिकार हम नफरत फैलाकर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर कश्मीर की आंद्रिया असाबी के माता-पिता उदार विचारों के थे। आंद्रिया ने इस्लाम पर एक ब्रिटिश लेखक द्वारा लिखी किताब पढ़ी। फिर वह अपने माता-पिता से झगड़ने लगी कि उन्होंने उसे सच्चे इस्लाम के बारे में कभी क्यों नहीं बताया? इसके बाद उसने 'दुख्तराने मिल्लत' बनाया और उसके जरिये अपने उग्र विचारों को जाहिर करती रही। आंद्रिया पुरुष के चार विवाहों की भी प्रबल समर्थक है। दुख की बात है कि ऐसे लोगों को अक्सर हमारे बुद्धिजीवी भटके हुए स्त्री-पुरुष कहकर अनदेखी करने की कोशिश करते हैं। वे कभी उनसे बहस नहीं करते। कभी उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। हम जानते हैं कि एक कट्टरवादी विचार दूसरे कट्टर विचार को बढ़ाता है। इस तरह वे एक-दूसरे के गहरे मित्र होते हैं। मीडिया ऐसे विचारों को लगातार दिखाता है। धर्म को लेकर जहां-जहां भी आतंकवाद पनप रहा है, यह देखकर हैरत होती है कि उसमें पढ़े-लिखे लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जिन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया वे सब खूब पढ़े लिखे थे। यही नहीं आतंक का शायद गरीबी, अमीरी से भी कोई लेनादेना नहीं है। अक्सर बुद्धिजीवी कहते हैं कि शिक्षा से आतंकवाद और उग्र विचारों को दूर किया जा सकता है, मगर लगता है कि ये सब गए जमाने की बातें हो गई हैं। इसके उलट देखने में तो यह आता है कि कई बार पढ़ाई-लिखाई हमें अधिक कुटिल बनाती है। हम अच्छी बातों की भी अपनी सुविधा के हिसाब से गलत व्याख्या करने लगते हैं। आखिर असम को शेष देश से काटने की वकालत करने वाला और गांधी को फासिस्ट बताने वाला शरजील इमाम भी बहुत पढ़ा-लिखा ही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपत्तिजनक नारे लगवाने वाले अनुराग ठाकुर भी खूब पढ़े-लिखे हैं। इन्हें देखकर यही लगता है कि शिक्षा से हम अच्छा मनुष्य बनाने के मुकाबले सिर्फ एकतरफा नजरिये से सोचने वाले बनते हैं।

कुछ दिनों पहले फेसबुक पर एक पोस्ट पर नजर पड़ी। उसमें एक ऐसे अध्यापक के बारे में बताया गया था, जो हिटलर के प्रताड़ना शिविर से बच निकला था। उसने बताया था कि हिटलर ने जिन लोगों को पकड़ा था, उन्हें बेहद पढ़े-लिखे और प्रशिक्षित डॉक्टरों ने ही जहर के इंजेक्शन दिए थे। नर्सों ने बच्चों को जान से मार दिया था। मनुष्यों को मारकर उनकी खाल, दांत, हड्डियों से तरह-तरह की चीजें बनाने के लिए पढ़े-लिखे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने तरह-तरह के उपकरण विकसित किए थे। इस अध्यापक ने निष्कर्ष के रूप में यही कहा था कि जरूरी नहीं कि शिक्षा हमें अच्छा इंसान बनाए, वह मानवीय मूल्यों में हमारी आस्था दृढ़ करे, बल्कि इन दिनों तो यह फैशन भी चल पड़ा है कि जो जितना कट्टरपंथी हो, वह अपनी भाषा में जनवाद, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता और बराबरी आदि की बातें दूसरे को भ्रम में डालने के लिए लगातार करता रहे। कहने को तो हम यह कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन शायद धर्म ही है जो एक को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने के लिए आपसी मनमुटाव और भेदभाव पैदा करता है। राजनीतिक दल इस भेदभाव का खूब फायदा उठाते हैं। कहना तो यह चाहिए कि अब राजनीतिक दलों में इस बात की चाहत नहीं बची कि लोगों को आगे बढ़ाने का यत्न करें। उन्हें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएं। उनकी तरक्की में सहयोगी बनें, बल्कि उनकी मंशा रहती है कि कैसे लोगों को असली मुद्दों से भटकाकर धार्मिक मसलों में उलझा दिया जाए। चूंकि शिक्षा हमें एक-दूसरे के धर्मों के बारे में शिक्षित नहीं करती, इसीलिए हर कोई अपनी तरह से धर्मों की व्याख्या करता है। इन दिनों जब हर आदमी एक वोट में बदल गया है, तब आदमी को अधिक से अधिक अपने खोल में बंद करके इस्तेमाल किया जा सकता है। शिक्षित होकर भी हम क्यों हजारो साल पीछे लौट जाना चाहते हैं। दिलचस्प यह है कि हजारों साल पुराने विचारों को आज की तकनीक से फैलाया जा रहा है। सुविधाएं और तकनीक आज की हों और विचार सैकड़ों साल पुराना हो तो आखिर दोनों का क्या मेल है।

अफसोस की बात यह है कि जो जितनी तल्ख बात कहता है, मीडिया उसी की बात को बार-बार दिखाता है। नफरत, नफरत को बढ़ाती है, इस बात पर क्यों कभी ध्यान नही दिया जाता। सच तो यह है कि इन दिनों धर्मनिरपेक्षता का नाटक बहुत है। सब अपने-अपने वोटों की खातिर धर्म निरपेक्षता का नाटक करते हैं।

(लेखिका साहित्यकार एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन और चिंता

मानव जीवन का गंभीरता से अध्ययन करें तो यह सत्य सहजता से मुखर होता है कि इस दुनिया में मानव का चिंताओं से रिश्ता धरती पर सभ्यता के विकास सरीखा ही प्राचीन और सनातन है। चिंताएं खुले आकाश की तरह अनंत और गहरे सागर की तरह अगाध होती हैं। इनकी अपनी प्रकृति और प्रभाव होते हैं। कुछ चिंताओं से जीवन की दिशा अवरुद्ध हो जाती है तो कुछ चिंताएं आश्चर्यजनक रूप से उत्प्रेरक का कार्य करती हैं।

चिंताएं जीवन के साथ चलती हैं और ये जीवन के साथ ही खत्म होती हैं। यही कारण है कि चिंतारहित जीवन की संभावना महज कल्पना है, किंतु चिंताओं पर चिंतन यहीं खत्म नहीं हो जाता है। प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिज्ञ विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था कि जब भी कभी मैं अपने जीवन की चिंताओं के बारे में पीछे लौटकर देखता हूं तो मुझे उस बूढ़े व्यक्ति की कहानी याद आ जाती है जिसने अपनी मृत्यु शैया पर कहा था कि वह ताउम्र बेशुमार चिंताओं और भय से परेशान रहा, लेकिन उनमें से अधिकांश चिंताएं कभी भी घटित नहीं हुईं। आशय यह है कि हम चिंताओं से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, लेकिन उनके बोझ तले खुद के जीवन को अव्यवस्थित होने से तो बचा ही सकते हैं। यदि आप यह सोचते हैं कि आपके चिंता करने से जीवन में गुजरे कल और आने वाले कल की घटनाएं बदल जाएंगी तो आप पृथ्वी से इतर किसी अन्य ग्रह पर फंतासी की दुनिया में रह रहे होते हैं।

पतझड़ में किसी पेड़ से टूटे पत्ते को गौर से देखिए। इन पत्तों का अपना कोई वजूद नहीं होता है। तेज हवाएं इन्हें अपनी दिशा में उड़ा ले जाती हैं। मानव जीवन भी अंततः इन टूटे पत्तों सरीखे ही होता है। जिसे वक्त और प्रारब्ध की तेज आंधी बहा ले जाती है। हम यहीं बेबस हो जाते हैं, यही मानव की हार है। फिर चिंताओं को खुद के जीवन को बहा ले जाने क्यों दें? खुद पर भरोसा रखते हुए जीवन को बेपरवाह क्यों न जिएं?

श्रीप्रकाश शर्मा

बढ़ती जा रही है कैंसर की चुनौती

देवेंद्रराज सुथार

> भारत में 2018 में कैंसर के लगभग 11.6 लाख मामले सामने आए और इसके कारण 7,84,800 लोगों की मौत हो गई

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में 10 भारतीयों में से एक को अपने जीवनकाल में कैंसर होने और 15 में से एक की इस बीमारी से मौत होने की आशंका जताई है। भारत में 2018 में कैंसर के लगभग 11.6 लाख मामले सामने आए और कैंसर के कारण 7,84,800 लोगों की मौत हो गई। दरअसल कैंसर का तात्पर्य शरीर में अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने वाली कोशिकाओं से हैं। यह अनावश्यक रूप से वृद्धि कर ऊतक को प्रभावित करती है तथा शरीर के बचे हुए भाग को इसके संपर्क में ले लेती है। कैंसर एक ऐसा रोग है जो किसी भी उम्र में हो सकता है। यह एक साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक में पाया जा सकता है। कैंसर के सौ से अधिक प्रकार हैं। आमतौर पर दोषपूर्ण एवं असंतुलित खान-पान, व्यायाम नहीं करने, नशीले पदार्थों के रूप में अल्कोहल की अधिक मात्रा का सेवन करने से इस रोग के शिकार होने की संभावना अधिक रहती है।

नेशनल हेल्थ प्रोफाइल-2019 की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीडी क्लिनिक्स ने 2017 से 2018 के बीच कैंसर के मामलों की पहचान की है। इस एक साल के अंतराल में देश में कैंसर के मामले 324 प्रतिशत यानी तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ गए हैं। राजस्थान में 2017 में सरकारी एनसीडी केंद्रों में पहुंचे करीब 30 लाख लोगों में से 1,358 लोगों को सामान्य कैंसर निकला। वहीं 2018 के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 3,414 हो गया। गुजरात में 2017 में 3,939 कैंसर पीड़ितों की पुष्टि हुई थी। 2018 में यह संख्या बढ़कर 72,169 हो गई। गुजरात के बाद सबसे खराब हाल कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हर दिन औसतन 1300 से अधिक लोग इस डरावनी बीमारी के शिकार हो रहे हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक कैंसर के मामलों में 25 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में कैंसर रोग से प्रभावितों की दर कम होने के बावजूद यहां 15 प्रतिशत लोग कैंसर के शिकार होकर अपनी जान गंवा देते हैं। निःसंदेह यदि किसी व्यक्ति को कैंसर से बचाव करना है या कोई देश अपने को कैंसर मुक्त राष्ट्र बनाने का सपना देखता है तो उसे अपने देश में धड़ल्ले से बिक रहे मादक पदार्थों एवं शराब की फैक्ट्रियों पर राजस्व की चिंता कई बगैर रोक लगाने के लिए कदम उठाने होंगे। यहां तक कि मोटापे को बढ़ाने का कारण बन रहे जंक फूड पर फैट टैक्स लागू कर इनके सेवन से आमजन को बचाने के लिए प्रयत्न करने होंगे। कैंसर को लेकर जो प्रमुख बात निकलकर सामने आ रही है वह है लोगों की इस रोग के प्रति अंगभीरता। जाहिर है कि हमें इस रोग से जुड़े मिथकों एवं विकृत मानसिकता को मिटाने के लिए जन-जागृति कार्यक्रमों में तेजी लानी होगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अव्यावहारिक सुझाव

डॉ. भरत झुनझुनवाला ने अपने लेख दोहरा सबक सिखाने वाली आपदा में वैश्विक स्वास्थ्य आपदा से देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए इसके विश्व अर्थव्यवस्था से सीमित जुड़ाव का सुझाव दिया है। यह विचार सुनने में चाहे जितना अच्छा लगे, लेकिन है अव्यावहारिक। वैश्वीकरण के इस दौर में बंद अर्थव्यवस्था की कल्पना भी बेमानी है। यह संभव है कि आप कौशल विकास और शोध-अनुसंधानों की बदौलत काफी हद तक विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर लें, लेकिन उन विनिर्मित समानों को बेचने के लिए भी तमाम देशों के बाजारों की जरूरत होगी। देश का फॉरेक्स रिजर्व अधिक-से-अधिक वैश्विक निर्यात और निवेश पर ही आश्रित होता है। हां, इतना जरूर है कि इस समय जो हम चीन से छोटे-मोटे खिलौने से लेकर कलपुर्जे तक आयात कर रहे हैं, वह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कोई स्वस्थ संकेतक नहीं है। हमें इन चीजों के अपने देश में उत्पादन के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेखक ने कोरोना वायरस के प्रसार के लिए पर्यावरण से छेड़छाड़ को जिम्मेदार माना है। यह सही है कि धारणीय विकास की अवधारणा में पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को महत्व दिया जाता है, लेकिन कोरोना या इसके पूर्व सार्स नामक वायरस के प्रसार का संबंध पर्यावरण के नुकसान से स्थापित नहीं किया जा सका है। इसके शुरुआती मामलों के तार दक्षिण चीन के सी फूड होलसेल मार्केट तक पहुंचे हैं और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि वहां बिकने वाले सांपों अथवा पक्षियों की किसी प्रजाति से यह वायरस मनुष्यों में पहुंचा है।

चंदन कर्ण, देवघर

मेलबाक्स

ग्रामीण भारत की कल्पना को मिले आकार

बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सार्स, अफ्रीका में जन्मा इबोला वायरस या फिर इन दिनों चीन में आतंक मचा रहा कोरोना वायरस। इन सभी वायरस में एक ही समानता है कि ये जानवरों से या फिर पक्षियों से उत्पन्न होकर मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर उनकी जिंदगी को लील लेते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह खतरनाक वायरस मानव शरीर में पहुंचते कैसे हैं? जाहिर है कि ये जानवरों या पक्षियों के संपर्क में आने से या फिर उनका मांस खाने से मानव शरीर में पहुंचते हैं। यदि हम वनस्पतियों को देखें तो दुनिया के आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाक सब्जियों अथवा फलों से कभी कोई इतना खतरनाक वायरस फैला हो, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया हो। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ज्यादातर लोग कंदमूल अथवा शाकाहार को तरजीह देते हैं। यदि हम चीन के वुहान शहर की तरफ देखें तो घनी आबादी वाला यह औद्योगिक शहर जिसमें फसलों या शाकाहार का वितरण कम होने के साथ ही मांसाहार प्रवृत्ति का दैनिक जीवन में शुमार होना ही खतरनाक कोरोना वायरस को जन्म देने का कारण रहा। चीन की तरह हम भी अब अपनी मिट्टी, हवा-पानी, जंगलों को खोते जा रहे हैं। आज समय की मांग है कि इन गांवों को गांधी की ग्रामीण भारत की कल्पना के अनुसार स्वावलंबी बनाकर बढ़ते शहरीकरण या औद्योगीकरण पर लगाम लगाई जाए ताकि दुनिया को मानवीय खतरों से बचाया जा सके।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

प्रशासन की लापरवाही का परिणाम

दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में जिस प्रकार से घटना घटी है उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में छात्रों के फेस्ट हो रहे हैं और इन कार्यक्रमों में एक दूसरे कॉलेज के छात्र भी शामिल होते हैं। अक्सर देखा गया है कि इस प्रकार से होने वाले कार्यक्रमों में किसी ना किसी कॉलेज में विवाद जरूर हो जाता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली विश्वविद्यालय के संबंधित कॉलेज प्रशासन की होती है, अगर प्रशासन द्वारा इस पर ठीक ढंग से कार्रवाई की गई होती तो ऐसी घटना दोबारा होती ही नहीं। लेकिन छात्राओं द्वारा कॉलेज के प्राचार्य से इसकी शिकायत करने पर उन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी उसे लापरवाही ही कहा जाएगा। अधिकतर कॉलेजों में चारदीवारी बहुत ही कम नजर आती है ऐसे में बाहरी लोग इस कार्यक्रम में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं और फिर बदसलूकी करते हैं। कुछ भी हो संबंधित कॉलेज को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

35 साल से कम उम्र के हैं देश में 72 फीसद स्टार्टअप कंपनियों के संस्थापक। यह एक शानदार उपलब्धि है।

आजकल

अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करे भाजपा

ऐसा लगता है कि स्थानीय मुद्दों के मद्देनजर भाजपा से लोगों का मोहभंग होने लगा है। ऐसे में यह जरूरी है कि भाजपा राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने से परहेज करे और लोगों की बुनियादी जरूरतों तथा स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की रणनीति पर विचार करे। बहरहाल यह देखने वाली बात होगी कि राज्यों के चुनाव में लगातार मिल रही हार के बाद भाजपा कितनी ईमानदारी से आत्मचिंतन करती है और आगामी विधानसभा चुनावों में उसकी रणनीति क्या होती है

रिजवान अंसारी
स्वतंत्र टिप्पणीकार

दिल्ली विधानसभा के चुनाव में एड़ी-चोटी का जोर लगाने के बाद भी भाजपा के लिए 21 वर्षों का सूखा खत्म नहीं हो सका। हालांकि 2015 के चुनाव के मुकाबले उसकी सीटों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़ों को नहीं छू सकी। ऐसे में जब एक के बाद एक राज्यवार चुनावों में भाजपा को हार मिल रही है तब यह जरूरी है कि वह अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करे। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक राजनीतिक दल को चुनाव जीतने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए थी, उतनी भाजपा ने की। गृह मंत्री अमित शाह खुद लोगों के दरवाजों पर दस्तक देते हुए दिखे और भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह सातवें आसमान पर भी दिखा, लेकिन चुनाव परिणाम ने बताया है कि भाजपा की रणनीतियां काम नहीं आ सकीं। झारखंड विधानसभा के चुनाव में भी यही देखने को मिला। भाजपा को अपनी रणनीतियों की खामियों को समझने के लिए छह साल पीछे जाने की जरूरत है।

दरअसल 2014 के आम चुनाव में जब पहली बार भाजपा बहुमत के साथ केंद्र में सत्ता में आई तब कई फैक्टर काम कर रहे थे। उसमें नरेंद्र मोदी की लहर सबसे अहम मानी जाती है। इसी लहर ने भाजपा को देश के कई राज्यों में सत्ता दिलाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने दिल्ली की सभी सातों सीटें जीत ली थीं। तब भाजपा को 46.40 फीसद वोट मिले थे। उसी समय आम आदमी पार्टी को 32.90 और कांग्रेस को 15.10 फीसद वोट आए, लेकिन अगले ही साल यानी 2015 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ तो बाजी एकदम से पलट गई। भाजपा के वोट फीसद में बड़ी गिरावट आई और यह 32.3 फीसद रह गई, लेकिन 'आप' के वोट फीसद में जबरदस्त उछाल आया और उसे 54.3 फीसद वोट मिले। 'आप' को लगभग 22 फीसद मतों का फायदा हुआ, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा को जबरदस्त बढ़त मिली और उसे 56.58 फीसद वोट मिले। नतीजतन वह फिर से दिल्ली की सातों सीटें जीत गई। वहीं 'आप' के वोट में जबरदस्त गिरावट आई और उसे महज 18 फीसद वोट ही मिले। अब जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है तो कहानी लगभग 2015 वाली फिर से दोहराई गई है। सवाल है कि भाजपा और 'आप' के वोट-ग्राफ में तेजी से बदलने वाली यह प्रवृत्ति क्या संकेत कर रही है?

दरअसल वोट फीसद का यह ग्राफ संकेत कर रहा है कि लोकसभा और विधानसभा के लिए लोगों की पसंद अलग-अलग है। कोई एक पार्टी दिल्ली की जनता के लिए दोनों ही चुनाव में फिट नहीं बैठती। इससे जो अहम बात निकल कर सामने आती है, वह यह कि जब चुनाव लोकसभा का हो तब लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का चुनाव करते हैं और जब मामला विधानसभा का हो, तब लोग स्थानीय मुद्दों पर वोट करते हैं, लेकिन भाजपा के चुनाव प्रचार के तौर-तरीकों से ऐसा मालूम पड़ता है कि वह मतदाताओं की नब्ज पकड़ने में नाकाम है।

> दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम से जो अहम बात निकल कर सामने आई है, वह यह कि लोकसभा चुनाव के दौरान लोग राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी को वोट देते हैं और जब मामला विधानसभा का हो, तब लोग स्थानीय मुद्दों पर मतदान करते हैं

भाजपा से जो चूक हुई है वह यह कि भाजपा दिल्ली के पूरे चुनाव प्रचार में स्थानीय मुद्दों पर ठीक से अपनी बात नहीं रख सकी। वह दिल्ली में भी उसी गलती की पुनरावृत्ति करती नजर आई जो कुछ दिन पहले झारखंड में करके सत्ता खो चुकी है। झारखंड में भाजपा की सरकार रहने के बावजूद भाजपा के नेता स्थानीय मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते नजर आए थे। उसी तरह दिल्ली चुनाव में भी भाजपा नेतृत्व अनुच्छेद-370, कश्मीर, पाकिस्तान, नागरिकता संशोधन कानून जैसे राष्ट्रीय मुद्दे गिनाता रहा। भाजपा ने यह समझने में गलती की कि दिल्ली की मौजूदा सरकार किस-किस काम को करने का दावा कर रही है और वह किन मुद्दों पर वोट मांग रही है। जाहिर है, भाजपा को भी उन्हीं मुद्दों पर केजरीवाल सरकार को घेरने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा यह कर न सकी। भाजपा को अपनी रणनीति तय करने के लिए झारखंड के इसी नतीजे को ध्यान में रखना काफी होता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उसे 55 फीसद वोट मिले, जबकि 6 माह बाद ही विधानसभा में भाजपा 33 फीसद पर आ गई। लिहाजा जनता ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर उसकी समस्याओं पर बात नहीं होगी तो वह किसी भी पार्टी को नकार सकती है।

वर्ष 2014 में केंद्र में सत्ता हासिल करने के बाद जब भाजपा कई राज्यों में पहली बार सत्ता में आई तब इसके पीछे कुछ वजहें काम कर रही थीं। उनमें एक वजह यह भी थी कि कई राज्यों में दशकों से एक ही पार्टी की सरकार थी। लोगों को लगा कि सत्ता में परिवर्तन होने से राज्यों को एक नई दिशा मिलेगी और राज्यों में सुधार होगा, लेकिन जब उन्हीं राज्यों में पांच साल बाद दोबारा चुनाव हुए तो एक-एक कर भाजपा के हाथ से सत्ता फिसलती चली गई। इससे पता चलता है कि स्थानीय मुद्दों के मद्देनजर भाजपा से लोगों का मोहभंग होने लगा है। ऐसे में यह जरूरी है कि भाजपा राज्यों के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को उठाने से परहेज करे और लोगों की बुनियादी जरूरतों और स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की रणनीति पर विचार करे। बहरहाल यह देखने वाली बात होगी कि राज्यों के चुनाव में लगातार मिल रही हार के बाद भाजपा कितनी ईमानदारी से आत्मचिंतन करती है और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उसकी रणनीति क्या होती है।

कांग्रेस की इतनी दुर्गति क्यों

रवि शंकर

दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से शून्य का स्वाद चखना पड़ा है। दिवंगत शीला दीक्षित के नेतृत्व में 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का लगातार दूसरी बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। इतना ही नहीं इस बार के चुनाव में पार्टी का वोट शेयर भी गिरकर आधा हो गया है। साल 2015 के मुकाबले कांग्रेस को इस बार 4.40 फीसद वोट मिला है, पिछले चुनाव में यह आंकड़ा 10 फीसद था। नतीजे साफ बता रहे हैं कि कांग्रेस उम्मीदवारों की स्थिति निर्दलीय उम्मीदवारों जैसी हो गई है। यह ठीक है कि दिल्ली के चुनावी दंगल में सीधी जंग बीजेपी और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई। कांग्रेस शुरू से न तो मुकाबले में दिखाई दी और न ही बेहतर स्थिति में थी। फिर भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस का पिछली बार की तरह इस बार भी खाता नहीं खुलेगा। अहम बात यह भी कि मई 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 70 में से 65 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि इस बार वह अपनी यह स्थिति भी बरकरार नहीं रख सकी। कांग्रेस के लिए निश्चित ही यह आत्ममंथन का समय है।

कांग्रेस को मिली करारी हार के लिए आला नेतृत्व पूरी तरह से जिम्मेदार है। गौर कीजिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सबसे ऊपर गांधी परिवार के तीन सदस्यों सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का नामा था। मगर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चुनाव में भागीदारी देखकर कहा जा सकता है कि उनके द्वारा प्रचार की खानापूर्ति भर की गई। जहां बीजेपी और आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी, वहीं कांग्रेस के दिग्गज आखिरी वक्त में प्रचार करने घर से बाहर आए। कांग्रेस की हार के पीछे एक बड़ी वजह यह भी रही। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में जमीन पर कांग्रेस का संगठन नहीं दिखा। कार्यकर्ताओं में मायूसी थी और इसका असर पार्टी के प्रचार अभियान पर साफ नजर आया। दिल्ली इकाई में कद्दावर चेहरों की कमी साफ नजर आई। चुनाव में दिल्ली यूनिट के अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन की मौजूदगी बेहद कमजोर नजर आई। दिल्ली इकाई में पार्टी के दूसरे दमदार नेता भी सुस्त नजर आए। महाबल मिश्र पर तो आप के टिकट पर लड़ रहे बेटे के लिए प्रचार का आरोप लगा।

साफ है, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन के बाद अब तक पार्टी को उनके कद के नेता का विकल्प नहीं मिल पाया है। दिल्ली में पार्टी के पास कपिल सिब्बल, सुभाष चोपड़ा और अजय माकन जैसे नेता हैं, मगर जनता के बीच किसी की अपील शीला दीक्षित जैसी नहीं है। पिछले कुछ विधानसभा चुनावों (हरियाणा और महाराष्ट्र) में कांग्रेस के आंतरिक मतभेद भी खुलकर सामने आए। दिल्ली में भी यह देखने को मिला। शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल नहीं होने को लेकर पार्टी के नेताओं पर ही आरोप लगा दिए।

दिल्ली में दलित और मुसलमान हमेशा से कांग्रेस का वोटबैंक रहे हैं, लेकिन राज्य में कांग्रेस का यह वोट बैंक भी दरक गया है और आप के पास चला गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट लेने के मामले में कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी और लगा कि पार्टी एक बार फिर कोर वोट बैंक के सहारे विधानसभा चुनाव में कुछ करिश्मा करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। 2020 की शुरुआत के साथ कांग्रेस दिल्ली में सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन उनका दावा तो इतना गलत साबित हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह यह भी रही कि जातिगत खांचों में वह अब फिट नहीं बैठ रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस की पराजय की वजह मुद्दों को लेकर सही रणनीति, खराब मैनेजमेंट और सही समय पर चेहरा न पेश कर पाना रही।

(स्वतंत्र टिप्पणीकार)

खरी-खरी

आजादी के मायने!

विजी श्रीवास्तव

चिराग से निकले जिन्न ने देखा कि उसे रगड़-रगड़ कर हुकुम बजवाने वाला तत्कालीन आका हार्ट अटैक से मर चुका है तो सबसे पहले उसने चिराग में एक जोरदार लात मारकर उसे गहरे गड्ढे में फेंक दिया। फिर जोशीली अंगड़ाई लेते हुए गुर्राया-ले के रहेंगे आजादी। उसने गौर से देखा, वो आजाद मार्केट में था। आजादी यहां-वहां पसरी पड़ी थी। सड़क पर पूरी आजादी से कब्जा जमाए लोग अपनी-अपनी तरह की दुकानदारी कर रहे थे।

जिन्न ने सोचा कि आजादी का जश्न मनाने से पहले परख तो लूं कि आजादी के मायने होते क्या हैं। इसलिए वह बड़ी तल्लीनता से मार्केट सर्वे में जुट गया। जिन्न ने देखा कि बहुत सारे लोग एक मैदान में जमा थे। वे रह-रहकर अंधेरे की ओर पत्थर फेंक रहे थे। कुछ लोग तो तीर भी चला रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि अंधेरे के पीछे क्या है। वे किसे और क्यों पत्थर मार रहे हैं। कुछ लोग उन पत्थर मारखांओं के कान में कुछ फूंक रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि वे 'ज्ञान' बांट रहे हैं। जिन्न से ज्यादा देर तक यह तमाशा देखा नहीं गया, उसने नोट किया-धुंधलके की आजादी।

आगे बढ़ा तो उसने लोगों को कुछ अजीब सा बनाते देख पूछा कि यह क्या चीज है। किसी ने बताया कि यह सरकार का पुतला है। इसे चौराहे पर जलाएंगे। उसने पूछा कि जलाना है तो बना ही क्यों रहे हो? मालूम हुआ कि वे लोग अक्सर नई-नई आजादियों के लिए चौराहे पर पुतला जलाते हैं। उनके पथ प्रदर्शक आकर बताते हैं कि आज कौन सी आजादी मांगनी है और कल कौन सी। जिन्न का आइक्यू लेवल तब तक थोड़ा बढ़ चुका था। उसने नोट किया-रोटी सेंकने की आजादी।

आजादी की इन अजीबोगरीब मांग से हैरान जिन्न सोच में था कि असली जरूरत छोड़ लोग आजादी के सिंदूर से मांग भरने के चक्कर में क्यों रहते हैं? इन्हीं विचारों में डूबा वो एक धरना स्थल पहुंच गया। यहां लोग सपरिवार गुलामी की पिकनिक मनाने के लिए जमा थे। एक बच्चा तो चीख कर आजादी मांग रहा था। जिन्न ने उसे हाथ में रखा बिस्कुट दिखाकर मुट्ठी बंद की और दूसरी खाली मुट्ठी बंद कर पूछा-बोलो तुम्हें आजादी चाहिए या बिस्कुट। बच्चे ने बिस्कुट वाली मुट्ठी पर हाथ रख दिया। जिन्न ने लिखा-नादानियों की आजादी।

ट्वीट-ट्वीट

दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही ईवीएम को लेकर अक्सर जताई जाने वाली आशंकाएं भी समाप्त हो जानी चाहिए।
शेखर गुप्ता@ShekharGupta

नेता भी कमाल करते हैं। आप जीते तो जनता को मुफ्तखोर बताते हैं और भाजपा की जीत पर उसे सांप्रदायिक करार देते हैं। कृपया जनता को थाली का बैंगन न समझें।
रोमाना इस्सार खान@romanaisarkhan

दिल्ली के चुनाव में हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं हुआ जबकि मुस्लिम जरूर एक पक्ष के साथ लामबंद हुए। ऐसे में यह कहना एकदम गलत है कि इस चुनाव में ध्रुवीकरण को मात मिली है। इस पर गुमराह न करें, बल्कि आंकड़ों पर गौर करें।
अभिनव प्रकाश@Abhina_Prakash

भाजपा का प्रदर्शन एक समय अपने चरम पर रही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम जैसा है कि वह असंभव से हालात में भी अच्छा प्रदर्शन करने का दमखम रखती है। भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा हार गई हो, लेकिन इसके बावजूद 40 प्रतिशत वोट शेयर भी उसकी बड़ी सफलता है।
ईशकरण सिंह भंडारी@ishkarnBHANDARI

भाजपा दिल्ली चुनाव हार गई। वैसे भी भाजपा दिल्ली में आप सरकार से पहले सत्ता में नहीं थी। उससे पहल कांग्रेस ने दिल्ली में पंद्रह साल तक राज किया। वह अपना खाता खोलना तो दूर, बल्कि 67 सीटों पर अपनी जमानत नहीं बचा पाई।
नंदिता ठाकुर@nanditathhakur

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या जीएसटी दरों में अब साल में सिर्फ एक बार ही बदलाव किया जाना चाहिए?

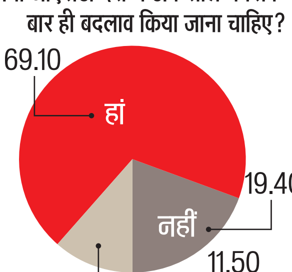

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या दिल्ली में मिली सफलता के बाद आम आदमी पार्टी के लिए अन्य राज्यों में संभावनाएं बढ़ेंगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

जनता ही सर्वज्ञ है सदा करे वह न्याय,
काम करे जो पार्टी ध्वज उसका फहराय।
ध्वज उसका फहराय 'आप' का ज्यों फहराया,
बाकी सब बकवास किसी का काम न आया।
यदि पब्लिक का काम रहेगा यूं ही बनता,
देगी खुलकर साथ 'आप' का हरदम जनता।
– ओमप्रकाश तिवारी

पंजाब डायरी

नाखून-मांस के रिश्ते का दर्द

अमित शर्मा
स्थानीय संपादक, पंजाब

पहले हरियाणा और फिर दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल (शिअद) एवं भाजपा में चुनावी गठबंधन टूटने के तुरंत बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या इसका सीधा असर आने वाले दिनों में पंजाब में पिछले दो दशकों से 'नाखून-मांस' के रिश्ते जैसे कहलाए जाने वाले अकाली-भाजपा गठबंधन पर पड़ेगा या नहीं? क्या भाजपा पंजाब में भी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिअद से नाता तोड़ अपने दम पर लड़ेगी? ऐसे तमाम कयासों के बीच बेशक हमेशा की तरह दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर इस बंधन को 'अटूट' बताते हुए दिल्ली में प्रेस वार्ता कर एक-दूसरे के प्रति पूरी तरह से कृतबद्ध होने का दावा किया है, पर इस बार प्रादेशिक स्तर पर विशेषकर भाजपा की स्थिति एवं रुख कुछ अलग है।

अकाली दल से नाता तोड़ अगले विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की ताकीद करने वाले प्रदेश के अनेक भाजपा नेता और कार्यकर्ता अब खुल कर इस बंधन से मुक्ति की बाते करने लगे हैं। बदले हुए रुख की अभिव्यक्ति की एक झलक पिछले महीने भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की ताजपोशी के दौरान देखने को मिली। मंच से ही भाजपा के चार पूर्व अध्यक्षों एवं पूर्व की तीन गठबंधन सरकारों में मंत्री पदों पर रह चुके कई वरिष्ठ नेताओं ने अकाली दल को 'खाली दल' की संज्ञा दे डाली और अपने-अपने बूते पर आगामी चुनाव लड़ने की सरेआम वकालत की। हालांकि समारोह के बाद दिल्ली में शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संयुक्त प्रेस वार्ता बुलाकर ऐसी तमाम संभावनाओं को सिरे से नकार दिया, लेकिन दिल्ली में शीर्ष नेताओं द्वारा दिखाई गई यह एकजुटता प्रदेश भाजपा नेताओं के पैमाने पर खरी नहीं उतरी।

वर्करों की आवाज और बदले नजरिये का हवाला देते हुए वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर मोहनलाल ने उन सवालों को एक बार फिर सुलगा दिया जिन्हें पिछले दो दशकों में भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार दबाता रहा है। उन्होंने सार्वजानिक तौर पर दो टूक कहा कि बेशक केंद्र में भाजपा अपना दबदबा बढ़ाने में लगातार कामयाब रही हो, कई अन्य राज्यों में पार्टी ने अपना ग्राफ ऊंचा किया हो, लेकिन हर बार अकाली दल की पिछलग्गू बन भाजपा पंजाब में कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगी। मुखर होती ऐसी भावनाओं के बीच गठबंधन राजनीति को लेकर आगे फैसला चाहे कुछ भी हो, पर इस घटनाक्रम ने इतना साफ कर दिया है कि राज्य में अकाली दल के साथ मिलकर तीन बार सरकार बनाने के बावजूद भाजपा इस स्थिति में कतई नहीं है कि अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ प्रदेश की राजनीति में अपना वर्चस्व साबित कर सके।

लेकिन ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब जहां राष्ट्रीय नेतृत्व भलीभांति जानता है वहीं पार्टी की राज्य इकाई भी इसके पीछे के कारणों से अनभिज्ञ नहीं है। इसी 'क्यों' के संदर्भ में थोड़ा बेबाकी से कहें तो गठबंधन राजनीति के इन 20 वर्षों में न तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने पंजाब भाजपा में किसी भी नेता को अकाली दल के सरपरस्त बादल परिवार के सदस्यों के समकक्ष उभरने दिया और न ही राज्य इकाई के कर्ताधर्ता इन नेताओं ने यदा कदा मिले ऐसे मौकों का पार्टी के विस्तार वास्ते उपयोग किया।

एक कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और शिअद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल।

2007 में दूसरी बार बनी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में राज्यपालों समेत कुछ अन्य गंभीर मसलों पर शिअद सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल से खूब मतभेद उभर कर सामने आए। यह जानते हुए कि उस दौर में अकाली दल सरकार बनाने में कामयाब ही भाजपा की 19 सीटों की बदौलत हुआ था, प्रदेश भाजपा ने पहली बार अकाली दल को खुली चुनौती दे पार्टी के राजनीतिक विस्तार की नींव रखी। प्रदेश भाजपा इकाई ने अकाली दल से समर्थन वापस लिए जाने या फिर अकाली सरकार को बाहर से समर्थन देने का प्रस्ताव पास किया, जिसे लेकर सीनियर नेता बलरामजी दास टंडन और स्टेट यूनिट के वरिष्ठतम सदस्य दिल्ली पहुंचे। लेकिन प्रदेश में भाजपा को अकाली दल के समकक्ष खड़ा करने का उद्देश्य लिए दिल्ली पहुंचे भाजपा के इस शीर्षमंडल को राष्ट्रीय नेतृत्व ने किस तरह बिना सुनवाई के सीधे वापस पंजाब लौटने के आदेश जारी कर दिए थे, यह किसी से भी छिपा नहीं है। नतीजतन प्रदेश के भाजपा नेता भी पार्टी के विस्तार के बजाय अकाली नेतृत्व की चापलूसी कर अपने राजनीतिक विस्तार पर ज्यादा ध्यान देने लगे। सूबे में अकाली और भाजपा के गठबंधन की राजनीति इस कदर बदरंग हो गई कि भाजपा के नेता ही मंत्री पद पाने या अन्य राजनीतिक लाभ लेने की होड़ में समय-समय पर बादल पिता-पुत्र के इशारों पर अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद करने से नहीं चूके।

खैर, गठबंधन को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का नजरिया या रुख कुछ भी हो, इस बात से कतई इन्कार नहीं किया जा सकता कि राज्य इकाई की भावनाओं को नजरअंदाज कर भाजपा प्रदेश में विस्तार सकती है। एक बार फिर पंजाब में राज्य के भाजपा नेताओं ने इस मसले को सुलगाया है तो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना होगा कि राज्य में भाजपा सदस्यों की संख्या रिकॉर्ड 21 लाख तक पहुंचने के बाद भी सूबे की राजनीतिक बिसात पर भाजपा का अस्तित्व आज भी अकाली दल की बैसाखियों पर क्यों निर्भर है?

मंथन

बुझने लगा स्टार्टअप का सितारा

मध्यवर्ग के युवाओं में नौकरी के बजाय अपना कारोबार शुरू करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन मुश्किल है कि इस नई पीढ़ी के पास कारोबार करने का ज्यादा अनुभव नहीं है

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था–एफआइएस ग्लोबल से संबद्ध

जिस देश में किसी दौर में सरकारी नौकरियों को ही सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था, उस देश में बीते 5-6 वर्षों में स्टार्टअप कंपनियों ने रोजगार के बेशुमार मौके देकर और कामयाबी की नई इबारतें लिखकर देश के विकास और बाजार, दोनों का रुख बदलकर रख दिया। इनकी सफलताओं की इतनी कहानियां देश ने सुनी हैं कि हाल तक ज्यादातर युवा जोखिम लेते हुए अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना रुतबे की बात मान रहे थे, लेकिन वर्ष 2014 से शुरू हुए इस ट्रेंड को मानो इधर ग्रहण लगने लगा है। बीते पांच साल में शुरू हुईं स्टार्टअप कंपनियों में से 90 फीसद या तो बंद हो गई हैं या बंदी की कगार पर हैं। हालत यह है कि बड़े पूंजीपति भी अब स्टार्टअप के नाम से कतराने लगे हैं और चेतावनी देने लगे हैं कि स्टार्टअप के नाम पर हर दूसरे कारोबार को जिंदा रखने के लिए पैसे जलाने का सिलसिला अंतहीन समय तक कायम नहीं रखा जा सकता है।

असल में इधर स्टार्टअप को लेकर चौकन्ना करने वाली कुछ खबरें नैसकॉम, जिनोव और टीमलीज के हालिया अध्ययनों से निकली हैं। इनके अध्ययन बताते हैं कि आइटी पेशेवरों का अब स्टार्टअप कंपनियों से मोहभंग होने लगा है और वे स्टार्टअप को छोड़कर बड़ी आइटी कंपनियों की नौकरी की तरफ वापस जा रहे हैं। अनुमान है कि वर्ष 2014-2019 के बीच देश में 8900-9300 स्टार्टअप कंपनियां बनीं, जिनमें आकर्षक वेतन और हिस्सेदारी मिलने की वजह से युवा पेशेवर इनसे जुड़ने को प्रेरित हुए थे, लेकिन आर्थिक सुस्ती के चलते इन स्टार्टअप कंपनियों को मिलने वाले कामकाज में गिरावट आई है, जिससे ऐसी कंपनियों के बंद होने का खतरा भी पैदा हो गया है।

हालिया चेतावनी की बात करें तो इसे लेकर एक तीखा बयान मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने दिया है। उन्होंने कहा है कि निवेशकों के पैसों को उड़ाने वाले स्टार्टअप को दूसरा या तीसरा मौका नहीं मिलेगा। उनका यह बयान पहले से उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि नई कंपनियां पुरानी कंपनियों की जगह लेंगी और नए लोग भारतीय उद्योग जगत के भविष्य को तय करेंगे। असल में स्टार्टअप को लेकर नजरिये में आ रहे बदलाव के कुछ खास कारण हैं। इनकी एक अहम वजह यह है कि स्टार्टअप कंपनियां जो उत्पाद बना रही थीं, उन उत्पादों की मांग में तेजी से तब्दीली आ रही है। स्टार्टअप छोड़ने वाले आइटी इंजीनियरों का तर्क है कि कई स्टार्टअप कंपनियां अपने उत्पादों को बाजार में उतारने में देरी करती हैं। उनके पास कोई पक्की योजना नहीं होती, जिससे उनके भविष्य के बारे में कोई मुकम्मल राय बनाई जा सके। चूंकि स्टार्टअप तेज तरक्की नहीं कर रहे हैं, इसलिए कर्मचारियों से लेकर निवेशकों तक में उन्हें लेकर मोहभंग की स्थितियां बनने लगी हैं। मुनाफा कमाने और ग्रोथ के मामले में चूंकि स्टार्टअप बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं, ऐसे में उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा होती है। इसलिए स्टार्टअप के धराशायी होने के मामले भी बढ़ गए हैं।

स्टार्टअप की नाकामियों के बारे में इन्फोसिस के पूर्व निदेशक टीवी मोहनदास पई कई साल पहले चेता चुके थे। उन्होंने दावा किया था कि नई पीढ़ी की केवल 10 फीसद कंपनियां (स्टार्टअप) आगे चलकर बेहतरीन ढंग से सफल होंगी, जबकि ज्यादातर स्टार्टअप कंपनियां विफल हो जाएंगी। स्टार्टअप कंपनियों के ढहने के कारणों की तह में जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर बड़ी कंपनियां तमाम खर्चों और घाटे के बावजूद लंबे समय तक अच्छे दौर के इंतजार में कैसे टिकी रहती हैं। असल में परंपरागत कारोबारियों ने बिजनेस के बुरे दौर को झेलने के लिए कई व्यवस्थाएं बना रखी हैं। उनका निवेश कई स्तरों पर होता है और वे कई उद्यमों से पैसा कमाते हुए घाटे में चल रही इकाइयों में तब तक पैसा लगाते हैं, जब तक कि वे अपने बल पर खड़ी न हो जाएं। इनके मुकाबले में नए कारोबारी अक्सर इस दौर में लड़खड़ाने लगते हैं। स्टार्टअप्स चाहते हैं कि उनके लिए पैसे जुटाने के नियम आसान हों, लेकिन खुद वे खर्च पर नियंत्रण रखने वाली व्यवस्था नहीं बनाते हैं। वे बड़ी कंपनियों की तरह बेशुमार मौके चाहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सतत घाटे की स्थिति में उनमें निवेश के रास्ते बंद हो सकते हैं।

वैसे यह सही है कि स्टार्टअप के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत का तीसरा स्थान है। कॉलेजों से निकले छात्र भी इस तरफ बड़ी संख्या में आ रहे हैं। दावा है कि पिछले वर्ष 350 नए उद्यम युवा विद्यार्थियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि स्टार्टअप कंपनियों की वजह से भारत में शिक्षा और रोजी-रोजगार को लेकर सोच बदली है। पहले व्यवसाय करने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, लेकिन सरकारी नौकरियों के कम होने और निजीकरण के बढ़ने के साथ माहौल बदला है। मध्यवर्ग समृद्ध हुआ है और इसके युवाओं में नौकरी के बजाय अपना कारोबार शुरू करने की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन मुश्किल है कि इस नई पीढ़ी के पास कारोबार करने का ज्यादा अनुभव नहीं है। उन्हें यह मंत्र सीखने की जरूरत है कि खर्च पर अंकुश रखकर और नवाचार के बल पर ही वे कोई सफलता हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हमारे जो स्टार्टअप यह समझदारी दिखाएंगे, उन्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा।

9000 किलोमीटर का आर्थिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव बजट में किया गया है। 150 रेल मार्ग पीपीपी मॉडल के तहत निजी कंपनियों के लिए खोले जाएंगे।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 12 फरवरी 2020

झारखंड

बेहतर होता माहौल सुधार रहा जीवन स्तर

भूमिगत आग से बदहाल जिंदगी, अवैध कोयला कारोबार, जानलेवा प्रदूषण जैसी तमाम दुश्वारियों के बीच यह एक अच्छी खबर है और उम्मीदें भी जताती है कि प्रयास हो तो परिणाम बेहतर होता जाएगा, माहौल बदल जाएगा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे के पब्लिक फीडबैक में देशभर में धनबाद 28वें पायदान पर है। यह आंकड़ा इसलिए सुखद है, क्योंकि वर्ष 2017 में देश की इस कोयला राजधानी की स्थिति अच्छी नहीं थी। तब धनबाद देश में 94वें स्थान पर था। झारखंड की बात करें तो धनबाद रांची से आगे है। राज्य की राजधानी रांची इस तालिका में 52 वें नंबर पर है। पब्लिक फीडबैक का अभियान 14 फरवरी तक चलेगा।

इस प्रदर्शन को देखकर कहा जा सकता है कि प्रयास हो रहे हैं। धनबाद की छवि सुधारने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। नगर निगम रैंकिंग सुधारने में लगा है। सकारात्मक परिणाम के पीछे बड़ा कारण ये है कि जिस सर्किल में सबसे कमजोर चल रहे हैं, वहां की स्थिति सुधारने पर अधिक जोर है। इसमें शहर के लोगों की राय का खास योगदान है, क्योंकि यहां उपलब्ध सेवा और सुविधाओं का आकलन उनकी टिप्पणी के आधार पर होगा। इसी से शहर की रैंकिंग भी तय होगी। सर्वे में झारखंड से सिर्फ धनबाद और रांची ही शामिल हैं। धनबाद के नगर आयुक्त के अनुसार ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे ज्यादा जोर प्रदूषण पर दिया गया है। प्रदूषण का क्या स्तर है और उससे निपटने के क्या-क्या उपाय किए गए हैं। वैसे भी झरिया और धनबाद जानलेवा प्रदूषण के मामले में देश में क्रमशः पहले और दूसरे नंबर पर हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए शहरी क्षेत्र में ग्रीन एरिया डेवलप करने पर विशेष रूप से फोकस हो रहा है।

> भूमिगत आग से बदहाल जिंदगी, अवैध कोयला कारोबार जैसी दुश्वारियों के बीच ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सर्वे में धनबाद ने बेहतर प्रदर्शन किया है

जलावन में कोयले का इस्तेमाल भी प्रदूषण का बड़ा कारण है। सर्वे का यह भी विषय है कि कितने लोग इसका उपयोग करते हैं और इससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए क्या-क्या करते हैं। इन तमाम चीजों के साथ सबसे अहम है जागरूकता। कैसे अपने शहर को स्वच्छ, स्वस्थ और निर्मल रखना है, यह शहरवासियों को ही तय करना है। सरकारी विभाग या एजेंसियां इस प्रयास में सकारात्मक भूमिका निभा सकती हैं और उनसे अपेक्षा भी यह की जाती है। यह मानी हुई बात है कि विकास एक सामूहिक और सतत प्रक्रिया है। सबके सहयोग से ही मुकाम तक पहुंचा जा सकता है।

एक देश-समाज के वास्तविक विकास का आकलन वहां के लोगों के स्वस्थ जीवनशैली से होती है। चिंता की बात यह है कि आधुनिकता की दौड़ में हम सबसे ज्यादा इसी से समझौता कर रहे हैं। हमें अपने न खान-पान की चिंता है और न रहन सहन की। और तो और इस क्रम में हमने अपने आसपास के वातावरण को भी तबाह करके रख दिया है। इन सबका दुष्परिणाम आज हमारे गिरते स्वास्थ्य के रूप में सामने आ रहा है। इस स्थिति को बदलने की दरकार है।

हिमाचल प्रदेश

स्कूली बैग में गड़बड़ी चिंताजनक

हिमाचल सरकार के शिक्षा विभाग की एक योजना सवालों के घेरे में है। वैसे तो सरकारें योजनाएं इसीलिए बनाती हैं ताकि लोगों को सुविधाएं मिलें, लेकिन अक्सर सुविधा के नाम पर असुविधाएं ही हिस्से में आती हैं। योजनाओं को धरातल पर उतारने एवं पात्र लोगों को लाभ पहुंचाने का जिम्मा अधिकारियों व कर्मचारियों पर होता है। यदि कार्यसंस्कृति बेहतर होगी तो योजनाएं सही तरीके से लागू होंगी, लापरवाही से पात्रों तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। इससे योजनाओं पर भी सवाल उठने लगते हैं। ताजा मामला स्कूली बच्चों को हिमाचल सरकार की तरफ से मिलने वाले बैग का है।

प्रतीकात्मक फोटो

> सरकारी स्कूलों के बच्चों को दिए गए बैग फटने का मामला संवेदनशील है। मामले की तह तक जाकर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए

शिक्षा विभाग के माध्यम से बच्चों को जो बैग उपलब्ध करवाए गए हैं, वे आवंटन के दूसरे दिन से ही फटने लगे हैं। इस संबंध में शिकायतें भी शिक्षा विभाग के पास पहुंची हैं। बच्चे नया बैग मिलने के बावजूद पुराने बैग में ही किताबें ले जाने को मजबूर हैं। इस बात को समझा जाना चाहिए कि सरकार की ओर से लोगों को दी जाने वाली किसी भी चीज की आपूर्ति से पूर्व कई तरह की औपचारिकताएं होती हैं। संबंधित वस्तु के सैंपल भी कई स्तर पर जांचे जाते हैं। मानकों पर खरा उतरने के बाद ही संबंधित कंपनी को उसकी आपूर्ति के निर्देश दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि बच्चों को दिए गए स्कूल बैग क्यों फटने लगे हैं? क्या इनकी गुणवत्ता जांची नहीं गई? क्या जो सैंपल दिए गए थे, वैसे ही बैग की आपूर्ति की जा रही है? इस तरह के कई सवाल हैं जिनकी जांच अवश्य की जानी चाहिए। यदि इनकी गुणवत्ता सही नहीं है तो कहीं न कहीं लापरवाही अवश्य है। सरकार की ओर से दी जानी स्कूली वर्दी भी बच्चों को काफी इंतजार करने के बाद मिली थी। शिक्षा विभाग को मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चत हो कि इसके जिम्मेदार पक्षों को चिन्हित किया जाए, बल्कि उन पर ऐसी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। काम में कोताही पर सरकार लापरवाह अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई करती तो है, लेकिन इस तरह के मामले फिर सामने आ जाते हैं। हालांकि यह जांच का विषय है कि आवंटन के 10 दिनों के भीतर ही फटने लगे हैं तो कुछ तो गड़बड़ी अवश्य है। इक्का-दुक्का मामलों से तो यह अपवाद माना भी जा सकता है, लेकिन यदि व्यापक स्तर पर शिकायतें मिली हैं तो कहीं न कहीं यह इसकी पुष्टि करता है कि गड़बड़ी बहुत बड़ी है। सरकार जो भी योजना बनाती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह सही तरीके से लागू हो। यदि योजनाएं धरातल पर खरी नहीं उतरती हैं तो सरकार का मकसद पूरा नहीं हो पाता है। उम्मीद है कि भविष्य में जो भी योजनाएं बनेंगी उनका पात्रों तक लाभ पहुंचेगा। कोई नीति कागज पर कितनी ही बेहतर क्यों न प्रतीत हो, जब तक धरातल पर उसकी सफलता के लिए प्रयास नहीं करते तब उसमें सफलता संदिग्ध ही प्रतीत होती है।

जम्मू-कश्मीर

रोजगार की दिशा में बड़ी पहल जरूरी

जम्मू कश्मीर में इस समय लाखों युवा रोजगार की आस लगाए बैठे हैं। व्यवस्था में बदलाव लाने की सरकार की मुहिम के चलते युवाओं को बेहतर भविष्य की बड़ी उम्मीदें हैं। यह अच्छा है कि उप राज्यपाल प्रशासन जम्मू कश्मीर में लंबित विकास की बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने की दिशा में गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है। बेरोजगारी दूर करने की दिशा में भी कोशिशें होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से पहले राज्यपाल शासन के दौरान पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के समय 50 हजार नौकरियां देने की घोषणा से जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के युवाओं में नई उम्मीदें बंधी थीं।

प्रतीकात्मक फोटो

इस समय राज्य में छह लाख से अधिक शिक्षित युवा बेरोजगार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य में रोजगार के अवसर काफी कम हैं। अब तक रोजगार देने की दिशा में कार्रवाई न होने से युवाओं में निराशा बढ़ रही है। उस पर सिविल सर्विस परीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के युवाओं को आयुसीमा में मिलने वाली पांच वर्ष की छूट भी समाप्त हो गई है। ऐसे हालात में बेहतर होगा कि केंद्र सरकार व उपराज्यपाल प्रशासन पढ़े लिखे लोगों को रोजगार का पैकेज दे, जिससे उनमें एक अच्छा संदेश जाए। ऐसे हालात में बेहतर होगा कि केंद्र सरकार सिविल सर्विस परीक्षा की छूट समाप्त करने के अपने फैसले पर फिर से विचार करें। इस फैसले से युवा निराश हैं व युवाओं के कुछ संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। युवाओं में रोजगार के मुद्दे पर बढ़ते आक्रोश पर कुछ विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी राजनीति तेज कर दी है। ऐसे हालात में सिविल सर्विस परीक्षा की छूट खत्म होने से उन्हें एक और मुद्दा मिल गया है। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी राजनीतिक पार्टियां पहले ही सक्रिय थीं। यह ठीक है कि जम्मू कश्मीर सरकार वैश्विक निवेशक सम्मेलन के आयोजन से बड़े पैमाने पर निवेश के विकल्प तलाश रही है। बड़े निवेश से रोजगार के साधन भी पैदा होंगे। इसके साथ जम्मू कश्मीर के लिए रोजगार पैकेज की घोषणा किया जाना भी समय की मांग है। इस समय जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं, प्रदेश के युवा भविष्य बेहतर बनाने के लिए अवसर मिलने के इंतजार में हैं। ऐसे में रोजगार देने की दिशा में भी कोई बड़ी पहल जरूरी है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में युवाओं का विश्वास बहाल किया जाना जरूरी है।

उत्तराखंड

निर्मल-स्वच्छ गंगा के लिए सराहनीय कदम

केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिशन क्लीन गंगा और प्लास्टिक-पॉलीथिन मुक्ति अभियान का सपना अब शायद उत्तराखंड में साकार हो जाए। हरिद्वार में प्रदेश के पहले कामन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिग प्लांट का शिलान्यास होने से इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों की गंभीरता का अहसास हो रहा है। इस प्लांट में न केवल गांवों से एकत्र कचरे का निस्तारण होगा, बल्कि उससे पीवीसी पाइप और प्लास्टिक के खिड़की-दरवाजे जैसे उत्पाद तैयार होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि प्लांट में छह माह में काम शुरू हो जाएगा।

कृषि और पंचायत राज मंत्री नरेंद्र तोमर ने एलान किया है कि उत्तराखंड के जिलों में भी ऐसे प्लांट लगाए जाएंगे। निश्चित ही ऐसे प्रयास से निर्मल गंगा का रास्ता तो प्रशस्त होगा ही, स्वच्छ भारत मुहिम को भी वास्तविक गति मिलेगी। बावजूद इसके मामला सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होता। यह पूरा अभियान तभी सफल माना जाएगा जब इसमें हर स्तर पर भागीदारी होगी। सबसे ज्यादा जरूरी है कि नदियों के तट पर बसे शहर में स्थानीय निकाय भी अपनी भूमिका से न्याय करें। अब तक के अनुभव बताते हैं कि चमोली हो या देवप्रयाग अथवा रुद्रप्रयाग, गंगा किनारे बसे शहरों में स्थानीय निकाय गंगा स्वच्छता को लेकर अपने दायित्व निभाने में नाकाम ही साबित हुए हैं। मसलन पॉलीथिन का मामला ही लें, पॉलीथिन पर प्रतिबंध तो लगा दिया गया, लेकिन इसे लागू करने में लगातार हीला-हवाली नजर आ रही है। यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को भी इस बारे में जागरूक करने के लिए कदम उठाए जाने थे, मगर इस दिशा में भी खास कुछ नहीं हो पाया।

> हरिद्वार में प्रदेश का पहला कामन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट उत्तराखंड में निर्मल गंगा और प्लास्टिक-पॉलीथिन मुक्ति अभियान की दिशा में एक कदम और है

एक-दो उदाहरण अवश्य ऐसे मिलते हैं। जैसे रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी खुद स्वच्छता कार्यक्रमों में शिरकत कर आम जन के लिए प्रेरक बने हुए हैं। इसके अलावा निर्माण कार्यों में जुटी एजेंसियों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि मलबा नदियों में न गिरने पाए। पूर्व में देखने में आया है कि ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान सड़क चौड़ीकरण का मलबा भागीरथी में डाल दिया गया। हालांकि इस मामले में शासन और सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन, सवाल यह है कि जिन महकमों पर गंगा को निर्मल रखने की जिम्मेदारी है, जब वे ही गंभीर नहीं हैं तो आम आदमी को वे कैसे जागरूक करने का दावा कर सकते हैं। सच तो यही है कि जब तक इस दिशा में ईमानदारी से पहल नहीं की जाएगी, तब तक सार्थक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बदलाव देखने को मिलेगा।

गंगा जैसी नदी का महत्व किसी से छिपा नहीं है। यह भारत के लोगों के लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक रूप से काफी अहम है। देश की चालीस फीसद आबादी अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर है। ऐसे में हमें इसके अस्तित्व को बचाए रखने के हरसंभव प्रयास करने चाहिए।

1857 में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से छीनी थी तोप

संजीव तोमर, मुजफ्फरनगर

- इतिहास के पन्नों में दर्ज है फिरंगियों के जुल्म की दास्तान
- 1857 में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर किया था हमला

उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर के पुरकाजी के हरिनगर गांव के भू-गर्भ से निकली तोप ब्रिटिशकालीन है। आगरा की प्रयोगशाला में तोप को लेकर कालखंड संबंधित तस्वीर साफ होने से कई सवाल खड़े हो गए हैं। आखिरकार तोप यहां कैसे आई? इसका सूली वाला बाग से क्या जुड़ाव है? इसे लेकर इतिहासकार मानते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान इन तोपों का इस्तेमाल हुआ। विद्रोह को कुचलने के लिए फिरंगियों ने आंदोलनकारियों को मौत के घाट उतारा था। उनका कहना है कि सूली वाला बाग में आंदोलनकारियों को फांसी दी गई। इसके पलटवार में आंदोलनकारियों ने अंग्रेजों पर हमला कर उनके हथियार छीन लिए थे, जिसमें तोप भी शामिल थी। यही वजह है कि भाकियू के लोग तोप को पुरकाजी के सूली वाला बाग में स्थापित करना चाहते हैं। वहीं प्रशासन इतिहास के पन्ने पलटने में लगा है।

मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में मिली तोप। जागरण आर्काइव

> प्रशासन ने तोप प्रकरण में मुझसे संपर्क किया था। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें मैं भी हूं। 1857 की क्रांति में मुजफ्फरनगर के लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। कई को फांसी भी हुई थी, लेकिन पुरकाजी क्षेत्र का नाम इतिहास के पन्ने में सामने नहीं आया है। इसकी शासन स्तर से वृहद जांच होनी चाहिए। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में इस विषय पर अध्ययन किया जाएगा, जिसमें समय लगेगा।
>
> **- डॉ. अशोक त्रिपाठी, अध्यक्ष इतिहास विभाग, एसडी डिग्री कॉलेज**

> करीब 200 साल पहले पुरकाजी क्षेत्र दलदल हुआ करता था। यहां अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को मार दिया था। इसके बाद लोगों ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया था, जिसके चलते वे हथियार छोड़कर भाग गए थे। पुरकाजी के जंगलों में मिली तोप उसी समय की है।
>
> **- डॉ. प्रदीप जैन, इतिहासकार**

यह है तोप की दास्तान : पुरकाजी स्थित हरिनगर में 20 जनवरी को एक किसान के खेत में प्राचीन तोप मिली थी, जिसका वजन करीब 40 क्विंटल था। भाकियू ने तोप को सूली वाला बाग में रख दिया था। प्रशासन ने तोप की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया था। दो दिन तक भाकियू ने सूली वाला बाग से तोप को नहीं उठने दिया था। उसका कहना था कि यह तोप यहां फिरंगियों से लड़ाई की निशानी है जिसे स्मृति चिन्ह के तौर पर यहीं रखा जाना चाहिए। भाकियू और प्रशासन के बीच रस्साकशी के बीच 22 जनवरी की आधी रात को प्रशासन ने तोप कड़ी सुरक्षा में आगरा प्रयोगशाला के लिए रवाना किया था। पुरातत्व विभाग की जांच में तोप ब्रिटिशकालीन बताई गई। भाकियू ने जांच के बाद तोप को सूली वाला बाग में स्थापित करने की मांग की है। हालांकि प्रशासन इस मामले पर मौन है। एडीएम प्रशासन अमित सिंह का कहना है मामले की जांच की जा रही है। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

भगवती देवी को तोप से उड़ा दिया था : अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी की अमिट गाथा है। देश की आजादी के लिए टोलियां बनाकर महिलाओं ने गांव-गांव में स्वाधीनता की अलख जगाई थी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी के आंदोलन तक मुजफ्फरनगर और शामली की वीरांगनाएं इतिहास के पन्नों में अपने त्याग, संघर्ष, देशभक्ति और बलिदान के लिए दर्ज हैं। शोभा देवी, आशादेवी गुर्जर, बख्तावरी देवी, भगवती त्यागी, भगवानी देवी, इंद्रकौर, जमीला पठान, रहीमो राजपूत, राजकौर, रणवीरी वाल्मीकि ने आंदोलन में हिस्सा लिया था। बताया जाता है कि भगवती देवी को ब्रिटिश सरकार ने तोप से उड़ा दिया था। थाना भवन की हबीबा खातून महिलाओं का जत्था लेकर गांव-गांव में घूमी थीं। बाद में उन्हें फांसी दी गई।

जमीन में दबा दी थी तोप : इतिहासकार यह भी मानते हैं कि 1857 की क्रांति के दौरान जब भारतीय वीरों ने अंग्रेजों पर हमला कर तोप समेत हथियार छीन लिए थे तो उन्हें जमीन में दाब दिया था। आंदोलनकारियों को यह अंदेशा था कि फिरंगी सेना गांव-दर गांव सर्च अभियान चलाएगी। इसके चलते छोटे हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, लेकिन भारी भरकम तोप को जंगल क्षेत्र में जमीन में दबा दिया गया।

मनमर्जी से क्लीनिक में दवाएं नहीं रख पाएंगे डॉक्टर

नईदुनिया, भोपाल

आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार वे अपनी अलमारी से दवा निकाल कर दे देते हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि अभी ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट में यह साफ नहीं है कि डॉक्टर कौन-सी और कितनी दवा अपने पास रख सकेंगे। बहरहाल अब इस पर सख्ती होने वाली है। इसके लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एवं कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (सीडीएससीओ) ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल 'के' में बदलाव की तैयारी कर रहा है। यह बदलाव होने के बाद डॉक्टरों को अति जरूरी दवाएं रखने की ही अनुमति मिलेगी।

नियम बनने और लागू होने के बाद डॉक्टरों को दवा दुकानों की तरह दवाओं का पूरा ब्योरा रखना होगा। उनके पास दवा कहां से आई और उन्होंने किसे दी, इसका भी हिसाब रखना होगा। इसके अलावा उपलब्ध स्टॉक की जानकारी भी रखनी होगी। सीडीएससीओ को जानकारी मिली थी कि कई डॉक्टर क्लीनिक में मेडिकल स्टोर्स की तर्ज पर बड़ी संख्या में दवाएं रखते हैं।

> ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल 'के' में बदलाव का प्रस्ताव है। इसके लिए समिति और उप समिति बनाई गई है। इनकी बैठकें हो रही हैं। इसके बाद नियम में बदलाव का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा।
>
> **-शोभित कोष्टा, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, मप्र**

मरीजों से फीस के साथ ही वे दवाओं के पैसे भी लेते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों में साफ है कि जहां से दवाएं दी जाती हैं वहां फार्मासिस्ट होना जरूरी है। लिहाजा फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा भी डॉक्टरों के दवाएं रखने और मरीजों को देने का विरोध किया जा रहा है। इस कारण सीडीएससीओ इसमें बदलाव करने जा रहा है। इसके लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआइ) ने समिति (कमेटी) बना दी है। इसके अधीन कुछ उप समितियां भी बनाई गई हैं। उप समितियों में मध्य प्रदेश के डिप्टी ड्रग कंट्रोलर शोभित कोष्टा को भी शामिल किया गया है। ड्रग एवं कास्मेटिक एक्ट में करीब 50 साल पहले शेड्यूल 'के' शामिल किया गया था। इसमें डॉक्टरों को दवाएं रखने की छूट दी गई थी।

तीर्थनगरी ऋषिकेश में गंगा ईको पर्यटन जोन में सुविधाओं का टोटा

दुर्गा नौटियाल, ऋषिकेश

ग्रीष्मकाल के दौरान तीर्थनगरी ऋषिकेश में सर्वाधिक पर्यटक राफ्टिंग के लिए आते हैं। खासकर सप्ताहांत पर तो गंगा के कौड़ियाला-मुनिकीरेती ईको टूरिज्म जोन में पर्यटकों की भरमार रहती है। बावजूद इसके पर्यटन सुविधाओं का यहां घोर अभाव है। स्थिति यह है कि वन विभाग और पर्यटन विभाग राफ्टिंग जोन में सही एप्रोच और चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं जुटा पा रहे।

- वन विभाग और पर्यटन विभाग नहीं दे रहा ध्यान, पर्यटकों को झेलनी पड़ती हैं दिक्कतें

तीर्थनगरी में गंगा का करीब 42 किमी लंबा कौड़ियाला-मुनिकीरेती ईको टूरिज्म जोन राफ्टिंग गतिविधियों के लिए विश्व मानचित्र में स्थान रखता है। वर्ष में करीब पांच माह तक चलने वाली राफ्टिंग गतिविधियों के लिए रोजाना हजारों की संख्या में देशी-विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। वर्तमान में गंगा में करीब 300 कंपनियां राफ्टिंग गतिविधियां संचालित करा रही हैं।

ऋषिकेश में गंगा ईको पर्यटन जोन में स्थित खारा स्रोत में पर्यटकों के लिए चेंजिंग रूम तक की सुविधा नहीं है, जबकि इस स्थान पर राफ्टिंग खत्म होती है। जागरण

करीब दस हजार से अधिक लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में इस व्यवसाय से लाभान्वित हो रहे हैं। फिर भी विडंबना यह है कि इस व्यवसाय को सुव्यवस्थित वाले विभाग ही इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। यह ईको टूरिज्म जोन नरेंद्रनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आता है, जबकि यहां पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी वन विभाग के साथ पर्यटन विभाग की भी है। बावजूद इसके आज तक राफ्टिंग के इनटेल और आउटटेल प्वाइंट को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले रास्ते तक दुरुस्त नहीं हो पाए। गंगा तटों पर न तो चेंजिंग रूम की व्यवस्था है, न टॉयलेट की ही।

प्रबंधन समिति भी नहीं बना पाई व्यवस्था : गंगा में राफ्टिंग गतिविधियों के संचालन और व्यवस्थाएं बनाने के लिए शासन स्तर से गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। जिलाधिकारी टिहरी की अध्यक्षता में गठित इस समिति में एसडीएम (उपाध्यक्ष), जिला पर्यटन अधिकारी (सचिव) व जिला कोषाधिकारी (कोषाध्यक्ष) के अलावा राफ्टिंग कारोबारी भी शामिल किए गए थे। गंगा नदी राफ्टिंग रोटेशन समिति के अध्यक्ष दिनेश भट्ट बताते हैं कि प्रबंधन समिति ने ढांचागत सुविधाओं के विकास को प्रति पर्यटक शुल्क लिए जाने का निर्णय लिया था। इससे करीब एक करोड़ रुपये की आय भी समिति को हुई, मगर इसमें से धेला भी पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर खर्च नहीं हुआ।

नैनी झील की गहराई ढाई मीटर घटी

जागरण संवाददाता, नैनीताल

- चार साल पहले थी 27 मीटर, अब मापी गई 24.6 मीटर
- पहली बार वैज्ञानिक सर्वे कर जुटाए झील की गहराई और आंतरिक आंकड़े

नैनी झील की गहराई करीब ढाई मीटर घट गई है। पहली बार वैज्ञानिक विधि से सर्वे कर जो आंतरिक डाटा जुटाया गया है। सर्वे के मुताबिक, झील की अधिकतम गहराई 24.6 मीटर और न्यूनतम चार मीटर है। वर्ष 2016 में सिंचाई विभाग ने रस्सी से झील की गहराई मापी थी, तब इसकी गहराई 27 मीटर आंकी गई थी।

डीएम सविन बंसल ने पहली बार वैज्ञानिक विधि से किए गए सर्वे की जानकारियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि करीब तीन महीने पहले आइआइआरएस देहरादून के वैज्ञानिकों ने नैनी झील का विश्लेषण किया था, जिसमें झील की गहराई व पानी की गुणवत्ता मापी गई थी। वैज्ञानिकों ने परीक्षण के बाद नमूने लिए थे। झील के करीब 78 हजार बिंदुओं की गहराई मापी गई। अब साल में दो बार इसरो से झील का विश्लेषण कराया जाएगा।

वैज्ञानिकों के अध्ययन में सामने आई नैनी झील की स्थिति। फाइल

डीएम ने सर्वे रिपोर्ट के हवाले से बताया कि नैनी झील के चार प्वाइंट सर्वाधिक गहरे हैं, जिसमें पाषाण देवी मंदिर के समीप सर्वाधिक गहराई 24.6 मीटर, शनि मंदिर के समीप 23.7, शनि मंदिर से कुछ आगे 23 मीटर और मल्लीताल नयना देवी मंदिर के समीप गहराई 22 मीटर के करीब है। झील का सर्वाधिक हिस्सा नौ से 13 मीटर गहरा है। इसकी औसत गहराई नौ मीटर दर्ज की गई है।

टीडीएस ने बढ़ाई चिंता : तल्लीताल फांसी गदेरा क्षेत्र और माल रोड के बीच के हिस्से की तरफ झील के पानी में टोटल डिजॉल्व सॉलिड (टीडीएस) की मात्रा करीब साढ़े सात सौ मिलीग्राम प्रति लीटर दर्ज की गई है, जो सामान्य से अधिक है। हालांकि, यह खतरे की स्थिति 900 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। झील का औसत टीडीएस 300 से 700 मिलीग्राम प्रति लीटर मिला है।

औसत से कम ऑक्सीजन : सर्वे में झील के कई हिस्सों में सामान्य से कम ऑक्सीजन मिला है। यह जलीय पारिस्थितिकी के लिए खतरनाक है। ऑक्सीजन की कमी के कारण ही अक्सर झील में मरी हुई मछलियां मिलती हैं। झील के पानी में अधिकतम डिजॉल्व ऑक्सीजन (डीओ) 7.5 मिलीग्राम प्रति लीटर, जबकि कई स्थानों पर न्यूनतम 5.8 दर्ज किया गया है। इसकी सही मात्रा छह से आठ मिलीग्राम प्रतिलीटर है। डीएम ने बताया कि जिन हिस्सों में डीओ कम पाया गया है, वहां पानी में हवा के जरिये ऑक्सीजन छोड़ी जाएगी, जिससे संतुलन बना रहेगा।

सेंसर से पता चलेगी झील की सेहत

नैनी झील की आंतरिक हलचल और पानी की गुणवत्ता अब सिर्फ विभागों तक सीमित नहीं रहेगी। शहरवासी भी इनकी पूरी जानकारी ले सकेंगे। यूएन की स्वीकृति और फंड से झील में लेक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगने से यह संभव होगा।

डीएम सविन बंसल का दावा है कि देश में झील के संरक्षण के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र से फंड जारी किया गया है। डीएम ने बताया कि झील की गहराई, पानी की अशुद्धि, ऑक्सीजन की मात्रा को जानने के लिए मॉनिटरिंग डिवाइस लगाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से बनाया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र से स्वीकृति मिल गई है। यूएन के प्रतिनिधियों से वार्ता भी हुई है। एमओयू होने के बाद करीब 55 लाख की लागत से तल्लीताल पंप हाउस और मल्लीताल पंप हाउस क्षेत्र में झील में लेक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। डिवाइस में लगे सेंसर की मदद से झील के आंतरिक आंकड़े जुटाए जाएंगे। आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए तल्लीताल डांठ पर स्क्रीन लगाई जाएगी। इससे शहर के लोग पल-पल की झील की आंतरिक हलचल को जान सकेंगे।

3000 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हो चुके हैं जनवरी में मुंबई उपनगर जिले के लिए। चार लाख पौधे मुंबई में 65 विभिन्न जगहों पर लगाए जाएंगे।

हिस्से में मिलने वाले हथियार खानदान की निशानी, संरक्षित करूंगी : नूर बानो

उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर के नवाब खानदान की बहू **नूर बानो** को तालीम उस जमाने में मिली जब मुस्लिम लड़कियों के लिए यह बहुत सहज नहीं था। राजस्थान के महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल में मिली तहजीब ने जिंदगी को आसान कर दिया। खुद इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकीं रामपुर की इस पूर्व सांसद के पास यादों का भी खजाना है। बेशुमार यादें हैं। नवाब रजा अली खां साहब ने कैसे उन्हें बहू बनाने का निर्णय किया और इस खानदान में वह कैसे आईं, यह उन्हें आज भी बखूबी याद है। जमीन-जायदाद के बंटवारे के बीच उनकी चिंता उन कुछ खास दस्तावेज को भी सहेजने की है, जिनमें खानदान की शानो-शौकत के किस्से दर्ज हैं। खासबाग महल की दीवारों पर लगी पेंटिंग के खराब होने का दुख उन्हें सालता है। उनसे मुरादाबाद के संपादकीय प्रभारी **भारतीय बसंत कुमार** की बातचीत के प्रमुख अंश :

साक्षात्कार

● रामपुर के इस नवाब खानदान से आपका ताल्लुक कैसे बना?

मैं राजस्थान में महारानी गायत्री देवी पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। मेरे वालिद अमीनुद्दीन खां साहब की रामपुर के नवाब रजा अली खां साहब से पहचान थी। वैसे तो हम लोग मूलरूप से फिरोजपुर झिरका (हरियाणा) के रहने वाले थे, लेकिन अंग्रेजों से अदावत के कारण रियासत छूट गई और जयपुर आकर बसना पड़ा। यहां उस समय देश में पहला स्कूल ऐसा खुला था, जहां लड़कियों की पढ़ाई की मुकम्मल व्यवस्था महारानी गायत्री देवी ने की थी। नवाब रजा अली खां साहब से एक दिन जयपुर किसी काम से आए थे और मेरे घर मेहमान थे। तभी उन्होंने मुझे बहू बनाने का फैसला कर लिया था।

● जीवन में किस चीज को सर्वाधिक अहमियत आप देती हैं?

मैं रिश्ते को बहुत महत्व देती हूं। धन-दौलत, शानो-शौकत सब समय के साथ मिट जाता है, छूट जाता है पर रिश्ता कायम रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी छाप बनी रहती है। मुझे देखिए, किस रिश्ते की बदौलत इतना सम्मान रामपुर के लोगों ने दिया। यह रिश्ता नवाब जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियां की बेगम या नवाब रजा अली खां खानदान की बहू होने से जुड़ा है। यह रिश्ता रामपुर के आम आदमी से मोहब्बत का है, तभी तो नवाब मिक्की मियां और मैंने सात बार भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया।

● अपने राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ बताइए?

राजनीति में मैं मिक्की मियां साहब के बाद आई। मुझे सबका बहुत सहयोग मिला। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हर पारिवारिक आयोजन में मैं मौजूद रही। मेनका गांधी और सोनिया गांधी को बहू रूप में जब नेहरू परिवार लाया था, मैं साक्षी बनी थी। मेरा सौभाग्य रहा कि महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी के बीच आपसी संबंध चाहे जैसे रहे हों, मैं दोनों का स्नेह पा सकी।

● क्या प्रिवी पर्स खत्म करने के फैसले के पीछे गायत्री देवी से खराब रिश्ता भी एक कारण था?

(इस सवाल को टाल कर वह कहती हैं-) देश की कई बड़ी हस्तियों के साथ ही इंदिरा गांधी का भी मेरे रामपुर वाले घर पर आना हुआ था।

● आपके शौक क्या थे और क्या हैं?

पहले पियानो बजाती थी, अब नहीं बजाती हूं। इस समय फूलों की क्यारी सजाने का शौक बना है। मुझे हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली थी। नवाब साहब हमें शिकार पर साथ ले जाते थे पर मैंने कभी शिकार नहीं किया। मेरे जीवन का एक शौक रक्षा बंधन का भी है। मैं करीब चार दशक से कोटा के राज परिवार के बृजराज सिंह को राखी बांधती हूं।

● संसदीय जीवन की कुछ यादें ?

सऊदी में हज यात्रियों के लिए बनी टेंट सिटी में जब 1997 में आग लग गई थी। तब मेरी अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार ने भेजा था। सऊदी में किसी मुस्लिम महिला का प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना महत्वपूर्ण बात थी। इसके बाद दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे संयुक्त राष्ट्र में जम्मू-कश्मीर पर आयोजित एक डिबेट में हिस्सा लेने भेजा था।

● बंटवारे के बाद ऐतिहासिक मूल्य की जो संपत्ति मिलेगी, उसका क्या करेंगी?

बहुत कुछ सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। मेरे खानदान ने हमेशा दुनिया के भले के लिए सोचा। नवाब साहब जब रामपुर में बेटियों की पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे थे, तब उनका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन आज इसकी अहमियत सबको मालूम है। दुनिया उसी को याद करती है जो दुनिया के लिए कुछ करता है। हथियारों का भी बंटवारा होगा। मेरी कोशिश होगी कि खानदानी विरासत की चीजें आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित रहें।

उत्तर प्रदेश के रामपुर में मंगलवार को नूरमहल में सवालों के जवाब देतीं नवाब खानदान की बहू व पूर्व सांसद नूर बानो। जागरण

करेगा मधुमेह की जांच और बताएगा कितना इंसुलिन लें

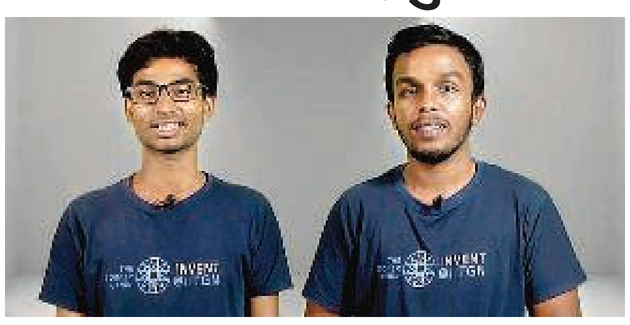
उपकरण डायबिटो केयर बनाने वाले आइआइटी आइएसएम धनबाद के छात्र यश (बाएं) और आइआइटी मद्रास के छात्र गोविंद। सौ. यश

आशीष सिंह, धनबाद

▸ **आइआइटी छात्रों ने दो हजार रुपये में तैयार किया यंत्र, जिसमें इंसुलिन पेन व ग्लूकोमीटर दोनों उपलब्ध**

▸ **वजन महज 70 ग्राम, कहीं भी ले जाना आसान, बाजार में उपलब्ध उपकरणों से कहीं सस्ता और कारगर**

जी हां, आइआइटी छात्रों ने सिर्फ दो हजार रुपये में ऐसा उपकरण तैयार किया है, जिसमें इंसुलिन पेन व ग्लूकोमीटर दोनों उपलब्ध हैं। यह शर्करा का स्तर तो बताएगा ही, साथ ही यह भी तुरंत बताएगा कि कितना इंसुलिन लें। वजन महज 70 ग्राम है और बाजार में उपलब्ध उपकरणों से कहीं सस्ता व कारगर।

झारखंड के धनबाद स्थित आइआइटी आइएसएम के छात्र यश और आइआइटी मद्रास के छात्र गोविंद ने मिल कर यह उपकरण तैयार किया है, जो मधुमेह रोगी के शरीर में शर्करा के स्तर को माप लेगा और उसके बाद जरूरत के मुताबिक इंसुलिन की उचित मात्रा भी बता देगा।

स्वस्थ समाज

इस उपकरण का नामकरण किया है, डायबिटो केयर। नए यंत्र का इस्तेमाल बेहद आसान है। बाजार में इंसुलिन पेन एवं ग्लूकोमीटर नामक दो अलग-अलग उपकरण उपलब्ध हैं, जबकि इंसुलिन पेन और ग्लूकोमीटर की कीमत भी अधिक है। वहीं, इस उपकरण का इस्तेमाल बहुत आसान है और कीमत भी कम। यंत्र की लागत महज दो हजार रुपये आई है। इस यंत्र का वजन महज 70 ग्राम है। पॉकेट में रख कर इसे कहीं भी लेकर जा सकते हैं। शोधार्थियों ने बताया कि इस शोध को पेटेंट कराने के लिए आवेदन किया जा चुका है।

यश ने बताया, यह स्वचालित मशीन है। यह मधुमेह के स्तर के आधार पर इंसुलिन की सही खुराक का निर्धारण करती है। इस्तेमाल के लिए पहले चरण में डिवाइस में मौजूद छिद्र में अंगुली डालनी है। दूसरे चरण में बटन दबाना है। तीसरे चरण में दो से तीन सेकंड तक खून की जांच होगी और तुरंत अपेक्षित इंसुलिन का मात्रा सामने आ जाएगी। इसके बाद आराम से इंसुलिन को शरीर में इंजेक्ट किया जा सकेगा। यश ने बताया कि उनके साथी गोविंद की दादी को मधुमेह है।

उपकरण डायबिटो केयर। सौ.-यश

गोविंद ने अपनी दादी को इंसुलिन लेने के लिए परेशान होते देख ऐसा उपकरण बनाने के लिए शोध करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फार्मेशन (एनसीबीआइ) ने भी माना है कि मधुमेह रोगियों को औसत के आधार पर इंसुलिन देना गलत है। इसे तात्कालिक जांच के आधार पर आवश्यकतानुरूप ही लिया जाना चाहिए। मधुमेह रोग विशेषत्र डॉक्टर जीएन सिंह ने इस उपकरण की आवश्यकता के बारे में कहा, शर्करा की माप कर जरूरत के मुताबिक ही इंसुलिन की मात्रा का निर्धारण करने वाली हल्की मशीन बेहद फायदेमंद होगी।

सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/positive-news

बंटवारे से पहले आमने-सामने नवाब खानदान के लोग

जागरण संवाददाता, रामपुर

संपत्ति के बंटवारे से पहले ही रामपुर नवाब खानदान के बीच मतभेद सामने आने लगे हैं। आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। नवाब स्वर्गीय मुर्तजा अली खां के बेटे नवाब मोहम्मद अली खां उर्फ मुराद मियां और बेटी शहजादी निखत आब्दी ने अपने चचेरे भाई नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां पर 10 करोड़ की संपत्ति पहले ही बेचने का आरोप लगाया है। मुराद मियां और निखत आब्दी ने मंगलवार को मीडिया से बात की। सबसे पहले तो नवाब खानदान की संपत्ति के मूल्यांकन को लेकर हो रही मीडिया कवरेज पर नाराजगी जाहिर की। कहा कि स्ट्रांग रूम सभी पैलेस में होते हैं। स्ट्रांग रूम काटने की जानकारी मीडिया के जरिए पूरे देश को क्यों दी जा रही है? क्यों बताया जा रहा है कि हमारे घर के अंदर क्या हो रहा है?

मुराद मियां ने बताया कि नवाब रजा अली खां के तीन बेटे और छह बेटियां थीं। अब यह संपत्ति इनके बीच बंटेगी। यह बंटवारा शिया शरीयत के मुताबिक होगा। इसके तहत बेटी का हिस्सा 25 फीसद और बेटे का 50 फीसद होता है। इस तरह आधी जायदाद तीन बेटों के वारिसों में बांटी जाएगी, जबकि आधी छह बेटियों के वारिसों में बंटेगी। उन्होंने चचेरे भाई पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां पर काफी संपत्ति पहले ही बेचे जाने का आरोप भी लगाया। कहा कि व्हाइट मनी में 10 करोड़ की संपत्ति बेचने की जानकारी है। यह संपत्ति मुंबई के कुछ लोगों को बेची गई है। उन्होंने कहा कि हमारा जिस संपत्ति पर कब्जा रहा, उसमें से हमने एक इंच भी जमीन नहीं बेची। कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान किया। हमने दो बार हाई कोर्ट से मुकदमा जीता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका भी पूरा सम्मान करेंगे। उन्होंने दादी को घर से निकालने संबंधी आरोपों को भी गलत बताया।

नहीं हुआ संपत्ति का सर्वे

नवाब खानदान की संपत्ति का सर्वे मंगलवार को नहीं हो सका। एडवोकेट कमिश्नर अरुण गुप्ता ने बताया कि अभी मूल्यांकन का काम चल रहा है। अब बेनजीर और कुंडा की संपत्ति का सर्वे किया जाएगा।

खरबों की जायदाद छिनने से मानसिक संतुलन बिगड़ा : नवेद

नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोनों भाई-बहन संपत्ति पर मात्र करीब 12 फीसद के हिस्सेदार हैं। उनके कब्जे से खरबों की जायदाद छिन गई, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। मेरे दादा नवाब सैयद रजा अली खां रामपुर रियासत के आखिरी नवाब थे। नवाब रजा अली ने ही शासन किया था। उनके इंतकाल के बाद मेरी दादी को खासबाग पैलेस से निकाल दिया गया था। रामपुर रियासत की शान खासबाग समेत सभी जायदाद को पहले इनके माता-पिता ने बर्बाद किया और उसके बाद दोनों भाई-बहन लूट-खसोट मचा रहे हैं। खासबाग को खंडहर बनाने, जायदाद बेचने, बेशकीमती धरोहरें विदेश भेजने और इस संपत्ति से मिलने वाली दौलत के बल पर मौज करने वाले लोग खुद को पाक-साफ बताने की कोशिश में लगे हैं। खासबाग पैलेस, नवाब स्टेशन, सरकारी कुंडा, बेनजीर और कोठी शाहबाद पर दोनों भाई-बहन का कब्जा अवैध है।

शाही खजाना पाने को रामपुर नवाब के वंशज बनकर पहुंच रहे कोर्ट

मुस्लेमीन, रामपुर

▸ **नए दावेदार खुद को बता रहे नवाब रजा अली के भाई और बहनों के नाती-पोते**

▸ **अदालत ने सभी की अर्जियां खारिज कीं, अब दावेदार हाई कोर्ट जाने की तैयारी में**

रामपुर नवाब खानदान में अरबों रुपये की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 16 हिस्सेदार हैं। इसके अलावा कई नए दावेदार खुद को नवाब का वंशज बताते हुए कोर्ट में अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं। ये लोग संपत्ति में हिस्सेदार बनना चाहते हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है। अब वे हाई कोर्ट जाने की तैयारी में हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पांच माह पहले रामपुर के आखिरी नवाब रजा अली खां की संपत्ति के बंटवारे के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी गई है। संपत्ति के हिस्सेदारों में नवाब रजा अली खां के बेटे-बेटियां और नाती-पोते शामिल हैं, लेकिन अब इनके अलावा और भी दावेदार सामने आ रहे हैं। ये लोग नवाब रजा अली खान के भाई और बहनों के नाती पोते हैं। इनमें एक दावेदार नवाब रजा अली खां की बहन कुलसुम बेगम उर्फ नन्ही बेगम के पोते साहबजादा सलमान अली खान भी शामिल हैं।

नवाब की बहन के पोते ने किया दावा : नवाब की बहन कुलसुम बेगम उर्फ नन्ही बेगम के पोते साहबजादा सलमान अली खान का कहना है कि शरीयत के हिसाब से उनका भी हिस्सा बनता है। रामपुर के मर्जर एग्रीमेंट में भी उनकी दादी का नाम शामिल है। उनके चाचा सैयद स्वाले मियां ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। उसमें उनके पिता सैयद जाफर अली खां का नाम भी शामिल रहा। इस अर्जी में पहले से चल रहे बंटवारे के मुकदमे में उन्हें भी शामिल करने का आग्रह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पांच माह पहले जो फैसला सुनाया है, उसमें उनकी अर्जी निस्तारित करते हुए कहा कि वह अपना हक जताने के लिए सिविल कोर्ट में वाद दायर कर सकते हैं। अब सलमान के पिता और चाचा की मौत हो चुकी है। इसलिए उन्होंने खुद जिला जज की कोर्ट में भी प्रार्थना पत्र दिया। इसमें सलमान खान के साथ ही उनकी बहन समन अली खान, शहरुत अली खान, मां शहजादी मेहरुन निशा बेगम और चाचा स्वर्गीय स्वाले अली खान की बेटी सायरा अली खान और शहवार अली खान भी शामिल हैं।

नवाब के भाई के पोते और पोती भी आगे आए : नवाब रजा अली खान के भाई जाफर अली खां उर्फ मझले साहब के पोते अली और पोती अतिया व राना की ओर से भी कोर्ट में अर्जी लगाई गई। नवाब रजा अली खां की एक और बहन सफदर मियां की बेटी हिना सफदर ने भी कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसे जिला जज ने खारिज कर दिया।

हाई कोर्ट जाएंगे सलमान : सलमान के वकील चेतन माथुर का कहना है कि जिला जज ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इन्हें संपत्ति बांटने का आदेश नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे के आदेश कर दिए हैं। दूसरी तरफ हमारे पक्ष को सिविल कोर्ट जाने को कहा है। जिला जज ने जो प्रार्थना पत्र खारिज किया है, उस मामले में हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने बताया कि जुगनू खां की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

संपत्ति 16 हिस्सों में ही बंटेगी : वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता हर्ष गुप्ता कई हिस्सेदारों के वकील हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बंटवारे के लिए हिस्सेदारों के नाम घोषित कर दिए हैं। सूची में 18 नाम हैं, जिनमें दो की मौत हो चुकी है। 16 बचे हैं, उनमें ही संपत्ति बंटेगी। इसलिए जिला जज ने नए दावेदारों के प्रार्थना पत्र खारिज किए हैं। आखिरी नवाब रजा अली खां की संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, जो उनकी औलाद के बीच होगाा।

आसमान से गुजरे प्रकाश पुंज ने मचाई हलचल

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी

ऐसा नजारा पहले नहीं देखा। हरियाणा के रेवाड़ी में मंगलवार को सुबह करीब 5 बजकर 18 मिनट पर आसमान से गुजरे तेज प्रकाश पुंज के कारण हलचल मच गई। कुछ क्षण के लिए आसमान रोशन हो उठा। इस प्रकाश पुंज के गुजरने के करीब डेढ़ मिनट बाद काफी तेज धमाका हुआ। जिले में सैकड़ों लोगों ने आसमान में हुई इस हलचल को देखा और सुना। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था कि आसमान में इस तरह की घटना उन्होंने पहले कभी नहीं देखी।

रोशन हुआ आकाश : नांगलमूंदी गांव निवासी दया यादव, अटेली निवासी बाबूलाल, स्वामीवाड़ा निवासी हेमंत सहित न जाने कितने ही लोग है जिन्होंने मंगलवार सुबह आकाश में हुई अजीबोगरीब हलचल देखी। लोगों का कहना है कि सुबह के समय इतनी तेज रोशनी हुई जैसे कि दोपहर के 12 बजे सूरज चमक रहा हो। इस रोशनी के बाद हुई तेज गर्जना ने तो सभी को डराकर रख दिया। लोग डर की वजह से अपने घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि पूर्व दिशा की ओर से रोशनी आती हुई दिखाई दी। रोशनी की एक रेखा सी खिंची और लुप्त हो गई। सीसीटीवी में भी यह घटना कैद हुई है जिसे दिनभर सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता रहा। इस बाबत दिल्ली स्थित नेहरू तारामंडल में बातचीत की गई तो बताया गया कि अभी तक इस बाबत जानकारी उनके पास नहीं पहुंची है। बुधवार तक स्थिति साफ हो जाएगी। केएलपी कॉलेज के भूगोल के पूर्व प्रोफेसर रतिपाल सिंह के अनुसार इस तरह की घटनाओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं। भूमंडल में उल्का पिंड और अन्य कण घूमते रहते हैं। पृथ्वी की कक्षा में आने के बाद घर्षण के कारण इनके नष्ट होने से रोशनी व तेज ध्वनि हो सकती है। वहीं विपरीत दिशा से आ रहे बादलों के आपस में टकराने से भी ऐसा हो सकता है। स्पष्ट तौर पर इस तरह की घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

सुबह पांच बजकर 18 मिनट पर तेज प्रकाश पुंज से यूं जगमगाया था आसमान। सौजन्य : पाठक

मानेसर में भी अचानक चमक उठा आकाश : मानेसर स्थित गांव मोकलवास के लोगों ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब पांच बजे अचानक आसमान चमक उठा। ऐसा लगा रहा था कि सुबह ही दोपहर हो गई है। मोकलवास निवासी कमांडर राम सिंह ने बताया कि वह घर के बाहर सुबह टहल रहे थे तभी आसमान में तेज गति से कोई चीज चमकते दिखी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते कि रोशनी की तीव्रता इतनी अधिक हो गई कि वह चकाचौंध हो गए। यह नजारा करीब 30 सेकेंड तक दिखा।

उत्तराखंड में एक क्लिक में मिलेगी जेलों में बंद कैदियों की पूरी सूचना

राज्य ब्यूरो, देहरादून: उत्तराखंड की जेलों में बंद कैदियों की पूरी सूचना अब एक क्लिक पर ही मिल जाएगी। ऐसा संभव हुआ है ई-प्रिजन योजना से। जेल प्रशासन का दावा है कि प्रदेश के सभी जेलों में अपराधियों के रिकॉर्ड फीड कर लिए गए हैं। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर उनकी ऑनलाइन पेशी भी की जा रही है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में सभी प्रदेशों में ई-प्रिजन योजना लागू की। इस योजना के तहत जेलों में बंद सभी कैदियों का रिकॉर्ड डिजिटाइज्ड करने के साथ ही इसे ऑनलाइन भी किया जाना है। इसका मकसद यह बताया गया कि इससे कैदियों के संबंध में एक ही क्लिक पर पूरी जानकारी मिल सकेगी। दरअसल, अभी तक अधिकांश प्रदेशों में कैदियों का रिकार्ड फाइलों में रखा जाता था। कैदियों के दूसरे जेलों पर शिफ्ट होने पर उनके रिकॉर्ड भी शिफ्ट किए जाते हैं।

जागरण विशेष

महान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर गुपचुप तरीके से पहुंचे शाहिद के घर, साथ में खेला क्रिकेट, खींची तस्वीरें, भविष्य संवारने में मदद का दिया भरोसा, अपनी आगामी किताब 'स्पिरिट ऑफ क्रिकेट' में लिखेंगे शाहिद पर चैप्टर

अब स्टीव वॉ की किताब में छाएगा क्रिकेट का 'वंडर किड'

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता

अपनी अद्भुत बल्लेबाजी से सोशल मीडिया पर धूम मचाने वाला तीन साल का शेख शाहिद अब क्रिकेट बुक में छाने को तैयार है। यह किताब कोई और नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तान स्टीव वॉ लिख रहे हैं, जो शाहिद से मिलने चुपचाप उसके घर पहुंचे। शाहिद की बल्लेबाजी से स्टीव इस कदर मुग्ध हुए कि उससे मिलने खुद गुपचुप तरीके से कोलकाता स्थित उसके घर पहुंच गए।

स्टीव ने नन्हे शाहिद के साथ क्रिकेट खेला, उसे बल्लेबाजी के टिप्स दिए, साथ में तस्वीरें खिंचवाई, तोहफे में बल्ला भेंट किया और उसके पिता को भरोसा दिलाया कि वे शाहिद का भविष्य संवारने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे।

इससे पहले टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली क्रिकेट के इस 'वंडर किड' को अपनी क्रिकेट अकादमी में भर्ती करने का आश्वासन दे चुके हैं। महान क्रिकेटरों में शुमार स्टीव वॉ गत दिनों गुपचुप तरीके से दक्षिण कोलकाता के बेहला अंचल के शकुंतला पार्क, मूचीपाड़ा स्थित शाहिद के घर पहुंचे। मीडिया को इसकी भनक नहीं लगने दी। शाहिद के साथ उन्होंने कुछ घंटे बिताए। शाहिद के पिता शेख शमशेर ने दैनिक जागरण को बताया, 26 जनवरी को सुबह करीब 10.30 बजे किसी ने हमारे घर का दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो दंग रह गया। सामने कोई और नहीं, काली टीशर्ट और शॉर्ट में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान महान क्रिकेटर स्टीव वॉ थे। साथ में कैमरामैन और बॉडीगार्ड थे। उनके कैमरामैन ने बताया कि सर शाहिद से मिलने आए हैं। मुझे लगा मानो कोई सपना देख रहा हूं। क्रिकेट की इतनी बड़ी हस्ती मुझ जैसे मामूली इंसान के घर खुद चलकर आई है। मैं मूक दर्शक बना खड़ा ही था कि स्टीव सर ने मुझसे कहा, मैंने सोशल मीडिया पर आपके बेटे की बल्लेबाजी के अब तक के सारे वीडियो देखे हैं। मैं उससे काफी प्रभावित हूं और मिलना चाहता हूं। स्टीव अंग्रेजी में बोल रहे थे। मुझे थोड़ी-बहुत अंग्रेजी समझ में आती है इसलिए बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। मैंने उन्हें अंदर आने को कहा।

दैनिक जागरण का शुक्रिया

शाहिद के पिता शेख शमशेर ने दैनिक जागरण का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'मेरे बेटे का वीडियो वायरल होने के बाद से उसे काफी सराहा जा रहा है, लेकिन दैनिक जागरण में उसकी कहानी प्रकाशित होने के बाद अब क्रिकेट के शुभचिंतक उसे काफी गंभीरता से लेने लगे हैं। स्टीव वॉ का मेरे घर तक चलकर आना इसका प्रमाण है कि मेरा बेटा अब केवल सोशल मीडिया की सनसनी भर नहीं है। इसके लिए मैं जागरण का शुक्रगुजार हूं।'

शाहिद के पिता ने आगे बताया, उन्होंने शाहिद को देखा, अपने चिर-परिचित अंदाज में मुस्कुराए और फिर उसे अपने साथ क्रिकेट खेलने का इशारा किया। हम उन्हें छत पर ले गए, जहां मैंने शाहिद की बल्लेबाजी प्रैक्टिस के लिए नेट लगा रखा है। स्टीव सर ने शाहिद को बल्लेबाजी करने को कहा। वे गेंदबाजी कर रह थे और मेरे बेटे की बल्लेबाजी को गौर से देख रहे थे। बीच-बीच में उसे टिप्स भी दे रहे थे, खासकर ड्राइव और फुटवर्क को लेकर। उसी दौरान उन्होंने अपने कैमरे से शाहिद की कई तस्वीरें भी खींचीं। उन्हें शाहिद का वन हैंड हिटिंग शॉट काफी पंसद आया, जो उसका सबसे चर्चित शॉट है। मेरी बीवी सोफिया उनके लिए चाय बनाकर लाई। चाय की चुस्की लेते हुए उन्होंने मुझसे कहा, आपके बेटे में विलक्षण प्रतिभा है। वो बहुत आगे जाएगा। उसे ठीक से गाइड करो, लेकिन ज्यादा दबाव मत देना, बस क्रिकेट का लुत्फ उठाने दो। देख लेना, एक दिन वह क्रिकेट में बहुत नाम कमाएगा। मैं आपके संपर्क में रहूंगा और शाहिद का भविष्य संवारने में अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा...।

उन्होंने आगे बताया, स्टीव ने कहा- मैं स्पिरिट ऑफ क्रिकेट नामक किताब लिख रहा हूं, जिसमें आपके बेटे के बारे में भी लिखना चाहता हूं। उन्होंने शाहिद को तोहफे में एक बल्ला भी दिया। न्यू अलीपुर के एक सैलून में काम करने वाले शाहिद के पिता शेख शमशेर ने कहा, मेरा बेटा सचिन, धौनी, विराट को तो जानता है लेकिन स्टीव वॉ को नहीं जानता था, अब पहचान गया है। गौरतलब है कि शाहिद के प्रशंसकों में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन व दिग्गज माइकल वान शामिल हैं।

जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें
www.jagran.com/topics/jagran-special

स्टीव वॉ की गोद में शाहिद। सौ. शेख शमशेर

राष्ट्रीय संस्करण
बुधवार 12 फरवरी 2020
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

अडानी सहित चार कंपनियों को 1246 करोड़ का प्रोत्साहन पैकेज

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रदेश सरकार अडानी सहित चार बड़ी कंपनियों को 1246 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज देगी। आरती ग्रीन टेक लिमिटेड को 30.06 करोड़, अडानी विलमर लिमिटेड को 65.94 करोड़, वंडर सीमेंट लिमिटेड के लिए 298 करोड़ और एंप्रैक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लिए 852 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की मंगलवार को हुई सातवीं बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इंटरनेट के इस दौर में संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कैसे लोग आपसे जुड़े हैं। इंस्टाग्राम पर आप सबसे जुड़ना शानदार अनुभव है। उम्मीद है यह साथ आगे भी बना रहेगा।
— रतन टाटा
चेयरमैन, टाटा ग्रुप

सेंसेक्स 40,216.14 ▲ 236.52	निफ्टी 12,107.90 ▲ 76.40	सोना प्रति दस ग्राम ₹ 41,269 ▼ ₹112	चांदी प्रति किलोग्राम ₹ 47,152 ▼ ₹108	डॉलर ₹ 71.28 ▼ ₹0.02	क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल $ 54.44

कांग्रेस के 'काबिल डॉक्टरों' ने किया अर्थव्यवस्था का गलत इलाज : सीतारमण

पलटवार ▶ बैंकों का एनपीए संकट, ट्विन बैलेंस शीट, दो अंकों की महंगाई इसी की देन

संप्रग ने तेल सब्सिडी से तेल कंपनियों की बैलेंस शीट सुधारी, मगर सच्चाई छुपाई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम के 'अयोग्य डॉक्टरों द्वारा अर्थव्यवस्था की बीमारियों का इलाज' कटाक्ष पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, 'हमें ऐसे लोगों से सीखने की जरूरत नहीं है जिन्होंने एनपीए के साथ दोहरी बैलेंस शीट का संकट खड़ा किया था। सच तो यह है कि संप्रग सरकार के 'काबिल डॉक्टरों' ने अर्थव्यवस्था का इतना गलत इलाज किया कि हमें अब उसे दुरुस्त करना पड़ रहा है।'

बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, '2012-13 में जब 'काबिल डॉक्टर' अर्थव्यवस्था को देख रहे थे तब प्रत्यक्ष एफडीआइ देश से बाहर चला गया था। रक्षा उपकरण न खरीदे जाने के कारण भारत का रक्षा क्षेत्र अपाहिज हो गया था। यह संप्रग शासन का दौर था जब एनपीए के साथ-साथ ट्विन बैलेंस शीट का संकट खड़ा हो गया था। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक संकट में आ गए और कुछ चालाक उद्योगपति देश छोड़कर भाग गए। उन तमाम समस्याओं को हमने दूर करने का काम किया है।' उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्री ने जिस दौर का हवाला दिया, उस वक्त चिदंबरम ही वित्त मंत्री थे। सीतारमण ने कहा कि आज जो लोग हम पर खातों में हेरफेर का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने 1.40 लाख करोड़ रुपये के ऑयल बांड जारी किए थे, जिस पर 9900 करोड़ का ब्याज देना पड़ा है। उन्हीं लोगों ने तेल कंपनियों की बैलेंस शीट सुधारने में तेल सब्सिडी का इस्तेमाल किया था। संप्रग के 'काबिल डॉक्टरों' के रहते महंगाई दर दहाई में रही और एफआरबीएम का खूब उल्लंघन हुआ। मगर इसे जनता से छुपाया गया, जबकि हमने कुछ भी नहीं छुपाया है।

विपक्ष के आरोपों को 'कम दमदार और ज्यादा कटाक्षपूर्ण' बताते हुए सीतारमण ने कहा कि संप्रग के समय किए गए मुक्त व्यापार समझौतों से देश को नुकसान हो रहा है। हमें इसे ठीक करना पड़ रहा है। हम खाने-पीने की चीजों की महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हुए हैं। राजकोषीय अनुशासन को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने लगातार कायम रखा है। उन्होंने कहा, 'हम निश्चित रूप से संप्रग की गलतियां न दोहराने की पूर्व धारणा से ग्रस्त हैं।'

बजट सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। एएनआइ

सुधर रहा जीएसटी संग्रह

जीएसटी को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी संग्रह में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। चालू वित्त वर्ष के छह महीनों में यह एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। वित्त मंत्री ने राज्यों को जीएसटी बकाए के भुगतान पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश की आशंका का भी जवाब दिया और कहा कि राज्यों को दो किस्तों में बकाए का भुगतान किया जाएगा।

उठाए जा रहे जरूरी कदम

एमएसएमई की उपेक्षा के आरोपों पर वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट की स्थापना, टर्नओवर सीमा में वृद्धि, कई वस्तुओं के आयात पर अंकुश के लिए सीमा शुल्क में बढ़ोतरी तथा नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जैसे विभिन्न कदमों की जानकारी दी। सीतारमण ने विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर दिया कि सरकार आयकर अधिनियम का उपयोग उद्योगपतियों के उत्पीड़न के लिए कर रही है।

कोरोना ने बढ़ाई कई सेक्टरों की चिंता

जेएनएन, नई दिल्ली

▶ चीन में वायरस के संकट से भारत में भी कुछ उद्योगों पर बंदी का खतरा

▶ ऑटोमोबाइल निर्यातक भी स्थिति से परेशान, कारोबार पर पड़ रहा असर

चीन में कोरोना वायरस के कारण उपजा संकट भारतीय उद्योगों के माथे पर भी चिंता की लकीरें खींच रहा है। सबसे ज्यादा चिंता ऑटोमोबाइल, डाई और स्मार्टफोन सेक्टर में देखने को मिल रही है। डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्री (रंग एवं रसायन उद्योग) चीन से आने वाले कच्चे माल की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण मुश्किल का सामना कर रही है। ऑटोमोबाइल व स्मार्टफोन सेक्टर भी चीन से कंपोनेंट आपूर्ति धीमी पड़ने से परेशान है।

चीन में एक माह से कोरोना वायरस का संकट छाया है। इस कारण से वहां बड़े पैमाने पर कारोबार बंद पड़े हैं, जिससे भारतीय उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। देश में डाई कारोबारी परेशान हैं। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा के ज्यादातर डाई कारोबारी कच्चा माल चीन से मंगाते हैं। कच्चे माल की आपूर्ति रुकने से इन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अकेले पानीपत में 600 टन डिस्पर्स डाइज की प्रतिमाह खपत होती है। यहां कारोबारियों के पास कच्चे माल का स्टॉक खत्म हो रहा है। उद्यमियों का कहना है कि अगर चीन से महीनेभर यही स्थिति रही तो कई उद्योग बंद हो सकते हैं। यहां डाइज एंड केमिकल एसोसिएशन के प्रमुख संजीव मनचंदा ने डाई इंडस्ट्री पर संकट को लेकर चिंता जताई। कमोबेश ऐसी ही स्थिति ऑटोमोबाइल सेक्टर की है। ऑटोमोबाइल निर्यातक काफी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यदि चीन को कोरोना की आपदा से जल्द निजात नहीं मिली तो इसका साइड इफेक्ट भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात पर पड़ना तय है। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट की आपूर्ति के क्षेत्र में चीन बड़ा नाम है। वहां अधिकतर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम बिल्कुल ठप है। ऐसे में दुनिया के उन देशों में वाहनों के उत्पादन पर असर पड़ेगा जो चीन से आने वाले कंपोनेंट पर निर्भर हैं।

गुरुग्राम की ओनेसिस ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ रोहित भाटिया ने कहा कि जब चीन से ऑटो कंपोनेंट दुनिया की वाहन निर्माता कंपनियों तक नहीं पहुंचेंगे तो पूरी चेन प्रभावित होगी। ऑटो कंपोनेंट्स तैयार करने वाली कंपनियों का विकल्प खोजना आसान नहीं होता। इसमें चार से पांच साल तक का समय लग सकता है।

भारत की स्मार्टफोन इंडस्ट्री भी काफी हद तक चीन पर ही निर्भर है। समाचार एजेंसी प्रेट्र से बातचीत में इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज मोहिंद्रो ने कहा कि स्मार्टफोन सेक्टर पर असर दिखने लगा है। कुछ प्रोडक्ट और मॉडल प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी कोरोना के व्यापक असर को लेकर कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर, रणथंभौर, पुष्कर और बीकानेर जैसे पर्यटन स्थलों पर भी वायरस की मार दिख रही है। कोरोना के संकट के कारण ज्यादातर विदेशी पर्यटक अपनी बुकिंग रद करा रहे हैं। कुछ जगहों पर 80 फीसद तक एडवांस बुकिंग रद हो गई है।

चीन में जा रही लोगों की नौकरी

शंघाई, रायटर : चीन में कोरोना से प्रभावित कंपनियां बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही हैं। मीडिया कंपनी शिनचाओ मीडिया ने 500 कर्मचारियों को निकालने की बात कही है। इससे पहले कुछ और कंपनियां भी इस तरह के कदम उठा चुकी हैं। कंपनियां छंटनी को लेकर कदम ऐसे समय में उठा रही हैं, जबकि चीन की सरकार ने कहा है कि वह वायरस के कारण पैदा हुए संकट में ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं गंवाने देगी। छंटनी के बीच अधिकारियों ने फिर कहा है कि रोजगार की हिफाजत के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

सहारा ग्रुप ने रिफंड अकाउंट में जमा किए 15,448 करोड़

▶ सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा कराई गई है राशि

▶ ग्रुप पर गलत तरीके से फंड जुटाने का चल रहा है मामला

नई दिल्ली, आइएएनएस : सहारा ग्रुप ने निवेशकों को लौटाने के लिए 15,448 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। यह राशि सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा की गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में दिए गए एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले महीने भी 41.59 करोड़ रुपये का चेक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। इसे बाद में सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में डाल दिया गया। हालांकि अभी निवेशकों के हक में किसी तरह की राशि जारी नहीं की गई है। सहारा ग्रुप पर गलत तरीके से फंड जुटाने का मामला चल रहा है।

सेबी ने अदालत को बताया था कि सहारा ग्रुप की दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट ने 19,400.97 करोड़ और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 6,380.50 करोड़ रुपये 3.07 करोड़ निवेशकों से अलग-अलग माध्यमों से जुटाए थे। इस दौरान इन कंपनियों ने निवेश के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया था। ठाकुर ने बताया कि इस मामले में सेबी को रिफंड के लिए 19,560 अर्जियां प्राप्त हुई थीं। इनमें 53,361 मूल बॉन्ड सर्टिफिकेट या पासबुक थीं, जिसमें कुल मिलाकर 81.30 करोड़ रुपये का मूलधन देय था। सेबी ने इसमें से 14,146 मामलों में कुल 109.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसमें 58.52 करोड़ रुपये मूलधन और 51.34 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाए गए हैं।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय और दो अन्य डायरेक्टर्स को 25,700 करोड़ रुपये जमा करने में विफल रहने के मामले में अगले आदेश तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जनवरी में अदालत ने रॉय और दो अन्य डायरेक्टर रवि शंकर दुबे और अशोक रॉय चौधरी को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों की राशि लौटाने की पर्याप्त कोशिशें नहीं की जा रही हैं। इसके बाद अदालत ने ग्रुप से 25,700 करोड़ रुपये सेबी के साथ जुड़े अकाउंट में जमा करने के लिए कहा था।

1,912 करोड़ जीएसटी रिफंड के 634 फर्जी मामले उजागर

नई दिल्ली, प्रेट्र : निर्यातकों द्वारा फर्जी जीएसटी रिफंड के मामले बड़े पैमाने पर सामने आ रहे हैं। सरकार ने संसद में बताया कि जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 के दौरान 1,912 करोड़ रुपये जीएसटी रिफंड के 634 फर्जी मामले पकड़ में आए हैं। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी तरीके से हासिल किए गए रिफंड में से 238.97 करोड़ रुपये रिकवर किए हैं। इस दौरान 35 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।

ठाकुर ने बताया कि डाटा एनालिटिक्स के जरिये सरकार दागी कारोबारियों पर नजर रख रही है। रिफंड करने से पहले फर्जी दावों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि फर्जी मामलों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआइ) का प्रयोग किया जा रहा है। फर्जी मामलों पर नियंत्रण के लिए परिचालन मानक भी निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा जीएसटी रिफंड की अनुमति के लिए शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। सरकार हर स्तर पर रिफंड के फर्जी दावों की पड़ताल कर रही है।

पंजाब नेशनल बैंक ने कहा, विलय के बाद नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : सार्वजनिक क्षेत्र के दो बड़े बैंकों ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआइ) के साथ विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का नाम नहीं बदलेगा। पीएनबी ने मंगलवार को ट्वीट कर स्पष्ट किया कि विलय के बाद नाम बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कुछ दिन पहले यूबीआइ के एक अधिकारी ने कहा था कि सरकार विलय के बाद बनने वाले बैंक के लिए नया नाम और लोगो जारी कर सकती है। नया बैंक पहली अप्रैल, 2020 से काम शुरू कर देगा।

पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओबीसी, यूबीआइ और पीएनबी के विलय का एलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस विलय से देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक अस्तित्व में आएगा। सरकार ने सिंडीकेट बैंक और केनरा बैंक तथा इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक के विलय का भी एलान किया है। इसी तरह आंध्र बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मिलाकर नया बैंक बनाने का भी एलान किया गया है।

▶ ओबीसी और यूनाइटेड बैंक के साथ हो रहा है पीएनबी का विलय

▶ यूबीआइ के अधिकारी ने नया नाम और लोगो जारी होने की कही थी बात

प्रतीकात्मक फोटो

बैंक ऑफ बड़ौदा का नहीं बदला था नाम

इससे पहले तीन बैंकों के विलय की एक प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसमें सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक का विलय कर एक बैंक बनाया था। इस मामले में विलय के बाद बने बैंक का नाम बैंक ऑफ बड़ौदा ही रखा गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा इस विलय में शामिल सबसे बड़ा बैंक था।

बराबरी का है विलय : पिछले हफ्ते ओबीसी के सीईओ व एमडी मुकेश कुमार जैन ने कहा था कि यह विलय बराबरी के स्तर वाले बैंकों में हो रहा है। उन्होंने कहा था, 'हमने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि विलय के बाद बनने वाले बैंक का नाम या तो तीनों बैंकों से एकदम अलग हो या फिर ऐसा हो जिसमें तीनों बैंकों की पुरानी पहचान शामिल रहे। इससे विलय में बराबरी की झलक रहेगी।'

तीसरी तिमाही में आइडीबीआइ बैंक को भारी नुकसान

मुंबई, प्रेट्र : चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान आइडीबीआइ बैंक को 5,763 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह लगातार 13हवीं तिमाही है, जब यह सरकारी बैंक घाटे में रहा है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान बैंक को 4,185 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि नए टैक्स नियमों के तहत आने के कारण बैंक को वन टाइम टैक्स के रूप में भारी राशि चुकानी पड़ी है।

इस दौरान बैंक ने 6,273 रुपये टैक्स के रूप में चुकाए हैं। इससे बैंक के नुकसान में इजाफा हुआ। शर्मा ने बताया कि अगर टैक्स की राशि नहीं चुकानी पड़ती तो बैंक को 480 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा होता। उन्होंने बताया कि समीक्षाधीन अवधि में बैंक के एनपीए में भी सुधार हुआ है। इस बीच मंगलवार को सिंडिकेट बैंक के तिमाही आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर-दिसंबर अवधि के दौरान बैंक को 434.82 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ है।

पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान सिंडिकेट बैंक को 107.99 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक की कुल आय 6,316.57 करोड़ रुपये रही। इस दौरान बैंक के एनपीए में भी कमी दर्ज की गई।

इलाहाबाद बैंक को भारी तिमाही नुकसान

नई दिल्ली, प्रेट्र : सार्वजनिक क्षेत्र के कर्जदाता इलाहाबाद बैंक को चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान 1,986.26 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान बैंक को 732.81 करोड़ रुपये का शुद्ध नुकसान हुआ था। समीक्षाधीन अवधि में बैंक को कुल 4,860.35 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 4,756.88 करोड़ रुपये रहा था। इस दौरान बैंक के एनपीए में 18.93 परसेंट का इजाफा हुआ।

विदेशी शाखाओं में ज्यादा पैसा लगा रहीं भारतीय कंपनियां

मुंबई, प्रेट्र : भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में किए जाने वाले निवेश में तेज उछाल देखने को मिला है। इस वर्ष जनवरी में यह करीब 40 परसेंट वृद्धि के साथ 210 करोड़ डॉलर (करीब 14,700 करोड़ रुपये) दर्ज किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष इसी अवधि में भारतीय कंपनियों ने अपनी विदेशी इकाइयों में करीब 147 करोड़ डॉलर (करीब 10,290 करोड़ रुपये) का निवेश किया था। दिसंबर, 2019 के दौरान निवेश 199 करोड़ डॉलर दर्ज किया गया था।

समीक्षाधीन अवधि में भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में किए गए कुल निवेश में 79.382 करोड़ डॉलर इक्विटी कैपिटल, 36.855 करोड़ डॉलर डेट कैपिटल के रूप में और शेष 89.075 करोड़ डॉलर गारंटी के रूप में निवेश किया गया था।

2024 तक रफ्तार पकड़ेगी ई-वाहनों की बिक्री : क्रिसिल

▶ चौपहिया वाहनों के मामले में एजेंसी ज्यादा उत्साहित नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : एनालिटिकल फर्म क्रिसिल ने 2024 तक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की बिक्री में तेज उछाल आने की बात कही है। हालांकि चौपहिया वाहनों के मामले में एजेंसी ज्यादा उत्साहित नहीं है। क्रिसिल के मुताबिक 2024 तक देश में बिकने वाले कुल नए वाहनों में तिपहिया ई-वाहनों की हिस्सेदारी 43-48 परसेंट तक हो सकती है। इसी अवधि में कुल दोपहिया वाहनों में करीब 17 परसेंट ई-वाहनों की हिस्सेदारी की उम्मीद है।

क्रिसिल के मुताबिक 2024 तक बिकने वाले कुल चौपहिया वाहनों में ई-वाहनों की पांच परसेंट हिस्सेदारी होने का अनुमान है। एजेंसी ने बताया कि इस अध्ययन में मांग, आपूर्ति, इलेक्ट्रिक वाहनों पर सरकारी नीति, ढांचागत सुधार, बैट्री और चार्जिंग स्टेशन जैसी बातों को ध्यान में रखा गया है। आमतौर पर डीजल और पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के मुकाबले ऐसे इलेक्ट्रिक वाहनों पर खर्च कम आता है। यही कारण है कि दोपहिया और तिपहिया ई-वाहनों की बिक्री में उछाल की उम्मीद जताई जा रही है। क्रिसिल के रिसर्च डायरेक्टर हेतल गांधी ने बताया कि ई-वाहनों की खरीद में आपूर्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पांच शीर्ष इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता 2024 तक अपनी वाहन निर्माण क्षमता में 30 लाख यूनिट्स का इजाफा करेंगे। एजेंसी के मुताबिक चौपहिया के मामले में ढांचागत विकास और उत्पादन लागत अधिक होने के चलते मुश्किल आ रही है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा और फोर्ड के साझा उपक्रम को मिली अनुमति

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआइ) ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को फोर्ड मोटर के मालिकाना हक वाली कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। इस सौदे के जरिये दोनों कंपनियां भारत में एक साझा उपक्रम लगाएंगी।

सीसीआइ की ओर से जारी वक्तव्य में इस सौदे को मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई। पिछले वर्ष महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इस सौदे की जानकारी दी थी। कंपनी ने अर्डोर ऑटोमोटिव में 51 परसेंट हिस्सेदारी खरीदने की बात कही थी। यह सौदा करीब 657 करोड़ रुपये का है। इसमें फोर्ड इंडिया का चेन्नई स्थित मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट भी शामिल है। गौरतलब है कि अर्डोर ऑटोमोटिव में फोर्ड मोटर की 100 परसेंट हिस्सेदारी थी, जो इस समझौते के बाद घटकर 49 परसेंट रह जाएगी।

ओला ने लंदन में शुरू की कैब सर्विस, 25 हजार ड्राइवर जुड़े

▶ भारतीय कंपनी ने 2018 में ब्रिटेन में की थी परिचालन की शुरुआत

▶ कंपनी ने कहा, वेतन और सुरक्षा से जुड़े स्थानीय मानकों का होगा पालन

लंदन, प्रेट्र : एप के जरिये कैब सेवा मुहैया कराने वाली भारतीय कंपनी ओला ने लंदन में अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। शुरुआती दौर में कंपनी के साथ 25 हजार ड्राइवरों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कंपनी यहां कंफर्ट, कंफर्ट-एक्सएल और एक्सेक राइड श्रेणियों में अपनी सेवाएं दे रही है। ओला इंटरनेशनल के प्रमुख साइमन स्मिथ ने लंदन में सेवा शुरू करने को मील का पत्थर बताते हुए जल्द ही अन्य शहरों में सेवाएं शुरू करने की बात भी कही।

स्मिथ ने कहा कि हम लंदन के लोगों को उच्च गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देंगे। हमारा ध्यान गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता पर रहेगा। गौरतलब है कि ओला ने 2018 में ब्रिटेन में कदम रखा था। कंपनी ने वेल्स और दक्षिण-पश्चिम इंग्लैंड से अपनी सेवाएं शुरू की थीं। कंपनी ने स्थानीय नियमों के मुताबिक अपने चालकों के वेतन और सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने की बात भी कही है।

कंपनी ने बताया कि कैब चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। उनके कौशल को मान्यता देते हुए ड्राइव-टेक परमिट जारी किए गए हैं। ग्राहकों के साथ बेहतर संवाद के लिए लंदन के सभी ओला चालक अंग्रेजी बोलने के टेस्ट से गुजरे हैं। इसके अलावा उन्होंने ओला कस्टमर सर्विस टेस्ट भी पास किया है। कंपनी ने लंदन के अपने शुरुआती ग्राहकों के लिए कुछ ऑफर भी देने की घोषणा की है।

सुधार

चीन के बाजार खुलने से आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद, सेंसेक्स 237 और निफ्टी 76 अंक चढ़कर हुआ बंद

दो दिन की गिरावट से उबरे बाजार

मुंबई, प्रेट्र : पिछले दो दिन की गिरावट से उबरते हुए मंगलवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। सकारात्मक ग्लोबल संकेतों के प्रभाव में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 236.52 अंकों के सुधार के साथ 41,216.14 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाले निफ्टी में 76.40 अंकों की तेजी देखने को मिली। यह 12,107.90 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स पैक में एनटीपीसी, मारुति सुजुकी, पावरग्रिड, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट और एक्सिस बैंक के शेयरों में 2.95 परसेंट तक का उछाल देखने को मिला। दूसरी ओर एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले इंडिया, टीसीएस और सन फार्मा के शेयर 0.75 परसेंट तक की गिरावट के साथ बंद हुए। सेक्टोरल इंडेक्स में यूटिलिटीज, पावर, मेटल, बैंक, हेल्थकेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के स्टॉक्स बढ़त दर्ज करने में सफल रहे। वहीं एफएमसीजी और टेलीकॉम सेक्टर के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस से पीड़ित चीन में नए वर्ष की छुट्टियों के बाद बाजार फिर से खुल गए हैं। इससे निवेशकों में कारोबार पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के रिसर्च हेड विनोद नायर के मुताबिक कोरोना के नए मामलों में कमी के चलते शेयर बाजारों ने राहत की सांस ली है। घरेलू बाजारों में निवेशकों की नजर तीसरी तिमाही के बाकी बचे नतीजों और महंगाई दर पर होगी।

मंगलवार को एशियाई देशों के अन्य शेयर बाजारों में शंघाई, हांगकांग और सियोल हरे निशान पर बंद हुए। यूरोप के शेयर बाजार भी सत्र के शुरुआती कारोबार के दौरान बढ़त दर्ज करने में सफल रहे।

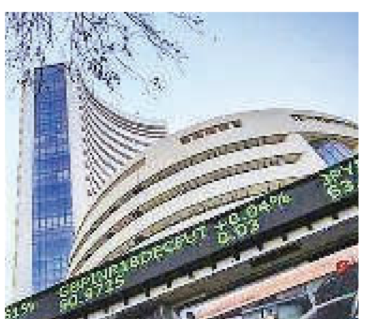

प्रतीकात्मक फोटो

सोना-चांदी के भाव में गिरावट

नई दिल्ली, प्रेट्र : मंगलवार को स्थानीय सराफा बाजारों में गिरावट देखने को मिली। इस दौरान सोना 112 रुपये की गिरावट के साथ 41,269 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। चांदी भी 108 रुपये की गिरकर 47,152 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। जानकारों के मुताबिक घरेलू मांग में कमी और ग्लोबल मार्केट में दबाव के चलते सोने की कीमत में नरमी देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में सोना 1,568 डॉलर और चांदी 17.72 डॉलर प्रति औंस (28.35 ग्राम) के भाव पर बिके।

जनवरी में हुआ गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश

नई दिल्ली, प्रेट्र : ग्लोबल इकोनॉमी में सुस्ती के बीच निवेशकों को सोने में निवेश खूब रास आ रहा है। पिछले महीने गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ईटीएफ) में 200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। यह सात वर्षों का उच्च स्तर है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआइ) के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वर्ष दिसंबर के दौरान 27 करोड़ रुपये गोल्ड इटीएफ में आए थे। इससे पहले नवंबर में 7.68 करोड़ का निवेश इस माध्यम में किया गया था।

दिसंबर, 2012 के दौरान यह 474 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। इस बीच जेम्स ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने बताया है कि पिछले महीने जेम्स ज्वैलरी के निर्यात में 8.45 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान 21,146.59 करोड़ रुपये मूल्य की जेम्स एंड ज्वैलरी का निर्यात किया गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में 23,099.57 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ था।

वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म-22 पर्याप्त : सड़क मंत्रालय

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट होने के बाद भी कई राज्यों में वाहन रजिस्ट्रेशन में होती है देरी

केंद्र सरकार ने नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन में देरी पर संज्ञान लिया है। केंद्र ने निर्माता की ओर से फॉर्म-22 के माध्यम से टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट देने के बावजूद नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ जांच पर जोर को गैरजरूरी बताते हुए राज्यों को ऐसे सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन करने को कहा है। इस संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की गई है।

मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि टेस्टिंग एजेंसियों का वैध टाइप अप्रूवल और फिटनेस सर्टिफिकेट होने के बावजूद कुछ राज्यों में परिवहन विभाग द्वारा फिजिकल इंस्पेक्शन के बिना वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में चार मई, 2017 को एक एडवाइजरी जारी की जा चुकी है। साथ ही संशोधित मोटर एक्ट में भी स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। नवीनतम एडवाइजरी में कहा गया है कि सेंट्रल मोटर रूल्स, 1989 के तहत सूचीबद्ध सभी टेस्ट एजेंसियां नए वाहन मॉडलों के प्रोटोटाइप की जांच कर टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। ये प्रोटोटाइप मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में उल्लेखित तकनीकी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करते हैं।

सेंट्रल मोटर रूल्स, 1989 के नियम 47 के तहत वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए प्रत्येक वाहन निर्माता को फॉर्म-22 भरना पड़ता है। यह फॉर्म सुनिश्चित करता है कि वाहन के कलपुर्जे सुरक्षा तथा प्रदूषण मानकों के अनुरूप हैं और वाहन सड़क पर चलाए जाने के लिए उपयुक्त है। ऐसे में निर्माता द्वारा प्रदत्त फॉर्म-22 को रजिस्ट्रेशन के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए।

100 साल में दूसरी बार बर्फबारी देखी है इराक की राजधानी बगदाद के निवासियों ने मंगलवार को। इसके पहले वर्ष 2008 में ऐसा मौका आया था। दरअसल, इराक में बर्फबारी आमतौर पर उत्तरी हिस्से खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में होती है।

डब्ल्यूएचओ ने कोरोना वायरस को बताया दुनिया का गंभीर खतरा

महामारी का प्रकोप ▸ चीन में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 1000 के पार पहुंचा

42 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित, दो वरिष्ठ अधिकारियों पर गिरी गाज

बीजिंग, एजेंसियां : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चीन में फैले कोरोना वायरस से दुनिया को गंभीर खतरा बताया है। चीन में इस रहस्यमय वायरस की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या एक हजार के पार हो गई है। अब तक 42 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। चीन की सरकार ने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हुबेई प्रांत के दो वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। इसी प्रांत की राजधानी वुहान से पूरे चीन समेत दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में वायरस फैल चुका है। चीन के एक विशेषज्ञ का कहना है कि कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन इसका प्रभाव अप्रैल से पहले खत्म होने की उम्मीद नहीं है। वहीं, विश्व बैंक ने कहा है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए वह चीन को कर्ज देने के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा। चीन अपने संसाधनों के दम पर ही इस बीमारी से लड़ने में सक्षम है।

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार, कोरोना वायरस की चपेट में आकर दम तोड़ने वालों की संख्या बढ़कर 1,017 हो गई है। 2,478 नए मामले सामने आए हैं, जिन्हें मिलाकर संक्रमित लोगों का आंकड़ा 42,708 हो गया है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की हुबेई इकाई के हवाले से बताया कि राज्य में पार्टी के स्वास्थ्य आयोग के प्रमुख झांग जिन और निदेशक लियू यिंगजी को सोमवार को बर्खास्त कर दिया गया। कोरोना वायरस से निपटने में असमर्थता को लेकर राज्य के अधिकारियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वायरस की सबसे पहले चेतावनी देने वाले वुहान के डॉक्टर ली वेनलियांग की गत गुरुवार को हुई मौत के बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। ली ने जनवरी के शुरू में ही वायरस की चेतावनी दी थी, लेकिन उस समय पुलिस ने चेतावनी को अफवाह मानकर कार्रवाई की धमकी दी थी।

वायरस पर डब्ल्यूएचओ की बैठक : कोरोना वायरस को लेकर डब्ल्यूएचओ की मंगलवार से जेनेवा में दो दिनी बैठक शुरू हुई। इस बैठक में वायरस से निपटने के लिए दवाओं, जांच और वैक्सीन के विकास में तेजी लाने पर चर्चा चल रही है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने बैठक में शामिल 400 से ज्यादा शोधकर्ताओं से कहा, 'चीन में 99 फीसद मामले सामने आने से ना सिर्फ इस देश बल्कि बाकी दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है।'

हांगकांग में खाली कराई गई 35 मंजिली इमारत : उधर एएफपी के हवाले से बताया गया है कि हांगकांग में कोरोना के चलते 35 मंजिली इमारत के एक ब्लॉक को खाली कराया गया है। इस ब्लॉक में 100 से ज्यादा लोग रहते थे।

हांगकांग में भी फैल रहा कोरोना : हांगकांग में एक हाउसिंग बिल्डिंग से पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी यहां रहने वाले लोगों के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। यहां इस तरह की चार इमारतों में कई लोगों के कोरोना से संक्रमित होने का मामला सामने आया है। जिसके बाद प्रशासन स्वस्थ लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। रायटर

कोरोना वायरस को दिया गया 'कोविड-19' नाम

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मंगलवार को कहा कि घातक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम 'कोविड-19' होगा। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम ने जेनेवा में संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि 'को' का मतलब 'कोरोना', 'वि' का मतलब 'वायरस' और ''डी'' का मतलब ''डिसीज'' (बीमारी) है।

'चिकन खाना है सुरक्षित'

नई दिल्ली, आइएएनएस : केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चिकन खाना सुरक्षित है क्योंकि वायरस के प्रसार में अभी तक उसकी संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। पशुपालन आयुक्त प्रवीण मलिक ने पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के सलाहकार विजय सरदाना को पत्र लिखकर कहा है कि वैश्विक स्तर पर किसी भी रिपोर्ट में कोरोना वायरस के प्रसार में मुर्गियों की संलिप्तता नहीं पाई गई है। दरअसल, सरदाना ने एक ईमेल भेजकर 'कोरोना वायरस' के संदर्भ में मवेशी उत्पादों के उपभोग लेकर स्पष्टीकरण की मांग की थी। मलिक ने जवाब में यह भी कहा, 'इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोरोना वायरस के प्रसार का प्रमुख जरिया मनुष्य से मनुष्य है।'

अब क्रूज में उतरेगी जापानी सेना

संतोष शुक्ल, मेरठ

कोरोना वायरस से मची दहशत के बीच जापान की सेना देवदूत बनकर बुधवार को पहली बार क्रूज में उतरने जा रही है। यात्रियों को दवा, मास्क और लिप बाम समेत जरूरी उपकरण भी देगी। बता दें कि मेरठ के पीयूष के पत्र के बाद भारतीय राजदूत की अपील पर जापानी सरकार हरकत में आई। पीयूष ने भारत के राजदूत अनिल कालरा से फोन पर भी बात की है।

सेना रोकेगी संक्रमण : भारत से हांगकांग होकर जापान पहुंचा क्रूज 25 जनवरी को योकोहामा तट पर रोक दिया गया था। इसमें मेरठ के साफ्टवेयर इंजीनियर पीयूष वशिष्ठ भी फंसे हुए हैं। मंगलवार को दैनिक जागरण से चैट में पीयूष ने बताया कि क्रूज में 130 से ज्यादा मरीज मिलने के बाद यात्रियों में अफरातफरी मच गई है। नमी वाले वातावरण में वायरस तेजी से फैलता है। क्रूज में रोजाना एंटी बैक्टीरियल विलयन का छिड़काव किया जा रहा है।

अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर एक प्रोमोबोट रोबोट लोगों को कोरोना वायरस से बचाव और उसके संक्रमित होने के लक्षणों की जानकारी दे रहा है। रोबोट पर लगी टच स्क्रीन पर कुछ सवालों की फेहरिस्त आती है। जिज्ञासु व्यक्ति के सवालों पर क्लिक करने पर यह जानकारी देता है। रायटर

न्यूज गैलरी

थेइ योंग हो। फाइल/एपी

उत्तर कोरिया के पूर्व राजनयिक द. कोरिया में लड़ेंगे चुनाव

सियोल : उत्तर कोरिया के पूर्व राजनयिक थेइ योंग हो ने मंगलवार को दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह अपने नए घर में अपनी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता का प्रदर्शन करेंगे। ब्रिटेन में उत्तर कोरिया के उप उच्चायुक्त रहे योंग ने अगस्त, 2016 में अपना पद छोड़कर दक्षिण कोरिया में शरण ले ली थी। योंग दक्षिण कोरिया के प्रमुख विपक्षी दल लिबर्टी कोरिया पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। योंग का कहना है कि उनकी जीत से उत्तर कोरिया के लोगों का उत्साह बढ़ेगा। साथ ही उत्तर और दक्षिण कोरिया के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा। योंग ने कहा, मैं उत्तर कोरिया की सरकार और व्यवस्था के बारे में किसी अन्य से ज्यादा जानता हूं। परमाणु हथियार संपन्न उत्तर कोरिया गरीबी की मार झेल रहा है। इसके बावजूद वह दक्षिण कोरिया के साथ हमेशा युद्ध की इच्छा रखता है। (एएफपी)

फिलीपींस में तस्करी में घिरे मेयर की गोली मारकर हत्या

मनीला : फिलीपींस में सुल्तान सुमाग्का नगरपालिका के मेयर अब्दुल वहाब सबाल (45) की सोमवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। ड्रग तस्करी के आरोप में घिरे अब्दुल का नाम उस सूची में शामिल रहा है, जिसे खुद राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के कहने पर तैयार किया गया है। सोमवार को राजधानी मनीला में अब्दुल को उस वक्त गोली मारी गई, जब वह पत्नी और सुरक्षाकर्मी के साथ एक होटल में प्रवेश करने वाले थे। फिलीपींस में मादक पदार्थों की तस्करी को खत्म करने को लेकर राष्ट्रपति दुतेर्ते का 2016 से विशेष अभियान चल रहा है। इसके तहत देश में अभी तक कम से कम 18 काउंसलर और मेयरों की हत्या की जा चुकी है। इनमें से अधिकतर का नाम दुतेर्ते द्वारा तैयार सूची में शामिल रहा है। मानवाधिकार संस्थाएं इसे दुतेर्ते सरकार के इशारे पर की जाने वाली गैरकानूनी हत्या बताती हैं। पुलिस के मुताबिक, देश में ड्रग तस्करी में शामिल 7,000 अपराधियों का सफाया किया जा चुका है। मानवाधिकार संस्थाएं हालांकि इन हत्याओं की तादाद 30,000 बताती हैं। (आइएएनएस)

ट्रंप ने प्रस्तावित किया 52 लाख करोड़ का रक्षा बजट

वाशिंगटन, प्रेट्र : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का रक्षा बजट 740 अरब डॉलर (करीब 52 लाख करोड़ रुपये) करने का प्रस्ताव रखा है। माना जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका को चीन और रूस से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर सेना के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए रक्षा बजट में भारी इजाफा किया है। वर्ष 2021 के रक्षा बजट में परमाणु आधुनिकीकरण के लिए 28.9 अरब डॉलर खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया गया है। उन्होंने अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए 18 अरब डॉलर, साइबर के लिए दस अरब डॉलर और हवाई क्षेत्र के लिए 57 अरब डॉलर प्रस्तावित किए हैं।

संसद में प्रस्ताव पर होगी बहस : भारत में वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करते हैं। लेकिन अमेरिका में इससे बिल्कुल अलग राष्ट्रपति बजट का प्रस्ताव जारी करते हैं। यह प्रस्ताव संसद के पास भेजा जाता है। संसद में लंबी बहस के बाद इस पर मतदान होता है।

नासा का बजट बढ़ाने की मांग : ह्वाइट हाउस ने संसद से अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के बजट को 25 अरब डॉलर (करीब 1.78 लाख करोड़ रुपये) करने की मांग की है। इस एजेंसी के बजट में पिछले कई साल से गिरावट हो रही है। बजट का बड़ा हिस्सा नासा के चंद्र और मंगल अभियानों पर खर्च किए जाने का अनुमान है।

12.6 लाख करोड़ रुपये रहा चीन का रक्षा बजट 2019 में

3.37 लाख करोड़ रुपये है 2020-21 के लिए भारत का रक्षा बजट

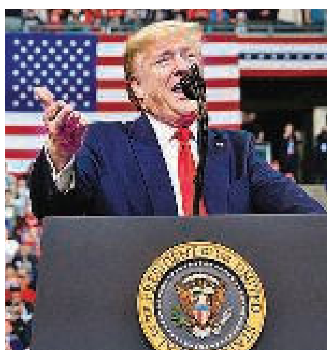

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। रायटर

अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के लिए खतरा है आइएस : यूएन

▸ इसकी दक्षिण एशिया शाखा ने टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों के साथ बनाए संपर्क

▸ अफगानी सुरक्षा बलों के दबाव के बावजूद कर रहा भर्तियां

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस्लामिक स्टेट (आइएस) की दक्षिण एशिया शाखा अभी भी सक्रिय और खतरनाक है और उसने तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) जैसे अन्य आतंकी संगठनों के साथ संपर्क बना लिए हैं। इसमें अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों में सुरक्षा वातावरण को खराब करने की क्षमता है।

इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट-खोरासन (आइएसआइएल-के) का गठन 10 जनवरी, 2015 को टीटीपी के पूर्व कमांडर और स्थापना तालिबान गुट के पूर्व कमांडरों ने की थी जिन्होंने आइएस और उसके मारे गए नेता अबु बकर अल बगदादी के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। इस समूह ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। आइएसआइएल-के से अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरे और सदस्यों देशों में इस खतरे का सामना करने में संयुक्त राष्ट्र की मदद की कोशिशों पर महासचिव की 10वीं रिपोर्ट के मुताबिक, आइएसआइएल-के 2019 के आखिर तक अफगानी सुरक्षा बलों और तालिबानी लड़ाकों के जबर्दस्त दबाव में आ गया जिसकी वजह से उसे एक तरह से अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत स्थित अपने मुख्यालय से हटना पड़ा।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में आतंकी संगठनों के विस्तार पर चिंता जताई गई है। प्रतीकात्मक

रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही अफगानी अधिकारियों ने आइएसआइएल-के लड़ाकों समेत 1,400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया हो, फिर भी यह आतंकी समूह क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। इसने ऑनलाइन भर्तियां और दुष्प्रचार जारी रखा हुआ है और इसके लिए यह काबुल यूनिवर्सिटी समेत धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों में अपनी गतिविधियों का आयोजन भी करता है। इसने जमात उल अहरार, तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान और लश्कर ए इस्लाम समेत अन्य आतंकी संगठनों के साथ अनौपचारिक संपर्क स्थापित कर लिया है जो पाकिस्तान की सीमा चौकियों पर निरंतर हमले करते रहते हैं। हिरासत में लिए गए आइएलआइएल-के के ज्यादातर लड़ाकों में अफगानी नागरिक थे, लेकिन इनमें अजरबैजान, कनाडा, फ्रांस, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की और उज्बेकिस्तान के नागरिक भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इस समूह के लड़ाकों की संख्या और उनके भौगोलिक फैलाव का असर उल्लेखनीय है। इस समय कुनार प्रांत में समूह के करीब 2,100 लड़ाके हैं जो अफगानिस्तान में उसका कोर क्षेत्र बन गया है। अफगानिस्तान के अन्य इलाकों में उसके करीब 400 लड़ाके हैं। लिहाजा पूरे देश में उनकी कुल संख्या करीब 2,500 है। पूर्व तालिबानी सदस्य कारी सलाहुद्दीन के नेतृत्व में करीब 25 सदस्यों का संगठन फरयाब प्रांत में खुफिया रूप से मौजूद है।

सुरक्षा परिषद की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति ने पिछले साल मई में आइएसआइएल-के को काली सूची में डाल दिया था जिसे आइएसआइएल दक्षिण एशिया शाखा, आइएसआइएल खोरासन, इस्लामिक स्टेट का खोरासन प्रांत और आइएसआइएल का दक्षिण एशिया चैप्टर भी कहा जाता है।

वाशिंगटन स्थित गैरलाभकारी नीति अनुसंधान संगठन 'सेंटर फॉर स्ट्रैटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज' की वेबसाइट पर आइएसआइएल की आतंकी पृष्ठभूमि के मुताबिक, 2014 में पाकिस्तानी नागरिक हाफिज सईद खान को इसका पहली अमीर चुना गया था। टीटीपी का वरिष्ठ कमांडर हाफिज कई अन्य प्रमुख टीटीपी सदस्यों को साथ लाने में सफल रहा था। इनमें समूह का प्रवक्ता शेख मकबूल व कई जिला प्रमुख शामिल हैं।

बंगाल की खाड़ी में डूबी रोहिंग्याओं से भरी नौका

बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविरों में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों से भरी एक नौका मंगलवार सुबह बंगाल की खाड़ी में डूब गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। बांग्लादेश के तटरक्षक दल के प्रवक्ता हमीदुल इस्लाम के अनुसार, मलेशिया जा रही मछली पकड़ने वाली नौका में करीब 130 लोग सवार थे। राहत और बचाव अभियान के तहत 70 लोगों को बचा लिया गया। बाकी की तलाश जारी है। इस तस्वीर में हादसे के बाद बचाए गए बच्चे का उपचार किया जा रहा है। एपी

करतारपुर साहिब जाएंगे यूएन महासचिव गुतेरस

संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : अगले हफ्ते पाकिस्तान की यात्रा के दौरान संयुक्त राष्ट्र (यूएन) महासचिव एंटोनियो गुतेरस करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने करतारपुर में अपनी जिंदगी के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।

पिछले साल नवंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे की शुरुआत को लेकर यूएन महासचिव ने प्रसन्नता जताई थी। उन्होंने इसे विभिन्न धर्मों के बीच समरसता और आपसी समझ को बढ़ाने वाला कदम बताया था। 4.7 किलोमीटर लंबा यह गलियारा पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरुदासपुर जिले स्थित डेरा बाबा नानक को जोड़ता है।

यूएन प्रवक्ता फरहान हक ने सोमवार को बताया कि यूएन महासचिव अफगान शरणार्थियों को आश्रय दिए जाने के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पाकिस्तान में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। रविवार को इस्लामाबाद पहुंचने के बाद वह प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ बैठक भी करेंगे।

अफगानिस्तान में सैन्य अकादमी पर आत्मघाती हमला, पांच की मौत

काबुल, एएफपी : अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार सुबह एक सैन्य अकादमी के बाहर आत्मघाती हमले में पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में चार सैन्यकर्मी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमले में छह लोग घायल भी हुए हैं।

करीब तीन माह की शांति के बाद अफगानिस्तान की राजधानी में हुई इस आतंकी वारदात की अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। आतंकी संगठन तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा, हमें इस हमले की कोई जानकारी नहीं है। हम इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हमलावर मार्शल फहीम सैन्य अकादमी को निशाना बनाने आया था। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, आत्मघाती हमलावर पैदल था। जांच चौकी के पास अकादमी के अंदर जा रहे एक वाहन से टकराकर उसने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया।

यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अफगानिस्तान में संघर्ष विराम के लिए अमेरिका, तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश में लगा है। हमले की निंदा करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि यह मानवता के खिलाफ अपराध है। काबुल में इससे पहले गत नवंबर में आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले से शांति के प्रयासों को फिर झटका लग सकता है।

अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार को मिलिट्री एकेडमी को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले के बाद घटनास्थल पर बिलखता पीड़ित। इस बम विस्फोट में एक नागरिक समेत चार सैन्यकर्मियों की मौत हो गई। रायटर

सच आया सामने

ईरानी मिसाइल हमले में घायल हुए थे 109 अमेरिकी सैनिक

हमले के एक माह बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने की पुष्टि, कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने किया था हमला

न्यूयॉर्क टाइम्स से

वाशिंगटन : इराक स्थित अमेरिका के दो सैन्य ठिकानों पर ईरान की ओर से किए गए हमले को एक माह से ज्यादा का वक्त गुजर गया है। अब सामने आया है कि हमले के चलते अल-असद एयर बेस में 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक दिमागी चोट ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी (टीबीआइ) से पीड़ित पाए गए हैं। ईरान ने अपने शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए गत आठ जनवरी को अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइलें दागी थीं। सुलेमानी की तीन जनवरी को बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी।

अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की प्रेस सचिव एलिसा फराह ने सोमवार को यहां कहा, 'अब तक 109 अमेरिकी सैनिक मामूली तौर पर दिमागी चोट से पीड़ित पाए जा चुके हैं। पीड़ित सैनिकों में से 76 ड्यूटी पर लौट आए हैं और बाकी का उपचार चल रहा है। इसके लिए हम अपने चिकित्सा पेशेवरों के आभारी हैं, जो हमारे सैनिकों की उचित देखभाल सुनिश्चित कर रहे हैं।' ईरान के हमले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोई अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ, सिर्फ सैन्य ठिकानों को कुछ नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी अधिकारियों ने हालांकि बाद में माना था कि हमले में 11 सैनिक घायल हुए हैं।

इन सैन्य ठिकानों को बनाया था निशाना : ईरान ने इराक में अल-असद एयर बेस के अलावा एक अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया था। दोनों सैन्य ठिकाने पर 22 मिसाइलें दागी गई थीं। ईरान ने इस हमले में 80 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था। हमले के वक्त असद एयर बेस में करीब 1500 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे। लेकिन हमले की पूर्व चेतावनी के चलते उन्हें बंकरों में पहुंचा दिया गया था।

क्या है टीबीआइ : ट्रॉमैटिक ब्रेन इंजरी (टीबीआइ) एक तरह की दिमागी चोट है। यह किसी दुर्घटना, गिरने, हिंसा और धमाके के चलते लग सकती है। इसके चलते भ्रम, धुंधला दिखना और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समस्या बढ़ने पर अक्षमता या मौत भी हो सकती है।

इराक स्थित अमेरिका के दो सैन्य ठिकानों पर बीते माह ईरान ने मिसाइलों से हमला किया था। फाइल

झूठ बोलने पर ट्रंप के करीबी को नौ साल जेल की मांग

▸ रूसी दखल मामले में दोषी करार रोजर स्टोन को 20 फरवरी को होनी है सजा

वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिकी अभियोजकों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लंबे समय से करीबी सहयोगी रहे रोजर स्टोन को संसद से झूठ बोलने के मामले में नौ साल तक की जेल की सजा देने की मांग की है। अमेरिका में 2016 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रूसी दखल मामले में स्टोन को गत नवंबर में दोषी करार दिया गया था। सजा का एलान 20 फरवरी को किया जाएगा।

रूसी दखल मामले की जांच करने वाले विशेष वकील रॉबर्ट मुलर द्वारा आरोपित किए जाने के बाद स्टोन को पिछले साल जनवरी में फ्लोरिडा स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया था। स्टोन पर संसद से झूठ बोलने और गवाहों को धमकाने के आरोप थे। अभियोजकों ने अपनी दलील में कहा कि स्टोन ने अच्छे बर्ताव का प्रदर्शन नहीं किया। स्टोन ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया था। जबकि अभियोजकों का कहना था कि स्टोन ने झूठ बोला और ट्रंप को बचाने के लिए गवाहों को धमकाया। स्टोन को गत नवंबर में जब दोषी करार दिया गया था, तब ट्रंप ने ट्वीट में कहा था, 'मैंने अपने देश के इतिहास में इस तरह का दोहरा मानदंड कभी नहीं देखा।'

ट्रंप के कैसिनो कारोबार के लिए करते थे लॉबिंग

67 वर्षीय स्टोन ने पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के राजनीतिक सहयोगी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। स्टोन ने कई साल तक ट्रंप के कैसिनो कारोबार के लिए लॉबिंग भी की थी। आरोप तो यहां तक लगाया गया था कि 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनके रूसी हैकरों से संबंध थे।

ये भी जानिए
भारतीय कप्तान विराट कोहली सीरीज में सिर्फ 75 रन बना सके। यह जून 2015 के बाद द्विपक्षीय वनडे सीरीज में उनका सबसे खराब प्रदर्शन है। तब उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों में 49 रन बनाए थे।

31 साल बाद भारत का सूपड़ा साफ

- तीसरा और अंतिम वनडे मैच पांच विकेट से जीता न्यूजीलैंड
- राहुल के शतक पर भारी पड़ी निकोल्स की 80 रन की पारी

माउंट मौंगानुई (न्यूजीलैंड), प्रेट्र: न्यूजीलैंड ने यहां तीसरे व अंतिम वनडे मैच में भारत को पांच विकेट से हराकर सीरीज 3-0 से अपने नाम की, जिसके चलते भारत को पिछले तीन दशक से ज्यादा समय बाद तीन या उससे ज्यादा मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। पिछले 31 साल में भारत का यह किसी ऐसी वनडे सीरीज में पहली बार 'सूपड़ा साफ' है, जिसके सभी मैच खेले गए। भारतीय टीम को पिछली बार 1989 में कैरेबियाई दौरे पर वेस्टइंडीज के हाथों 0-5 से क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। इत्तेफाक से भारत को इस परिणाम का सामना तब करना पड़ा है जब कुछ दिन पहले ही भारत ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज में न्यूजीलैंड का सफाया किया था।

भारत ने 296 रन बनाए: पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने के बाद भारत ने 50 ओवर में सात विकेट पर 296 रन का स्कोर किया। भारत को इस स्कोर तक पहुंचाने में केएल राहुल की अहम भूमिका रही, जिन्होंने वनडे करियर का अपना चौथा शतक जड़ते हुए 112 रन की पारी खेली। जवाब में न्यूजीलैंड ने 47.1 ओवर में पांच विकेट पर 300 रन बनाकर जीत अपने नाम की। हेनरी निकोल्स ने 103 गेंद में 80 और मार्टिन गुप्टिल ने 46 गेंद में 66 रन की पारी खेली। उनके अलावा निचले क्रम में कोलिन डि ग्रैंडहोम ने 28 गेंद में नाबाद 58 रन बनाते हुए 17 गेंद बाकी रहते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई।

मयंक हुए फेल: भारतीय टीम की शुरुआत फिर खराब रही। काइली जेमिसन (1/53) ने सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल (01) को आउट किया। सातवें ओवर में भारत को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कप्तान विराट कोहली (09) हैमिस बेनेट (4/64) की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ ने 42 गेंद में 40 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और दो छक्के शामिल थे, लेकिन वह 13वें ओवर में रन आउट हो गए। इस तरह भारत ने 13वें ओवर में तीन विकेट 62 रन पर गंवा दिए थे, लेकिन राहुल ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। दोनों ने डटकर बल्लेबाजी की। अय्यर ने 52 गेंद में 50 रन पूरे किए, जो इस सीरीज में उनका तीसरा 50 से अधिक का स्कोर है। अय्यर को जिमी नीशाम (1/50) ने पवेलियन भेजा। अय्यर ने 63 गेंद में 62 रन की पारी खेली। उन्होंने राहुल के साथ चौथे विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की।

राहुल की उम्दा बल्लेबाजी: इसके बाद राहुल ने 66 गेंद में 50 रन पूरे किए। राहुल ने मनीष पांडे के साथ पांचवें विकेट के लिए 107 रन की साझेदारी निभाई। उन्होंने केदार जाधव की जगह मौका पाने वाले मनीष पांडे के साथ मिलकर भारत को 45वें ओवर में 250 रन तक पहुंचाया। पांडे ने 48 गेंद में 42 रन बनाए। उन्हें बेनेट ने पवेलियन भेजा। राहुल का शतक 104 गेंदों में पूरा हुआ। उन्होंने कुल 113 गेंद में नौ चौकों और दो छक्कों की मदद से 112 रन बनाए। भारतीय टीम ने अंतिम ओवरों में 27 रन के भीतर तीन विकेट गंवाए, जिसकी वजह से टीम 300 रन पार नहीं कर सकी।

कीवियों की तेज शुरुआत: जीत के लिए 297 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत शानदार रही। गुप्टिल और निकोल्स ने पहले विकेट के लिए 40 गेंद में ही 50 रन की साझेदारी कर डाली। कुल मिलाकर दोनों ने पहले विकेट के लिए 106 रन की साझेदारी की। भारत की ओर से नई गेंद के तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर (1/87) और नवदीप सैनी (0/68) काफी महंगे साबित हुए और अपनी लय पाने के लिए संघर्ष करते रहे। वहीं, जसप्रीत बुमराह (0/50) को पूरी सीरीज में कोई भी विकेट नहीं मिला। युजवेंद्रा सिंह चहल (3/47) ने 17वें ओवर में गुप्टिल को बोल्ड कर साझेदारी तोड़ी। गुप्टिल ने अपनी पारी में छह चौके और चार छक्के जड़े। दूसरे छोर से मैन ऑफ द मैच निकोल्स ने कीवी पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए 72 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने चोट से उबरकर वापसी करने वाले केन विलियमसन (22) के साथ 53 रन की साझेदारी की। चहल ने विलियमसन को मयंक के हाथों कैच कराकर इस साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद रवींद्र जडेजा (1/45) ने फॉर्म में चल रहे रॉस टेलर (12) को भी सस्ते में चलता किया। टेलर इस सीरीज में पहली बार आउट हुए और उन्होंने इस सीरीज की तीन पारियों में कुल 194 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन आफ द सीरीज चुना गया।

विस्फोटक ग्रैंडहोम: एक छोर पर जमे निकोल्स को शार्दुल ने राहुल के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। निकोल्स के आउट होने से 33वें ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर चार विकेट पर 189 रन हो गया। इसके बाद जिमी नीशाम (19) भी कुछ खास नहीं कर सके और चहल ने उन्हें आउट कर अपना तीसरा विकेट झटका। नीशाम के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड को जीत के लिए 63 गेंदों पर 77 रन की जरूरत थी और उसके पांच विकेट बाकी थे। यहां से भारत वापसी करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसे में डि ग्रैंडहोम ने विस्फोटक पारी खेलते हुए 21 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने टॉम लाथम (नाबाद 32) के साथ सिर्फ 46 गेंदों पर 80 रन की अटूट साझेदारी कर भारत के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ग्रैंडहोम ने अपनी 28 गेंदों की पारी में छह चौके और तीन छक्के लगाए। सीरीज में भारत की फील्डिंग एक बार फिर लचर रही और वे कीवी बल्लेबाजों पर दबाव नहीं बना सके। जिससे नतीजा यह रहा कि न्यूजीलैंड की टीम ने पूरे मैच में पकड़ बनाए रखी।

भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज मंगलवार को 3-0 से जीतने के बाद खिताबी ट्रॉफी के साथ न्यूजीलैंड की टीम के खिलाड़ी और सदस्य • एएनआइ

स्कोर बोर्ड

टॉस: न्यूजीलैंड (गेंदबाजी)
परिणाम: न्यूजीलैंड पांच विकेट से जीता
मैन ऑफ द मैच: हेनरी निकोल्स
मैन ऑफ द सीरीज: रॉस टेलर

भारत 296/7 (50 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
पृथ्वी रन आउट (डि ग्रैंडहोम/लाथम)	40	42	03	02
मयंक अग्रवाल बो. जेमिसन	01	03	00	00
विराट कोहली का. जेमिसन बो. बेनेट	09	12	00	01
श्रेयस का. डि ग्रैंडहोम बो. नीशाम	62	63	09	00
लोकेश राहुल का. जेमिसन बो. बेनेट	112	113	09	02
मनीष पांडे का. सेंटनर बो. बेनेट	42	48	02	00
रवींद्र जडेजा नाबाद	08	07	01	00
शार्दुल का. डि ग्रैंडहोम बो. बेनेट	07	06	01	00
नवदीप सैनी नाबाद	08	06	02	00

अतिरिक्त: (बा–1, वा–6) 7
कुल: 50 ओवर में सात विकेट पर 296 रन

विकेट पतन: 1–8 (मयंक, 1.6), 2–32 (कोहली, 6.4), 3–62 (शॉ, 12.1), 4–162 (अय्यर, 30.3), 5–269 (राहुल, 46.4), 6–269 (पांडे, 46.5), 7–280 (शार्दुल, 48.2)
गेंदबाजी: टिम साउथी 9–0–59–0, काइली जेमिसन 10–0–53–1, हैमिश बेनेट 10–1–64–4, कोलिन डि ग्रैंडहोम 3–0–10–0, जिमी नीशाम 8–0–50–1, मिशेल सेंटनर 10–0–59–0

न्यूजीलैंड 300/5 (47.1 ओवर)

	रन	गेंद	चौके	छक्के
मार्टिन गुप्टिल बो. चहल	66	46	06	04
हेनरी निकोल्स का. राहुल बो. ठाकुर	80	103	09	00
विलियमसन का. अग्रवाल बो. चहल	22	31	02	00
रॉस टेलर का. कोहली बो. जडेजा	12	18	01	00
टॉम लाथम नाबाद	32	34	03	00
जिमी नीशाम का. कोहली बो. चहल	19	25	01	01
कोलिन डि ग्रैंडहोम नाबाद	58	28	06	03

अतिरिक्त: (बा–1, लेबा–2, नोबॉ–2, वा–6) 11
कुल: 47.1 ओवर में पांच विकेट पर 300 रन

विकेट पतन: 1–106 (गुप्टिल, 16.3), 2–159 (विलियमसन, 27.1), 3–186 (टेलर, 31.5), 4–189 (निकोल्स, 32.5), 5–220 (नीशाम, 39.3)
गेंदबाजी: जसप्रीत बुमराह 10–0–50–0, नवदीप सैनी 8–0–68–0, चहल 10–1–47–3, शार्दुल ठाकुर 9.1–0–87–1, रवींद्र जडेजा 10–0–45–1

वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने किया क्लीन स्वीप

बनाम	मेजबान	जीत का अंतर	साल
भारत	न्यूजीलैंड	2–0	1976
भारत	न्यूजीलैंड	2–0	1981
इंग्लैंड	न्यूजीलैंड	3–0	1983
श्रीलंका	न्यूजीलैंड	3–0	1983
श्रीलंका	न्यूजीलैंड	3–0	1991
जिंबाब्वे	जिंबाब्वे	2–0	1992
वेस्टइंडीज	न्यूजीलैंड	5–0	2000
बांग्लादेश	बांग्लादेश	3–0	2004
ऑस्ट्रेलिया	न्यूजीलैंड	3–0	2007
बांग्लादेश	न्यूजीलैंड	3–0	2007
बांग्लादेश	न्यूजीलैंड	3–0	2010
जिंबाब्वे	न्यूजीलैंड	3–0	2012
पाकिस्तान	न्यूजीलैंड	2–0	2015
बांग्लादेश	न्यूजीलैंड	3–0	2016
वेस्टइंडीज	न्यूजीलैंड	3–0	2017
पाकिस्तान	न्यूजीलैंड	5–0	2018
श्रीलंका	न्यूजीलैंड	3–0	2019
बांग्लादेश	न्यूजीलैंड	3–0	2019
भारत	न्यूजीलैंड	3–0	2020

वनडे सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ

विजेता	मेजबान	हार का अंतर	साल
इंग्लैंड	इंग्लैंड	0–2	1974
न्यूजीलैंड	न्यूजीलैंड	0–2	1976
न्यूजीलैंड	न्यूजीलैंड	0–2	1981
इंग्लैंड	इंग्लैंड	0–2	1982
वेस्टइंडीज	भारत	0–5	1983
वेस्टइंडीज	वेस्टइंडीज	0–5	1989
न्यूजीलैंड	न्यूजीलैंड	0–3	2020

यह शानदार प्रदर्शन था। बेहद शानदार। भारत ने हमें दबाव में डाला, लेकिन हमारे खिलाड़ी गेंद और बल्ले से वापसी करने में सफल रहे। भारत के इस दौरे का दूसरा भाग हमारे लिए अच्छा रहा। हमें पता है वे हर प्रारूप में बेहतरीन टीम है, लेकिन हमारे लिए खिलाड़ियों के काम को लेकर स्पष्टता जरूरी थी।
केन विलियमसन, कप्तान, न्यूजीलैंड

टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में हारने के बाद 3-0 की जीत के साथ वापसी करना अच्छा रहा। जिस तरह से मार्टिन गुप्टिल ने बल्लेबाजी की उससे हमें काफी मदद मिली। हमारी किस्मत अच्छी थी कि इस सीरीज में हमें अच्छी शुरुआत मिली।
हेनरी निकोल्स, मैन ऑफ द मैच

कुल मिलाकर अगर आप देखो तो पिछले चार-पांच साल में हमने सिर्फ चौथी या पांचवीं सीरीज गंवाई है। दूसरी टीम भी खेलती हैं। आप प्रत्येक मैच नहीं जीत सकते। हमने एक सीरीज जीती, दूसरी हार गए। इसलिए यह इतना गंभीर नहीं है।
युजवेंद्रा सिंह चहल, लेग स्पिनर, भारत

विराट कोहली बोले, हम वनडे सीरीज में जीत के हकदार नहीं थे

माउंट मौंगानुई, प्रेट्र: भारतीय कप्तान विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद मंगलवार को यहां खराब गेंदबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीम में धैर्य की कमी दिखी। कोहली ने मैच के बाद कहा, 'हम उतना खराब भी नहीं खेले जैसा कि सीरीज के अंतिम परिणाम में दिख रहा है। हमें जो मौके मिले हम उसे भुनाने में नाकाम रहे। हमारे प्रयास अंतरराष्ट्रीय मैच को जीतने के लिए काफी नहीं थे। गेंद से हम नियमित अंतराल पर विकेट चटकाने में नाकाम रहे। हमारा क्षेत्ररक्षण बिलकुल भी अच्छा नहीं रहा। हम इतना बुरा भी नहीं खेले, लेकिन जब आप मौके भुनाने में नाकाम रहेंगे तो फिर आप जीत के हकदार नहीं रहते। बल्लेबाजों ने कठिन परिस्थितियों से अच्छी वापसी की, लेकिन हमने जिस तरह से क्षेत्ररक्षण और गेंदबाजी की वह जीत के लिए काफी नहीं था।' सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की नाकामी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सीरीज में एक विकेट भी नहीं ले सके। कोहली ने न्यूजीलैंड की तारीफ करते हुए कहा, 'न्यूजीलैंड ने शानदार तरीके से खेला। हम जीत के हकदार नहीं थे, क्योंकि हमने धैर्य नहीं दिखाया।' भारतीय बल्लेबाजी की धुरी माने जाने वाले कोहली ने कहा कि टीम इस निराशा की भरपाई 21 फरवरी से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज में करेगी।

दो भारतीय व तीन बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर कार्रवाई

दुबई, प्रेट्र: अंडर-19 विश्व कप फाइनल के बाद हुई अप्रिय घटनाओं के लिए आइसीसी ने भारत के दो खिलाड़ियों आकाश सिंह और रवि बिश्नोई के अलावा तीन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को दोषी ठहराया है। बांग्लादेश के मुहम्मद तौहीद, शमीम हुसैन और रकीबुल हसन को आइसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया। सभी खिलाड़ियों ने अपनी गलती मान ली है और उनको निलंबन अंक मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर-19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश की भारत पर तीन विकेट से जीत के बाद दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ियों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी।

आइसीसी ने अनुसार, 'पांच क्रिकेटरों को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को आइसीसी की आचार संहिता के लेवल-3 के उल्लंघन का दोषी पाया गया। इन पर धारा 2.21 के उल्लंघन का आरोप है। वहीं बिश्नोई पर इसके अलावा धारा 2.1 के उल्लंघन का भी आरोप है। सभी ने सजा स्वीकार कर ली है।' खेल की बदनामी करने में आइसीसी की धारा 2.21 का उल्लंघन माना जाता है। इसमें दुराचार, अनियंत्रित सार्वजनिक व्यवहार और अभद्र बयान आते हैं, जिससे खेल पर बुरा असर पड़ता है। एक निलंबन अंक का मतलब है कि खिलाड़ी एक वनडे या टी-20, अंडर-19 या ए टीम अंतरराष्ट्रीय मैच से प्रतिबंधित किया जा सकता हे। हालांकि यह सभी खिलाड़ी सीनियर स्तर की ओर बढ़ेंगे और ऐसे में वह इस प्रतिबंध से बच सकते हैं क्योंकि सीनियर स्तर पर यह लागू नहीं होगा। आइसीसी के अनुसार, 'भारतीय खिलाड़ी आकाश ने सजा स्वीकार कर ली है और उनको आठ निलंबन अंक दिए गए हैं। यह दो साल तक उनके रिकॉर्ड में रहेंगे।' बिश्नोई को कुल सात निलंबन अंक मिले हैं। आइसीसी ने कहा, 'बिश्नोई ने धारा 2.5 के लेवल-1 के उल्लंघन का भी आरोप स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अभिषेक दास के आउट होने के बाद आक्रामक तेवर दिखाए जो सामने वाले को उकसा सकते थे।' बांग्लादेश के तौहीद को 10, शमीम को आठ और हसन को चार निलंबन अंक मिले हैं। सभी आरोप मैदानी अंपायरों सैम एन और एड्रियन होल्डस्टोक, तीसरे अंपायर रवींद्र विमलासिरि व चौथे अंपायर पैट्रिक बोंगनी जेले ने लगाए। भारतीय टीम के सिर्फ दो ही खिलाड़ियों को यह निलंबन अंक मिले हैं।

अंडर-19 विश्व कप विवाद

ये था मामला
नई दिल्ली: फाइनल मुकाबले के दौरान कुछ बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने जीत का जश्न मनाते हुए अभद्रता की थी जिसके लिए उनके कप्तान अकबर अली ने माफी भी मांगी थी। वहीं भारतीय कप्तान प्रियम गर्ग ने इस हरकत को भद्दा कहा था। पहली बार चैंपियन बनी बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ियों ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाए। उनके तेज गेंदबाज शोरिफुल इस्लाम हर गेंद फेंकने के बाद भारतीय बल्लेबाजों को उकसाते दिखे। जिस समय बांग्लादेश की टीम ने जीत का एक रन लिया, उस वक्त भी शोरिफुल को कैमरे पर ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखा गया। जैसे-जैसे मैच समाप्त हुआ बांग्लादेशी खिलाड़ी और भी ज्यादा उग्र हो गए। हालांकि आइसीसी ने भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार को भी गलत पाया।

विश्व कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों से भिड़ गए थे बांग्लादेशी खिलाड़ी

आप खराब बल्लेबाजी करते हो। खराब गेंदबाजी करते हो। खराब क्षेत्ररक्षण करते हो। यह सब चलता है क्योंकि यह खेल का हिस्सा है लेकिन मैदान के अंदर विपक्षी खिलाड़ियों के साथ धक्का-मुक्की करना अशोभनीय है। इसमें उम्र की मासूमियत बिल्कुल नहीं दिख रही थी। आप उनकी अभद्र भाषा को आराम से देख सकते थे।
बिशन सिंह बेदी, भारत के पूर्व कप्तान

वार्नर ने दिए टी-20 से संन्यास के संकेत

सिडनी: ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा है कि वह टेस्ट और वनडे करियर को विस्तार देने और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए अगले कुछ साल में टी-20 क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का एलन बॉर्डर पदक जीतने वाले वार्नर पुरस्कार पाने के बाद फफक पड़े थे।

वर्ष 2018 में गेंद से छेड़खानी के कारण एक साल का प्रतिबंध झेलने के बाद शानदार वापसी करते हुए वार्नर ने यह पुरस्कार जीता है। उन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टी-20 क्रिकेटर भी चुना गया। 33 वर्षीय वार्नर ने कहा कि टी-20 क्रिकेट में लगातार विश्व कप खेलने हैं। इस प्रारूप को मैं अगले कुछ साल में अलविदा कह सकता हूं। तीनों प्रारूप में खेलना कठिन है। उन सभी को शुभकामनाएं जो ऐसा कर पाते हैं। यह चुनौतीपूर्ण है। टेस्ट और वनडे दोनों में वार्नर का औसत 40 से ऊपर का है और टी-20 में उनका स्ट्राइक रेट 140 का है।

मैच में अगला पैर बाहर देखेगा तीसरा अंपायर

महिला विश्व कप में होगा प्रयोग, पहली बार किसी आइसीसी टूर्नामेंट में इस्तेमाल होगी यह तकनीक

दुबई, प्रेट्र: ऑस्ट्रेलिया में इस महीने शुरू हो रहे आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप के दौरान अगले पैर की नो बॉल की निगरानी तीसरा अंपायर करेगा। आइसीसी की तरफ से मंगलवार को बताया गया कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुई सीरीज में सफल परीक्षण के बाद इस सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लागू करने का फैसला किया गया है, जिसके तहत तीसरा अंपायर फ्रंट फुट नो बॉल की निगरानी करेगा।

तीसरे अंपायर को प्रत्येक बॉल के बाद यह देखना होगा कि गेंदबाज का अगला पैर क्रीज के अंदर था या बाहर। वह हर गेंद के बाद मैदानी अंपायर को सही और गलत की जानकारी देगा। मैदानी अंपायरों से कहा गया है कि जब तक तीसरा अंपायर न कहे, वे फ्रंट फुट नो बॉल को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय न दें। मैदानी अंपायरों के पास खेल के दौरान अन्य प्रकार के नो बॉल का फैसला लेने का अधिकार रहेगा। इस तकनीक का इस्तेमाल हाल ही में 12 मैचों के दौरान किया गया। इस दौरान 4717 गेंदें फेंकी गईं और 13 नो बॉल नोटिस किए गए। सभी नो बॉल को लेकर बिल्कुल सटीक फैसला किया गया। आइसीसी के महाप्रबंधक (क्रिकेट) ज्यौफ एलरडाइस ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह तकनीक आइसीसी महिला टी-20 विश्व कप में फ्रंट फुट नो बॉल में होने वाली गलतियों को कम कर देगी। नो बॉल की पहचान करने में मैदानी अंपायरों को दिक्कत होती है और इस तकनीक से ऐसा नहीं होगा। साथ ही इस तकनीक से खेल की गति पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में यह तकनीक बेहतरीन साबित होगी।

एक नजर में

साक्षी ने ट्रायल की मांग की

नई दिल्ली: लय हासिल करने के लिए जूझ रही पहलवान साक्षी मलिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदों को बनाए रखने के लिए एक बार फिर से ट्रायल कराने की मांग की है। साक्षी इन दिनों एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के भाग लेने की तैयारी कर रही है जहां वह गैर ओलंपिक वर्ग में चुनौती पेश करेंगी। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता को ओलंपिक के 62 किग्रा के लिए हुए ट्रायल में सोनम मलिक ने हरा दिया था। साक्षी ने कहा कि मुझे एक दौर के ट्रायल की उम्मीद है। अगर मैं ट्रायल में क्वालीफाई कर जाती हूं तो मेरे पास ओलंपिक का टिकट हासिल करने के दो मौके होंगे। मैं इनके जरिये क्वालीफाई करना चाहती हूं।' (जेएनएन)

खेलो इंडिया में तलवारबाजी

नई दिल्ली: पहली बार तलवारबाजी को सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम में जगह मिली है जिसे 22 फरवरी से एक मार्च तक भुवनेश्वर में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में जगह मिलने से देश भर के तलवारबाजों में खुशी है। इन खेलों में गुरु नानक देव विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी जगमीत कौर ने कहा कि खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों में शामिल होना तलवारबाजी के लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि यहां बहुत ज्यादा प्रतियोगी नहीं होंगे। जगमीत ने पिछले साल दक्षिण एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। (जेएनएन)

भारतीय बैडमिंटन टीम जीती

मनीला: किदांबी श्रीकांत की अगुआई में भारत ने एशिया टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के पहले ग्रुप मैच में कजाखिस्तान को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल प्रवेश की उम्मीदें प्रबल कर ली। श्रीकांत के अलावा लक्ष्य सेन और शुभांकर डे ने अपने-अपने सिंगल्स मुकाबले जीते। श्रीकांत ने दमित्री पनारिन को 23 मिनट में 21-10, 21-7 से हराया। वहीं, सेन ने ऑर्थर नियाजोव को 21 मिनट में 21-13, 21-8 से मात दी। डे ने खैतमुरात कुलमातोव को 21-11, 21-5 से हराया। विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता बी साई प्रणीत और चिराग शेट्टी को डबल्स वर्ग में कजाखिस्तान के नियाजोव और पनारिन के हाथों 21-18, 16-21, 19-21 से पराजय झेलनी पड़ी। (प्रेट्र)

एफआइएच की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी बनीं लालरेमसिमी

लुसाने, प्रेट्र: भारतीय फॉरवर्ड लालरेमसिमी को 2019 की एफआइएच की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी चुना गया। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआइएच) ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। भारत की 19 वर्ष की स्ट्राइकर ने अर्जेंटीना की जूलिएटा जांकुनास और नीदरलैंड्स की फ्रेडरिक माटला को हराया जो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं।

लालरेमसिमी • फाइल फोटो, ट्विटर

मिजोरम की इस खिलाड़ी को 40 प्रतिशत वोट मिले। उन्हें राष्ट्रीय संघों से 47.7 प्रतिशत, मीडिया से 28.4 प्रतिशत और प्रशंसकों व खिलाड़ियों से 36.4 प्रतिशत वोट मिले। बेलारूस के खिलाफ 2017 में पदार्पण करने के बाद लालरेमसिमी भारतीय टीम की अहम सदस्य हैं। वह 2017 में कोरिया और 2019 में स्पेन के खिलाफ सीरीज में सर्वाधिक गोल करने वाली खिलाड़ी थीं। हिरोशिमा में एफआइएच सीरीज फाइनल्स में भारत ने ओलंपिक क्वालीफायर्स में जगह बनाने की होड़ में शामिल आठ दूसरी टीमों को हराया था और अमेरिका को शिकस्त देकर टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया था। टूर्नामेंट के दौरान लालरेमसिमी के पिता का निधन हो गया था, लेकिन इस दुख के बावजूद उन्होंने खेलने का फैसला किया। लालरेमसिमी ने कहा, 'मेरे गांव में हॉकी काफी मशहूर नहीं है। इसे बहुत कम लोग खेलते हैं लेकिन मेरी हमेशा से हॉकी में रुचि थी। यही वजह है कि मैंने थेंजाल जाने का फैसला किया, जो मेरे गांव से काफी दूर था।' वहीं, हॉकी इंडिया ने लालरेमसिमी को इस पुरस्कार के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने उसकी तारीफ भी की।

फुटबॉल डायरी इटालियन कप के सेमीफाइनल में भिड़ेंगे जुवेंटस व एसी मिलान, क्रिस्टियानो और ज्लाटन से गोल करने की उम्मीद

रोनाल्डो और इब्राहिमोविक होंगे आमने-सामने

मिलान, एएफपी: जुवेंटस के दिग्गज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो और एसी मिलान के ज्लाटन इब्राहिमोविक गुरुवार को आमने-सामने होंगे जब दोनों टीमें इटालियन कप में सेमीफाइनल के पहले चरण के मुकाबले में एक-दूसरे का सामना करने उतरेंगी। दोनों ही स्ट्राइकरों ने टीम के पिछले मैचों में गोल किए थे और दोनों ही टीमों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था।

जुवेंटस को वेरोना के हाथों 1-2 से हार झेलनी पड़ी थी जबकि इंटर मिलान ने इब्राहिमोविक की एसी मिलान को 4-2 से हराया था। वेरोना के खिलाफ टीम को मिली हार के बाद रोनाल्डो ने कहा था कि जो हम नतीजा चाहते थे, यह वो नहीं है। 35 वर्षीय रोनाल्डो की निगाह लगातार 11 मैचों में गोल करके गेब्रियल बतिस्तुता और फैबियो क्वागलिरारेला के रिकॉर्ड की बराबरी करने पर लगी है। वह इस सत्र में सभी टूर्नामेंटों को मिलाकर कुल 23 गोल कर चुके हैं। वहीं, 38 वर्षीय इब्राहिमोविक पिछले महीने ही अपने नए क्लब एसी मिलान से जुड़े थे और अभी तक उन्होंने तीन गोल दागे हैं।

इब्राहिमोविक • फाइल फोटो, एएफपी

इब्राहिमोविक ने कहा था कि उन्होंने उस मैच में गोल करके दिखा दिया था कि वह अभी भी मैच में अंतर पैदा कर सकते हैं। जुवेंटस के मैनेजर मौरिजियो सारी टीम के घर के बाहर हुए प्रदर्शन से थोड़ा चिंतित होंगे क्योंकि टीम पिछले दो मैचों में हार झेल चुकी है। वेरोना के खिलाफ हार के बाद सारी ने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि हम इसका समाधान निकाल लेंगे। वहीं, बुधवार को लीग के दूसरे सेमीफाइनल के पहले चरण में इंटर मिलान का सामना नापोली से होगा। इंटर को अपने मुख्य स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू से अच्छे प्रदर्शन की आस होगी।

कोरोना वायरस के कारण एएफसी के मैच हुए रद: कोरोना वायरस के कारण एएफसी फुटबॉल कप के मैच अप्रैल तक के लिए रद कर दिए गए जिसमें पूर्वी एशिया की टीमें शामिल थी। एशियन फुटबॉल कंफेडरेशन (एएफसी) ने गुरुवार को ही इसकी जानकारी दी है। एएफसी कप-2020 में प्रारंभिक प्लेऑफ और ग्रुप स्तर के मैच खेले जाने थे लेकिन अब ये सभी मैच सात अप्रैल के बाद होंगे।

अवसाद से जूझ रहे हैं पेले
रियो डि जेनेरियो: दुनिया के महानतम फुटबॉलर पेले के बेटे ने कहा है कि ब्राजील को तीन बार विश्व कप खिताब दिलाने वाले महान खिलाड़ी और उनके पिता एक तरह के अवसाद से पीड़ित हैं। इस अवसाद का कारण यह है कि खराब स्वास्थ्य के कारण 79 साल के पेले का कहीं आना-जाना नहीं हो पा रहा है। हाल के दिनों में पेले कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित रहे हैं। पिछले साल अप्रैल में मूत्र में संक्रमण के कारण उन्हें 13 दिनों तक अस्पताल में बिताने पड़े थे। हाल ही में पेले की कूल्हे की रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और इस कारण उन्हें चलने-फिरने के लिए फ्रेम का सहारा लेना पड़ रहा है। पेले के बेटे इडिन्हो ने कहा, 'पिता इन दिनों हमेशा ऊंघते हुए दिखाई देते हैं और उनके चेहरे पर निराशा का भाव रहता है। वह एक तरह से राजा थे और राजा की तरफ अपना जीवन जीते थे लेकिन अब असहाय महसूस कर रहे हैं। वह एक तरह से अपने ऊपर शर्मिंदा हैं। वह बाहर जाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में यही किया है, पर अब सब कुछ बदल गया है। वह अपने घर से दूर कहीं नहीं जा सकते और इसी कारण वह अवसाद की चपेट में हैं।'

क्रिस्टियानो रोनाल्डो • फाइल फोटो, रायटर

साकेत मिनेनी बेंगलुरु ओपन के अगले दौर में पहुंचे

बेंगलुरु, आइएएनएस : वाइल्ड कार्ड से प्रवेश पाने वाले निकी पूनाचा ने चेक गणराज्य के 16वीं सीड लुकास रोसोल को हराकर बेंगलुरु ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। 24 वर्षीय पूनाचा ने पहले दौर के मुकाबले में रोसोल को 6-4, 2-6, 6-3 से मात दी। अन्य मुकाबलों में पिछले साल के उपविजेता भारत के साकेत मिनेनी ने भी उलटफेर करते हुए रूस के डोनस्काय को 6-3 6-3 से हराया।

> हमने वनडे विश्व कप के लिए वर्ष की शुरुआत से ही लय पा ली थी, लेकिन खराब समय के कारण विश्व कप नहीं जीते।
> – आरोन फिंच, ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम के कप्तान

भारतीय महिलाओं की नजरें टी-20 खिताब पर

क्रिकेट डायरी ▸ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ त्रिकोणीय टी-20 सीरीज का फाइनल आज

मेलबर्न, प्रेट्र : बल्लेबाजों के फॉर्म में लौटने के साथ आत्मविश्वास से भरी भारतीय महिला टीम बुधवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में उतरेगी तो उसका इरादा त्रिकोणीय टी-20 सीरीज अपने नाम करने का होगा। पहले तीन लीग मैचों में एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी भारतीय टीम ने शनिवार को ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दोनों टीमें एक-दूसरे के खिलाफ लीग चरण में एक-एक मैच जीत चुकी हैं।

सीनियर सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और कप्तान हरमनप्रीत कौर लगातार रन बना रही हैं। वहीं, 16 वर्ष की शेफाली वर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछले मैच में रन बनाए। मेजबान टीम ने पांच विकेट पर 173 रन बनाए थे, लेकिन भारत ने 19.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। शेफाली ने 28 गेंद में 49 और मंधाना ने 48 गेंद में 55 रन बनाए। जेमिमाह रोड्रिग्ज ने भी 19 गेंद में 30 रन की पारी खेली। भारतीय गेंदबाजों का भी प्रदर्शन अच्छा रहा है। दीप्ति शर्मा और राजेश्वरी गायकवाड़ लगातार अच्छा खेलती आई हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लीग मैच में कम स्कोर बनाने के बावजूद भारत ने जीत दर्ज की। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत से हारने के बाद इंग्लैंड को हराया। उसकी बल्लेबाज मेग लैनिंग और एलिसे पैरी ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

बांग्लादेश के राष्ट्रीय चयनकर्ता अंडर-19 खिलाड़ियों से प्रभावित

कोलकाता : बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और राष्ट्रीय चयनकर्ता हबीबुल बशर को उम्मीद है कि अंडर-19 विश्व कप जीतने वाली टीम के कई खिलाड़ी लंबे समय तक सीनियर टीम के लिए खेलेंगे। बांग्लादेश अकबर अली के नेतृत्व में रविवार को भारत को डकवर्थ-लुइस नियम के तहत तीन विकेट से हराकर पहली बार कोई आइसीसी विश्व कप जीतने में सफल रहा। बशर इस समय पाकिस्तान में हैं, जहां उनकी टीम को सोमवार को पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान के हाथों पारी और 44 रन से हार का सामना करना पड़ा है। बशर ने कहा कि यह हमारे क्रिकेट के लिए बहुत ही अच्छा है। हम एशिया कप फाइनल और निदहास ट्रॉफी फाइनल में खिताब जीतने में विफल रहे। लेकिन, हमारी जूनियर टीम ने फाइनल में हारने के द्वंद्व को तोड़ दिया। यह विश्व कप हमारे लिए बेहद सकारात्मक संदेश है। बशर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस टीम के कई खिलाड़ी सीनियर टीम में खेलेंगे और लंबे समय तक क्रिकेट की सेवा करेंगे।

पाक की पहली टेस्ट टीम के सदस्य हसन का निधन

कराची : पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट खेलने वाली टीम के सदस्य वकार हसन का 87 साल की उम्र में सोमवार को निधन हो गया। निधन से पहले वह इस टीम के अंतिम जीवित सदस्य थे। 12 सितंबर 1932 को अमृतसर में जन्मे वकार ने 1952 में पाकिस्तान की पहली टेस्ट टीम के साथ भारत दौरा किया था। इस टीम ने भारत के साथ नई दिल्ली में अक्टूबर 1952 में पहला टेस्ट मैच खेला था। उस सीरीज में वकार ने दिल्ली टेस्ट में आठ एवं पांच, लखनऊ टेस्ट में 23, मुंबई टेस्ट में 81 एवं 65, चेन्नई टेस्ट में 49 और कोलकाता टेस्ट में 29 तथा 97 रनों की पारी खेली थीं। वकार उस टीम का भी हिस्सा थे, जिसने 1954 में द ओवल मैदान पर इंग्लैंड को 24 रनों से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। वकार ने पाकिस्तान के लिए कुल 21 टेस्ट खेले और 1071 रन बनाए। 1959 में उनका करियर खत्म हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अहसान मनी ने वकार के निधन पर दुख व्यक्त किया है। वकार ने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद प्रशासनिक पदों पर काम किया। वह 1982-83 में चयनकर्ता भी रहे।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। फाइल फोटो, एएफपी

कोई चमत्कार ही दिल्ली को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाएगा

रणजी ट्रॉफी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

दिल्ली की टीम को अगर रणजी ट्रॉफी नॉकआउट में जगह बनाने की किसी भी उम्मीद को जीवंत रखना है तो बुधवार से यहां राजस्थान के खिलाफ शुरू हो रहे अपने अंतिम ग्रुप मैच में बड़ी जीत दर्ज करने के अलावा अन्य मैचों के नतीजों के अपने पक्ष में रहने की उम्मीद करनी होगी। दिल्ली की टीम के भी सात मैचों में 18 अंक हैं और वह क्वार्टर फाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है। टीम फिलहाल 18 टीमों के क्रास पूल-ए और बी में 10वें स्थान पर चल रही है, लेकिन राजस्थान के खिलाफ बोनस अंक सहित जीत और अन्य मैचों के नतीजे पक्ष में आने से दिल्ली की उम्मीद बन सकती है।

दिल्ली के विदर्भ के समान अंक हैं, लेकिन खराब रन रेट ने उसकी मुसीबत बढ़ा दी है। टीम को राजस्थान के खिलाफ बोनस अंक सहित जीत दर्ज करने के अलावा पंजाब और कर्नाटक की हार की दुआ करनी होगी, जबकि उम्मीद करनी होगी कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का मैच ड्रॉ पर छूटे। लेकिन, विदर्भ अगर हैदराबाद के खिलाफ अपना अगला मुकाबला जीत जाता है तो बोनस अंक के साथ जीत भी दिल्ली के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसके बाद भी दिल्ली को अपनी रन गति कर्नाटक से बेहतर रखनी होगी और इतनी सारी जटिल संभावनाओं को देखते हुए दिल्ली के आगे बढ़ने की संभावना बेहद मुश्किल है।

चयन विवादों का सामना करने वाली दिल्ली के लिए मौजूदा रणजी सत्र काफी खराब रहा, जिसमें टीम अब तक सिर्फ दो मैच जीत पाई, जबकि चार मैच ड्रॉ रहे। टीम को एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ राजस्थान की टीम सात मैचों में सिर्फ 16 अंक के साथ नॉकआउट की दौड़ से बाहर हो गई है। राजस्थान ने दो मैचों में जीत दर्ज की, जबकि चार मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि एक मैच ड्रॉ पर छूटा। गुजरात संयुक्त ग्रुप-ए और बी में सात मैचों में 29 अंक के साथ सौराष्ट्र (28) और आंध्र (27) से आगे है।

उत्तर प्रदेश की नजर नॉकआउट पर

खेल संवाददाता, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की टीम रणजी ट्रॉफी के वर्तमान सत्र में पहली बार लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कोई मुकाबला खेलने उतरेगी। हिमाचल प्रदेश के खिलाफ बुधवार से शुरू हो रहे इस अहम मैच के लिए दोनों टीमों ने कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन इस बार बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। अभी तक खेले गए सात मुकाबलों में उसे सिर्फ दो में जीत नसीब हुई है, जबकि पांच मैच ड्रॉ रहे। वहीं, हिमाचल की टीम ने इतने ही मुकाबलों में सिर्फ एक में जीत दर्ज की है। ऐसे में मेजबानों के पास अपने घरेलू मैदान पर बड़ी जीत दर्ज कर नॉकआउट दौर में पहुंचने का सुनहरा मौका होगा।

सिर्फ बोनस अंक से ही फायदा : उत्तर प्रदेश के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है। उसकी टीम यह बात अच्छी तरह जानती है कि यहां उसे सिर्फ जीत नहीं, बल्कि बड़ी जीत दर्ज कर बोनस अंक ही नॉकआउट का टिकट दिला सकता है। हालांकि, उसे घरेलू मैदान का मनोवैज्ञानिक फायदा भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश को अगर नॉकआउट दौर पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखना है तो कमजोर हिमाचल प्रदेश पर बोनस अंक के साथ जीत दर्ज करनी होगी। मालूम हो कि अपने पिछले मैच में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को उसके घर में हराया था। इससे मेजबान टीम के खिलाड़ियों के हौसले निश्चित रूप से बुलंद होंगे। उत्तर प्रदेश को खेल के हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। अंकित राजपूत की अगुवाई में उत्तर प्रदेश टीम का गेंदबाजी आक्रमण शानदार है। खासकर, फिरकी गेंदबाज सौरभ कुमार ने अभी तक कमाल का प्रदर्शन किया है। वहीं, बल्लेबाजी में उनके पास सैफ, शौकत, अक्शदीप नाथ और रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अच्छी लय में हैं।

कबड्डी टीम की जांच करेगा खेल मंत्रालय

▸ **45 खिलाड़ी व 12 अधिकारी बिना किसी आधिकारिक अनुमति के पड़ोसी देश गए, भारत लौटने के बाद शुरू होगी जांच**

नई दिल्ली, प्रेट्र : खेल मंत्रालय पाकिस्तान में एक सर्कल शैली के कबड्डी विश्व कप में 'अनधिकृत' तौर पर भारतीय टीम की भागीदारी की जांच पर विचार कर रहा है। खेल मंत्रालय के मुताबिक लगभग 45 खिलाड़ी और 12 अधिकारी बिना किसी आधिकारिक अनुमति या मंजूरी के पड़ोसी देश गए हैं।

खेल मंत्रालय के सूत्र ने कहा, 'मंत्री (किरन रिजिजू) इस मामले की जांच शुरू करवाने वाले हैं।' अन्य सूत्र ने बताया, 'कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई खिलाड़ियों के वापस आने के बाद ही शुरू होगी।' सर्कल शैली की कबड्डी, सामान्य शैली से अलग तरह से खेली जाती है। एशियन गेम्स में अधिकृत सामान्य शैली की कबड्डी में दोनों टीमों में 80 किग्रा से कम वजन वाले सात-सात खिलाड़ी होते हैं। सर्कल शैली में वजन का कोई पैमाना नहीं होता है और वृताकार मैदान में खेले जाने वाले इस प्रारूप में दोनों टीमों में आठ-आठ खिलाड़ी होते हैं।

भारतीय ओलंपिक संघ (आइओए) ने सोमवार को कहा कि उसने विश्व स्तर के टूर्नामेंट के लिए किसी भी कबड्डी टीम के पाकिस्तान दौरे को मंजूरी नहीं दी है। चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए भारत से दल शनिवार को वाघा बॉर्डर के जरिये लाहौर पहुंचा, जिसका आयोजन पहली बार पाकिस्तान में किया जा रहा है। टीम के वहां पहुंचने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हुईं, जिससे भारतीय खेल जगत में हलचल मच गई। अंतरराष्ट्रीय कबड्डी महासंघ (आइकेएफ) के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत ने कहा कि टूर्नामेंट को शीर्ष निकाय द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। गहलोत ने कहा, 'यह फर्जी टूर्नामेंट है, इसमें फर्जी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पाकिस्तान में खेले जा रहे सर्कल विश्व कप में भाग ले रहे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देश अंतरराष्ट्रीय महासंघ से मान्यता प्राप्त नहीं हैं। इन देशों में सर्कल कबड्डी नहीं खेला जाता, इसलिए ये फर्जी खिलाड़ी इन देशों का नेतृत्व कर रहे हैं।' भारतीय एमेच्योर कबड्डी महासंघ (एकेएफआइ) ने दावा किया कि उन्होंने किसी भी खिलाड़ी को पाकिस्तान में खेलने की मंजूरी नहीं दी है। इस मामले में पंजाब कबड्डी संघ की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि टूर्नामेंट में भाग लेने गए लगभग सभी खिलाड़ी राज्य संघ से पंजीकृत हैं।

जम्मू-कश्मीर इतिहास रचने से बस एक कदम दूर

जागरण संवाददाता, जम्मू

जम्मू-कश्मीर की रणजी टीम छह वर्षों के बाद एक बार फिर से इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गई है। टीम अभी तक खेले गए आठ मुकाबलों में छह में जीत दर्ज की है, जबकि दो मुकाबले ड्रॉ रहे। टीम 39 अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि ओडिशा की टीम 35 अंकों के साथ दूसरे, सर्विसेज की टीम 33 अंकों के साथ तीसरे और हरियाणा की टीम 30 अंकों के चौथे स्थान पर है।

जम्मू के जीजीएम साइंस कॉलेज के हॉस्टल मैदान में बुधवार से जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के बीच रणजी मुकाबला शुरू होगा। अगर बारिश की वजह से मुकाबला पूरा नहीं पाता है तो होता है तो दोनों टीमों को एक-एक अंक मिलेगा। इससे जम्मू-कश्मीर के 40 और हरियाणा के 31 अंक हो जाएंगे।

अगर जम्मू-कश्मीर की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है तो प्रतिद्वंद्वी टीम के खिलाफ पहली पारी में बढ़त हासिल कर लेती है तो जम्मू-कश्मीर को तीन अंक मिलेंगे। इससे वह 42 अंक हासिल करने में कामयाब रहेगी। जम्मू-कश्मीर टीम अगर हरियाणा को परास्त कर देगी तो जीत के रूप में टीम को छह अंक मिलेंगे और कुल अंक 45 हो जाएंगे। इससे जम्मू-कश्मीर की टीम आसानी से वर्ष 2014 के बाद दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब रहेगी।

विविध

दोषी पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांगी जानकारी

▸ **सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया चार हफ्ते का समय**

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को निर्देश दिया कि वह 1992-93 के मुंबई दंगों की जांच करने वाले आयोग द्वारा कथित रूप से दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जस्टिस बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाले जांच आयोग ने 1998 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए कुछ नहीं किया और अदालत के आदेशों का अक्षरशः पालन नहीं किया।

जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एस. रविंद्र भट और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन की पीठ ने अपने आदेश में महाराष्ट्र सरकार के सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि वह श्रीकृष्ण जांच आयोग की रिपोर्ट के संलग्न चार्ट में दर्ज प्रत्येक पुलिस अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई और जिन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उसका विस्तृत विवरण चार हफ्ते में पेश करें। पीठ ने कहा कि हलफनामे में पीड़ितों को दिए गए मुआवजे और उसकी रकम की जानकारी भी दी जाए।

शीर्ष अदालत जस्टिस श्रीकृष्ण जांच आयोग की सिफारिशों पर अमल के निर्देश के लिए 1998 से ही दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने मुंबई के अधिवक्ता शकील अहमद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विज की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। जस्टिस श्रीकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पद से अवकाश ग्रहण किया है। जस्टिस श्रीकृष्ण को जब मुंबई में दिसंबर, 1992 और जनवरी 1993 के दौरान हुए दंगों की जांच के लिए आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था तो वह बांबे हाई कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार द्वारा नियुक्त इस जांच आयोग को 1995 में शिवसेना-भाजपा गठबंधन सरकार ने 1996 में खत्म कर दिया था। हालांकि, 1996 में ही इसका पुनर्गठन किया गया और इसके दायरे में मार्च, 1993 में मुंबई में हुए बम विस्फोट की जांच का मुद्दा भी जोड़ दिया गया था। श्रीकृष्ण आयोग ने अप्रैल, 1998 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में कुछ नेताओं और पुलिस अधिकारियों पर भी अंगुली उठाई थी।

जवानों को मिलती है सीमित छुट्टी न लगवाएं दफ्तरों के चक्कर

नईदुनिया, रायपुर

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (सेना और अर्द्ध सैनिक) की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्यों को एक पत्र भी भेजा है। इसमें कहा है कि जवानों को सीमित छुट्टी मिलती है। कई बार उनकी पूरी छुट्टी सरकारी कार्यालयों में अपने काम के लिए चक्कर लगाने में खत्म हो जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि न केवल जवानों बल्कि उनके स्वजनों के प्रति भी सरकारी कार्यालयों में सम्मानपूर्वक व्यवहार हो। इससे जवानों का हौसला बना रहेगा। कई बार घरेलू समस्याओं की वजह से ही जवान तनाव में रहते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के उप सचिव आरपी राठिया ने इस संबंध में विभागों को निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि हमारे सशस्त्र बल विषम एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी जान की परवाह किए बगैर देश की सेवा

प्रतीकात्मक

▸ **केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया राज्यों को निर्देश**

▸ **प्राथमिकता पर हो जवानों की समस्याओं का निराकरण**

एवं सुरक्षा में तत्पर रहते हैं। वे अपने घर-परिवारों से हजारों किलोमीटर दूर जोखिम भरे इलाकों और खराब मौसम में भी देश की सुरक्षा में दिन-रात लगे रहे हैं। उनमें थलसेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र बल जैसे कि बीएसएफ, आइटीबीपी और सीआरपीएफ आदि व सेवानिवृत्त कर्मी और अधिकारी शामिल हैं।

वे साल में सीमित समय के लिए ही अपने घर जाकर लंबित घरेलू काम-काज को देख पाते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो कि राज्य सरकारों में विभिन्न स्तरों और विभिन्न कार्यालयों से संबंधित होते हैं। अतः ऐसी व्यवस्था आवश्यक है जिससे जवानों की समस्याओं का निराकरण शीघ्र पूर्ण निष्ठा, लगन व सम्मान के साथ हो सके।

तत्काल नियमानुसार की जाए कार्यवाही : जीएडी उप सचिव ने कहा है कि इन जवानों से संबंधित कोई भी समस्या निराकरण के लिए अपने विभाग, कार्यालय को प्राप्त होती है तो उस पर तत्काल नियमानुसार कार्यवाही की जाए। जब भी ये या इनके परिवार के लोग किसी कार्य के लिए सरकारी कार्यालय में जाएं तो उनके साथ स्नेह और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हुए उनके कार्यों को शीघ्र निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें ताकि वे अपनी घरेलू समस्याओं से निश्चिंत होकर न केवल अपने कार्य को भलीभांति कर सकेंगे बल्कि और अधिक बुलंद हौसले के साथ देश की सेवा में तत्पर रहेंगे।

पीएम कार्यालय पहुंचा गुजरात का एलआरडी भर्ती मामला

विवाद

▸ **भाजपा के चार सांसदों ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र**

▸ **रबारी, भरवाड व चारण को एसटी वर्ग से हटाने की मांग**

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद

गुजरात में लोक रक्षक दल (एलआरडी) की भर्ती में अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र को लेकर पैदा हुआ विवाद अब प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गया है। आदिवासी समुदाय के चार भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रबारी, भरवाड व चारण जाति को एसटी वर्ग से बाहर करने की मांग की है। उधर, कांग्रेस ने भी बैठक कर आदिवासी समुदाय की मांग का समर्थन किया है।

आदिवासी समुदाय के चार भाजपा सांसद जसवंत सिंह भाभोर, मनसुख वसावा, गीताबेन राठवा तथा प्रभु वसावा ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि वर्ष 1958-59 में केंद्र सरकार के सर्कुलर (परिपत्र) के आधार पर रबारी, भरवाड व चारण समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन वर्ष 1972 में इन जातियों को ओबीसी वर्ग में शामिल कर दिया गया। अब ये जातियां दोनों ही वर्ग में आरक्षण का लाभ ले रही हैं, इसलिए इन्हें एसटी वर्ग से बाहर कर देना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि गुजरात के गांधीनगर में पिछले दो महीने से एलआरडी भर्ती परीक्षा में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के लिए अलग आरक्षण की मांग को लेकर युवतियां धरना दे रही हैं। वे सौराष्ट्र के गिर व बरडा क्षेत्र निवासी रबारी, भरवाड व चारण समुदाय के लोगों को एसटी का दर्जा देने का विरोध भी कर रही हैं। हालांकि, गुजरात के आदिवासी कल्याण मंत्री गणपतसिंह वसावा साफ कर चुके हैं कि एलआरडी भर्ती में एक भी फर्जी एसटी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

सरकार ने गत वर्ष जारी सर्कुलर को रद करने के दिए संकेत

गुजरात सरकार ने एलआरडी भर्ती में आरक्षण को लेकर जारी आंदोलन के बीच एक अगस्त 2018 को जारी सर्कुलर रद करने के संकेत दिए हैं। भाजपा सांसद व अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज के नेताओं की मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ चर्चा के बाद सरकार इसे रद करने को राजी हो गई है। सर्कुलर के अनुसार एलआरडी भर्ती के लिए महिला अभ्यर्थियों की एक ही प्रतिभा सूची बनाई गई है। एससी-एसटी वर्ग की अभ्यर्थी अपने लिए अलग से प्रतिभा सूची की मांग कर रही हैं।

एक हजार करोड़ के घोटाले में शासन के अलग-अलग शपथपत्र

▸ **पहले शपथपत्र में तत्कालीन सीएस ने स्वीकारी थी 200 करोड़ के घोटाले की बात**

▸ **रिव्यू पिटीशन में राज्य सरकार ने कहा- नहीं हुआ कोई घोटाला**

नईदुनिया, बिलासपुर

भाजपा शासनकाल में कागजी संस्था के नाम पर समाज कल्याण विभाग में हुए एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले में हाई कोर्ट ने सीबीआइ जांच के निर्देश दे रखे हैं। सीबीआइ ने जांच भी शुरू कर दी है। अब शासन की ओर से हाई कोर्ट में दो अलग-अलग समय पर शपथपत्र देने की बात सामने आई है। इनमें दोनों में ही अलग-अलग दावे किए गए हैं। भाजपा शासनकाल के तत्कालीन मुख्य सचिव अजय सिंह ने जांच के बाद 150-200 करोड़ रुपये के घोटाले की बात स्वीकारी थी। वहीं, वर्तमान शासन ने रिव्यू पिटीशन में जो शपथपत्र लगाया है उसमें घोटाले की बात को ही सिरे से खारिज कर दिया गया है।

इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा शासनकाल में हुए घपले के सामने आने के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस सरकार हमलावर होगी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। सरकार अधिकारियों के बचाव में उतर आई है। वजह यह कि पुरानी सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी ही इस सरकार में भी प्रभावी भूमिका में हैं। जो दो पूर्व मुख्य सचिव रिटायर हो चुके हैं उन्हें सरकार ने संविदा पर नियुक्ति दे रखी है।

यह है मामला : समाज कल्याण विभाग में संविदा कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे कुंदन सिंह ने स्थाई नियुक्ति के लिए जब विभाग में आवेदन लगाया तब उन्हें पता चला कि वर्ष 2015 में ही उसकी स्थाई नियुक्ति हो गई है और माना कैंप स्थित निःशक्तजन स्रोत संस्थान से नियमित कर्मचारी के रूप में प्रति महीने उसका वेतन भी निकल रहा है। कुंदन को माना कैंप के फर्जी एनजीओ दफ्तर में वर्ग दो कर्मचारी के रूप में पदस्थ बताया है। इसके बाद कुंदन ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी जुटाई। इसमें पता चला कि विभागों में तैनात चतुर्थ श्रेणी के दर्जनों कर्मचारियों की तैनाती कागजी संस्था में भी दर्शायी गई है। आरटीआइ को आधार बनाकर कुंदन ने हाई कोर्ट में अपील की। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने कहा था। इस पर तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अजय सिंह ने 150-200 करोड़ घोटाले की बात स्वीकार की थी। सुनवाई के दौरान घोटाले के एक हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने के साक्ष्य मिलने लगे। इसके बाद हाई कोर्ट ने सीबीआइ को जांच के निर्देश दिए। इसी आदेश के खिलाफ राज्य शासन की ओर से समाज कल्याण विभाग में पदस्थ जिला पुनर्वास अधिकारी चमेली चंद्राकर ने रिव्यू पिटीशन दायर की है।

सीबीआइ को रोक नहीं पाई सरकार, याचिका खारिज

एक हजार करोड़ के घोटाले की जांच में सीबीआइ को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की मशक्कत काम नहीं आई। हाई कोर्ट ने शासन के रिव्यू पिटीशन को लेकर तल्ख टिप्पणी के साथ याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने समाज कल्याण विभाग में कागजी एनजीओ के जरिये एक हजार करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल एक दर्जन अधिकारियों के खिलाफ जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया है। इसी बीच राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए रिव्यू पिटीशन दायर की थी। महाधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष सीबीआइ के बजाए राज्य पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपने की मांग की थी। महाधिवक्ता ने डिवीजन बेंच से मांग की थी कि राज्य पुलिस द्वारा इस मामले की किए जाने वाली जांच को हाई कोर्ट अपनी निगरानी में रखे। महाधिवक्ता के तर्क के बाद डिवीजन बेंच ने रिव्यू पिटीशन दायर करने के संबंध में सवाल किया था कि ऐसा कौन सा कारण है जिसके चलते इस गंभीर मामले में राज्य शासन को रिव्यू पिटीशन दायर करना पड़ा।

मौसम विशेष

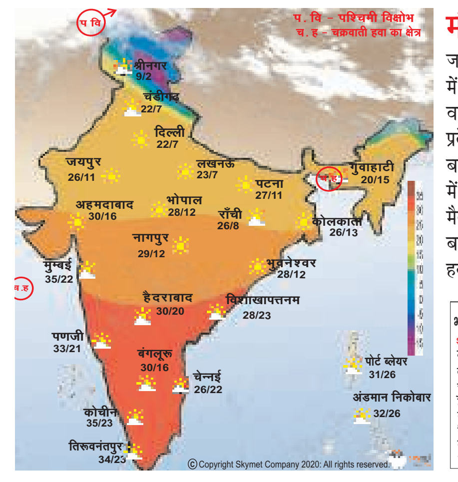

जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में बादलों में वृद्धि होगी। अनेक स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी संभव है। हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में भी वर्षा व बर्फबारी होगी। दिन के तापमान में गिरावट आएगी। दिल्ली सहित मैदानी भागों का मौसम छिटपुट बादलों के साथ व मध्यम गति की हवाओं के साथ शुष्क रहेगा।

भारत के मुख्य शहरों का तापमान:

शहर		शहर	
मुम्बई	34/21/आंबा	अहमदाबाद	29/09/सा
कोलकाता	27/14/सा	बड़ौदा	31/11/सा
चेन्नई	31/21/सा	नागपुर	30/11/आंबा
हैदराबाद	31/19/सा	इन्दौर	30/14/आंबा
बंगलूरू	31/16/सा	राँची	27/09/आंबा
त्रिवेन्द्रम	34/23/सा	पटना	26/11/आंबा
गुवाहाटी	22/13/सा	जमशेदपुर	28/09/आंबा
गंगटोक	14/06/सा	पुणे	31/16/सा

लगान बढ़ाने के विरोध में बारदोली आंदोलन की घोषणा

आज ही 1928 में 22 फीसद लगान बढ़ाने के विरोध में बारदोली सत्याग्रह शुरू हुआ। सरकार ने पहले कठोर कदम उठाए। बाद में किसानों की मांगों को मान लिया। आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया, जिसके बाद उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली।

साढ़े आठ अरब की पेंटिंग 'स्क्रीम' पहली बार चोरी हुई

आज ही 1994 में एडवर्ड मुंच की पेंटिंग 'स्क्रीम' नॉर्वे की नेशनल गैलरी से पहली बार चोरी हुई। यह मानवीय हालात को बयां करती है। दो बार चुराया गया। 2012 में इसके दूसरे वर्जन को लिओन ब्लैक ने करीब 8 अरब 55 करोड़ रुपये में खरीदा था।

क्रम विकास का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन

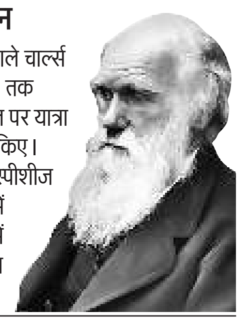

आज ही वर्ष 1809 में क्रम विकास का सिद्धांत देने वाले चार्ल्स डार्विन का जन्म इंग्लैंड में हुआ। सन 1818 से 1825 तक उन्होंने श्रॉसबरी में पढ़ाई की। 1831 में बीगल जहाज पर यात्रा के दौरान उन्होंने जीवों का अध्ययन किया और नमूने एकत्रित किए। 1837 में पहला पेपर लिखा। 1859 में पुस्तक ऑरिजन ऑफ स्पीशीज प्रकाशित हुई। सजीवों की उत्पत्ति और विविधता को समझाने में मदद की। उन्होंने प्रतिपादित किया कि परिवर्तनशील अवयवों में जो अनुकूल होते हैं, वे बच जाते हैं। 19 अप्रैल 1882 को उनका निधन हो गया।

मनुष्यों के पहुंचने से पहले ही प्रभावित हो गए थे ग्लेशियर

- अमेरिकी की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया दावा
- कहा– औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 18वीं सदी में यहां पहुंच गए थे जहरीले पदार्थ

यह अध्ययन पीएनएएस नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। प्रतीकात्मक

वाशिंगटन, प्रेट्र : बढ़ती मानवीय गतिविधियों का सबसे ज्यादा असर हमारे ग्लेशियरों पर पड़ रहा है। कई लोगों का मानना है कि यह प्रभाव कुछ दशकों पहले ही पड़ना शुरू हुआ है लेकिन एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि हिमालय की चोटियों में मनुष्य के पहुंचने से दशकों पहले ही लोगों ने अपनी गतिविधियों के जरिये इसे काफी दूषित/प्रभावित कर दिया था।

पीएनएएस नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि 18 वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कोयले के जलने के उसके बायप्रोडक्ट्स (धुएं में मौजूद जहरीले पदार्थ) ने दसुओपु ग्लेशियर तक अपनी पहुंच बना ली थी। यह ग्लेशियर लंदन से 10, 300 किलोमीटर दूर स्थित है। माना जाता है कि लंदन से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी।

अमेरिकी की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के पोउलो गैब्रियल ने कहा, 'औद्योगिकी क्रांति ऊर्जा के उपयोग की क्रांति थी और इसीलिए कोयले का दहन भी उत्सर्जन का एक प्रमुख कारण था, जो हवाओं के जरिये हिमालय तक पहुंच गया था।'

शोधकर्ताओं का दल एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय टीम का हिस्सा था। यह टीम 1997 में दसुओपु की यात्रा पर गई थी। इस दौरान शोधकर्ताओं ने समुद्र तल से लगभग 7200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस ग्लेशियर के आइस कोर तक खोदाई कर यहां की जलवायु का महत्वपूर्ण डाटा जुटाया था। दासुओपु चीन के शीशापंगमा में स्थित विश्व के 14 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। ये सभी ऊंचे पर्वत हिमालय में ही स्थित हैं। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 1997 में दसुओपु के कोर से जुटाए गए 23 धातुओं के नमूनों का विश्लेषण किया।

समय रेखा का काम करते हैं बर्फ के टुकड़े : शोधकर्ताओं ने कहा कि बर्फ के टुकड़े एक समय रेखा का काम करते हैं और निश्चित समय बाद परतों में परिवर्तित हो जाते हैं। ग्लेशियरों की खोदाई करने पर पता चलता है कि जितने नीचे से बर्फ के टुकड़ों को विश्लेषण के लिए एकत्र किया जाता है कि वह उतने ही पुराने समय की जलवायु के बारे में बता सकते हैं।

जंगलों की आग से हुआ नुकसान : गैब्रियल ने कहा कि 18वीं सदी में जनसंख्या विस्फोट भी हुआ और लोगों की आय का मुख्य जरिया खेती ही थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हुई और खेतों के निर्माण के लिए लोगों ने जंगलों में आग भी लगाई गई। जिसके कारण वायुमंडल में कार्बन का स्तर काफी बढ़ गया और हवाएं चलने से यह कार्बन ग्लेशियरों तक पुहंच गया, जिसके कारण ग्लेशियर काफी प्रभावित हुए थे। अब जब उद्योग-धंधे बढ़ गए हैं तो इनकी स्थिति और खराब हो गई है।

जहरीली धातुओं की मौजूदगी

अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं पाया कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यानी लगभग वर्ष 1780 के आसपास बर्फ में कैडमियम, क्रोमियम, निकिल और जिंक यानी जस्ते सहित कई जहरीली धातुएं भारी मात्रा में मौजूद थी। इनमें से ज्यादातर धातुएं कोयले के बायप्रोडक्ट्स हैं, जो 18 वीं शताब्दी के अंत में और 19 वीं और 20 वीं शताब्दी में उद्योग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि इसका मतलब है कि ये धातुएं हवा के जरिये पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई आईं, जिसके कारण हिमालय के ग्लेशियर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हिमालयी ग्लेशियरों में जिंक की मात्रा बढ़ने के संबंध में शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 18वीं सदी के अंत में भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई और जंगलों की आग से कारण वायुमंडल में जिंक की मात्रा बढ़ी होगी।

अच्छी जॉब चाहते हैं तो सोच–समझ कर करें सोशल मीडिया पर पोस्ट

- अमेरिका की पेंसिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया अध्ययन
- कहा–विवादास्पद मुद्दों पर राय न रखने से मिल सकता है फायदा

प्रतीकात्मक

न्यूयॉर्क, आइएएनएस : यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं तो विवादित मुद्दों पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से बचें। यदि आप ऐसे विषयों पर अपनी राय फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसी सोशल साइटों में रखते हैं तो हो सकता है कोई काम आपको मिलते-मिलते रह जाए। एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है नियोक्ता ऐसे अभ्यर्थियों का चयन करने से बचते हैं जो विवादित मुद्दों पर भी सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिलेक्शन एंड असेसमेंट में प्रकाशित इस अध्ययन में पाया गया कि ऐसे लोगों की नियुक्ति होने की संभावना भी कम रहती है जो ड्रग्स या शराब के उपयोग की सामग्री पोस्ट करते हैं।

अमेरिका की पेंसिलवेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के माइकल टस ने 'करियर बिल्डर' के हवाले से बताया कि वर्ष 2018 में 70 फीसद नियोक्ताओं ने अपने संभावित कर्मचारियों की सोशल मीडिया पोस्टों का मूल्यांकन किया और नकारात्मक और विवादित मुद्दों पर टीका-टिप्पणी करने वाले 60 फीसद अभ्यर्थियों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि इसलिए कहा जा सकता है कि जॉब की तलाश कर रहे लोगों को सोशल मीडिया कर पोस्ट करने से पहले तटस्थ रहना चाहिए क्योंकि प्रबंधकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण होता है कि जिनका वे चयन करने जा रहे हैं, उनमें नकारात्मकता तो नहीं भरी पड़ी है। या वे कितना सकारात्मक सोचते हैं और अपने काम को कैसे अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। दरअसल, लोगों के चाल-चलन में उनकी मानसिक स्थिति और कार्यक्षमता परिलक्षित होती है।

ऐसे किया अध्ययन : इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने नियोक्ताओं के निर्णय को प्रभावित करने वाले तीन नकारात्मक विषयों (आत्म तल्लीनता, स्वच्छंदता और शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल) को लेकर जांच की। इसके लिए उन्होंने अलग-अलग संस्थानों के 436 नियोक्ताओं की निर्णय प्रक्रिया का आकलन किया। शोधकर्ताओं ने सभी संस्थानों को काल्पनिक अभ्यर्थियों का पर्चा दिया, जिसमें सभी सवालों के जवाब शानदार तरीके से दिए गए थे। नियोक्ताओं को अभ्यर्थी की फेसबुक प्रोफाइल की समीक्षा कर नौकरी मिलने की संभावना बताने को कहा गया। प्रोफाइल को देखने के बाद नियोक्ताओं ने अपने संस्थान के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चुनाव किया।

आत्म–तल्लीनता है नुकसानदेह : शोधकर्ताओं ने बताया कि नियोक्ताओं ने आत्म-तल्लीनता को नौकरी पाने के लिए नकारात्मक गुण के रूप में देखा। टस ने कहा कि सोशल मीडिया साइट्स आत्म तल्लीनता को बढ़ाने का काम करती हैं। नियोक्ता यह देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप में ही ज्यादा तल्लीन रहते हैं उनसे अन्य कर्मचारियों और संस्थान को फायदा होने की संभावना कितनी होगी... क्योंकि वे लोग अपने में ही गुम रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है वे अपना काम तक नहीं कर पाते ऐसे में संस्थान का काम भी प्रभावित होता है।

योग्यता को प्रभावित करती है नकारात्मक पोस्ट : अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि सोशल मीडिया साइटों के जरिये लोग किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपने विचार रखते हैं। ऐसे में कई बार लोग ऐसी पोस्ट भी शेयर कर देते हैं जो विवाद पैदा कर देते हैं और धर्म-संप्रदायों के बीच लड़ाई का कारण भी बन जाते हैं। नियोक्ताओं ने ऐसे लोगों की गणना झगड़ालू और असहयोगी के तौर पर की है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ऐसे पोस्ट अभ्यर्थी की योग्यता से अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए जॉब की तलाश कर रहे लोगों को चाहिए कि वे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐसी कोई भी पोस्ट न करें जिससे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो या लोग एक-दूसरे के बैरी बनते हों।

इधर–उधर की

लड़की के गंदे नाखून ने चुरा ली सगाई की खुशी

लंदन, एजेंसी : शादी–सगाई की खुशियों में दूसरों को शामिल करने के लिए हम

अक्सर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, लेकिन कई बार ये ही चीजें हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती है। एक लड़की ने फेसबुक पर हाथ में पहनी सगाई की अंगूठी शेयर की। यह अंगूठी उसके हाथ में फंसती नजर आने पर लोगों ने शुभकामनाओं के साथ इसे ठीक कराने की सलाह भी दे डाली। हालांकि लोगों की नजर जब नाखून पर पड़ी तो सलाह की जगह आलोचना ने ले ली। बहुत से लोगों ने नाखून को लेकर कमेंट करने शुरू कर दिए। लड़की के नाखून तस्वीर में बहुत ही गंदे नजर आ रहे थे। कुछ लोगों ने लिखा कि इतने गंदे नाखूनों के साथ कैसे रह सकती हो तो दूसरे ने लिखा कि गंदे नाखूनों के लिए लोग शर्मिंदा क्यों नहीं होते। कुछ लोगों ने बधाई दी और कहा कि हमें उसकी खुशी को कम नहीं करना चाहिए। साथ ही, लोगों से अपील की कि वह खुशी के मौके पर आलोचनाएं ना करें।

तलाशी राह ▸ राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने विकसित की नई तकनीक

बनेंगे सस्ते नैनो–इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

नई दिल्ली, आइएसडब्ल्यू : इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निर्माण में उपयोग होने वाली विद्युत की संवाहक स्याही से लेकर टच स्क्रीन और इन्फ्रारेड शील्ड्स तक विभिन्न नैनो-इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विकास में नैनोवायर का महत्व लगातार बढ़ रहा है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे के शोधकर्ताओं ने सिल्वर नैनोवायर के निर्माण की किफायती तकनीक विकसित की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नई तकनीक की मदद से बड़े पैमाने पर भविष्य के नैनो-इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाए जा सकते हैं।

मनुष्य के बालों से सैकड़ों गुना पतले नैनोवायर की सतह इलेक्ट्रॉन्स की स्टोरेज और ट्रांसफर के अनुकूल होती है, जिसका उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) के महानिदेश डॉ. शेखर सी. मांडे ने हाल में पुणे स्थित एनसीएल परिसर में नैनोवायर उत्पादन के लिए एक पायलट प्लांट स्थापित किया है। इस प्लांट के बारे में कहा जा रहा है कि यह निरंतर नैनोवायर उत्पादन की क्षमता रखता है।

यह पायलट प्लांट एक दिन में 500 ग्राम नैनोवायर का उत्पादन कर सकता है।

- नैनोवायर उत्पादन के लिए एक स्थापित किया है पायलट प्लांट
- एक दिन में 500 ग्राम नैनोवायर का कर सकता है उत्पादन
- वैश्विक दरों से कम से कम 12 गुना सस्ते होंगे सिल्वर नैनोवायर्स

नैनोवायर उत्पादन के लिए स्थापित किए गए प्लांट का अवलोकन करते राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे के वैज्ञानिक। साभार : आइएसडब्ल्यू

शोधकर्ताओं का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर उत्पादन दर को बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न आकारों (20 से 100 नैनोमीटर व्यास) के सिल्वर नैनोवायर्स का अंतरराष्ट्रीय बाजार मूल्य 18,000 से रुपये 43,000 रुपये प्रति ग्राम तक है। जबकि, इस तकनीक से उत्पादित सिल्वर नैनोवायर्स वैश्विक दरों से कम से कम 12 गुना सस्ते हैं। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त नैनोवायर्स के निर्माण के लिए इस उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग किया जा सकता है।

रसायन विज्ञान की संश्लेषण विधि : एनसीएल के केमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोसेस डेवलपमेंट डिविजन के प्रमुख शोधकर्ता डॉ. अमोल कुलकर्णी ने बताया कि यह रसायन विज्ञान की एक प्रचलित संश्लेषण विधि है, जिसे प्रयोगशाला में नियंत्रित मापदंडों के अनुसार, अंजाम दिया जाता है। इस नई पद्धति का उद्देश्य एक ऐसी तकनीक का निर्माण करना है, जो विद्युत रसायनों के क्षेत्र में अपनी पहचान कायम कर सके। भविष्य में इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव आएगा।

पेटेंट के लिए किया आवेदन

भारत नैनोवायर की अपनी जरूरतों के लिए फिलहाल आयात पर निर्भर है। यह नई तकनीक बड़े पैमाने पर सटीक नैनोवायर के उत्पादन में मददगार हो सकती है। इस प्रौद्योगिकी की सुरक्षा के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किए गए हैं। इस पायलट प्लांट पर उत्पादित नैनोवायर का परीक्षण विद्युत की संवाहक स्याही सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया गया है।

अवसरों की नहीं है कमी

डॉ. मांडे ने कहा है कि नैनोवायर्स का एक विस्तृत वैश्विक बाजार है। इसलिए इसे बनाने वाले उत्पादकों के लिए इस क्षेत्र में अवसरों की कमी नहीं है। सीएसआइआर की यह पहल दीर्घकालिक प्रासंगिकता के इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रवेश करने में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है। नैनोवायर उत्पादन की इस तकनीक का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एडवांस्ड मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (एएमटी) पहल पर आधारित है।

फोटो न्यूज

...और प्रिंस विलियम ने मार ली बाजी

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने मंगलवार को लफबरो स्थित डिफेंस मेडिकल रिहैबिलिटेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर प्रिंस विलियम ने मरीजों के साथ व्हीलचेयर बास्केटबॉल में हिस्सा लिया। व्हीलचेयर पर बैठकर विलियम ने बॉल को बॉस्केट की तरफ उछाला लेकिन चूक गए। ऐसे में साथ में मौजूद उनके पिता और प्रिंस चार्ल्स आगे बढ़कर विलियम के कंधों को सहलाते हुए हौसला अफजाई की। विलियम ने फिर कोशिश की और इस बार वह सफल हो गए। एपी

असमय मौत का कारण बनता है ओजोन प्रदूषण

शोध अनुसंधान

वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर हमारी धरती को बचाने वाली ओजोन गैस जमीनी स्तर पर इंसानों के लिए घातक बन सकती है। एक नए अध्ययन में पाया गया है कि ओजोन प्रदूषण वाली आबोहवा में रोजाना रहने से असमय मौत का खतरा बढ़ सकता है। यह निष्कर्ष 20 देशों के 400 से ज्यादा शहरों में किए गए अध्ययन के आधार पर निकाला गया है। इसमें पाया गया कि विभिन्न देश अगर वायु गुणवत्ता के मानकों को सख्ती से लागू करें तो छह हजार से ज्यादा लोगों को असमय मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है। ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने शहरी और उपनगरीय इलाकों में जमीनी स्तर पर उच्च प्रतिक्रिया वाली ओजोन को पाया। ओजोन ऑक्सीजन के तीन अणुओं से मिलकर बनी गैस है। सांस के जरिये शरीर में पहुंचने पर यह फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। -प्रेट्र

टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर से महिलाओं में डायबिटीज का रहता है खतरा

शोधकर्ताओं का कहना है कि जिन महिलाओं में आनुवांशिक तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उच्च स्तर होता है, उनमें टाइप–2 डायबिटीज जैसे मेटाबोलिक रोग का खतरा बढ़ सकता है। नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, टेस्टोस्टेरोन के उच्च स्तर के कारण महिलाओं में स्तन कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। जबकि पुरुषों में इस हार्मोन के उच्च स्तर के चलते प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। यह निष्कर्ष कई अध्ययनों के विश्लेषण के आधार पर निकाला गया है। आनुवांशिक तौर पर उच्च टेस्टोस्टेरोन वाली महिलाओं में टाइप–2 डायबिटीज का खतरा 37 फीसद ज्यादा पाया गया। जबकि पुरुषों में इस हार्मोन के उच्च स्तर के चलते टाइप–2 डायबिटीज का खतरा 14 फीसद कम पाया गया। ब्रिटेन की एक्सेटर यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता कैथरीन रुथ ने कहा, 'हमारे नतीजों से जाहिर होता है कि बीमारी पर टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव की गहराई से पड़ताल की गई है। इसका स्तर संतुलित रखने से लाभ मिल सकता है।' -आइएएनएस

स्क्रीन शॉट

मैं सुस्त हूं, नौ साल लग गए सिंगल लाने में : अदनान

हाल में पद्मश्री से नवाजे गए गायक अदनान सामी नौ साल के अंतराल के बाद अपना सिंगल 'तू याद आया' लेकर आए हैं। मंगलवार को मुंबई में सिंगल के लॉन्च के मौके पर इतने लंबे अंतराल के सवाल के जवाब में अदनान ने मजाकिया लहजे में कहा कि वह सुस्त हैं। यही वजह रही कि उन्हें सिंगल लाने में इतना लंबा वक्त लग गया। उन्होंने कहा, दरअसल, मैं और टी-सीरीज के भूषण कुमार काफी समय से दोस्त हैं। हम काफी अर्से से साथ में काम नहीं कर रहे थे लेकिन साथ में काम करने की बात कर रहे थे। इतना वक्त कैसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। जब हमने वाकई सोचा कि आखिरी बार कब एक साथ काम किया था तो लगा नौ साल हो गए। इस मौके पर भूषण कुमार ने बताया कि अदनान के गाने 'तेरा चेहरा' को किसी फिल्म में लाने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वह गजलों की एक सीरीज भी लाने की तैयारी में हैं। यह मौजूदा गायकों के साथ होगी। उसे भी जल्द ही लांच किया जाएगा।

अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर के बीच की टेलीपैथी

सोशल मीडिया पर सक्रिय अमिताभ बच्चन अक्सर कभी अपने विचार,अपने परिवार और इंडस्ट्री में अपने करीबियों को लेकर कुछ न कुछ ट्वीट करते रहते हैं। इस बार उन्होंने अपने 3438वें ट्वीट में जिक्र किया है भारत रत्न और स्वरकोकिला लता मंगेशकर का। उन्होंने लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ उनके बचपन की एक तस्वीर साझा की है। तस्वीर में लता दीदी और आशा ताई को पहचानना मुश्किल है। इस तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'लता जी और आशा जी के बचपन का चित्र। आज लता जी के ट्वीट में पढ़ा कैसे उन्होंने अपने गुरुओं को याद किया और अचानक यह चित्र मुझे मिल गया! टेलीपैथी!!' दरअसल, लता मंगेशकर ने

मंगलवार को अपने गुरुओं को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने लिखा था, 'आज मेरे पिता समान कवि पंडित नरेंद्र शर्मा जी और मेरे आध्यात्मिक गुरु पंडित जम्मू महाराज जी की पुण्यतिथि है। मैं इन दोनों महान विभूतियों को कोटि-कोटि प्रणाम करती हूं।' इस ट्वीट के साथ उन्होंने वर्ष 1983 की फिल्म 'सुबह' के गाने 'तुम आशा विश्वास हमारे...' वीडियो भी पोस्ट किया है।

शादी की सालगिरह पर संजय और मान्यता ने एक–दूसरे को दी बधाई

संजय दत्त और मान्यता दत्त ने मंगलवार को अपनी शादी की बारहवीं सालगिरह मनाई। दोनों ने 11 फरवरी, 2008 को शादी के फेरे लिए थे। इस मौके पर संजय और मान्यता ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को बधाई दी। मान्यता के साथ कई तस्वीरों वाले वीडियो को साझा करते हुए संजय ने लिखा, 'मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बिना मैं क्या करता। शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं मान्यता...।' वहीं मान्यता ने संजय के साथ एक तस्वीर साझा कर उन्हें सालगिरह की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, 'दुनिया में यह सबसे अच्छा अनुभव है कि हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए कोई हमेशा हमारे साथ रहे। इतने वर्षों से मेरी जिंदगी में वह इंसान

बनने के लिए धन्यवाद संजय। आगे भी इसी तरह मेरे साथ रहना।' शादी की सालगिरह पर संजय के प्रशंसकों ने भी उनको शुभकामनाएं दीं। यह संजय की तीसरी शादी है। उन्होंने पहली शादी साल 1987 में रिचा शर्मा से की थी। ब्रेन ट्यूमर से रिचा की मौत के बाद उन्होंने साल 1998 में रिया पिल्लई से दूसरी शादी की। दोनों के बीच साल 2008 में तलाक हो गया था। संजय और मान्यता के जुड़वा बच्चे शहरान और इकरा हैं।

'कभी ईद कभी दिवाली' में सलमान संग होंगी पूजा हेगड़े

सलमान खान की फिल्मों में हीरोइन को लेकर हमेशा ही एक दिलचस्पी बनी रहती है। जब से सलमान खान ने अगले साल ईद पर रिलीज होने वाली अपनी फिल्म 'कभी ईद कभी दिवाली' की घोषणा की है, तब से उसकी हीरोइन को लेकर चर्चा गर्म थी। अब इससे पर्दा उठ चुका है। 'कभी ईद कभी दिवाली' के लिए पूजा हेगड़े को फाइनल कर लिया गया है। रितिक रोशन के साथ फिल्म 'मोहनजो दारो' से हिंदी फिल्मों में डेब्यू करने वाली अभिनेत्री पूजा हेगड़े हाल ही में फिल्म 'हाउसफुल 4' में नजर आई थीं। यह पूजा की तीसरी हिंदी फिल्म होगी। पूजा पहली बार सलमान के साथ स्क्रीन साझा करेंगी।

फिल्म के निर्माता और लेखक साजिद नाडियाडवाला का कहना है कि 'हाउसफुल 4' में पूजा के

साथ काम करने के बाद उन्हें लगा कि वह इस फिल्म के लिए एकदम परफेक्ट हैं। साजिद का कहना है कि सलमान और पूजा की जोड़ी पहली बार बन रही है इसलिए अक्टूबर में शूटिंग शुरू होने से पहले दोनों के लिए एक वर्कशॉप रखी जाएगी। खबरे हैं कि फिल्म में सलमान खान बिल्कुल नए अवतार में होंगे। उनके लुक पर काम चल रहा है।

एशिया के सबसे बड़े शिपयार्ड में हुई भूत फिल्म की शूटिंग

फिल्म में वास्तविकता लाने के लिए मेकर्स हर संभव कोशिश करते हैं। ऐसी ही एक कोशिश फिल्म 'भूत पार्ट वनः द हॉन्टेड शिप' के लिए भी की गई है। इस फिल्म में एक भुतहा जहाज दिखाया गया है, जो किनारे आकर खड़ा हो जाता है। इस डरावने जहाज के लिए मेकर्स को वास्तविक जहाज की जरूरत थी इसलिए उन्होंने गुजरात के अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड में इसे शूट किया। यह यार्ड एशिया का सबसे बड़ा शिपयार्ड है जहां बड़े-बड़े जहाजों को तोड़ा जाता है। फिल्म के लेखक और निर्देशक भानु प्रताप सिंह का कहना है कि इस फिल्म को शूट करने के लिए वह परफेक्ट जगह थी। लेकिन वहां शूट करना उनके लिए आसान नहीं था। भानु प्रताप के मुताबिक एशिया के सबसे बड़े शिप ब्रेकिंग यार्ड में शूट करने की परमिशन लेने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। इसे पहले फिल्मों में इस जगह को कभी दिखाया नहीं गया है। ऐसे में अधिकारियों को मनाने के लिए फिल्म से जुड़े लोगों को भावनगर

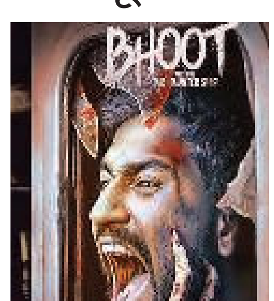

में एक महीने तक रुकना पड़ा था। काफी मेहनत करने के बाद वहां फिल्म शूटिंग की इजाजत मिल गई। उन्होंने यह भी बताया कि शूटिंग से पहले हमें साफ कर दिया गया था कि वहां पर हम कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या स्मोक नहीं ले जाएंगे क्योंकि उससे आग लगने का खतरा था।

भानु प्रताप ने यह भी बताया कि जहाज पर पावर सप्लाई नहीं थी, ऐसे में उन्हें छोटी लाइट्स से काम चलाना पड़ रहा था। फिल्म में विक्की कौशल और भूमि पेडणेकर मुख्य भूमिका में हैं।

'लव आज कल' के अंतरंग सीन पर चली सेंसर की कैंची

कार्तिक आर्यन और सारा अली खान अभिनीत फिल्म 'लव आज कल' को सेंसर बोर्ड ने यू/ए सर्टिफिकेट दिया है। इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सारा और कार्तिक के कई अंतरंग दृश्यों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कैंची चला दी है। खबरों के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए किसिंग सीन को छोटा करवा दिया है। साथ ही, एक लव मेकिंग सीन में भी सुधार करवाया है। फिल्म के दूसरे हिस्से में कलाकारों के कपड़े उतारने वाले

दृश्यों को भी हटा दिया गया है। कई जगहों पर फिल्म के ऑडियो को भी सेंसर और म्यूट किया गया है। गालियों को भी दूसरे शब्दों में तब्दील करने के लिए कहा गया है।